

Sixth Series, No. 35

Wednesday, April 11, 1979

Chaitra 21, 1901 (Saka)

## **Lok Sabha Debates**

**(Seventh Session)**



**LOK SABHA SECRETARIAT**

**New Delhi**

**Price Rs-4.00**

## CONTENTS

*No. 35, Wednesday, April 11, 1979, Chairra 21, 1901 (SAKA)*

	COLUMNS
Oral Answers to Questions.	.
* Starred Questions Nos. 680 to 685 and 687	1—25
Written Answers to Questions :	
Starred Questions Nos. 686, 688 to 699 and 701	26—40
Unstarred Questions Nos. 6601 to 6605, 6607 to 6621, 6623 6623 to 6646, 6648 to 6745, 6747 to 6770 and 6772 to 6800	40—256
Correcting Statement to Unstarred Question No. 4343 dated 20-12-1978	256—258
Re. Motion for Adjournment	258, 261— 263
Papers Laid on the Table	258—260
Committee on Private Members' Bills and Resolutions:	
Thirty-first Report	263
Committee on Papers Laid on the Table:	
Fifteenth Report	263
Committee on Petitions:	
Ninth Report	268
Public Account Committee:	
Hundred and Twenty-second Report	268
Committee on Public Undertakings:	
Twenty-second and thirty-third Reports	268—269
Matters Under Rule 377—	
(i) Need for the abolition of capital punishment:	
Shri Ram Vilas Paswan	269—270

---

The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

(ii) Amenities to the workers of the Steel Yard in Mandi Govind Garh, Punjab:	270-271
Shri P. Rajagopal Naidu . . . . .	270-271
(iii) Reported strike by the employees of Indian Agricultural Research Institute, Pusa, New Delhi:	
Shri Saugata Roy . . . . .	272
(iv) Reported Power crisis in West Bengal:	
Prof. Samar Guha . . . . .	273
Re : Discussion on Demands for Grants . . . . .	273-274
Demands for Grants, 1979-80 . . . . .	274-373
Ministry of Agriculture and Irrigation:	
Shri Nathu Singh . . . . .	274-277
Shri K. Suryanarayana . . . . .	277-282
Shri Mukhtiar Singh Malik . . . . .	282-287
Shri Palas Barman . . . . .	287-290
Shri Tej Pratap Singh . . . . .	290-294
Shri Kacharulal Hemraj Jain . . . . .	294-296
Shri Chandra Shekhar Singh . . . . .	296-303
Shri Venugopal Gounder . . . . .	303-307
Shri Bharat Bhushan . . . . .	307-311
Shri B. K. Nair . . . . .	312-317
Shri R. P. Das . . . . .	317-323
Shri Baldev Singh Jasrotia . . . . .	324-326
Shri Dajiba Desai . . . . .	327-330
Chowdhry Balbir Singh . . . . .	331-334
Shri A. C. George . . . . .	335-339
Shri Dharamasinhbhai Patel . . . . .	339-342
Shri A. R. Badri Narayan . . . . .	342-346
Shri Bhanu Pratap Singh . . . . .	347-358
Shri M. Ram Gopal Reddy . . . . .	358-360
Shri Harikesh Bahadur . . . . .	361-365
Shri K. Mallanna . . . . .	365-369
Shri Hakum Deo Narain Yadav . . . . .	369-373
Half-an-hour Discussion:	
Postal Accounts in Haryana:	
Shrimati Mrinal Gore . . . . .	373-375
Dr. Ramji Singh . . . . .	375-376
Shri Brij Lal Verma . . . . .	376-380

## LOK SABHA DEBATES

Wednesday, April 11, 1979/Chaitra 21,  
1901 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the  
Clock

[MR. SPEAKER in the Chair]

### ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

#### Seepage of Cement

+

\*680. SHRI NATHU SINGH:

SHRI CHATURBHUJ:

Will the Minister of INDUSTRY  
be pleased to state:

(a) whether Government are aware  
of the widespread discontent among  
the consumers of cement due to seep-  
age of cement from 10 per cent to 40  
per cent;

(b) whether Government propose  
to make it mandatory on cement com-  
panies to use kraft paper bags or  
paper laminated jute sacks to prevent  
seepage of cement; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF INDUSTRY  
(SHRI GEORGE FERNANDES): (a) to (c). Complaints have been received  
from consumers of loss of cement  
from the jute bags due to seepage of  
varying quantities. Government have  
taken action to encourage the deve-  
lopment of better types of jute bags  
which would minimise seepage to the

extent possible. Two different types  
of improved jute bags are currently  
undergoing mass trials to judge their  
suitability. Government are also  
considering reduction of the propor-  
tion of second-hand bags to the mini-  
mum to keep down seepage. It is not  
considered economical to use kraft  
paper bags or laminated jute sacks for  
packaging cement.

श्री नाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं  
आपको बधाई देता हूँ कि आज के दिन और आपके  
नाम को इतिहास याद रखेगा, क्योंकि पार्लियामेंटरी  
प्रैविटेस के इतिहास में पहली बार यह हुआ है कि आप  
चार मिनट देरी से आये हैं।

एक माननीय सदस्य : कोरम नहीं था।

श्री ज्योतिर्मय बसु : जब तक कोरम नहीं होगा  
तब तक वह नहीं आ सकते हैं। (व्यवधान,)

MR. SPEAKER: You cannot have  
both things.

श्री नाथ सिंह : मैं ने आपको धन्यवाद और बधाई  
दी है। अभी मंत्री महोदय ने बताया कि हम इस  
बारे में प्रयास कर रहे हैं। आपको मालूम होगा कि  
इस समय सीमेंट का जितना अधिक ब्लैक हो रहा है,  
उतना शायद कभी नहीं हुआ है। इसके साथ साथ  
उपभोक्ताओं को दूसरे तरीके से यह नुकसान हो रहा है  
कि सीमेंट को रखने के लिए जो बैग्ज, बोरे, बनाये  
जाते हैं, उनमें से बहुत सा सीमेंट बाहर निकल जाता  
है और उपभोक्ताओं को सीमेंट बहुत कम मात्रा में  
मिल पाता है। इसके बारे में आज तक कोई प्रयास  
नहीं हुआ है।

इसके अलावा कुछ लोग लाभ उठाने के लिए  
पत्थर पीस कर और राख की सीमेंट में मिला देते हैं।  
सीमेंट की स्थिति बहुत नाज़क होती जा रही है। बहुत  
खराब सीमेंट मिलता है, जिसकी बजह से बड़ी बड़ी  
विलिंडरज और पुलियां बगैरह टट जाती हैं। क्या  
सरकार कोई ऐसा इन्तजाम करेगी कि जब सीमेंट  
कंपनियों में कट्टूं या बोरों में सीमेंट भरा जाता है,  
उससे पहले उनकी जांच हो, ताकि सीमेंट का सीपैज  
न हो? जो पुराने बोरे फट चुके हैं, खराब हो चुके  
हैं, क्या सरकार उनके इस्तेमाल पर पावन्दी लगायेगी  
और यह व्यवस्था करेगी कि नये बैग्ज काम में लाये  
जायें?

श्री जार्ज़ क्रान्स्टीस : इस समय अधिकांश बोरे ने इस्तेमाल किये जाते हैं, भगव बुल्ल पुराने भी इस्तेमाल किये जाते हैं। भगव सीपेज का सबात केवल पुराने बोरों का नहीं है, नये बोरों के बारे में भी यह कहा जा सकता है। आम तोर पर यह सही है कि लगभग 5 फीसदी सीमेंट सीपेज से निकल सकता है। इस बारे में हम कई काम कर चके हैं। एक तो सीमेंट रेग्युलेशन एकाइट की मदद से सीमेंट रिसर्च हस्टी-ड्यूट्स के माध्यम से काम करा कर हम दो कंपनियों द्वारा बनाये गये नये बोरों को बाजार में लाए रहे हैं, और उसके अनुबंध के आधार पर हम आगे का काम करेंगे।

माननीय सदस्य ने मिलाकट बोरर की बात शेखी। अधिकांश राज्य सरकारों ने सीमेंट के वितरण की जिम्मेदारी अपने हाथ में ली ही है। जो एक ये राज्य बचे हैं, हम प्रयत्न कर रहे हैं कि वे भी हम के वितरण की जिम्मेदारी अपने हाथ में लें, और इस प्रकार राज्य सरकारें इन मारी शिकायतों को दूर करने के लिए कदम बढ़ायें।

श्री नाथ सिंह : मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वह इस बारे में बहुत जागरूक है। क्या वह बतायेगे कि सीमेंट इम्पोर्ट किया जाता है, उसमें कौन से बैंज काम में लाये जाते हैं—जूट के बने हुए या पालियोन के बने हुए? यदि उसमें पालियोन के बैंज काम में आते हैं, जो बरसात में पानी से सीमेंट को खुराक नहीं होने देते हैं, और जो बहुत ड्यूरेबल हैं, तो क्या सरकार का इस तरह का कोई विचार है कि जूट के बैंज के बैंज को बैंज अधिक काम में लाये जायें? जट के बैंज भी इस्तेमाल किये जायें, ताकि जट हॉटस्टूप को भी नुकसान न हो, लेकिन हुआ मात्रा में पालियोन के बैंज भी काम में लाये जायें, जिससे सीमेंट का रखाव टीक रुग्न से ही सके।

श्री जार्ज़ क्रान्स्टीस : यह सही है कि विदेशी सीमेंट का आवायत वेपर पालियोन बैंज में हो रहा है। लेकिन हमारे यहां एक असें से सीमेंट बेंचने का काम जूट के बोरों में ही होता रहा है, और जूट उद्योग का भविष्य भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। इस लिए मैं नहीं सहमत हूँ कि हम इस समय इससे कोई बदल कर सकते हैं। भगव यह भी बात है कि ये को कामज और पोलियोन के बोरे में जूट के बोरे से हूँ। माननीय सदस्य यह भी ब्यान में रखें।

SHRI JYOTIRMOY BASU: It is a fact that due to serious regional imbalance in the field of production while the cost of production in all plants for a bag of cement is Rs. 4/- and in a new plant Rs. 5/-, the black-market price today has touched the figure of Rs. 60/- per bag. I would like to know from the hon. Minister whether it is or it is not a fact that on an average, a bag of cement has

to travel 685 kms. from the point of production to the point of consumption which is much higher than what is used to be sometime ago?

SHRI GEORGE FERNANDES: It is true that the cement has to travel a little longer distance than it used to be in the past. But we are trying to resolve this problem to the extent possible. There are obvious difficulties because cement plants are located in certain parts of the country.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: It is a serious regional imbalance.

SHRI GEORGE FERNANDES: We have inherited this imbalance. There is nothing that I can do overnight to set it right. But in respect of the new cement units that we are now commissioning, we are now going in for split location plants where the circling of the limestone would be done at one place where the limestone is available and the grinding would be done as far as possible at the principal points of consumption. We have started adopting this new policy. But it will take two years before it really comes into effect. So, we are going to have the problem for a while.

So far as black-marketing is concerned, I want to insist again that today the State Governments are distributing cement. We appealed to the State Governments. There is nothing that I can do as Minister of Industry to end this if the State Governments do not cooperate. Every State Government today is responsible for distributing cement through their agencies and stockists. I would like the State Governments to be a little more concerned about this question and appoint only such stockists who do not indulge in black-marketing. Wherever a stockist indulges in black-marketing, it is possible for the Police and the district administration to identify him and get rid of him. This the State Governments must do and help us.

**बीचरी बलवीर सिंह :** क्या मंत्री महीदय इस बात को कोशिश करेंगे कि जैसे आर्ट की जो बोरिया होती है उनके अंदर पोलिथिन का एक पैकेज जुदा तोर पर दौता है और बाहर दूसरा जूट बैग होता है, जबी तरह सीमेट में भी बह कर दें? अगर वह कहत है कि बाहर से ट्रैपट नेपर या दूसरा पोलिथिन का बैग मगवाने में ज्यादा खर्च होता है तो पोलिथिन जो यहां बनता है और आद में प्रालरेडी बह इट्रोड्यूस्ट है उस सिम्टम को क्या यहा इट्रोइटम करेंगे ताकि बर्गत में बाहर का पानी भी असर न कर सके और बोरी जब गिरती है तो उसमें सीमेट बाहर न निकल सके? एक बार अगर बोरी सीमेट की नीचे गिर जाये तो एक किलो हर बार उसमें से सीमेट बाहर निकल जाती है। (व्यवहारान) . . . . . यह बात है कि दो बार सीमेट का थेला बह फेंक देने हैं, और उसमें से दो किला सीमेट निकल जाती है। तो यह बोर इससे कैक जाती है अगर पोलिथिन का रैप अलाहिदा से हो जाये और उपर जूट बैग हो जाये। . . . . (व्यवहारान)

**MR. SPEAKER:** This is an advice to the Government.

**बी बार्ब कर्नार्डोस :** यह जो नये बैग्स का भैने यहा चिक किया ये दो किलम के हैं। यह कहते हैं कि आज जो जूट बैग है उनको और अच्छे बैग से बीच करा कर जरा मजबूत बैग बनाए जायें, यह काम हो जूका है। दूसरे बिट्टीन लाइन बैग इस समय हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लीमिटेट बैग को इसमें इस्तेमाल ये लाना समव नहीं है, इस नियर्कर्प पर हम लोक पहुंच गए हैं।

**बी एम रामबोलाल रेहडी :** मध्यक जी, मधी मंडी जी ने कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर इसकी विभेदारी है। मैं कहता चाहता हूं कि स्टेट गवर्नमेंट्स पर विभेदारी ढालने से इसमें कोई सुधार नहीं हुआ है वजिक सीमेट की ट्रैक-मार्केट प्राइस और बह नहीं है। जहां पहले सीमेन्ट के एक बैग्स के पीछे 4-5 रप्प ट्रैक-मार्केट प्राइस थी वहां यह बह बढ़कर 10 रप्प ही नहीं है। इस तरह से स्टेट गवर्नमेंट्स पर विभेदारी ढाल करा, जो मालका मकान था कि आब कम हो जायें, बह मकान पूरा नहीं हुआ है। ऐसी हालत में क्या आप कोई दूसरा आल्टर्नेटिव सोच रहे हैं?

**बी बार्ब कर्नार्डोस :** इसके बारे में हम कात्तीत कर सेंगे।

**SHRI RAGAVALU MOHANARAN-GAM:** Even this size of the man cannot catch your eyes so easily!

Sir, it is a well-known fact that especially after the introduction of this permit system consumers are not in a position to get their cement very easily because of inordinate delay on the part of the officers. Here I am not going to talk about the State and the Centre because I know fully well that the hon. Minister has the knack of handling the problems very easily by saying that the State Governments are responsible for this. I want to know a very direct answer for this. Especially after the introduction of the permit system, there is inordinate delay on the part of the officers and the consumers are not in a position to get the permits very easily for their own construction work. I want to know the exact answer from the hon. Minister.

**SHRI GEORGE FERNANDES:** Sir, there is no Centre-State question involved in this. The distribution of cement is not done by the Ministry of Industry or by the Government of India. The allocation to the State is done by the Ministry of Industry, by the Cement Controller. In so far as the distribution is concerned, it is the State Government's Civil Supplies Department or the concerned Department of the State Government which is today concerned with the distribution of cement in the respective States. They are the ones to give the permits, they are the ones who appoint the stockists and they are the ones to regulate all this. So, as far as I am concerned...

**SHRI RAGAVALU MOHANARAN-GAM:** Let us not have the permit system....(Interruptions).

**SHRI GEORGE FERNANDES:** I am coming to that. It is for each State Government to decide how it wants to sell the cement and prevent black-marketing. I can only appeal to the State Governments to use the administrative machinery at their disposal

to see that any kind of malpractice is put down.

### Development of a Semi-Automatic Dialysis Machine

\*681. SHRI DHARMA VIR VASISHT: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the National Engineering Industries, Jaipur, had developed a semi-automatic peritoneal dialysis machine with complete indigenous material; and

(b) if so, whether it had passed the experimental stage together with the details of the unit?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI GEORGE FERNANDES): (a) and (b). It has been ascertained from National Engineering Industries Ltd., Jaipur that no dialysis machine, as such, has been developed by them. At the instance of the Doctors of Sawai Mansingh Hospital, Jaipur the Company's Engineers have only cooperated with the Doctors and developed, designed and manufactured an automatic pump to be used with the dialysis machine of the hospital to expedite dialysis. This pump is undergoing trial tests at the hospital.

SHRI SAUGATA ROY: Sir, this again is another question which has nothing to do with the Central Government. It is not in the national interests. It is meant to favour one company, that too belonging to Birlas. But these things are coming up in Lok Sabha.

SHRI VAYALAR RAVI: It must be in the national interests. Private interests cannot be discussed in this House. (Interruptions).

MR. SPEAKER: Please sit down. I cannot understand this type of disturbance. (Interruptions). There is nothing prohibiting to talk about a private company because the country is interested in knowing scientific developments. (Interruptions).

SHRI VAYALAR RAVI: This Parliament cannot be made so ridiculous.

(Interruptions)

SHRI RAGAVALU MOHANARANGAM: They talk so many things about the Members because they are raising a point on a particular company.

श्री धर्मवीर वासिष्ठ : अध्ययन में दोष, नेशनल हॉसिनियरिंग इंस्टीट्यूट में एक ऐसी मशीन डेवलप की गई है। मिनिस्टर साहब ने जवाब दिया है कि डायलेमिस बायातबूद ईंजाव नहीं की गई है लेकिन एक ऐसी स्वचालित परिप्रेरण मशीन जबर बनाई गई है जिससे डायलेमिस करने में जल्दी हो सके। यह मन्त्री महोदय यह बताना पसन्द करेगे कि जिससे जल्दी डायलेमिस हो सके और सुक्रिया हो सके—क्या ऐसी स्वचालित मशीन डेवलप की गई है ?

श्री जार्ज फर्नांडीस : प्रश्न नेशनल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट लिं. जयपुर के बारे में है जोकि विडमा को एक कम्पनी है—इंस्टीट्यूट के बारे में नहीं है। यह कम्पनी डायलेमिस मशीन बनाने वाली कम्पनी नहीं है।

Ball Roller and Taper Roller bearings, bicycle steel balls, Rolled Rings, Roller bearing Axleboxes, Spherical Roller bearings for Axleboxes, Steel Castings, Spindle Inserts and Jockey Pulleys.

इन जीवों को बनाने का नामसंस उनके पास है और यह जीवों वे बना रहे हैं। डायलेमिस के लिए, किसी ग्रोवडिंग या बरीज के इस्तेवाल में आगे बासे किसी यात्र के लिए उनके पास कोई लाइसेंस नहीं है और न कोई सम्बन्ध है। अस्पताल के डाक्टर्स यह ये और उन्होंने कहा कि हमारी एक समस्या है, इसमें अगर आप कोई यात्र कर सकते हैं तो करें। कम्पनी को जो इंजीनियरिंग है, उन्होंने अपने डॉग से इस काम को उरके उम अस्पताल को बाब वहूँचाने का काम किया है। इस काम को बना कर न हो देने का उनका कोई इरादा है और न यह कोई इस प्रकार का इंस्टीट्यूट है जो इसी तरह डेवेलपमेंट से सम्बन्धित है।

श्री धर्मवीर वासिष्ठ : जो स्वचालित पर्य बना है उसके लिये मिनिस्टर साहब ने बताया है कि इनका डायल हो रहा है। यह आप यह भी बनाने की रुपा करने कि यह डायल कितने दिनों से हो रहा है और अब तक उमका नामिया क्या रहा है ?

SHRI GEORGE FERNANDES: When we got the question, we made enquiries

and this is what the company has informed us:

—I am quoting from their letter—

“That facts are that the Sawai Mansingh Hospital, Jaipur has a dialysis machine. The doctors wanted improvement in the performance of this machine. Our engineers co-operated with them, developed, designed and manufactured an automatic pump to be used with this machine to expedite dialysis. This pump is under trial in the hospital. This was a gesture of our giving technical help in the field of medicine.”

They have got nothing out of this. Nor are we in a position to say that we will utilise their facilities to develop a dialysis machine.

**SHRI B. SHANKARANAND:** I am on a point of order on this question.

**MR. SPEAKER:** During Question hour, there is no point of order.

(Interruptions)

**MR. SPEAKER:** Mr. Saugata Roy takes upon himself the responsibility to decide.... (Interruptions).

**SHRI B. SHANKARANAND:** Members' right to ask questions depends upon certain rules and the question should be restricted under the Rules. My point of order is...

**MR. SPEAKER:** If questions on private companies are restricted, then many questions will not come.

What does the rule say?

**SHRI B. SHANKARANAND:** The right to ask a question is governed by the conditions mentioned in Rule 41(2). Sub-rules (vii) and (xvi)... (Interruptions).

**MR. SPEAKER:** There is no point of order during Question Hour. Research and Development is primarily the concern of the Central Government.

**SHRI B. SHANKARANAND:** This question is not on research and development.

Rule 41(2) says:

“The right to ask a question is governed by the following conditions, namely...”

Sub-rule (vii) reads:

“it shall not relate to a matter which is not primarily the concern of the Government of India”.

This question has nothing to do with the Government of India. Sub-rule (xvi) says:

“it shall not raise matters under the control of bodies or persons not primarily responsible to the Government of India.”

**MR. SPEAKER:** There is no point of order.... (Interruptions).

**MR. SPEAKER:** Qn. 682.

धंस घाटी लेत का विकास करने की योजना।

682. श्री अर्जुन तिह भवोरिया : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोटा से इटावा तक धंस घाटी लेत का मानविक विकास करने हेतु केन्द्रीय स्तर पर किन योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है ; और

(ब) इसके परिणामस्वरूप कितने परिवारों को लाभ पहुंचा है ?

योजना धंसालय में राज्य मंत्री (श्री कलातर इहमान) : अध्यक्ष जी, इसमें तीन तरह की स्कीमें बत रही है— 1. मैट्रल पायलेट प्राइवेट, जिससे समतल भूमि टीक रखी जाय, 2. कार्बोरेशन-डाइ-साइल, और 3. लंबवल-वेली की डेवलेप-मेंट स्कीम— ये तीन स्कीमें बत रही हैं।

जहां तक इसमें एम्प्लायमेंट देने की बात है— हर परिवार के मुताबिक इतिला देना मुश्किल है, लेकिन ये तमाम काम ही जाय तो समयम् 20 हजार रुपयों को परमामेंट गौकरी निल सकती है।

श्री अर्जुन तिह भवोरिया : अध्यक्ष जी, मैं आज प्रश्न बार किसी मंत्री को बताइ इस सभे दे रहा हूँ कि उन्होंने इस सवाल के जवाब को समाप्त किया

पर न रख कर मदन में इस का उत्तर दिया है। ब्रांड से ये उत्तर बन कर आते हैं—वट नानिंग कमीशन एक मफेद हाथी है और प जवाहरलाल नेहरू से इस मफेद हाथी को जन्म दिया था। लेकिन वे याय महावन थे, जो उम पर सवारी करते थे और अक्षय भी रखने पर, लेकिन अब यह मांड हाथी यह नानिंग कमीशन, बिल्ल द्वीप ही निर्दूष हो गया है। और बांग पर नीकुण्ठारी बैठ कर जिम हग से मदना के उत्तर बनाने हैं, वह उचित नहीं है। इस सवाल का जा उत्तर अभी प्राप्त नहीं है। म आर्थी प्राप्ता में यह जानना चाहता हूँ कि पहले मन 1970-71 में तकालीन प्रयान मवी ती तरह जो जा 100 फूँ मी०, शंदारिन एकोनामिक कम्युनिटा की महायता स होने वाला काम था, उमको दृष्टि के लिए तकालीन प्रधान मवी न एक कमेटी वा निर्माण किया था लेकिन बनाना रारकार न उम कमेटी को भग कर दिया और इमरा कमेटी का जन्म नहीं दिया है, तो क्या फिर मवी महादय दूरप डाकुओं से अतिक्रम उन भयहर दूरप वादियों चम्बल, यमुना, क्वारी और अन्य महावक नदियों के कटाव और वहा की जनता की कठिनाइयों, उनके अधावयस्त जीवन और उसी प्रावयस्ताद्वारा का देव कर उनके अनुकूल कार्द योजना बनी हुई है या जो बनी है तो उम किस तरह से अग्रल हो, इसके लिये बोर्ड पालियामेट्री टीम बनाने के लिए, क्या वे कार्द स्वीकृति दा।

श्री कल्पन रहमान माननीय मदस्य न मवाल ता बा० तन्वा किया। मैं यहा बनावा चाहता हूँ कि ऐसे जो लोन विधयों का नाम लिया है, वे लोनों स्थीमे आपके लिये हैं। उममे डाकुओं की बैली और जो आपको जीवनी है, जो आप का जीवन है, वह सब करव ही जाना है। अब जहा तक पालियामेट्री कमेटी बनाने की वात है तो अध्यक्ष महोदय, आप तो हाउम के सर्वेसर्वी हैं। अगर आप कोई कमेटी बनाते हैं तो मैं उममे रोड नहीं बन सकता।

श्री अमृत सिंह भवोरिया हमें बड़ी खींची है कि इस टीम के निर्माण के लिए जिम्मदारी अध्यक्ष जी, आप पर डाली गई है और मैं ऐसा समझता हूँ कि आप इसे जरूर स्वीकार करें।

हमारा जो इमरा पूरक प्रयान है वह वह है कि बल्ड बैंक को तरफ से पचनदे पर, पजाव में तो पांच नदियों निकली हैं लेकिन उत्तर प्रदेश से जहा पचनदा है वे नदिया एक जगह गिरी है और उनका वहा समय हुआ है, एक बोध बनाने के लिए एक योजना 1970-71 में बनी थी और वह 60 करोड़ रुपये की योजना थी। बल्ड बैंक को उस योजना पर, जिसका सबूं हुआ था, जो बांग और जाव होने के बाव उस पर मरमल करने की विधि होने के कारण हमें बड़े बड़े तो मैं मवी महोदय में यह जावय चाहता हूँ कि क्या आपको इस योजना की

जानकारी है जिसके तहत विश्व बैंक से महायता लेकर एक बांध बनाने की बात थी? मैं इसका नाफ उत्तर चाहता है कि क्या वह योजना कार्यान्वित होगी या नहीं और होगी तो कब तक?

श्री कल्पन रहमान : अध्यक्ष महोदय, योजना किसी खास स्कीम की बल्ड बैंक से बनी थी, इच्छा की इतिला तो मूले नहीं है लेकिन इतना मूले पता है कि 57 करोड़ रुपया इस नदी बाटी योजना के लिए, बबल बैंली के लिए मिला था और उस में से अभी तक आप की प्राप्तीय गरकार सिंके 17 करोड़ रुपये खब कर पार्द है।

डा० रामबी तिह अध्यक्ष महोदय, चम्बल बाटी में जो कुछ हुआ है, वह इन्हाँस को विशेष बान है, जहाँ 400 बडे डाकुओं ने आमगमर्याण किया था। चम्बल पानी ता मरमल राई ना एष्ट आईर का नमस्या बहा है, वह आर्थिक और मानसिक नमस्या है। तो क्या मैं मवा जी में यह जान सकता हूँ कि चम्बल बाटी शानि मिलन की जो योजना मरकार के पास निवन है, उममे से किन्तु को उन्होने स्वीकृति दी है और किन्तु के विषय में वे विचार कर रहे हैं। प्रांत वहा की जीवन संी विशेष योजना है। आदरणीय प्रयान मवी जी में चम्बल बाटी शानि मिलन के लाग मिले वे और वे बहुत आवाजान हैं। उनके लिये आर्थिक सर्वेक्षण का कार्यक्रम चाल हो चुका है या नहीं और उनके लिए आर्थिक योजना को पूरा करने के लिए वर्तमान सरकार काम कर रही है? इस के बारे में मैं जानना चाहता हूँ?

श्री कल्पन रहमान अध्यक्ष महोदय, स्थीमा की जहा तरु सूची का सवाल है, माननीय मदस्य अगर इसके लिए अन्य से सवाल पूछे, तो मैं जबाब दे दूरा मरमल मैंने जो जबाब में बनाया है वह यह है कि ये सारी स्थीमे पाइसेट प्राइवेट, कंजर्वेशन आफ सारी, डेलपमेंट आफ केवल एटिया आफ कम्बल बैली, ये सारी जीजे एक दूसरे से सम्बन्धित हैं, जिस से वहा की योजना वो सुरक्षा हो, ऊदां-वाक्त योजना दीको जाए, एपारां-वन तो योर ईर्मेशन की फैसलीदी होती है। 3200 गरीया का मदेन्डर रजते हुए, यह सब किया गया है।

अब जहा तक डैक्टो का मवाल है, मैं माननीय सदस्य से यह आपह करूँगा कि इसका जबाब देने के लिए कार्यान्वित हुम निश्चिन्द हैं। यह स्थीम बना देंगे कि कब कैसे होगा।

श्री अवन्नत राज आवस्ताल . बल्ड बैंक की सहायता से इस बाटी के विकास के लिए जो योजना बनाई गई है उसके नियामन वे आपने बताया है कि मानी तक लेकिन 12 करोड़ वर्ष हुआ है और जावय करोड़ वर्ष नहीं हुआ है। वह योजना आवृत्त 1974 में बनी थी। जो जानना चाहता हूँ कि इसकी जिम्मेदारी

किस पर है, राज्य पर है या आप पर है। मैं यह भी जानता चाहता हूँ कि गति को तेज़ करने के लिए आपने क्या किया है?

‘इस विकास के काम को आपने क्या राज्य पर टी छोड़ दिया है या केन्द्र के पास मे भी दम के लिए कुछ किया जा रहा है?

\* श्री फल्गुर रहमान : जहाँ तक योजना विभाग का सबाल है आवश्यकता के अन्तराल, जूँग्हों का महेनजर रखते हुए हम सकैज्ज और जान बनाते हैं। जहाँ तक प्रभावित्यशन का गवाल है ज्यादा तर प्रभावित्यशन राज्य सरकारी द्वारा किया जाता है। कोई भी सरकार हो वह नियित नहीं बैठ मकानों है। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि वया क्या दिवरों पर आती है रक्कीम का एकीकूण करने से।

श्री अमनस राम जायसवाल : चारोंमास के बीच बदले नहीं हुए? गेक यारे मे आप क्या कर रहे हैं?

श्री फल्गुर रहमान जारी सम्बोध व्यवस्था नक कि यह नहीं है, उगमां गवालियर लभ्य बलना है। जर्मन धरण मिल जाए, मारी सुरक्षाधार्मन जाए और जिस एक्सिय मे काम करना है उस एक्सिय में किन्तु बढ़िताई है ये सब जोड़े आदे आता है। मैं भानलीय मदम्य से कहूँगा कि एक बार जा कर स्वयं दृश्य ले और मुझे आशा है कि देखने के बाद वह कहेंगे कि बहुत महत्व पर बाद यह मनरक्ष करेंगे आप खबर हुए हैं।

#### Fire in Nuclear Fuel Complex Hyderabad

\*683. SHRI M. RAMGOPAL REDDY: Will the Minister of ATOMIC ENERGY be pleased to state:

(a) whether fire broke out in one of the wings of the Nuclear Fuel Complex at Hyderabad on the 12th March, 1979; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE AND IN THE DEPARTMENTS OF ATOMIC ENERGY, ELECTRONICS & SCIENCE AND TECHNOLOGY AND SPACE (PROF. SHER SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) The fire broke out in the Zircaloy Fabrication Plant of the Nuclear Fuel Complex, Hyderabad a little after mid-night in the night shift of 12th March, 1979.

SHRI RAM GOPAL REDDY: It is a very dry reply. The Minister has not given details about the damage. The Minister has not taken a serious note of my question. पछा आग नहीं क्या, जबाब दे दिया आग नग गई।

It is not the way of replying my question. I have also requested for the details regarding the damage it has done as to how the fire broke out and what are the remedial measures he proposes to take in future. He has not mentioned about this.

PROF SHER SINGH: He has asked a question as to how the fire broke out. The hon. Member has also asked about the damage. There has been a damage to the roof slab, above the kerosene tanks and steel structural members were badly damaged PVC electrical fittings were completely burnt. PVC exhaust system has also melted. These are the losses. The loss comes to about Rs. 20 lakhs.

SHRI RAM GOPAL REDDY: This is a very serious thing and it is a very dangerous thing and such things are happening in our nuclear complex. I want to know what are the remedial measures which he proposes to take and whether any inquiry has been instituted. If so, what are the details? If the inquiry has not been instituted, I want to know why there is negligence on the part of the Government.

PROF SHER SINGH: An investigation Committee was constituted and that Committee submitted its report. The report is under examination. In the report they have also suggested some measures which should be taken to avoid recurrence of fire.

SHRI SAUGATA ROY: Sir, it is not the first time after the Government has taken over the nuclear complex that there has been fire in such a vital nuclear installation. As you know, last year there was a fire in the Baroda Heavy Water Plant which has put off our nuclear energy programme by almost one year and now we have fire

in the Nuclear Fuel Complex at Hyderabad. There is a consistent effort here and abroad to do some damage or other to the nuclear installations so that the nuclear energy programme of India does not go ahead as per schedule. I would like to know from the hon. Minister whether he would undertake a comprehensive inquiry into the whole security system of our nuclear installations and also find out whether there is any linkage between the different fires and accidents that have occurred in the nuclear installations during the last two years to find out whether there are foreign connections or domestic connections for these accidents.

**SHRI JYOTIRMOY BOSU:** Or American hand in the matter.

**PROF. SHER SINGH:** The Investigation Committee has come to the conclusion that this fire was accidental and there was no sabotage involved in this.

**DR. KARAN SINGH:** With the growth of utilisation of nuclear technology for peaceful purposes, there is going to be expansion of nuclear plants and, as the recent incident in Harrisburg in the United States has shown, there are very real dangers, unless safety measures are built into the system from the very beginning. Will the Government please let the House know whether they are taking adequate measures to ensure that, with the growth of our nuclear capability and technology, these safety measures are built in so that our population is saved from the possible adverse effects of radiation? The Harrisburg incident which is going on even now is a pointer to what should be done by this Government as a preventive measure. Is it being done or not?

**PROF. SHER SINGH:** Safety measures are in-built into the system and all precautions are taken to see that accidents do not take place. The hon. Member has referred to the Harrisburg incident. Our system is a little

different from theirs, but still there could be a possibility. So, all precautions are being taken. I have recently been to the ERC and I myself asked this question whether we have taken all precautions to foresee what type of accidents can take place and whether we have made arrangements for safety measures in-built into the system itself. I have been told that we have done that.

**PROF. SAMAR GUHA:** It is known that nuclear technology involves very sophisticated machinery and also, that any accident in the nuclear installations may lead to disaster. The Minister has said that precautionary measures are in-built into the system but, in view of what happened earlier in our heavy water plant and also in Hyderabad and, as Dr. Karan Singh has pointed out, in view of the recent incident which created great havoc in USA also, will the Government take immediate steps for reviewing the safety and precautionary measures which are in-built, to see whether these in-built precautionary measures are sufficient or some additional precautionary measures are necessary? Will the Government review the whole system of precaution and safety in all our nuclear installations all over the country?

**PROF. SHER SINGH:** I welcome the suggestion of the Hon. Member and will take steps to see that all precautions are taken and also to foresee what could be the causes of accidents and how to avoid them.

**E.E.C. Delegation to study Electronics Industry**

+

**\*684. SHRI SHANKERSINHJI VAGHELA:**

**SHRI MUKHTIAR SINGH MALIK:**

Will the Minister of ELECTRONICS be pleased to state:

(a) whether a delegation from European Economic Community visit-

ed India recently to study Electronics Industry of the country;

- (b) if so, the details thereof; and
- (c) whether any agreement has been signed?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE AND IN THE DEPARTMENTS OF ATOMIC ENERGY, ELECTRONICS & SCIENCE AND TECHNOLOGY & SPACE (PROF. SHER SINGH): (a) yes, Sir.

(b) A delegation consisting of 27 experts representing major computer companies from the EEC Countries visited India during March, 1979 to explore cooperation in the field of Computers & Electronic Components.

(c) No, Sir.

श्री शंकरसिंह जी वारेला : इलैक्ट्रोनिक इंडस्ट्रीज की आजानक इंडियन इंडस्ट्रीज नाम के बहुत बड़ी डिमांड है और इसका अध्ययन करने के लिये यूरोपीय आर्थिक ममदारण से एक प्रातिनिधि-मंडल यहां आया था और उसके साथ इलैक्ट्रोनिक एक्सिपर्मेंट मेनफ़ैक्चर करने वाली हमारी डिफ़ेस प्रॉटोकल्यूमेंट्स के बारे में भी चर्चा हुई थी ? देश की सुरक्षा के बारे में ऐंडार एक बहुत नाजुक साधन है। क्या उसके बारे में भी चर्चा हुई थी ?

मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि 10 साल में जो बेकारी दूर करने की जाती है, उसको देखते हुए कम्प्यूटर के मामले में गवर्नमेंट की नीति क्या है ? जब कम्प्यूटर बेकारी को और बढ़ावा देंगे, तो भी क्या सरकार कम्प्यूटरों की ओर भाग करेगी ? जो प्रतिनिधि-मंडल यहां आया था, क्या उसके आगे का परपत्र विवेदन था ?

श्रोता सेर लिह : मैंने विवेदन किया कि यह किप्प-मंडल भार्च के हसी महीने में आया था और पिछले माल भी एक शिप्पिंग-बल एरिया डिफ़ाइन करने के लिये आया था कि कौन से एरिया में काम हो सकता है, जिसमें दोनों की को-आपरेशन हो सकती है। इस बार जो शिप्प-मंडल आया, उसने पिछले शिप्प-मंडल का अनुमोदन किया और आगे के लिये कोई ज्ञानान्वेषक निविल इंस्ट या अकारीकन कंट्रीज में सम्भव सकते हैं, ड्रेनिंग से कुछ हो सकता है या हार्ड-वेयर और सोफ्ट वेयर की समावृत्ति कर सकते हैं, और अपने देश में बैठा कर सकते हैं और हम अपना एक्सपोर्ट कीजे बढ़ा सकते हैं। इन सब बाबों पर विचार हुआ, और आगे के लिए क्या हो सकता है, वे सब एरियाएं

भार्टेंटीफ़ाई हुए। इस प्रतिनिधि-मंडल ने भी पिछले प्रतिनिधि-मंडल का अनुमोदन किया।

श्री शंकरसिंह जी वारेला : हर एक प्रतिनिधि-मंडल का अपना आशय होता है। जो प्रतिनिधि-मंडल यहां आया था, क्या उसके साथ इलैक्ट्रोनिक एक्सिपर्मेंट मेनफ़ैक्चर करने वाली हमारी डिफ़ेस प्रॉटोकल्यूमेंट्स के बारे में भी चर्चा हुई थी ? देश की सुरक्षा के बारे में ऐंडार एक बहुत नाजुक साधन है। क्या उसके बारे में भी चर्चा हुई थी ?

श्रोता सेर लिह : डिफ़ेस के बारे में विवेदन पर से जो एक्टोनिक्स चाहिए, उग्ने वारे में कोई विवेदन चर्चा नहीं हुई।

SHRI MUKHTIAR SINGH MALIK: Mr. Speaker, Sir, it is said that they have been invited for a meeting and a discussion and exchange of views had taken place and then we dispersed. Now, as far as part (c) of the question is concerned, the hon. Minister has not informed the House as to whether any agreement has been reached or not. The Delegation came to India last year and this year too. I want to know from the hon. Minister whether the delegation that visited last year and this year also had come on its own or they were invited by the Government of India. I want to know whether this delegation drew blank or whether it had met with a total failure.

PROF. SHER SINGH: Sir, under the auspices of the Indo-EEC Joint Commission, our team consisting of 12 computer experts—and they were in a delegation—went to EEC countries including Brussels in November 1977. Now, that was under the auspices of Indo-EEC Joint Commission and their delegation also came to India last year and again we have also received another delegation. Now, this is under the auspices of the Indo-EEC Joint Commission and as I said it is not that they withdrew blank. Areas were identified where we would have co-operation in future. Even for increasing the export in those countries and so many other things were discussed. It is not that they drew blank. But

no formal agreement was signed. But areas of potential co-operations were identified.

SHRI VINODBHAI B. SHETH. In this country we have got electronics Engineers of a very high calibre and still we are lagging behind in so far as electronic appliances are concerned. I would like the hon. Minister to give specific reply as to whether the Government is thinking to introduce electronic devices in the services like ports, railways, aircrafts, etc.

MR. SPEAKER. It does not arise here.

#### प्रनियंत्रित कपड़े के मूल्य में वृद्धि

-

\* 685. श्री अनन्त राम जायसदाल :  
श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) यह यह मत है कि मितम्बर, 1978 ग्राम्य, 1979 तक की अवधि में ₹ 2 के मूल्य में कमों होने के बावजूद कपड़ा मिरो न हम प्रयोग में अनियंत्रित रियर के कारण के मन्दा में वृद्धि की थी,

(ख) यदि हाँ, तो 1 निवार, 1978 से 31 मार्च, 1979 तक की अवधि में ₹ 2 के थोक विद्युत मूल्य सूचकाक में किन्तु कमी हुई थी और उसी अवधि में अनियंत्रित कियर के कपड़े के मूल्य में किन्तु वृद्धि की गई थी,

(ग) वर्ष 1977-78 और 1978-79 में ग्रामीय कपड़ा नियम के मिरो तथा निजी क्षेत्र की मिरों द्वारा नियार किये जाने वाले अनियंत्रित कियर के कपड़े के मूल्य में किन्तु वृद्धि की गई है, और

(घ) क्या सरकार का विचार अनियंत्रित कियर के मूल्य में वृद्धि पर नियत्रण करने का है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यापा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उड्डो ! नंदी (श्री जार्ज कर्नार्लोस) : (क) जी, हाँ।

(क) सितम्बर, 1978 से मार्च, 1979 की अवधि में कम्पी रुई के थोक विक्री मूल्य सूचकाक 2.4 प्रतिशत घिरा, जबकि उसी अवधि में जूती कपड़े के थोक विक्री मूल्य सूचकाक में 1.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

(ग) और (घ). कपड़े के मूल्या में घटा-बढ़ी के सम्बन्ध प्रश्न के सभै में सूती बत्त उद्योगपतियों ने चर्चा ही नहीं तथा उद्योगपतियों से कपड़े के मूल्यों का कम करने के बारे में वृत्तन कदम उठाने के लिये कहा गया था। उद्योगपतियों ने कृत भूत्याव दिये हैं जो सरकार के विचारार्थी हैं।

श्री अनन्त राम जायसदाल. क्या याकिन की कमी की बजह से आपने दण वीं आवार्दी का एक बहुत बड़ा इमारा साल के उद्यादा हिस्से में प्रश्ननामा रहता है और मन् 6.4-6.5 के मानांगिने प्रति व्यक्तिन माल की बत्त में मन् 7.7-7.8 में 3.4 मीटर की कमी हुई है जो आपने में आप से बहुत एकामिग है। उसके बाबा आपने ने वह ल. मानांगे बौद्धिकार दी है। आप भर की यह स्थिति है कि जटा पर रुई के दाम जिरे हैं गारे ने परगेट दण बासें के दाम करीब तीन परसेट ल. १५ ग्रे २ मारे कपटे के ही नहीं, सूत के, धांसे के भी दाम बर गये हैं। आपका नाम नाम है, हिन्दू नाम, जिन उद्यादा का प्राप्त बताना नाहोने हैं, हिन्दू नाम, बगरह, उन को इन में न-उमाम न-प्रा हैं किंतु आपने के दाम उन्हें बढ़ दिए हैं मैंने में फ्रांस का बताए के भी और क्लाय वर्स व भी ही कि उस का चलना मर्जिकर ना रहा। वह एक डेनीयेन्सन प्राप्त से मिला था। तो मैं यह बहुत रुई हूँ कि जा ठप्पररु, कल्यामर और रियान उन नीनों की बीमार पर मिल मालिनक दाम बताते चले जा रहे हैं उस के बारे में आपने आपने जावाब में कहा नित्र नहीं किया है कि आप वीं तरफ से उसके लिए क्या कायवाही हा रही है। आप ने खाली यह बता दिया कि साम्राज्यिका की तरफ से यह आए है। आपने इन दामों को नकारने के लिए क्या नियिक जारीवाही की यह बताने का बाट करेंगे।

श्री जार्ज कर्नार्लोस : हम तो राईयन काटन मिस्स फेटरेशन के लोगों से मिले और उन से हमने यह कहा कि उन लोगों ने आज जिस रूप में दाम बढ़ाए है वह कम किए जाने चाहिए। उसके बाद यह दाम कम करने की दिक्षिण से उन की तरफ से तीन सुझाव आए हैं जिनमां में ने यहाँ पर जिक्र किया। हम तो उन से बताया है कि ये तीनों सुझाव हमें मंजूर नहीं हैं और उन्हें गिराना पड़ेगा। सूत और कपड़ा दोनों लेक्कों में जहाँ भी दामों को बहुत बढ़ाने का मिलमिला चला है उस को गिराने का काम उन्हें करना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से किसी और कदम के उडाए जिन दामों को गिराने का काम वह करेंगे। इन बहस उन लोगों की बानधात हमारे मकालय के नाम बल रही है और यहाँ रुपर उन ही तरफ से दाम बढ़ाने के हमें मजबूर हो तो हम कोई और कदम उपनी तरफ से उठाएंगे जिस के द्वारा दामों को गिराने में मदद मिले।

श्री अनन्त राम जायसदाल : पहले कपड़े के हर मीटर पर रिटेल प्राइस छापा करती थी। आजकल जाकी एक्स-फैक्ट्री प्राइस प्लस इन्टी आप देते हैं और जिकायत यह है कि वह वीं इनाम बढ़ा कर छापते

है कि जिस से बूब कायदा उठाएँ। तो क्या आप पहले की तरह रिटेल प्राइस छापाएंगे और दूसरे, मूल्य को नियंत्रित करने के लिए तुरंत कंट्रोल लगा करें? इस के प्रतावा साल भर तक जो यह स्थिति रही कि बराबर कपड़े के दाम बड़े रहे इस बीच में आग का मंत्रालय क्यों सोता रहा इस पर कुछ प्रकाश आप दालेंगे?

श्री जार्ज फर्नांडोस : अध्यक्ष महोदय, जहाँ नक दामों पर कंट्रोल लगाने का सवाल है यह जहाँ तक हमारी समझ हीं कि क्योंकि कपड़े के दाम पर कंट्रोल लगा कर उस को किर प्रमाल में लाना एक समझव जैसी चीज हमें नजर आती है। लेकिन और कई उपाय हैं जिस को अमल में लाना जो सकता है जिस के बारे में हम इस समय विचारकर रहे हैं और जहाँ तक हर मीटिंग पर कपड़े का दाम आपने का सवाल है यह मामला इस समय सरकार के विचाराधीन है।

माननीय सदस्य ने यह भी पूछा कि जब दाम एक अर्थसे से कड़ने रहे तो सरकार ने उस के बारे में कोई कदम क्यों नहीं उठाया?

श्री अनन्त राम आयसवाल : अरबों रुपया मिल मालिकों ने कमा दिया और आली प्राइवेट ने ही नहीं सेशनल टेंकमटाइल कारपोरेशन ने भी कमाया है।

श्री जार्ज फर्नांडोस : नेशनल टेंकमटाइल कारपोरेशन इस समय 40 प्रतिशत अपना कपड़ा कंट्रोल कपड़ा बना रहा है और आपको जो नेशनल टेंकस्टाइल कारपोरेशन का कपड़ा है वह आम तौर पर चार मीटर पांच रुपये प्रति मीटर के दाम के भीतर है, तो अरबों रुपया नेशनल टेंकस्टाइल कारपोरेशन के द्वारा मूलाफ के कप में कमाने का सवाल नहीं है। यह सही है कि निचो मिलों ने इस प्रकार की काफ़ी अपनी नीतय नहीं देखा है जिस से यह मालूम हो कि लोगों को कपड़ा उचित मूल्य पर मिल सके इस जिम्मेदारी को उन लोगों ने निभाया हो। तो इस पर जो कार्यवाही हमें करनी है वह कार्यवाही हम लोग करने जा रहे हैं।

श्री विजनपार्ह एवं शुक्ल : जहाँ तक इस इंडस्ट्री का सवाल है की सरकार की बात इन्होंने नहीं मारी है।

They are taking Government for granted.

तो मैं यह बूँदना चाहूँगा कि सरकार रा मीटीरियल और किनिश गुद्दस, इन दोनों के बीच में कितना कर्म होता चाहिए यह मानती है तो सरकार जो मानती है उस के लिए यह क्या कदम उठाना चाही है?

एक बात मैं और पूछना चाहूँगा। मेरे बिल वाले कभी भी मानने साले नहीं हैं। तो क्या सरकार विश सक्त कदम की बात करती है उस बीच वह बहुत भी गोपेंगी कि सारी विलों में केवल स्पिरिंक होने दे, दुराई न होने दे?

दुराई का काम भारत सरकार हथकर्षा उद्योग को सौंपे। जबकि यह नहीं होगा तब तक कि अपना मुनाफा कम करने वाले नहीं हैं वयोंकि उनको मुनाफा कमाने की आदत ही गई है।

श्री जार्ज फर्नांडोस : मैं माननीय सदस्य की भावनाओं को समझता हूँ। इसमें मेरा उनसे कोई भ्रम नहीं है कि विल मालिक इस माल में जो रुक्ष अपना रहे हैं वह लोकोंने बाला रुक्ष नहीं है। मामाय लोंगों की समस्याओं के बारे में उनको किसी प्रकार की कोई जितना नहीं है—यह बात विकुल स्पष्ट है। लेकिन माननीय सदस्य का जो प्रबन्ध है कि हम सिर्फ स्पिरिंग का काम इन मिलों में करें और सारा बीविंग ना काम बाहर निकाल दें—यह समझव नहीं होता। जितनी पूंजी इस उद्योग में लाई है और जितना कपड़ा बनाती है उसको महेनजर रखते हए यह चोंड इस बदल समझव नहीं है। रामेटीरियल और किनिश प्रोडक्ट के जो रिश्ते का स्थान भी वह ग्रलग अवश उद्योगों में अलग अलग किस्म का होता रहेगा। टेंकस्टाइल मिलस में भी रामेटीरियल और किनिश प्रोडक्ट का जो अन्तर है उसमें जबर फैस रहेगा।

श्रीमती अनन्तरामी : अध्यक्ष महोदय, 1966-67 में जब रुई का भाव शायद 400—500 रुपए के बीच रहा तब कपड़ा साड़े चार, पांच रुपए मीटर पर पर या लेकिन आज रुई का भाव 260 पर चले जाने के बाद रुपांची 1.1 रुपा मीटर बिक रहा है। मैं मंकी जी से जानना चाहती हूँ क्या सरकार ने इस मुनाफे को कटौत करके, रुई के जो उत्पादक हैं उनके साथ कोई सामंजस्य करने की चेष्टा भी की है?

श्री जार्ज फर्नांडोस : यही चेष्टा इस समय हो रही है।

श्री कंबर साल गुप्त : मंकी जी ने आप्य शायद दो तीन दिन पहले कहा कि सरकारी काटन टेंकस्टाइल मिले इस साल बहुत नफा कमायेंगी। उसका कारण यह नहीं है कि उनकी एफीलिएन्सी बड़ गई है बल्कि उसका कारण यह है कि रुई के दाम बहुत गिर गए हैं और काटन कलाय के दाम बड़ा रहे हैं। प्राइवेट मिलों उगम से भी ज्यादा गढ़वाल कर रही है। यह मंत्रालय पिछले दो साल से पेंसिव स्पेंक्टर रहा है। एक एक गज पर बीस-बीस पैसे दाम बढ़े हैं। मेरे पास कटन का इन्डेक्स है।

The cotton index for May 1977 was 214, and for October 1977 it has come down to 160.6. There is a fall of 22.6 per cent.

मैं मंकी जी से पूछना चाहता हूँ कि आप दाम कितना कम करना चाहते हैं और क्या मांग पापने रखी है? अगर वे दाम कम नहीं करते हैं तो आप क्या कार्यवाही करेंगे? अभी जैसा यहां पर रिटेल प्राइस आपने के लिए कहा गया तो अगर पहले यह दाम लापने जो सकते थे तो वह क्यों नहीं लापे जा सकते हैं? आप उनकी कास्टिंग करके एक्स-मिल प्राइस छापिएं, जिसके हाथ में दें दि कि यो भी काहूँ दे जाएं दें।

श्री जार्ज कर्नान्डील : जहां तक एन टी सी मीडू ज के मुनाफे वा मवाल है, इस भाग पहली बार गयी ही है। विलो ने दीन कारोबू का मुनाफा कमाया है। मैं माननीय सदस्य की हस रात्रि से सहमत नहीं हो सकता कि यह मुनाफा रई का दाम कम होने के कारण या कपड़े का दाम बढ़ाने के कारण हुआ है। जैसा मैं ने पहले कहाया, एन टी.सी.की मिल प्रति वर्ष आनीम करोड़ गज कन्ट्रोल का कपड़ा बनाने के काम में नहीं है जिसमें मुनाफा कमाने की कोई बात नहीं है। जो दाम कपड़ा बनाने में लगता है वही दिया जाता है एन टी.सी. निरो में मुनाफे का कारण यह है कि माइनिंडेजन का काम बहु पर किया गया है और एफीडीएन्डी बड़ाने का काम भी हुआ है। मैंनेजमेंट में जहा जहा कमज़ोरिया थी उनको भी दूर करने का बास हुआ है। ऊपर से लेकर नीचे तक वर्दि प्रकार के प्रयास हमने टेंड माल में किए हैं। हमने पहली बार एन टी सी की 111 मिलों के जनरल मैनेजर्स को एक जगह पर बैठाकर, उनकी ममस्याप्री को समझ कर, उनकी ममस्याओं को हल करने वा प्रयास दिया ताकि उनका काम टीक हो गे हो। हम तरह से हम ने इस दिशा में कई प्रकार के प्रयास किए हैं जिसका नतीजा यह है कि आज एन टी सी. मुनाफे की ओर बढ़ रही है।

जहा नव मिलो द्वारा मुनाफा बनाने का मवाल है, मिले मुनाफा अस्तर कमायेगी। कोई मिल मुनाफा कमानी है, यह कोई मवाल नहीं हो सकता है मुनाफा अस्तर होगा—उद्योग में जिनी खेत हों या सावंजनिक खेत हों—मुनाफा होगा, इस के बारे में काई अगड़ा नहीं है। लैंकन मवाल यह है कि जो उद्योग मुनाफा कमा रहे हैं और दारों पर लगाम लगाने में सहयोग नहीं कर रहे हैं—इस मन्दन्ध में उन की तरफ से तीन प्रस्ताव हमारे समाने पाये हैं और हम ने कहा है कि मे हमें मन्ज़र नहीं है। अब जो छोट मूलाब है वे हम ने रखे हैं और उन से जैसा जबाब आयेगा किंतु उस पर कायेकाही बरेंगे।

#### Memorandum by Christian Welfare Association, Bihar

\*687. SHRI KISHORE LAL: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Christian Welfare Association presented a Memorandum to Governor of Bihar in a mass deputation on 5th March, 1979.

(b) what are their main demands;

(c) whether it is a fact that during the last one year there have been many attacks on their missions/institutions/individuals in various parts of Bihar; and

(d) the forces/institutions behind this?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL): (a) to (d) The information is being collected from the Government of Bihar and will be laid on the Table of the House. But just a few hours back we got information from the Bihar Government and on the basis of that I wish to correct my answer.

In regard to part (a), whether it is a fact that Christian Welfare Association presented a memorandum to the Governor of Bihar, the answer is: Yes, on the 5th March a memorandum was submitted to the Deputy Secretary to the Governor.

With regard to (b), the demands are: to institute a high level enquiry into the matter of the incident and find out whether there is any institutionalised agency behind this and to bring the culprits to book.

As regards the other parts of the question, information is being collected from the Government of Bihar.

श्री किशोर लाल : प्रध्यक्ष महोदय, मैं यह जानता चाहता हूँ—इन के मेमोरेंडम देने से पहले वह किंतु नियन्त्रित के मर्डर हुए, जिस से उन के अन्दर सेन्ट्रल एफीडीएस्टीजोर्डीटी पैदा हुई तथा जिन नियन्त्रित के मर्डर हुए क्या उन के बारे में कोई इन्वेस्टीगेशन हुआ ? मैं यह भी जाना चाहता हूँ—या कोई सेन्ट्रल एजेंसी जैसे इन्वेस्टीगेशन एवं या कोई अन्य एजेंसी इन किंत्रियन नियन्त्रित के मर्डर की जांच में लगी हुई है ?

श्री अश्विन लाल मन्दल : मानव में एक किंत्रियन कादर की मूल्य ही है, उस के बाद यह मेमोरेंडम राज्यपाल महोदय को दिया गया। उस मेमोरेंडम में उसके पहले की बटनामों के बारे में जो बातें कही गई हैं—उन में कहा गया है कि मुंबेर में हस तरह की घटना हुई है, उस के बाद बरौदी में हुई, बनपुटिया, चम्पारन में हुई, रोहतास में हुई—इस तरह की कुछ घटनायों का दिया गया है। जहां-जहां इस तरह की घटनायें हुईं, उन के सम्बन्ध में मैं जैसी जांचा है, लैंकन इन पर को सूचना मार्गी गई है, वह हम को अभी उपलब्ध

नहीं है, इस लिये इन सम्बन्ध में हम प्राप्त नहीं बताता सकते हैं।

**श्री किशोर लाल :** उस नेमोरेण्डम की चार बटनामों का जिक्र मर्ती बहोदय में किया, जो बिहार में हुई है। ये बटनामें डिस्ट्रिक्ट टाउनज में हुई है और 5 मार्च के बाद एक महीने से ज्यादा हो गया है, बिहार सरकार ने गवर्नरमेंट आक इण्डिया को मर्ती तक इतिला नहीं दी। यथा गवर्नरमेंट आक इण्डिया यह मुनासिब नहीं मानती कि माइनरिटी कम्युनिटीज ने जो नेमोरेण्डम दिया है और उन के बान्धन जो सम्प्राक्त-इन्सियोरिटी पैदा हुई है — उस को दिल्ली में रखते हुए सी०बी०धाई० या किसी अन्य सैन्य एजेंसी से इन्वेस्टीगेशन करावे, ताकि जो लोग उस के पीछे हैं या जो इस्टीचूबान्ध उन के बिलाकाही हैं — उन के बिरुद्ध शीघ्र कायदाही की जा सके और हमारी माइनरिटी कम्युनिटीज में जो सेन्ट-काप इन्सियोरिटी पैदा हो गई है, उस को दूर किया जा सके? यथा गवर्नरमेंट इस बात को कानीडर करेगी कि वह अपनी किसी सैन्य एजेंसी के बिरुद्ध इसको इन्वेस्टीगेट कराये?

**श्री ब्रिटिश लाल मंडल :** बहोदय, इस में सी०बी०धाई० की एन्कडायरी की बात नहीं है। अभी जिन बटनामों का जिक्र किया गया है — वे उस नेमोरेण्डम में ही नहीं हैं — मोकामा, हवेली-बहगुरु, बरीनी, चनपुटिया, रोहाम-ये सब डिस्ट्रिक्ट टाउनज नहीं, हीं जैसा कि मानवीय सदस्य ने कहा है। इन के सम्बन्ध में बिहार सरकार से जानकारी नहीं गई है, वह अभी हमें मिली नहीं है। हम जल्द कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द जानकारी आ जाय, जो देंगी हुई है, उस के लिये हमें जो द है।

**SHRI B. P. MANDAL:** I want to know, when on 5th March a deputation met the Governor of Bihar, what steps were taken and whether the Governor of Bihar, as the agent of the Government of India, brought it to the notice of the Government of India that minorities in Bihar, especially the Christian minorities, are harassed? May I know also whether it is a fact that RSS is behind these atrocities? (Interruptions).

**SHRI DHANIK LAL MANDAL:** No, Sir.

## WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

### Development of productivity services by the National Productivity Council

\*686. **SHRI NATVARLAL B. PARMAR:** Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether the National Productivity Council had considered proposals for development of productivity services; and

(b) if so, the details thereof?

**THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI GEORGE FERNANDES):** (a) and (b). The development of productivity services is a continuing process with the National Productivity Council since its inception, brief details of which are set out below:

(i) It has developed specialised services in Industrial Engineering, Fuel Efficiency, Plant Engineering, Production, Engineering, Behavioural Science and Financial Management.

(ii) It provides training and productivity survey and implementation service in the above areas, undertakes applied research projects and propagates these through publications and various audio-visual aids.

(iii) It is engaged in developing productivity services for small scale industries through the cells established in close collaboration with State Govts.

(iv) It has undertaken the National scheme on supervisory development leading to the award of National Certificate in Supervision and development of trade unions and workers in Productivity.

(v) It is engaged in the development of productivity services

in Corporate Planning, Management Information System, Marketing, Training Technology and electronic data processing.

(vi) It has developed specialised services in the conservation of furnace oil and non-ferrous metals, postharvest operations of agriculture and rural marketing surveys.

The NPC at its meeting held at New Delhi on 15th March, 1979 decided to reorient its activities to the economic and industrial policy objectives of the Government. The NPC has identified the following areas for immediate action:—

- (i) Development of soap and match industries in collaboration with Khadi & Village Industries Commission, Development Commissioner, Small Scale Industries and others.
- (ii) Development of Small Scale Sector—Productivity improvement in the existing units and promoting growth of Small Scale Units for the reserved items in collaboration with DCSSI.
- (iii) Productivity improvement in public sector organisations where productivity is low or are considered sick. Some of the units/areas identified for immediate studies are State Electricity Board, sick units of the National Textile Corporation and Engineering Industry, Bombay Port, Railway yard in Mugalsarai, etc.
- (iv) Promoting appropriate schemes for securing involvement of Trade Unions to enable them to adopt Productivity as an integral part of their movement.

The NPC has already worked out detailed proposals for development of

soap and match industries in the cottage, small sector. Proposals in respect of other areas are being worked out by the NPC.

प्राथिक आकड़ों का संकलन करने की प्रक्रिया

\* 688. श्री रम बिलास पासवान : क्या योजना मंत्री मह बनाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्राथिक आकड़ों को एकत्र करने की पद्धति और तरीका बतायाग योजना के लिये पर्याप्त और प्रभावी है ?

(ख) यदि नहीं, तो इसे प्रभावी और प्रधिक व्यापक बनाने के लिये सरकार द्वारा क्या दोस्रा कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) यदि हां, तो योजना के निए एकत्र आकड़ों का मद-वार और वर्ष-वार व्योग क्या पर्याप्त है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फलतुर रहमान) : (क) में (ग). प्राथिक आकड़ों के एकत्र करने की प्रक्रिया तथा पद्धतियों को सुधारने के लिए विस्तर प्रयाग किए जा रहे हैं, ताकि ये प्राथिक प्रभावी तथा व्यापक बन सकें। इस दिया में जो मुख्य कदम उठाये गये हैं उन को दर्शाने वाली एक टिप्पणी (मनुवन्ध्य—I) तथा एक विवरण (मनुवन्ध्य—II) जिस में मद-वार तथा वर्ष-वार आकड़ों का एकत्र करना दर्शाया गया है, सभा पटल पर रखे गए हैं। [मनुवन्ध्य में रखा था। वैस्त्रिय संख्या LT.—4280]. 79]

#### Presence of Mineral deposits in the seas around Andamans

\* 689. SHRI CHITTA BASU: Will the Minister of SCIENCE AND TECHNOLOGY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the presence of highly productive pockets and traces of mineral deposits in the seas around Andamans has been indicated in the preliminary survey by the National Oceanographic Survey Researches recently;

(b) if so, whether Government consider it desirable and feasible to take further exploratory drive in this behalf; and

(c) if not the reasons thereof?

**THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI):** (a) The National Institute of Oceanography, Goa, carried out a preliminary survey of the waters around the Andaman islands in January-February, 1979. The surveys indicated pockets of high biological productivity and trace metals in the waters off the Andamans.

(b) The area is proposed to be surveyed more intensively after completion of the analysis of data already taken

(c) Does not arise.

**Plan for better process of Handloom cloth**

\*690 **SHRI C. K. JAFFER SHARIEF:** Will the Minister of INDUSTRY be pleased to lay a statement showing:

(a) whether Government have made any plan or propose to take initiative or creating infrastructure like production of yarn, creating facilities for pre-weaving and post weaving and for better processing of the handloom cloth during the Sixth Five Year Plan; and

(b) if so, the details regarding the expected investment?

**THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI GEORGE FERNANDES):** (a) and (b). Consistent with the priority given to handloom in the Textile Policy announcement, an integrated set of proposals has been submitted by the Sub-Group for Handlooms and Powerlooms to the Main Working Group on Textiles. This includes production of an additional 120 million Kgs. of hank yarn, for which about 1 million new spindles will have to be established. Half of these will be in existing units and the other half in new units proposed to be set up. As regards pre-weaving, post-weaving and processing facilities, a total sum of Rs. 406 lakhs has so far been released by the Central Government to 12 States/Union Territories for the creation of such facilities in the last three

years. During the sixth plan period, the Sub-Group of the Main Working Group has proposed a Central outlay of Rs. 1200 lakhs for this purpose. It is envisaged that this amount will be matched by a sum of Rs. 1500 lakhs in the State sector for the same purpose. These facilities will be set up near handloom clusters to improve the quality and marketability of handloom cloth. The final report of the Main Working Group on Textiles is awaited

**Correspondence in Hindi for Banks and Public Undertakings**

\*691. **SHRI A. BALA PAJANOR:**

**SHRI P. S. RAMALINGAM:**

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Central Hindi Committee have decided that correspondence should exclusively be in Hindi for Banks and Public Undertakings in Hindi speaking States, and

(b) if so, the rationale of the decision in the light of the assurances against imposition of Hindi given from time to time?

**THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI H. M. PATEL)** (a). No Sir, After a discussion on the subject, the Committee decided that the Deputy Prime Minister (Finance) will consider the issue in the context of the existing rules and the assurances given by the Government.

(b) Does not arise.

**Progress of Rajasthan and Narora Atomic Power Stations**

\*692. **SHRI EDUARDO FALEIRO:** Will the Minister of ATOMIC ENERGY be pleased to state:

(a) whether the Rajasthan and Narora Atomic Power Stations are lagging behind schedule;

- (b) if so, the reasons thereof; and
- (c) the steps taken in this regard?

**THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI):** (a) Yes, Sir.

(b) The full quantity of heavy water required for initial filling up of the Rajasthan Station and final commissioning is not yet available. As regards Narora Atomic Power Project there have been delays in the manufacture of some critical nuclear equipments, which could not be obtained from other sources.

(c) In respect of the second unit of the Rajasthan Atomic Power Station, Government has already made arrangements for the procurement of the bulk of heavy water required for the initial inventory and the balance is expected in the current year. As far as Narora Atomic Power Project is concerned, all efforts are being made to expedite the manufacture of critical nuclear equipments.

#### Utilisation of Raw material for Textile Industry

**\*693. SHRI CHITTA BASU:** Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether the attention of Government has been drawn to the news item in the *Times of India*, New Delhi, dated February 22, 1979 in connection with the scientific break through in technology for gainful utilisation of agricultural waste materials like banana sheath and pineapple leaf for the utilisation of raw materials for the textile industry;

(b) if so, whether Government have taken any follow-up measures in this regard; and

(c) if so, details thereof?

**THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI GEORGE FERNANDES):** (a) to (c). The news item in reference has

been seen. This refers to certain processes developed by the Jute Technological Research Laboratory, Calcutta. However, local and indigenous technology using banana leaf and pineapple fibre has been developed in Kerala and Manipur respectively where fabric is being made out of these materials. Government have decided to give full support to the further development of this technology in order to spread this further. Detailed programmes are being formulated in consultation with the concerned State Governments.

#### H.M.T. Watches

**\*694. SHRI ISHWAR CHAUDHRY:** Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that proper facilities for sale of H.M.T. watches are not available in the capital;

(b) whether it is also a fact that the maintenance cost is much higher in comparison with those of other makes of watches;

(c) whether Government's attention has also been drawn to short supply of H.M.T. watches resulting in higher price being charged from buyers; and

(d) if so, the measures being taken to improve the situation?

**THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI GEORGE FERNANDES):** (a) No, Sir.

(b) No, Sir.

(c) and (d). There is an increasing demand for H.M.T. watches because of their quality and performance. These watches both at Delhi and elsewhere in the country are sold at prescribed prices through HMT's authorised outlets. In order to eliminate scope for possible malpractices arising from unfulfilled demand for HMT watches,

and to cater to the increasing public demand for these products throughout the country, the production of these watches has been increased. HMT's production in 1978-79 was 33,38,197 watches as compared to 20,58,000 in 1977-78 and 11,71,710 watches in 1976-1977.

**New Switch Board Factory by Siemens**

\*695. SHRI K. A RAJAN: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Siemens India has a proposal to set up a new Switch Board factory near Calcutta; and

(b) if so, the details of the proposal and Government's reaction there-to?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI GEORGE FERNANDES): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

**Criminal cases filed for Demolition of Buildings in Turkman Gate, Delhi**

\*696. SHRI RASHEED MASOOD: SHRI DINEN BHATTA-CHARYA:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether criminal cases were filed against the residents of Turkman Gate while their buildings were demolished;

(b) if so, the number thereof; and

(c) the number of cases which have been withdrawn so far and the number still pending for withdrawal and the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI S. D. PATIL): (a) to (c).

Four cases were registered on 19-4-1976. For reasons of inadequacy of evidence, the investigation by the police was closed in respect of two cases. The other two cases were withdrawn. No case, is, therefore, now pending.

सिविल सेवाओं में पदों के लिए साकाशकार में भावा का प्रयोग

\*697. श्री बलपत्र सिंह परस्ते :

धो सरत कार:

क्या गृह मंत्री यह बनाने की कृपा करेगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार ने सिविल सेवाओं में पदों के लिये साकाशकार में प्रयोग की जाने वाली भाषाओं का चयन कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी घोरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार बैंकिंग सेवा आयोग, रेलवे तथा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं में अंग्रेजी को बैंकलिंग विषय बनाने का है?

गृह मंत्रालय तथा विधि, न्याय और कल्याणी-कार्य मंत्रालय में राष्ट्रीय भौती (भी एस०जी० पालिल) : (क) तथा (ख) एक विवरण सदन के पठल पर रखा जाता है।

(ग) करवरी, 1977 में गठित बैंकिंग सेवा आयोग को मई, 1978 में समाप्त कर दिया गया था। राष्ट्रीय भौती बैंकों में लिपिकीय स्टाफ तथा अधिकारी स्टाफ की भर्ती का कार्य भव असाधिक आधार पर बैंकिंग सेवा भर्ती के सात बोर्डों को सौंप दिया गया है। विभिन्न बैंकिंग भर्ती बोर्डों के अध्यक्षों ने सामान्यतया: (क) बस्तुनिष्ठ स्वरूप के परीक्षण तथा (ख) निवन्ध तथा संक्षेपण के लिये लिंगम किया है। बस्तुनिष्ठ स्वरूप के परीक्षण में तर्क के परीक्षण तथा अंग्रेजी के परीक्षण सहित कई प्रश्न पत्र आयिए होते हैं। निवन्ध तथा संक्षेपण का प्रश्न पत्र अंग्रेजी में होता है। बैंक अमी भी अपना अधिकारी कार्य अंग्रेजी में कर रहे हैं और इस प्रकार अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक समझा जाता है।

कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में केवल अंग्रेजी तथा हिन्दी के प्रयोग की अनुमति दी जाती है। इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है कि उन परीक्षाओं में अंग्रेजी को बैंकलिंग विषय बनाया जाए, जिन में इस भाषा का कुछ ज्ञान अनिवार्य समझा जाता है।

कारबिल्य लिपिकों, बाणिज्यिक लिपिकों, टिकट फ्लेटटोरों, संहायक स्टेक्चर भास्टरों आदि बीमि, गैस-तकातीकी सामान्य-भगों [जी भर्ती के लिए रेल सेवा आयोग द्वारा भी जाने वाली लिकित परीक्षा में उम्मीदवारों को सामान्य अंग्रेजी के प्रश्नों के उत्तर देने आवश्यक होते हैं । रेल कर्मचारियों का तबादला समस्त भारतीय रेलों में किया जा सकता है । अतः यह सामान्यक समझ गया है कि समृद्ध "ग" सेवाओं को उम्मीदवारों को रेलों के दिन प्रति दिन के कार्य के लिये अंग्रेजी का ज्ञान हीना चाहिये । अंग्रेजी को बैकल्पिक विषय के रूप में रखने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

### विवरण

संघ सोक सेवा आयोग द्वारा अधिकल भारतीय तथा केंद्रीय सेवाओं की श्रेणी—I तथा श्रेणी—II में भर्ती के लिए अपनाई गई प्रणाली की जाव करने और उस पर रिपोर्ट देने के लिए तथा परीक्षाओं की योजना तथा चयन पद्धतियों में ऐसे परिवर्तनों की नियांत्रित करने के लिए जिनसे कि राष्ट्रीय विकास एवं पुर्वीनिर्णय के कार्यों के संदर्भ में उत्तर सेवाओं की भूमिका तथा कार्यों के परिषेय में सर्वृच्छा ज्ञान, कौशिल्य तथा शुद्धों पर परापूर्ण बल विद्या जाए, विनांक 6-2-74 को संघ सोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त कीठारी समिति के नाम से प्रसिद्ध, भर्ती नीति एवं चयन पद्धति समिति ने साकात्कारों में प्रश्नों का उत्तर देने को लिए भारतीय भाषाओं का प्रयोग करने के संबंध में निम्नलिखित सिफारिश की थी ।—

"विचार के लिए हमें भेजा यथा एक प्रश्न यह है कि क्या साकात्कारों में प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उम्मीदवारों को संविधान को भाठडी भनूँची में संभिलित भारतीय भाषाओं का प्रयोग करना चाहिए । बड़ी सावधानी के साथ विचार करने के बावह हमारी यह राय है कि सामान्य रूप से उम्मीदवारों को अंग्रेजी में उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित किया जाए । इससे निर्णय की प्रक्रिया में सुविधा ही ही, ब्योक्ति साकात्कार बीड़ के मध्य, जैसाकि बल है, वेश के विभिन्न प्रवेशों से लिए जाते हैं, उन सभी को सामान्य भाषा के रूप में अंग्रेजी का ज्ञान हीता है । इससे किसी उम्मीदवार को इनी उम्मीदवारों की गुलना में, योग्यता का निर्णय करते समय एकलक्ष्यता बनाए रखने में मदद मिलेगी । किर भी, साकात्कार में उम्मीदवारों की योग्यता की जाव करते समय उनके अंग्रेजी भाषा पर अधिकार को इतना संधिक महस्त न देकर उनके शुद्धों, विशेषताओं और उनके विचार-तत्व को महस्त दिया जाए । अगर किसी आपवादिक भाषण

में कोई उम्मीदवार किसी भारतीय भाषा में बोलने भी इच्छा ब्रक्ट करता है तबोकि वह अंग्रेजी में अपने विचार पर्याप्त रूप में स्पष्ट करने में अनुभव है, तो साकात्कार बीड़ को उम्मीदवार को भारतम बोला चाहिए और उसे किसी भी भारतीय भाषा में उत्तर देने की प्रवृत्ति दे दें ।"

सरकार ने कोठारी समिति की इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है । संघ सोक सेवा आयोग भी इस सिफारिश को उपयुक्त रूप में कार्यान्वित करेगा ।

### Number of Foreign Contracts obtained by E.P.I.

\*698. SHRI SUBHASH CHANDRA BOSE ALLURI: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to lay a statement showing:

(a) what is the total number and value of foreign contracts obtained by the Engineering Projects India Ltd. (E.P.I.) during the last three years;

(b) how many of those foreign contracts have been executed; and

(c) what is the position about the remaining contracts during the same period?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI GEORGE FERNANDES): (a) The Engineering Projects (India) Lt., (E.P.I) secured fifteen contracts of the total value of Rs. 557.57 crores during the three years 1976-77 to 1978-79. A statement showing the names and value of the contracts is placed on the table of the House.

(b) Four, out of fifteen contracts have been completed.

(c) The remaining eleven contracts are at various stages of implementation.

## Statement

Foreign contracts secured by EPI during the period 1976-77 to 1978-79

Year in which contract secured/Name of Project	Value of Project (Rs. in lakhs)	Remarks
<b>1976-77</b>		
1. Water Treatment Plant, Bangkok . . . . .	192.00	Completed.
2. Ain Baghze (Ardiya) Housing Project, Kuwait . . . . .	23000.00	
3. Mechanical Training Centre, Iskandriya, Iraq . . . . .	1027.00	Completed.
4. Supply of Surveying Instruments, Iraq . . . . .	6.04	Completed.
5. Consultancy Report for Guyana Steel Plant . . . . .	1.30	Completed.
	<b>24226.34</b>	
<b>1977-78</b>		
1. Wadi Jizan Electrification Scheme, Saudi Arabia . . . . .	1842.00	
2. Sief Palace Area Building, Kuwait . . . . .	3264.00	
3. 35th Brigade Camp, Kuwait . . . . .	8010.00	
	<b>13116.00</b>	
<b>1978-79</b>		
1. Northern Grain Silos, Iraq . . . . .	4600.00	
2. Water Research Centre, Iraq . . . . .	1550.00	
3. Central Grain Silos, Iraq . . . . .	4200.00	
4. SAAD-3 Project, Iraq . . . . .	4200.00	
5. Radio & Coloured TV Centre, Iraq . . . . .	1950.00	
6. Civil Works for Ruwais Refinery, Abu Dhabi . . . . .	2000.00	
7. Oil Storage Tanks Project, Jaddak, Saudi Arabia . . . . .	515.00	
	<b>18415.00</b>	

Grand Total (Value)—Rs. 55,757.34 lakhs.

## कागज की शालावाकारी

699. श्री गंगा अक्षर सिंह : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की हृपा करते हैं कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि उपाई के लिए प्रयोग में लाये जाने वाले सफेद कागज के व्यापार में काला बाजारी हो रही है जिसके परिणामस्वरूप करोड़ों ह० का कागज निर्धारित मूल्य पर बेचे जाने के स्थान पर अधिक कीमतों पर बेचा जाता है,

(ख) यदि हा, तो इसको रोकने के लिये सरकार ने क्या काम उठाए हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार उपाई के लिए प्रयोग में लाये जाने वाले सफेद कागज के व्यापार में एकाधिकार को समाप्त करने का है जिससे कि आपेक्षाने को यह कागज उचित मूल्य पर मिल सके।

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्दोस) : (क) और (ख). कागज के मूल्यों पर कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है; फिर भी, यह मत है कि कागज निर्माण तथा व्यापारी कागज की मात्र में तेजी से हुई बढ़ि का लाभ उठार कागज के मूल्यों में अनुचित बृद्धि कर रहे हैं। सरकार कागज की मात्र व पूर्ति के बीच के बीच के समान असंतुलन के कारण कागज के मूल्यों में सहे संबंधी बृद्धि न होने देने का सुनिचय करने हेतु कागज का उत्पादन बढ़ाने हेतु अनेक कदम उठा रही है और वह कागज का भायात करने पर भी विचार कर रही है। कागज उत्पादन के साथ एक बैठक हुई थी जिसमें उनसे कहा गया था कि वे मूल्यों को कम करें। कागज उत्पादन की ओर से अभी तक कोई उत्तर नहीं मिला है। सरकार कागज उत्पाद द्वारा मुनाफाज्ञी को समाप्त करने एवं कागज का अधिक समान वितरण करने के लिये अनेक उपायों पर विचार कर रही है।

(ग) कागज के उत्पादन या वितरण में से किसी पर भी एकाधिकार नहीं है।

## Progress in use of Thorium for Atomic Energy

\*701. SHRI A. K. ROY: Will the Minister of ATOMIC ENERGY be pleased to state:

(a) the progress made in India to use Thorium in place of enriched uranium as the principal source of deriving atomic energy in the country;

(b) whether it is a fact that India's source of low quality meagre uranium ore would never make her uranium based atomic energy a viable commercial solution to her energy problem; and

(c) if so, the facts in details and the steps taken thereon?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) Thorium cannot replace enriched uranium in reactors which are based exclusively on use of enriched uranium. However, a programme is in hand which will ultimately provide for generating power using thorium which is relatively more abundant. A prototype fast reactor is being constructed at Kalpakkam near Madras.

(b) and (c). The reserves of natural uranium in the country are adequate for the level of nuclear power programme currently envisaged.

## Use of CRP in atrocities on Adivasis in Baharagorh Area of Singhbhum District, Bihar

6601. SHRI A. K. ROY: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether he is aware of the atrocities on Adivasis in Baharagorh area of Singhbhum District in Bihar in the month of January, 1979; if so, the facts in details;

(b) whether Adivasis houses have been demolished and ladies have been tortured in the same area, if so, the facts in details;

(c) whether C.R.P. was used in the torture of Adivasis; and

(d) whether Central Government would put a ban on use of CRP by the State Government against the Harijans and Adivasis?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL):  
(a) and (b). The Bihar Government has reported that no incident of atrocity in the Bahar-gorah area in January 1979 has been brought to its notice, nor any case of molestation or torture. There was, however, one case of alleged rape but on enquiry by the local administration the allegation was found to be incorrect.

(c) and (d) The C.R.P. has been deployed in the area for maintenance of law and order and not for torturing the adivasis. The C.R.P. is deployed whenever re-inforcement is necessary and the State police fall short of requirement.

मध्य प्रदेश कपड़ा निगम के अधीन मिलों को हानियाँ

6602. श्री हृष्ण चत्व लक्ष्मण : यदा उत्तरोत्तर असारकित प्रश्न स 0 1387 दिनांक 29 नवम्बर, 1978 के उत्तर के बारे में यह बताने की रुप्ता करें कि :

(क) मध्य प्रदेश कपड़ा निगम के अधीन 6 मध्य बपट फिल्म में दैरान कितनी हानि हुई;

(ख) उपरोक्त अवधि के दैरान जिन विभिन्न पारियों और कफों को तैयार कपड़ा बेचा गया उनसे अदायगिता प्राप्त न हो वे कारण कितनी हानि हुई, और

(ग) उक्त मिलों के कपड़े के उत्पादन में प्रयोग से लाये गये बटिया रसायनों और रसों एवं रही माल से कपड़े में आये दोषों के कारण कितनी हानि हुई।

उत्तरोत्तरात्मक में राज्य अंतर्गत (भी अपार्टमेंट प्रश्नावाल) : (क) जनवरी, 1976 से नवम्बर, 1978 के दौरान राष्ट्रीय बस्त निगम (मध्य प्रदेश)

लिमिटेड के नियंत्रणाधीन 6 मध्य बस्त मिलों में से प्रत्येक मिल को निम्न प्रकार हानि हुई :—

(लाख रुपयों में)

मिल का नाम हानि/लाभ की राशि (प्रतिनिम्न)

1. हीरा मिल्स	(—) 155 66
2. स्वदेशी काटन एंड फ्लोर मिल्स	(—) 290 74
3. न्यू भोपाल ट्रैक्सटाइल मिल्स	(—) 145 77
4. बुरहानपुर नाप्टी मिल्स	(—) 44 75
5. हन्दौर युनाइटेड मिल्स	(—) 595 01
6. कल्याण मिल्स	(—) 319 02

(ब) विभिन्न पारियों व कफों द्वारा भूगतान न करन/हिँड़िया वापिस कर देने की बजह से इन 6 मिलों को जनवरी, 1976 से नवम्बर, 1978 की अवधि में हुई हानि मबद्दी जानकारी अन्त ने उपलब्ध नहीं है। नवापी, उपर्युक्त वाराणी मध्य प्रदेश, 1975 से अप्रैल, 1978 की अवधि में 4,00, 111 11 रुपए की हानि हुई थी। (उपरोक्त हानियाँ में भूगतान न किए जाने/हिँड़िया वापिस हो जाने की बजह से कार्यकारी पूजी में आई कमी के कलम्बरूप हुई हानि जैसी न दिखने गाली हानियाँ भी जारी हैं।

(ग) उपरोक्त में लाए जाने वाले माल के नमूनों की जाव वास्तविक उपयोग से पूर्व की जाती है तथा बटिया माल का उपयोग नहीं किया जाता है। अत इसकी बजह से हानि होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

#### Contracts won in foreign countries by Indian firms in the field of Textiles

6603. SHRIMATI MOHSINA KIDWAI: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) how many Indian Firms have won contracts in foreign countries for providing training, teaching and consultancy services in the field of textiles during the last one and a half year;

(b) the amount of the contracts signed by each; and

(c) whether these firms have clean record as far as the payment of taxes in the country is concerned?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) to 'c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

जम्मू व काश्मीर में हथकरथा उद्योग का विकास

6604. श्रीमती शार्दूली देवी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की हुपा करेंगे कि ।

(क) क्या केंद्र सरकार जम्मू व काश्मीर में हथकरथा उद्योग के विकास के लिये किसी परियोजना पर विचार कर रही है; और

(ब) यदि हा, तो उसका व्योरा क्या है ।

उद्योग मंत्रालय में राज्य संबंधी (श्री अगवानी प्रसाद यादव) : (क) और (ब). जी, हा । जम्मू तथा काश्मीर सरकार ने कहीं शाल उद्योग के विकास हेतु एक परियोजना स्थापित करने के लिए प्रस्ताव भेजा है । प्रस्ताव में कार्यकारी पूँजी के अन्तरिक्ष, तीन वर्ष में 9 43 लाख ८० के अनुमानित व्यय से 100 करबे स्थापित करने की कल्पना है । इसमें सामान्य जाड़ों में 350 व्यक्ति नियुक्त किये जाएंगे और तीसरे वर्ष के अन्त तक वार्षिक उत्पादन 600 शालों का होगा ।

#### Production of Cotton in Punjab

6605. CHOWDHURY BALBIR SINGH: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Punjab is producing a lot of cotton;

(b) whether it is also a fact that there is no cotton and spinning mill there in Public Sector;

(c) if so, the reasons therefor;

(d) whether Government propose to open the same in the backward district of Hoshiarpur for the uplift of the same; and

(e) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) Yes, Sir.

(b) A spinning mill has been set up at Bhatinda in public sector.

(c) Does not arise.

(d) and (e). There is no proposal at present to set up a cotton spinning mill in public sector in Hoshiarpur District. However, in addition to one spinning mill of about 50,000 spindles already working in private sector in that District, another spinning mill is being set up there in joint sector.

#### Bharat Industries and Commercial Corporation

6607 SHRI SURENDRA BIKRAM: Will the Minister of ELECTRONICS be pleased to state:

(a) what items of electronics will be manufactured by Bharat Industries and Commercial Corporation and what will be their uses;

(b) when this Corporation is expected to go into production and what items will be manufactured in the initial stages,

(c) how much employment will be provided by this unit directly and indirectly; and

(d) will this unit export certain items manufactured by it and also impart know-how to Indian industries abroad?

#### THE MINISTER OF STATE ELECTRONICS (PROF. SHER SINGH):

(a) and (d). The Department of Electronics has not received any proposal for small scale approval or industrial licence for the manufacture of electronics goods from a firm named M/s. Bharat Industries and Commercial Corporation.

**Improvement in Financial Condition of Harijans**

**6608. SHRI JANARDHANA POOJARY:** Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state the extent to which the financial condition of the Harijans in the country has been improved during the last two years?

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL):** The assessment of the improvements in the financial conditions of the Harijans in the country would require extensive and detailed studies. No information on this scale and magnitude is available. The Planning Commission in the Draft Five Year Plan 1978-83, has made references to the financial conditions of Harijans, like the following:—

“The prevalence of poverty and inequality, virtually unchanged over the years, can be seen most clearly in the conditions of life of the two disadvantaged groups in our society, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes... So far they have been only marginally involved in the process of development... Scheduled Castes generally constitute a substantial fraction of the population below the poverty line. They have few assets and are generally dependent on share-cropping or agricultural labour.”

**Charter of Demands by Employees of Rajasthan Atomic Power Project**

**6609. SHRI MADHAVRAO SCINDIA:** Will the Minister of ATOMIC ENERGY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the charter of demands submitted by the employees of the Rajasthan Atomic Power Project is pending consideration with Government for more than five years and as a result the employees

have now threatened to go on an indefinite hunger strike to press the Government to meet their demand in near future;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the steps proposed to be taken to take a decision in the matter and preventing the hunger strike?

**THE MINISTER OF STATE ATOMIC ENERGY (PROF SHER SINGH):** (a), (b) and (c). No, Sir A charter of demands was submitted in June 1977 by the employees of the Rajasthan Atomic Power Project. Conciliation proceedings were held. But they failed. There was then a strike in the Station from September 8, 1977 to January 7, 1978. After the strike was called off unconditionally a series of discussion were held with the Union leaders upto the level of Union Labour Minister. Certain concessions were offered to the employees with a view to an amicable settlement. The Union, however, rejected the offer. Two workmen representing non-recognised union started relay hunger strike on March 12, 1979. In addition another workmen commenced hunger strike on March 19, 1979 and was removed by the police on March 26, 1979. Conciliation proceedings with the recognised Union are in progress.

कारों, लूटारों और दायरों तथा दूसरों के मूल्यों में बढ़ि

6610. श्री धर्मसिंह भाई पटेल : क्या उद्योग मंत्री यह बनाने की कृता करते हैं कि :

(क) 1 अगस्त, 1978, तथा 28 फरवरी, 1979 को ट्रैकरों, ट्रकों, मोटरकारों, लूटारों, माइकलों तथा दूसरों और दायरों के दाम क्या क्या हैं;

(ख) क्या इनके मूल्य घटाने के लिये कोई कायंवाही की गई है;

(ग) यदि हाँ, तो उसका व्यौदा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इनके मूल्यों को कब तथा कैसे क्या किया जाएगा?

उद्दोल नंदगालय में राष्ट्रीय बंगली (बी जगदबादी असाध यादव) : (क) विवरण I तथा II संलग्न है।

(ब) से (घ)। इस समय ट्रैक्टरों, ट्रॉली, मोटर कारों, स्कॉटरों, साइकलों तथा टायरों और ट्रूपों की कीमतों पर कोई कानूनी नियन्त्रण नहीं है। किर भी मरकार स्थिति पर नियंत्रणी रखे हुए हैं।

### विवरण—I

धोक मूल्य सूचकांक में शामिल किए गए परिवहन उपकरणों की कीमतें।

वस्तु	विविधता	विपणन	(कीमत २० में) 1-4-1978 को 28-2-79 को
1	2	3	4
ट्रैक्टर	एम एफ-19. 35 डीजल ट्रैक्टर (छुदरा कीमत)	गतव्य स्थान तक रेल भाडा मूक्त	42966.53 5395 0 50
ट्रक	(1) अशोक लेलैंड "कोमट एस्को 3/1-76" डब्ल्यू की गुडस चैरी (2) टाटा माठल एल बी 1210 ई/ 52-5195	मद्रास में कारखाने से निकलते समय की कीमत कारखाने से निकलते समय की कीमत	90012.47 97062.56 93021 56 95175 22
कार	(1) स्टेट्ड गेंज कार (2) प्रीमियर पद्मनी कार (3) सफेद किनारा (साइजो) हिन्दुस्तान एंडेसडर कार	बही	21686 47 कीमत प्राकडे उपलब्ध नहीं है बही 28477.48 1-1-79 से तालबनी होने के कारण कीमत प्राकडे उपलब्ध नहीं है।
स्कूटर	(1) साम्बी स्कूटर 150 सी सी (2) बजाज स्कूटर 150 सी सी बेस्पा	बम्बई में कारखाने से निकलते समय का मूल्य	31056.87 35508.95 4172.61 4355.88 कारखाने से निकलते समय का मूल्य 34.11,51 4052,59
साइकल	(1) एटलस साइकल (2) रेले 24 साइकल (छुदरा कीमत) (3) हरकूलिस पापुलर ब्लैक टी प्राई साइकल	गतव्य स्थान तक रेल भाडा मूक्त विलसी	262.23 358.00 287.43 396.00 गतव्य स्थान तक रेल भाडा मूक्त 312.28 345.00

## विवरण-II

धोक भूम्य सूचकांक में शामिल किए गए टायरों तथा ट्यूबों की विवरक बनाते मम्यूंडों कीमत

क्रमांक	विविधता के माध्य वस्तु	विषयन	इकाई	कीमत ६० में
टायर		गतव्य स्थान तक रेल भाड़ा मदत	एक	1 4 79 को 28-2-79 को
1	द्वार टायर रेन वी एम डबल्यू बाड-II इनरप कोट क्व 6 70 15— 6 प्लाई रेटिंग डैक मी० ४९	वी	वही	279 71 331 28
2	5 90-16	मी० १९	वही	वही 229 74 279 22
3	5 20-14	मी० ४९	वहा	वहा 19/ 19 241 36
4	5 60-13	सी० ४९	वही	वही 208 23 235 05
	द्वार ग्राम्य ग्राम्य स्ट्राउ लाय 5 आर आई वी 9 25-0 1-प्लाई रेटिंग डैक डबल्यू/105	वही	वही 1077 43 1304 59	
6	9 00-20 12 पी० आर० डबल्यू 115/ डबल्यू० डबल्यू० 19/	वही	वही 1370 85 1558 57	
7	साइकल टायर 29-1-1/2 इन्य० दो० गोल्ड मीस	वही	वही 12 20 3 40	
8	मोटर माइक्रो टायर 3-25-19 4 प्लाई रेटिंग यनिवसर	वा०	वही 112 36 122 46	
9	इनरप र रिवर नायर 50-10 4 प्लाई	वहा	वही 73 23 80 80	
10	ट्रक्टर टायर रियर 11 2-29 10-28 जी० जो० ए०टी० 6 प्लाई एकम 99	वही	वही 893 87 999 00	
11	ट्रक्टर टायर रियर 12 4 3/11-28 जी जी० / टी० आर ए टी० एप्प एप्प आर 6 प्लाई	वही	वही 1074 39 1232 00	
12	प्राफ वी हाई वे टायर्स नायलन टायर्स 12 00 24/25/16 प्लाई	वही	वही 3113 99 4065 85	
13	प्राफ वी हाई वे टायर्स नायलन नायर्स 18 00— 24/25 20 प्लाई	वही	वही 9905 74 9805 74	
ट्यूब		गतव्य स्थान तक रेल भाड़ा मदत	एक	1-4-78 को 28-2-79 को
1	मोटर वार्टट्यूब्स 5 90-15(जी०-15)	वही	वही	33 13 37 86
2	बड़ी ट्रक ट्यूब्स 9 00 2 (वाइटाइल)	वहा । ।	वही । । 120 05 140 40	
3	मोटर साइकल ट्यूब्स 3 25 से 16	वही	वहा	22 72 26 51
4	ट्रू विलर स्कूटर ट्यूब 3 50 10	वही	वही	16 41 18 94
5	साइकल ट्यूब्स हैवी सर्विस	वही ।	वही । 5 00	15 55
6	साइकल ट्यूब्स (रोड स्टार)	वही ।	वही । 5 15	5 70
7	ट्रक्टर ट्यूब्स 2 4 28/11-28 जी०जी०टी० आर०/ए०टी०ए०फ० एप्प आर०	वही	वही । । 126 10	145 00
8	ट्रक्टर ट्यूब्स 13 6 29 (12-28) ए०टी०ए० ए०फ० एप्प आर	वही ।	वही । 175 12	200 00
9	प्राफ वी हाई वे ट्यूब्स नायलन 12 00-24/25	वही ।	वही । । 217 21	233 44
10.	प्राफ वी हाई वे ट्यूब्स नायलन 18 00-24/25	वही	वही 6,3 21	653 21

### Review of Controlled Cloth Scheme

6611. SHRI K. MALLANNA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under the consideration of Government to review the controlled cloth scheme;

(b) whether there has been decline in the standard cloth; and

(c) if so, the details regarding the policy of Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) No, Sir.

(b) and (c). As against the production of 419.63 million sq. metres of controlled cloth in mill sector and handloom sector during the entire year 1977-78, production during April, 1978 to December, 1978 (9 months) is about 337.66 million sq. metres. While production figures for the period January, 1979 to March, 1979 are not yet available, the production for the year, 1978-79 as a whole is likely to be higher than the production level of 1977-78.

### Preparation of Panel for Selection Grade (Deputy Secretary) of C.S.S.

6612. SHRI ISMAIL HOSSAIN KHAN: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether for preparing panel for Selection Grade (Deputy Secretaries) of the Central Secretariat Services only those officers of Grade-I of the Service (Under Secretaries) whose last five years' reports have been categorised atleast 'very good' are considered.

(b) if so, whether this criteria is being adopted in respect of other services also or only in the case of Central Secretariat Service;

(c) whether adequate weightage is given to the officers who have put in sufficiently long service as Under Secretaries and have also reached the maximum of the scale; or is there any proposal to compensate them by giving them special increments or allowance; and

(d) whether there is any proposal for the premature retirement of such of the officers who have been left over for promotion for several years by giving them same retirement benefits such as cash payment of Leave Salary etc.?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI S. D. PATIL): (a) No, Sir. Vacancies in the Selection Grade of the Central Secretariat Service are to be filled up by promotion of permanent officers of Grade I who have rendered not less than 5 years approved service in that Grade and are included in the Select List for Selection Grade prepared under sub-rule 4 of Rule 12 of the C.S.S. Rule 1962 and related regulations framed thereunder.

(b) Does not arise.

(c) and (d) The selection of eligible Grade I officers of the C.S.S. for promotion to Selection Grade is made on the basis of merit. No proposal for compensating the officers left over for promotion is under consideration.

### Representation from the Staff of Richardson and Cruddas Ltd.

6613. SHRI R. K. MHALGI: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government have received a representation dated 20th February, 1979 from the members of the Staff of Richardson and Cruddas Ltd. Byculla Bombay (a Govt. of India Undertaking);

(b) if so, when and what are the grievances put forth and demands made therein; and

(c) what action Government have taken so far or propose to take in near future?

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI):** (a) Yes, Sir.

(b) The monthly rated staff and peons of the Byculla Iron Works of M/s. Richardson & Cruddas (1972) Lt, went on strike from 7-9-78 to 8-1-79. During the period of the strike, some employees were found indulging in acts of vandalism and inciting other striking employees to indulge in such acts of misconduct. Thirteen such employees were suspended pending completion of departmental enquiries against them. In the representation dated 20-2-79, two of the suspended employees had requested for withdrawal of orders of suspensions and payments of wages for the period of their suspension. They had also stated that the management had not taken similar action in respect of the employees of the Mulund Works of the Company, who were also on strike during the same period.

(c) After the suspended employees had submitted a written apology expressing regret for their conduct, the management have withdrawn the orders of suspension and they have also closed the enquiries against them. These employees have since been allowed to resume their duties. Since the Company's Standing Orders do not provide for payment of wages during the period of suspension, it is not possible for the Company to pay wages to these employees for that period.

No charge sheets were served on the employees of the Mulund Works as none of them had indulged in acts

of vandalism or misconduct during the period of strike.

#### **Seizure of Tools of Cultivators in Andaman and Nicobar Islands**

**6614. SHRI MANORANJAN BHAKTA:** Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that in 1st week of February, 1979, the tools of the cultivators belonging to Mowa Dera, Tushnabad Panchayat, under South Andaman Tahsil in Andaman and Nicobar Islands were seized by the Forest Officers by using armed forest Guards,

(b) whether it is a fact that these cultivators were working on the land allotted to them by Andaman and Nicobar Administration; if so, the reasons of harassing the cultivators and seizing their agricultural tools with details of the tools and the further development in the matter, and

(c) whether Government are aware about the similar seizure of Agricultural tools from the farmers of Chouldari while they were working on their allotted lands on the 10th January, 1978 by one K. P. Achaiya, Range Officer; if so, the details thereof and the action Government propose to take against the Forest Department?

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL):** (a) Yes, Sir.

(b) According to the report received from Andaman and Nicobar Administration these cultivators were clearing forest growth within an area which according to forest records and maps was protected forest area and clearing of forest growth within such areas is prohibited under the forest Act. Five dahas and two felling axes were seized from them which were subsequently released on intervention by the revenue authorities.

(c) Seizure of Agricultural tools from the farmers of Chouldari area was made because they were clearing forest growth within the protected forest area. The seized implements are still in the custody of the Forest Department pending finalization of the case.

**News Item Captioned 'Tribunals for Government Employees'**

6615. SHRI VASANT SATHE: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether attention of Government has been drawn to the news report appearing in the *Indian Express* dated the 21st March, 1979 under the caption "Tribunals for Government employees", and

(b) if so, what is the reaction of Government to the various decisions reported to have been taken or under consideration of Government, facts of the matter and the latest position regarding the proposals finalised and details of action taken/proposed for the implementation of the same?

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI S. D. PATIL):** (a) A news item captioned 'Tribunals for Government employees' appeared in the *Indian Express* dated the 21st March, 1979.

(b) The details of the proposal to set up Administrative Tribunal for employees engaged in connection with the affairs of the Union have not yet been finalised.

**News item captioned 'Abdullah ready for Partition of State'**

6616. SHRI VIJAY KUMAR N. PATIL: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the attention of Government has been drawn to the news

report appearing in the *Indian Express* dated 21st March, 1979 under the caption "Abdullah ready for partition of State"; and

(b) if so, what is the reaction of Government to the various observations made therein?

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL):**

(a) Yes, Sir.

(b) According to our information, the Chief Minister of Jammu and Kashmir had, while speaking in the State Legislative Assembly on the 21st March, 1979, refuted the allegation that he wanted a division of the State

The Government are opposed to, and disapprove of, any suggestion or move towards the division of the State on regional considerations.

**Setting up of Vanaspati Factory in Orissa**

6617. SHRI D. AMAT: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government of Orissa has planned to set up a Vanaspati factory and a spinning mill at Bolangir and Titlagarh of Bolangir district of Orissa; and

(b) if so, when the concerned factory and mill will be set up and the proposed amount to be invested in these concerns?

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV):** (a) and (b). Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

**Engaging of a Lawyer by CSIO, Chandigarh****Suspension of Pension to Freedom Fighters**

6618. DR. SARADISH ROY: Will the Minister of SCIENCE AND TECHNOLOGY be pleased to state:

(a) whether the Central Scientific Instruments Organisation (CSIO) Chandigarh engaged a lawyer for representing them before the Assistant Labour Commissioner (Central) Chandigarh and before the Registrar, Trade Unions, Chandigarh in the matter of certain industrial disputes between the management and the workers;

(b) how much fees was paid to the lawyer and whether lawyer represented the management in both the cases; and

(c) why the job could not be done by the full time Law Officer of CSIR to save the expenditure?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE AND IN THE DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY, ELECTRONICS, SCIENCE AND TECHNOLOGY AND SPACE (PROF. SHER SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) A sum of Rs. 1,500/- (Rupees one thousand and five hundred only) was paid as fee to the lawyer. He was engaged to represent the management in both the cases. However, the Assistant Labour Commissioner (Central) did not allow him to represent the management before him.

(c) In accordance with the practice in vogue in CSIR, lawyers are engaged to present/defend cases in various Courts. In this case a local lawyer experienced in Labour Laws was considered necessary and was engaged in addition to the Law Officer of the CSIR who deals with legal matters of all the National Laboratories/Institutes.

6619. SHRI C. K. CHANDRAPPAN: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1214 on 28th February, 1979 regarding pension to freedom fighters and state:

(a) in how many cases Government have stopped or suspended the pension given to freedom fighters in each State after March 1977;

(b) the reasons for doing so; and

(c) in how many pending cases decision to grant or not to grant pension has been taken during the same period?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL):

(a) and (c). Pension has been sanctioned in 2028 cases, rejected in 4999 cases, suspended in 2281 cases and stopped (cancelled) in 550 cases during the period from 1-4-1977 to 31-3-1979. A State-wise statement is attached.

(b) The pension has been suspended/stopped on one or more of the following grounds:—

(i) Applicant is not a genuine freedom fighter.

(ii) Suffering is less than six months.

(iii) Suffering not in connection with freedom movement.

(iv) Submission of false documentary evidence.

(v) Internment/externment/absconcence is not supported by evidence based on official records.

(vi) Annual income from all sources is more than Rs. 5000/-.

## Statement

Statement showing the number of cases in which pension has been sanctioned, rejected, suspended and stopped (cancelled) during the period from 1-4-1977 to 31-3-1979 (State-wise)

States/Union Territories	1	Sanctioned	Rejected	Suspended	Stopped (Cancelled)
		2	3	4	5
1. Andhra Pradesh . . . . .	157	286	16	20	
2. Assam . . . . .	19	107		10	
3. Bihar . . . . .	178	1600	46	44	
4. Chandigarh . . . . .			1		
5. Delhi . . . . .	4	20		9	
6. Goa . . . . .	20	25	1		
7. Gujarat . . . . .	19	96	8	1	
8. Haryana . . . . .	2	32	30	1	
9. Himachal Pradesh . . . . .	2	12	11	1	
10. Jammu & Kashmir . . . . .	2	7	4		
11. Kerala . . . . .	87	405	..	47	
12. Karnataka . . . . .	105	365	1241	74	
13. Madhya Pradesh . . . . .	26	76	..	33	
14. Maharashtra . . . . .	225	497	75	14	
15. Manipur . . . . .	..	..	..	7	
16. Meghalaya . . . . .	..	..	4	13	
17. Orissa . . . . .	17	35	..	21	
18. Pondicherry . . . . .	4	23	..	36	
19. Punjab . . . . .	29	104	47	15	
20. Rajasthan . . . . .	7	18	16	3	
21. Tamil Nadu . . . . .	52	201	..	76	
22. Tripura . . . . .	3	77	..	35	
23. Uttar Pradesh . . . . .	42	456	402	90	
24. West Bengal . . . . .	551	283	70	93	
25. INA Personnel . . . . .	468	206	312	8	
<b>Total . . . . .</b>	<b>2028</b>	<b>4999</b>	<b>2281</b>	<b>550</b>	

**Constitution of Thana Level Peace Committees in Delhi**

6620. SHRI MAHI LAL: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the procedure and criteria adopted for the constitution of Thana Level Peace Committees in the respective Police Stations in Delhi;

(b) the constitution, functions of these peace committees and the qualifications of a person for being a member of such a peace committee;

(c) whether the present enrolment of members for the Thana Level Peace Committees is screened by the Police authorities and finally cleared by the Member of the Metropolitan Council of a particular political party; and

(d) if so, the reasons for giving authority to the members of a particular political party only of clearing the final list of candidates for the peace committees which are considered to be purely non-political?

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI S. D. PATIL):** (a) to (d). A Thana Level Committee with the Member of the Metropolitan Council of the area as the Chairman is functioning in each Police Station in the capital. The Committee is constituted in accordance with the guidelines (Statement attached) formulated by the Delhi Administration in this regard.

**Statement**

1. Guidelines regarding constitution of the Thana Level Committee in Delhi.

1. There will be one Committee for each police station in the Union Territory of Delhi whose Chairman will be the Metropolitan Councillor of the

area. Where there are more than one Metropolitan Councillor in the jurisdiction of a police station, they will be nominated as Chairman of the Committee each for a year by rotation. Chairman will be appointed by the Chief Executive Councillor.

2. The Asstt. Commissioner of Police of the area will be the convener of the Thana Level Committee within his jurisdiction.

3. There will be not more than 25 members in each committee two of whom shall be ladies. The names of the members will be approved by the Chairman. The names suggested by the Commissioner of Police and others can also be considered by him.

The following are the categories of persons from whom nominations shall be made:—

(i) Municipal Councillor (S) of the area/Member of the NDMC.

(ii) President/Secretary of the renowned religious Institutions.

(iii) President/Secretary of the local Bazar Association.

(iv) Principal of the local School/College.

(v) Representative of the Residents Welfare Association.

(vi) Representative of Industrial Labour.

There is no objection to more than one or two members being drawn from each category according to need, but the ceiling of membership as a whole should be kept at 25.

4. The approval of the Chairman regarding the names of persons to be associated in Thana Level Committees from the categories as above shall be subject to review by the Admn., as may be called for.

5. The Thana Level Committee shall meet at least once a month and

the convenor shall record the proceedings of the meeting and send copies thereof, *inter alia* to the Lt. Governor, Chief Executive Councillor, Chief Secy. and Secy. (Home) Delhi Administration.

6. Deputy Commissioner of Police of the Distt. shall attend all meetings of the Committee within his jurisdiction.

7. The term of Committee shall be one calendar year and the Chairman/Members will be eligible for renomination.

8. The convenor of the Committee shall finalise the constitution of the respective committee by the month of November preceding the year for which the Committee is to be constituted.

9. The Committee constituted as at present will continue to function till new Committees in their place are constituted in accordance with these guidelines. . . .

#### **(G.P. Fund of Delhi Administration Employees**

6621. SHRI HALIMUDDIN AHMED: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to refer to the statement of the Chief Executive Councillor, Delhi regarding issuing the Pass Books to Delhi Administration employees about their GPF contribution from April 1979 onwards and state:

(a) what action is being taken to issue the statement of account of GPF contributions for the year 1976-77 and 1977-78 by the Controller of Accounts, Delhi Administration, Delhi; and

(b) what remedy is being suggested to adjust the missing credits of GPF of the employees which runs into crores of rupees and how will it be reflected in the Pass Books?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI S. D. PATIL): (a) Delhi Administration have intimated that statement of GPF Account in respect of their employees for the year 1976-77 which were to be issued by the Controller of Accounts, Ministry of Finance (Computer Cell) could not be issued so far since all the computers in Delhi in which the programme can be run are out of order.

The Statement of Accounts for the year 1977-78 are likely to be issued by the Controller of Accounts, Delhi Administration by the 31st October, 1979

(b) The Administration propose to obtain collateral evidence from the offices of the employees in respect of whom credits are missing for necessary adjustment and for this purpose the Administration propose to depute perapatic parties to visit the concerned offices.

The question of reflecting missing credits in the Pass Books will arise only after the Delhi Administration decides to introduce the system of Pass Books.

#### **Regularisation of Class III and IV Employees Appointed on Ad-hoc Basis**

6623. SHRI RAMANAND TIWARY: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Class III and Class IV employees have been appointed on *ad-hoc* basis in various Ministries/Departments of the Central Government;

(b) if so, the year-wise (up to December, 1978) number and class of the *ad-hoc* employees in various Ministries/Departments,

(c) whether it is stated in Ministry of Home Affairs OM No.

30/10/E.G. 1/60 dated 14th December, 1960 that there is no objection in regularising the services of the *ad-hoc* employees who have at their credit the service of not less than one year;

(d) if so, whether a copy thereof will be laid on the Table of the House and whether this order is being implemented;

(e) if not, whether Government propose to regularise such *ad-hoc* employees who have completed the service from one to three years; and

(f) if so, the time by which and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI S. D. PATIL): (a) and (b). The recruitments rules prescribe for all appointments to be made in a regular manner. However, due to exigencies of service and immediate needs, in some cases, *ad hoc* appointments are resorted to by Ministries/ Departments themselves. Government do not monitor such information.

(c) and (d). The O.M. No. 30/10-EG I/60 dated 14th December, 1960 issued from Ministry of Finance (not from M.H.A.) relates to conversion of temporary posts into permanent ones at successive reviews and does not contain anything about regularising the services of *ad-hoc* employees. Copy of the above O.M. is placed on the Table of the House. [Placed in Library. See No. LT-4281/79].

(e) and (f). Appointments can be made only in accordance with the prescribed Recruitment Rules. While making regular appointments, persons appointed on *ad-hoc* basis can also apply for being considered alongwith other eligible persons, provided they satisfy the requirements prescribed in the Recruitment Rules.

#### Per Capita Income of Poors

6624. SHRI B. C. KAMBLE: Will the Minister of PLANNING be pleased to state:

(a) is it a fact that severe destitute and the poor constitute nearly 85 per cent of our Indian people;

(b) what kinds of social groups to which each of these categories of people belong;

(c) what is the *per capita* income of each of the above mentioned three categories of people; and

(d) what are specific schemes and the details of each of such schemes to relieve the distress of these categories Government have undertaken or propose to undertake?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING (SHRI FAZLUR RAHMAN): (a) No, Sir. According to the norm adopted by the Planning Commission in the formulation of the Draft Five Year Plan 1978-83, the percentage of the people below the poverty line including destitutes was 46.33 in 1977-78. It was stated in the Fourth Five Year Plan document that the poorest 10 per cent of the population consist mostly of destitute, disabled persons and others who cannot participate much in economic activity.

(b) Precise information is not available about the social composition of the population below the poverty line. However, as indicated in the Draft Plan 1978-83, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are among the poorest sections of the population. The vast majority of the poor are landless labourers and marginal farmers. Village artisans progressively thrown out of their traditional employment are included among these groups.

(c) Precise estimates of the *per capita* income of the three categories

of people viz. the destitute, the poor and the not-so-poor are not available.

(d) The main thrust of the development strategy now adopted aims at significant reduction of poverty and unemployment in a decade. The Draft Plan (1978-83) has, therefore, accorded the highest priority to agriculture and allied sectors, irrigation and village and cottage industries which have the greatest capacity to absorb surplus labour. An expanded Minimum Needs Programme has also been provided for so that the living standards of the poor can be directly supplemented by the provision of certain basic amenities.

The Plan also gives special attention to the poor. It seeks to integrate provisions for the backward classes in general development programmes so that these can be effectively implemented. It provides for special sub-plans for the tribal areas. For area planning the selection of blocks is made in such a manner as to favour backward classes, agricultural labourers and small and marginal farmers.

In some States, such as Rajasthan, Antyodaya schemes are being implemented. These attempt to attack directly the poverty of the poorest and the destitutes.

**Cotton Growers hit by unrestricted imports of Viscose Fibre**

6625. SHRI D. D. DESAI: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether the cotton growers in the country have been badly hit by the unrestricted imports of viscose fibre from Japan; and

(b) if so, the measures proposed to be taken to protect the interests of cotton growers?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) and (b). In view of acute domestic shortage of cotton during the cotton

season 1976-77, Government made it obligatory on cotton textile mills to use from January, 1977 non-cotton fibres to the extent of at least 10 per cent of their total fibre consumption and for this purpose liberal imports of man-made fibres were permitted. With the cotton situation turning out to be favourable during the current season (1978-79), the Government imposed import duty on viscose staple fibre and also increased excise duty on indigenous viscose staple fibre from January, 1979 and also withdraw the above statutory stipulation in February, 1979.

**Ashes of Netaji Subhash Chandra Bose**

6626. SHRI K. T. KOSALRAM: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the action taken on the suggestion of General Fujiwara of the Japanese Imperial Army, the custodian of the ashes of Netaji Subhash Chandra Bose for ceremoniously handing it over to the Government of India;

(b) whether the Chief Monk, Matsusuki of Renkoji Shrine near Tokyo under whose care the urn containing the ashes is being kept has been contacted for this purpose; and

(c) if so, when the Government of India are going to receive the urn of ashes?

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL):**

(a) In the light of reasonable doubts cast on the correctness of the conclusions reached in the two inquiry reports on the death of Netaji Subhash Chandra Bose, Govt. find it difficult to accept that the earlier conclusions are decisive. It will, therefore, not be possible to take any action at present on the suggestion of General Fujiwara.

(b) and (c). Do not arise.

**Conference of senior police officials and M.P.s. on Law and Order in Delhi**

6627. PROF. P. G. MAVALANKAR: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether he held recently a high level conference of senior police officials and Members of Parliament from Delhi to discuss the law and order situation in the capital;

(b) if so, the facts thereof

(c) whether it is a fact that he expressed dissatisfaction at the said conference over the prevailing law and order situation in the capital; and

(d) if so, what measures are being taken by Government to improve the situation and what steps were suggested in this regard at the said conference?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI S. D. PATIL): (a) to (d) Yes, Sir. A meeting was taken by the Home Minister on 16-3-1979 to discuss the law and order situation in Delhi. A copy of the minutes is laid on the Table of the House [Placed in Library. See No LT-4282/79]

The police organisation in Delhi, has taken and is taking a number of steps to improve its efficiency and functioning. These include creation of a new police district called West Delhi, setting up of 8 new police stations and 12 police posts, increasing the number of CRP Bns. from 4 to 6, intensifying patrolling with the help of CRP and Home Guards, launching special drive against bad characters (233 persons have been exterted between 1-8-1978 and 5-3-1979) and setting up of a special centralised squad for dealing with important cases and for improving the intelligence system. The

Police Commissioner keeps close contact with his senior officers, meeting them everyday to review the situation in various parts of the city. The Lt. Governor also periodically reviews the situation.

**Development of Sericulture Industry**

6628. DR. VASANT KUMAR PANDIT: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government have drawn up definite programme for wider development of Sericulture industry in the country, if so, what are the details;

(b) how many silk Research Centres are operating in Madhya Pradesh; and

(c) whether Government propose to encourage development of Sericulture in Mulberry and non-mulberry backward areas of Madhya Pradesh, if so, the details of such plans?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) Yes, Sir. The Central Silk Board has drawn up programmes for the development of sericulture industry in the country during the Sixth Plan period with the following objectives:

(i) Doubling the production of raw silk in the country to 75 lakh Kgs.,

(ii) Trebling the exports of silk goods to Rs. 100 crores per annum; and

(iii) Providing additional employment to 10 lakh persons.

(b) None at present.

(c) Particulars of the programmes drawn up for development of Sericulture in Madhya Pradesh during the Sixth Plan period are as under:

(i) to establish 92 tasar production centres and a few production-

cum-training centres with a view to increase production of tasar silk from 51000 Kgs. to 2,34,000 Kgs.

(ii) to expand the area of mulberry cultivation to 1000 acres and achieve a production level of 20,000 Kgs. mulberry raw silk;

(iii) to provide additional employment to 3700 families.

#### Representation from Workers of Wimco Match Factory

6629. PROF. SAMAR GUHA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether the workers of Wimco Match Factory have made a representation to Government expressing their fear that if the increase excise duty on matches is not reduced, the five units of the company are likely to face closure;

(b) if so, facts thereabout; and

(c) the reaction of Government about the Memorandum and various other appeals made to the Government for deduction of taxes on manufacture of matches by Wimco?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) to (c) The workers of WIMCO Match Factory have submitted a representation to Government expressing their fear that if the increased excise duty on matches produced in the mechanised sector is not reduced there is a likelihood of closure of some of the units of this company and large scale retrenchment of its workers. The rates of duty announced in the Budget Proposals for the year 1979-80 is a conscious decision of the Government and is expected to accelerate the

growth of non-mechanised sector in general and cottage units in particular. It is hoped that the tax differential should induce WIMCO to expedite formulation of its plans for diversification of its activities to maintain its financial liability. Pending such diversification it should be possible for WIMCO to absorb a substantial portion of the incidence of enhanced excise duty. According to the provisions of Industrial Disputes Act (Amended) units employing more than 300 persons are required to obtain prior permission of the appropriate Govt. before any retrenchment is effected.

माण्डवा तथा सोनगढ़ गुजरात के आदिवासी लोगों का परियोजनाओं पर व्यय

6630. श्री छोटू भाई गामित: क्या गृह मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण ममा-पट्टन पर रखने की कृपा करें कि-

(क) गुजरात में माण्डवी नदा सोनगढ़ के आदिवासी लोगों से परियोजनाओं पर ज.न. 1978 तक किये गये व्यय का व्यूहा क्या है

(ख) (योजनावार) किननी धनराशि वर्व की गई है और आदिवासी कृषि श्रमिकों के लिए योजना पर किननी धनराशि वर्व की गई है; और

(ग) उक्त योजना के लिए चालू वर्व के दौरान केंद्रीय भरकार का किननी सहायता देने का विचार है?

गृह मंत्रालय वे राश्य संघी (जी एसएस लाल मण्डन) (क) और (ख) : उत्तरवाच सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) गुजरात में वर्ष 1979-80 के लिए जनजातीय उप-योजना लोगों के लिए 4.86 करोड़ 65ए की स्थाई धनराशि निर्वाचित की गई है।

## विवरण

बर्ब की गई बताराति (29 मार्च, 1978 को राज्य सरकार द्वारा यथा सूचित) और गुजरात के सोनगढ़ और माण्डवी जेलों की योजनाओं के अंतरों का विवरण।

न० स०	परियोजना का नाम	बर्ब की गई राशि
1	सोनगढ़ (जिला सूरत)	49,06,710
2	माण्डवी (जिला सूरत)	95,90,154
	धैराराति विस्तरित कार्यक्रमों पर बर्ब की गई राशि	
1	हृषि	2 भूमि सुधार
3	लघु भिचाई	4 भूमि तथा जल सरकार
5	जेल विकास	6 डेरी विकास
7	पशु पालन	8 भस्त्र उद्योग
9	वन	10 हृषि भवधी वित्तीय संस्थाओं में निवेदा
11	मानवाधिक विकास (क) सामान्य (पचावते) (ख) सामुदायिक विकास (ग) ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम	12 सहवारिता
13	भिचाई	14 विद्युत
15	बाढ़ नियवण	16 उद्योग
17	ग्रामीण और लघु उद्योग	18 खनन और धातु उद्योग
19	पन्नत प्रवाण गृह और नौवहन	20 सर्वे तथा पुल
21	सड़क यानायात	22 पर्यटन
23	बला और सस्कृति सहित केन्द्रीय शिक्षा	24 तकनीकी शिक्षा
25	चिकित्सा लोक स्वास्थ्य और सकाई	26 भल व्यवस्था और जन पूर्ति
27	आवास	28 शहरी विवास ।
29	सूचना और प्रचार	30 श्रम नथा श्रम कल्याण
31	समाज वित्त्याण (मध्य निवेदा) ॥	32 पोषण
33	विकास केन्द्र	34 जन-जातीय क्षेत्र उप-योजनाके लिये प्रशासनिक तंत्र
35	तालव स्थाना पर आवासीय क्वाटर्स	

## Textile Machinery Manufacturing Industry

during the current year is expected to be only about Rs 100 crores,

(b) if so, the reasons for the same; and

(c) the steps being taken to improve the productivity of the textile machinery manufacturing industry?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI-MATI ABHA MATI) (a) to (c).

6631 DR P V PERIASAMY Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state

(a) whether it is a fact that out of the licensed capacity of Rs 250 crores and installed capacity of Rs 230 crores in the textile machinery manufacturing industry, the production

Because of lack of demand from the textile industry, the utilisation of capacity of the textile machinery industry has not registered appreciable progress. The industry has been given facilities for stepping up production, modernisation and diversification to manufacture machinery of new types and also exports. Production of textile machinery during the year 1978 has been around Rs. 120 crores, being 42 per cent higher as compared to the production during 1977. Based on the current pattern of production, particularly during the last quarter of 1978, it is expected that production during 1979 will be over Rs. 150 crores.

**ईरान द्वारा भारत हेवी इंडस्ट्रिकल्स के कर्मचारियों को सेवाओं के लिये अनुरोध**

6632. श्री भानु कुमार शास्त्री : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या ईरान सरकार ने भारत हेवी इंडस्ट्रिकल्स के इंजीनियरों और कृशल कर्मचारियों की सेवाओं के लिये अनुरोध किया है ; और

(ब) यदि हा, तो किनने इंजीनियरों की सेवाओं के लिये अनुरोध किया गया है और उन्हें कब तक मेजा जायेगा ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आमा माईरी) - (क) जी, हाँ ।

(ब) ईरान सरकार के एक उद्यम ईरान ट्रास्फोर्म ने श्रीमंती हाईटाल० के इंजीनियरों और कृशल कर्मचारियों की सेवाओं के लिये अनुरोध किया था । दूसरे निश्चित कार्यव्रम के अनसार जनवरी, 1979 में जन, 1979 तक दोनों में 16 इंजीनियर ईरान पहुंचने थे परन्तु तेहरान में भारतीय दूतावास की मलाह पर कार्रवाही स्थगित कर दी गई है ।

#### Setting up of a Paper Mill using Bagasse in Tamil Nadu

6633. SHRI R. KOLANTHAIVELU: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) the policy followed in encouraging paper production from ba-

gasse indicating the quantum of paper already produced from bagasse;

(b) whether there is a proposal to start such paper mills using bagasse in Tamil Nadu; and

(c) if so, the names of the mills proposed to be set up in Tamil Nadu and their location?

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV):** (a) In order to encourage the utilisation of bagasse for manufacture of paper, Government have decided on a package of policy measures which include priority in consideration of such schemes for institutional assistance exemption from excise duty for writing and printing paper made with at least 75 per cent bagasse for a period of three years initially, and priority in movement of coal by the Railways.

(b) and (c). An application has recently been received from the Government of Tamil Nadu for a licence under Industries (Development and Regulation) Act, 1951 for setting up a new unit in the Salem District (Tamil Nadu) for the manufacture 83,000 tonnes/annum of Newsprint and 17,000 tonnes/annum of writing and printing paper utilising bagasse as the main raw material.

#### Malpractices in Distribution of Inputs

6634. SHRI S. R. DAMANI: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the malpractices in the distribution of inputs, failure of multi-agency approach and lack of coordination which are causing damage to the rural industrial development, and

(b) if so, the steps being proposed to remedy the situation?

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV):** (a) and (b) Rural industrial development is primarily the responsibility

of State Governments. The Central Government has not received any information or complaint of mal-practices in the distribution of inputs. The problems of multi-agency approach and lack of coordination among the various agencies responsible for rural industrial development are sought to be overcome by evolving closer coordination among the different agencies, involved in the rural development effort. Guidelines have been issued by the Department of Rural Development on interaction between District Industries Centres and Integrated Rural Development Blocks in regard to assistance programmes for rural artisans. A Co-ordination Committee of decentralised sector agencies at the Central level has been formed, which meets regularly to review common programmes, interfacing of multi-agency activities and linkages. The District Industries Centres is conceived as an administrative mechanism to coordinate inter-agency efforts to provide the assistance and support to small entrepreneurs and rural artisans in a well defined district action plan.

#### **Setting up of Industries in W.B**

6635. SHRI DHIRENDRA NATH BASU: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government are considering to take up a scheme for setting up different industrial units in the Hill district and also backward areas of West Bengal through State Level Corporations;

(b) whether the Centre have received any request or suggestion from the State Government in this regard; and

(c) if so, what are the details of the proposed units and the time limits for the implementation of the scheme?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) In the Draft Five Year

Plan (1978-83), the Government of West Bengal have proposed to set up industrial units through various State Corporations in hill/backward areas

West Bengal Industrial Infrastructure Development Corporation has proposed to expand the growth centres at Kalyani and Haldia and develop a new one at Siliguri.

West Bengal Sugar Industries Development Corporation has obtained an industrial licence for expanding the capacity of Ahmedpur Sugar Mills (Birbhum District) from 600 TCD to 1250 TCD.

The West Bengal Tea Development Corporation proposes to expand its activities by developing new gardens and purchasing 18 gardens in hill areas of the State.

In addition to the modernisation of Kalpani Spinning Mills, a spinning mill with 25,000 spindles is proposed to be set up at West Dinajpur.

West Bengal Mineral Development and Trading Corporation is currently engaged in drawing up new schemes for ceramic raw materials complex and a pozzolana cement project in Purulia/Bankura.

The departmental quinine factory at Darjeeling is proposed to be modernised and a project for bottling the thermal spring water at Bakreswar is under consideration.

(b and c). The suggestions of the State Government are contained in the Draft Five Year Plan proposals which are yet to be finalised.

#### **Expenditure for the modernisation of the N.T.C.**

6636 SHRI KANWAR LAL GUPTA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) is it a fact that Government propose to spend a large amount of money for the modernisation of the National Textile Corporation;

- (b) if so, the details thereof,
- (c) how much amount will be spent in the next year in the public sector for its modernisation and improvement; and
- (d) what specific steps Government propose to take to improve the working of the public sector undertakings?

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV):** (a) and (b). The National Textile Corporation has prepared a plan for Rs. 250 crores for modernisation of the textile mills being managed by it to be implemented by the end of the Sixth Year Plan. Out of this amount, modernisation programme costing Rs. 130 crores have already been sanctioned by the National Textile Corporation.

(c) During the financial year 1979-80, the National Textile Corporation proposes to spend Rs. 42 crores for modernisation and improvement of its units.

(d) The following steps have been taken and/or being taken to improve the working results of these mills:

- (i) modernisation/renovation of machinery;
- (ii) bulk procurement of raw material on centralised basis;
- (iii) improved marketing strategy;
- (iv) rationalisation of work loads and labour force;
- (v) techno-economic survey of heavily losing mills.

**Bringing down prices of Non-controlled Cloth**

**6637. SHRI M. N. GOVINDAN NAIR:** Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

- (a) whether he has asked the cotton textile industry to come out with

concrete proposals immediately for bringing down the prices of non-controlled variety of cloth; and

- (b) if so, the details and industry's response thereto?

**THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI GEORGE FERNANDES):**

(a) Yes, Sir.

(b) The industry has responded with the following three alternatives:—

(i) a roll back to the level of cloth prices prevailing in December 1978;

or

(ii) a price freeze on cotton cloth at the levels prevailing prior to 16th March, 1979;

or

(iii) a reduction in ex-mill prices of cotton cloth to the extent of two percent of the invoice rates obtaining prior to 16th March, 1979

None of these alternatives has been acceptable to Government. The Government is presently considering measures to compel the mills to roll back the prices to a reasonable level.

**Opposing the Nationalisation of Industries**

**6638. SHRI G. Y. KRISHNAN:** Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government have received 'No' from big business houses in regard to nationalisation of certain bringing down the prices of non-con-

(b) if so, the details regarding the arguments placed by big business interests opposing the Government's move in this regard?

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV):** (a) Government have not so

far taken any decision in regard to nationalisation of industries. Big business houses who are likely to be affected would naturally oppose such proposals.

(b) Does not arise.

#### Finalisation of Sixth Five Year Plan

6639 SHRI K. GOPAL: Will the Minister of PLANNING be pleased to state:

(a) when the Sixth Plan is expected to be finalised;

(b) the reasons for delay in the finalization of the Plan even though one year of its implementation is already over, and

(c) whether resources mobilization is one of the factors standing in the way of finalization of the plan?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING (SHRI FAZLUR RAHMAN): (a) to (c) As the Hon'ble Member is aware the Draft Five Year Plan for 1978-83 prepared by the Planning Commission was submitted to the National Development Council in March, 1978. The Council accepted the objectives and strategy proposed in the Draft Plan and recommended that the Plan should be finalised in the light of the decision of the Government of India on the recommendations of the Seventh Finance Commission and decisions to be taken in regard to the principles of distribution of Central Plan assistance to the States. These exercises have since been completed and approved by the National Development Council in late February, 1979. The work of finalising the Plan is now under way. There has, therefore, been no delay in the finalisation of the Plan; nor has it been affected by any difficulties in resource—mobilisation.

#### Bringing out of a separate Land Document

6640. SHRI DURGA CHAND: Will the Minister of PANNING be pleased to state.

(a) whether there is any proposal under the consideration of the Planning Commission to bringing out a separate land document exclusively for hilly and backward states in the country in view of their special requirements;

(b) if so, the details thereof;

(c) if not, the reasons thereof; and

(d) whether any hilly and backward states have approached the Planning Commission for the purpose, if so, the names of such states?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING (SHRI FAZLUR RAHMAN): (a) and (b) The meaning of 'land document' is not clear. Perhaps the question really refers to a 'plan document'. It is not proposed to bring out such document.

(c) The National Plan deals with the strategy and programmes for development of backward areas including hill areas in different States. Provision for hill areas and tribal areas is made separately in the Plans of the States in which these areas lie, and special central assistance is earmarked for these schemes. It has not been considered necessary to publish a separate plan document for hilly and backward States.

(d) No State has suggested a separate plan document of this nature.

#### Facilities in Tihar Jail

6641. SHRI HARI VISHNU KAMATH: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question

Dy. No. 3262 on the 13th December, 1978 and state:

(a) the details of the remedial measures taken with a view to removing the deficiencies in regard to over crowding, unhygienic and insanitary conditions and inadequate medical and drinking water facilities in Tihar Jail; and

(b) what action has been taken against the officials indicated by the Baweja Inquiry Commission?

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI S. D. PATIL):** (a) and (b). The Delhi Administration have reported that with a view to removing overcrowding in the Central Jail, Tihar, one Camp Jail with a capacity of 500 undertrials was started on 11-4-1978. Similarly, seven special jails, each with a capacity of 500, have been set up. As a long-term solution of the problem a proposal for construction of two District Jails one at Shahdara and the other at Hyderpur, is under consideration of the Administration. To remove the insanitary and unhygienic conditions, a new sewerage line has already been laid. A sterilisation plant is being installed for disinfecting the clothes and the bedding. The water supply from the Municipal Corporation of Delhi, has been supplemented by energising one extra tube-well. The Central Jail has a 28 bedded-hospital with four doctors to attend to the patient prisoners. The serious and emergent cases are referred to the Lok Nayak Jay Prakash Narayan hospital and a Jail van is earmarked for transportation of these patients.

2. On the basis of the Baweja Inquiry Commission Report, seven officials were found responsible for the lathi charge in the Central Jail on 2nd October, 1975. Three of them were on deputation from different states. They have been reverted to

their respective States and the charge-sheets in respect of them have been sent to the concerned State Governments. Disciplinary proceedings have been initiated against the remaining four officials by the Delhi Administration. Besides, the Delhi Administration have decided to initiate departmental proceedings against the then Deputy Inspector General (Prison) against whose conduct, the Baweja Commission had made certain observations.

**Licences issued to Entrepreneurs for setting up industries in Assam and North Eastern region**

**6642. SHRI BEDABRATA BARUA:** Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) how many licences and letters of intent were issued for new industrial enterprises in the last two completed years;

(b) in how many cases of these licences and letters of intent are the locations specifically mentioned and approved State-wise;

(c) how many licences and letters of intent have been issued for locations of industry in Assam and North Eastern area; and

(d) what are the proposed industrial projects for Assam for which these licences and letters of intent have been issued?

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADEV):** (a) Under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, 211 Letters of Intent and 141 Industrial Licences were issued during 1977 and 206 Letters of Intent and 93 Industrial Licences were issued during 1978 for setting up a new industrial undertakings.

(b) The state-wise location has been indicated specifically in every Letter of Intent and Industrial Licence

issued during 1977 and 1978 for the establishment of new industrial undertakings.

(c) One Letter of Intent and 2 Industrial Licences during 1977 and 3 Letters of Intent and 1 Industrial Licence during 1978 were issued for location of new undertakings in Assam. Similarly 3 Letters of Intent and 2 Industrial Licences during 1977 and 3 Letters of Intent and 1 Industrial Licence during 1978 were issued for location of new undertakings in North Eastern area.

(d) The Letters of Intent and Industrial Licences issued during the last two years for setting up of new undertakings in Assam are for taking up the manufacture of items relating to Chemical industries, Vanaspatti, Leather Goods, Timber products and Paper and Pulp including Paper products.

#### Acquisition of Tribal Lands for Projects

6643. SHRI P. K. KODIYAN: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it has come to the notice of Government that although many big industries and construction projects have come up in tribal areas, the Scheduled Tribes are not benefited from these developments;

(b) whether it has also come to the notice of Government that in a number of cases good agricultural lands belonging to the tribals were acquired for projects, but the displaced tribal were not provided with any alternate land for rehabilitation;

(c) if so, what steps Government propose to take to protect the interest of such displaced tribal people; and

(d) the steps Government propose to take to ensure proper rehabilitation of tribal people whenever their lands are acquired for future projects?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL):

(a) Government is aware that members of Scheduled Tribe communities have not benefited much from big industries and construction projects established in tribal areas.

(b) Further, the Government is also aware that goods agricultural land belonging to the tribals was acquired and in lieu thereof they were not provided with alternative land for rehabilitation.

(c) The Centre has suggested to the State Governments that wherever lands belonging to tribals have been taken away, special area programmes should be undertaken for their rehabilitation.

(d) Guidelines have been issued that all areas where medium and major industries have been established, or are likely to be established in the next five or ten years should be identified, and special area programmes should be drawn up and implemented for their development. Further, advance action should be taken to educate and train the tribals for their absorption in the projects.

बिहार के जिला भागलपुर में स्वतंत्रता सेनानियों को पेशन

6644. डॉ रामजी सिंह : क्या यह भंडी यह बनाने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिला भागलपुर के किनने स्वतंत्रता सेनानियों को इम समय पेशन प्राप्त हो रही है और किननों की पेशन शोक दी गई है ; और

(ख) क्या बिहार राज्य का यह विभाग ऐसे सामर्थ्यों में स्वतंत्रता सेनानियों के आवेदन पत्र केन्द्र को भेजने अवधारा सिफारिश करने में अत्यधिक विलम्ब करता है जिनमें स्पष्टीकरण प्रयोजन होता है और ग्रामीणरण न मिलने पर केन्द्र को इस बारे में उसे वायरलेस डारा जानकारी मांगनी पड़ती है ?

यह भंडालय में राज्य भंडी (श्री अधिकारी लाल मण्डल) (क) बिहार के जिला भागलपुर में

अब तक स्वतंत्रता सेनानियों के 2564 मामलों में पेशन स्वीकृत की गई है। १८मे से, दांगे और जाच हुने २क ४८ फ.३ सो में देश १० फि बर दी गई है, 26 मामलों में पेशन राज्य सरकार द्वारा आवध्यक जाच करने के बाद अतिम रूप से रद्द कर दी गई है।

(ब) स्वतंत्रता सेनानियों की पेशन के लिये विहार से आवेदन पढ़ों की संख्या 47,000 से अधिक हो चुकी है तथा लगभग 12,000 मामलों को पर्याप्त दस्तावेज़ी साध्य और/या राज्य सरकार की विशिष्ट निकारिश के अन्वाव में अभी अन्तिम रूप दिया जाता है। राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट भेजने में नि मन्देह कुछ विलम्ब हूँगा है सभवत हस्तिए कि उन्हें हजारों मामलों में जिला प्राधिकारियों से उनकी जाच करवाई गई हो, रिपोर्टों का सामान्य पढ़ व्यवहार तथा बायरलैस सदैयों के अर्थे सावधिक अनुस्मारक भेज कर शीघ्र प्राप्त करने के लिये हर सभव प्रयाम किये जाएंगे।

**Promotion case of Delhi Police Personnel**

6645. SHRI C. R. MAHATA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the Government have ascertained the position in connection with the promotion case of Delhi Police Personnel whose promotions have been held up pending the decision of the Supreme Court in Criminal Case No. 86/73 State versus Vijay Pal; and

(b) if so, the details thereof?

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI S. D. PATIL):** (a) and (b) The Government have ascertained the position in this regard. No promotion of any personnel of the Delhi Police has been held up pending a decision in the criminal case No. 86/73 State versus Vijay Pal.

**Multinational Companies producing Consumer Goods**

6646. SHRI S. S. SOMANI: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) what are the details regarding the multinational companies which are presently engaged in the production of consumer goods; and

(b) the efforts of Government to ensure that there is minimum dislocation in the production of consumer goods and that there is no adverse effect on the existing employment?

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV):** (a) This information is not centrally maintained in the Ministry of Industry. However, a list of foreign companies, having more than 40 per cent foreign equity and engaged in the manufacture of certain consumer goods, is given in the attached statement.

(b) It is presumed that the reference is to the Government's Industrial Policy, as laid before the Parliament on 23rd December, 1977, which provides that where large scale units are already engaged in the manufacture of items since reserved for the small scale sector, the share of these large units in the total capacity for these items will be steadily reduced and that of small scale and cottage sector increased. Consistent with this policy, a dialogue has been initiated with the large scale manufacturers of certain consumer goods to work out a plan of action by which the organised sector vacates its manufacturing activities in favour of the small scale sector, at the same time ensuring that there is minimum dislocation in the production of these consumer goods and that there is no adverse effect on the existing employment.

**Statement**

*A list of foreign companies having more than 40 per cent foreign equity engaged in the manufacture of consumer goods.*

S. No.	Name of the Company	Items of manufacture
1	M/s Brooke Bond India Ltd.	Tea, seafoods etc.
2	M/s Lipton Tea India Ltd.	Tea
3	M/s Dunlop India Ltd.	Cycle tyres and tubes
4	M/s Goodyear India Ltd.	Do.
5	M/s Ceat Tyres of India Ltd	Do.
6	M/s Hindustan Lever Ltd.	Soaps, toothpaste etc.
7	M/s Ciba-Geigy of India Ltd.	Toothpaste, cosmetics etc.
8	M/s Hindustan Milkfood Manufacturers Ltd.	Do.
9	M/s Geoffrey Manners and Co. Ltd.	Do.
10	M/s Burroughs Wellcome & Co. (I) Pvt. Ltd.	Cosmetics, toiletries etc.
11	M/s Glaxo Laboratories (I) Ltd.	Cosmetics, food items etc.
12	M/s Johnson and Johnson Ltd.	Cosmetics, toiletries etc.
13	M/s Cadbury Fry (I) Ltd.	Chocolate confectionery etc.
14	M/s Corn Products Co. (I) Ltd.	Food items.
15	M/s Godfrey Philips (I) Ltd.	Cigarettes.
16	M/s Shalimar Paints Ltd.	Paints, Enamels etc.
17	M/s Alkali and Chemical Corp. of India Ltd.	Do.
18	M/s Union Carbide India Ltd.	Flash-light cases, dry cells.
19	M/s Electric Lamp Mfg. (I) Pvt. Ltd.	Electric lamp, miniature lamp.
20	M/s Philips India Ltd.	Do.
21	M/s Polydor of India Ltd.	Gramophone records etc.
22	M/s G.E.C. (INDIA) Ltd.	Electric fans.
23	M/s Hooghly Ink Co. Ltd.	Inks etc.
24	M/s Tube Investments of India Ltd.	Cycle and its parts
25	M/s Sansar Machines Ltd.	Sewing machines.

**NOTE:** This list includes the companies which have got their schemes for reduction of foreign equity to 40% approved.

**Survey of Problems of Undeveloped Areas**

**6648. SHRI S. R. REDDY:** Will the Minister of PLANNING be pleased to state:

(a) whether Government have appointed any committee to survey and study problems of undeveloped areas and to have views of the various State Governments and public representatives in the matter; and

(b) if so, the details?

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING (SHRI FAZLUR RAHMAN):** (a) and (b). A National Committee on the Development of Backward Areas has been constituted with the following terms of reference:

1 To examine the validity of the various concepts of backwardness underlying the definitions in use or present policy purposes and recommend the criteria by which backward areas should be identified.

2. To review the working of:

(a) Existing plans for dealing with the general developmental problems of backward areas like tribal sub-Plans, Plans for Hill Areas etc., and

(b) Existing schemes for stimulating industrial development in backward areas such as the schemes for concessional finance, investment subsidy, transport subsidy, sales tax concessions etc., similar schemes in the agricultural and allied fields like DPAP, and general measures for tackling the problems of poverty and unemployment with a view to find out their efficacy in the removal of backwardness; and

3. To recommend an appropriate strategy or strategies for effectively tackling the problem of backward

areas, classified, if necessary, according to areas, causes for prescribed remedies.

**Collaboration of Escorts with Yamaha of Japan for manufacture of Broader Range of Motor Cycles**

**6649. SHRI JYOTIRMOY BOSU:** Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether the Government have finally opened the doors for foreign collaboration in the automotive sector,

(b) whether the first such collaboration has been allowed to Escorts with the world renowned Yamaha of Japan for the manufacture of a broader range of motor cycles;

(c) if so, what are the details thereof; and

(d) the reasons why collaboration has been allowed in this field particularly when indigenous know-how is readily available?

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI):** (a) Proposals for foreign collaboration in respect of automotive sector are approved on merits taking into account the need for upgradation, technological advancements provided by the foreign collaborator particularly in respect of fuel efficiency, better performance, export generation, material conservation etc.

(b) and (c). Escorts have been allowed to make lumpsum payment to Yamaha Motor Company Limited, Japan, for upgradation of the motorcycle engine. The amount is US \$ 3,12,000/- subject to the deduction of applicable Indian taxes. The arrangements with Yamaha were approved in 1977. Foreign collaboration in the automotive sector have also been approved earlier.

(d) Lumpsum payment in this case would permit the upgradation of the engine of the motor-cycle for increased efficiency and low fuel consumption with substantial material conservation since the weight of the entire motor-cycle dove-tailed to the engine of the new version would be substantially less compared to the existing motor-cycle. The competitiveness of the product in the export market would also improve.

#### Production of Standard Cloth

6650 SHRI K S VEERABHADRA-PPA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state

(a) the details regarding the production of standard cloth in the country during the last three years, State-wise, in length,

(b) the details regarding the production of standard cloth in the large scale and the handloom sectors for the current year, and

(c) whether there has been any decline in the production of standard cloth in the year 1977-78?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) Information is being collected and will be placed on the Table of the House.

(b) Production of controlled cloth during the current year (April-December, 1978) is as under:—

	Production in Million Sq. Metres.
Mill Sector . . . .	219.00
Handloom Sector . . . .	88.66
<b>TOTAL . . . .</b>	<b>337.66</b>

(c) No, Sir.

#### Consumption of Iodine Salt

6651. SHRI AMAR ROYPRADHAN: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government are aware that only Iodine Salt is consumed by the North Bengal people;

(b) whether it is a fact that Iodine Salt is procured from other places for the consumption of North Bengal people as there is no industry in that area, and

(c) if so the details thereof and whether Government have any intention to open an Iodine Salt Factory in North Bengal, if so, when, and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI): (a) to

(c) Iodised Salt is supplied to districts of Darjeeling, Jalpaiguri, West Dinapur, Cooch Behar and Malda in North Bengal, which have been declared as goitre-endemic areas, from the four iodisation plants installed at Howrah. As salt is imported by sea route at Calcutta, the location of these iodisation plants at Howrah ensures adequate and regular supplies of common salt for iodisation and facilitates despatch of iodised salt to the goitre-endemic North Eastern region of the country. It is not considered necessary to install an iodisation plant in North Bengal exclusively for meeting the local requirements

#### Criteria of C.R. for Promotion of S.C. and S.T. Candidates

6652 SHRI SOMJIBHAI DAMOR: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Confidential Reports of SC and ST employees are spoiled without any basis and sometimes letters are issued highlighting even the very small mistakes of SC and ST employees whereas for a similar or bigger mistakes of general candidates, no cognisance is taken;

(b) what steps Government propose to take to remove such disparity; and

(c) whether Government would frame some rules whereby the CRs should not be the only criteria for considering a SC and ST candidate for promotion of higher posts?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI S. D. PATIL). (a) The Department of Personnel and Administrative Reforms is not aware of such situations.

(b) Does not arise.

(c) Rules already exist under which, for certain categories of promotion other methods and criteria than mere assessment of past performance as reflected in the CR e.g. departmental examination, interviews etc. are resorted to for all classes of employees. For Scheduled Caste/Scheduled Tribe members, in promotion by selection upto the lowest rung of Group A (Class I), and in promotion by seniority, in all Groups of posts, there is reservation, and relaxed standards of suitability and assessment are applied for them—whatever be the method of promotion, either seniority, or selection through the C.R., limited examination, interview, etc.

#### MHD Power Generation

6653. SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU: Will the Minister of ATOMIC ENERGY be pleased to state:

(a) whether research on MHD power generation (power through low temperature thermal plasma) is being made; and

(b) If so, the result thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE AND IN THE DEPARTMENTS OF ATOMIC ENERGY, ELECTRONICS, SCIENCE AND TECHNOLOGY AND SPACE (PROF. SHER SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) The first phase of the programme, which comprises some of the auxiliary laboratories and a 5 MW (Thermal) R&D Plant, is expected to be operational by 1982. Results of this R&D effort would be available thereafter.

संसद सदस्यों, विधायकों तथा अति विशिष्ट व्यक्तियों के लिए बजाज और प्रिया स्कूटरों की बूकिंग

6654. श्री दया राम शास्त्री : क्या उच्चोग मर्दी यह बनाने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या प्रतिशत्का कर्मचारियों और अन्तिविशिष्ट व्यक्तियों का प्रावधानिकाना के प्राधार पर प्रिया और बजाज स्कूटर की सप्लाई करने हेतु उनके लिए बूकिंग की व्यवस्था की गई थी और विधायकों तथा संसद सदस्यों ने अनेक बैठकों से इन स्कूटरों के लिए बूकिंग करा रखी थी तथा क्या उच्चोग बूकिंग के प्राधार पर यह स्कूटर नहीं दिया जा रहा है और यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या मरकार विंडोफों को निवेश देगी कि जिनके नाम बूकिंग हो रही है, उन्हें स्कूटर दिए जाएं ?

उद्दोग बंकालय में राज्य मंत्री (बोधली शामाईल) : (क) श्री (व). स्कूटरों के वितरण तथा विकी पर लगा कानूनी नियवण, जो आज्वीर में बजाज और प्रिया भेक के स्कूटरों पर लगू था, 1 जनवरी, 1978 से ममान कर दिया गया है ताकि देश में मार्गों को कारबग डग से प्रुरा करने हेतु सारे स्कूटर उद्दोग की प्रयुक्तिवादियों और विकास को बढ़ावा मिल सके। बजाज नथा प्रिया भेक के स्कूटरों का कोई विशेष कोटा दिनी थी और भेजी के व्यविधियों को बाबटन करने के लिए अब उपलब्ध नहीं है। अनेक दूसरे भेक के स्कूटर उपलब्ध हैं जिनमें मरकारी लीब के उपकरण—स्कूटर इंजिन लिमिटेड—द्वारा निश्चित स्कूटर भी शामिल हैं। बजाज/प्रिया भेक के स्कूटरों के लिए मार्ग की पूर्ति अथ भेक के स्कूटरों, अदि प्राहक ऐसा बहे,—से की जा सकती है, जिनमें सरकारी लीब के उपकरण—स्कूटर इंजिन लिमिटेड, द्वारा निश्चित स्कूटर भी शामिल है।

कपड़ा मिलों और उपाई कारखानों का बन्द होगा

6655. श्री बीमल राव लारण : क्या उपाई मंत्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) देश में कितनी कपड़ा मिलों और कपड़े की उपाई और रंगाई के कितने कारखाने बन्द पड़े हैं तथा कब से बन्द पड़े हैं और उनके क्या कारण हैं;

(ख) इसके परिणामस्वरूप कितने ध्वनित बैरोबार हुए तथा उन्हें रोकार दिलाने के लिए क्या उपाय किये गये हैं;

(ग) इसके परिणामस्वरूप उन्पादन की कितनी हानि हुई है तथा इसके परिणामस्वरूप सरकार को कितने राजस्व की हानि हुई है;

(घ) सरकार तथा बैंकों ने उनमें कितनी कितनी पूँजी लगाई है तथा इस पूँजी की मुरक्का के लिये क्या उपाय किये गये हैं; और

(ङ) क्या उक्त मिलों के मालिकों तथा निवेशकों ने भी इन मिलों और कारखानों का बंदाने में उन्हें हो रही कठिनाईयों को हल करने के बारे में सरकार को अध्यावेदन दिये थे, तथा क्या इस मामले में कोई कार्यवाही न किये जाने पर मिलों को बन्द करना पड़ा?

उपाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लक्ष्मण प्रसाद बालब) : (क) से (ङ) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रखी जायेगी।

#### Allotment of Mutton Tallow to Govt. Soap Factory, Bangalore

6656. SHRI K. LAKKAPPA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government have stopped the allotment of mutton tallow, an essential ingredient in the manufacture of soaps, to the Government Soap Factory, Bangalore; and

(b) if so, the reasons for the same and whether Government are aware that the stoppage of supply of mutton tallow will adversely affect production in the factory?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) and (b). The policy is that units in the organised sector who do not have hydrogenation facilities should set up such facilities at the earliest. Pending establishment of such facilities requests for import of mutton tallow are being considered by Government.

The Government Soap Factory, Bangalore, is a unit without hydrogenation facilities and it has been asked to establish such facilities at the earliest. Ad-hoc import allocations of mutton tallow were made to this unit till 1977. For the licensing period 1978-79, the question of allocation of imported mutton tallow has been taken up with the Ministry of Commerce.

#### Issue of Licences

6657. SHRI VIJAY KUMAR MALTHOTRA: Will the Minister of INDUSTRY be please to state:

(a) how many new licences and letters of intent have been issued by Government during the last six months; and

(b) the items for the manufacture of which the licences and letters of intent were issued?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) A total number of 226 Letters of Intent and 192 Industrial Licences were issued under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 during the last 6 months i.e. from 1st September, 1978 to 28th February, 1979.

(b) The Letters of Intent and Industrial Licences were issued for the manufacture of items falling under Scheduled industries viz. metallurgical industries, electrical equipment

transportation, industrial machinery, machine tools, chemicals, textiles, paper and pulp including paper products, sugar, food processing industries, vegetable oils and vanaspati, leather and leather goods, ceramics, cement, timber products, etc. Details of all these Letters of Intent and Industrial Licences including name of the party, item of manufacture, capacity, location of the unit etc. issued under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 are published in the "Weekly Bulletin of Import Licences, Export Licences and Industrial Licences" and in the Supplement to the "Monthly News Letter" published by the Indian Investment Centre. Copies of these publications are available in the Parliament Library.

**Issue of Identity Cards to Persons of Non-Indian Origin entering North Eastern States**

6658. SHRI PURNANARAYAN SINHA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether a proposal has been received to prepare a sort of Nationalities Register for persons of Bangladesh (former East Bengal/East Pakistan), Nepal and other non-Indian origin and issue them with Identity Cards so that persons illegally entering States of North Eastern Council area could be detected;

(b) if so, whether Government propose to hold a special census in order to ascertain the national status of all residents of the States of North Eastern Council; and

(c) if so, when?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL):

(a) No, Sir.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

**Appointment of Managers of District Industries Centres**

6659. SHRI KUMARI ANANTHAN: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether the Planning Commission has questioned the wisdom of appointing Managers of District Industries centres without giving them any statutory powers in the absence of which they would not be able to disburse effectively the financial or other material help to District Industries Centres;

(b) whether it is felt that this scheme of District Industries Centres would promote multiplicity of development agencies and create avoidable confusion in rural industries department;

(c) whether a high level inter ministerial working group has been set up to suggest the necessary changes in the District Industries Centres scheme; and

(d) if so, whether the expenditure on DICs is going to be infructuous till the submission of the Report by the above working Group?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) No, Sir. However, with a view to enable the District Industries Centres to render effective assistance and support to the Small entrepreneurs, a schedule of delegated powers has been circulated to all State Governments. Central and State Governments are progressively delegating powers at various levels.

(b) No, Sir. The District Industries Centre is conceived as an administrative mechanism to remove bottlenecks and coordinate the different activities and inter-agency requirements for setting up small and rural industries.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

तुरु बस्तुओं का उत्पादन लघु लोह के एकत्रों के लिए तुरुकित करता

6660. डा० लक्ष्मी नारायण वार्डेप : क्या उत्तराखण्ड मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय साबून, टूथपेस्ट, मार्बिस, चमड़े के छूटे और स्टेनलैस स्टील के बहतों का नियोग लघु लोह के लक्कों के लिए तुरुकित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है;

(ब) क्या यह सच है कि बस्तोवयोग वे भी छाती, तीलिया और गाम उपयोग की ऐसी ही बस्तुओं को बावरहूम और हैण्डलूम सेक्टर में तुरुकित रखा जाना चाहिए; और

(ग) यदि हा०, तो इस पर सरकार की क्या व्यतिक्रिया है और इन मम्बन्ध में घोरा क्या है?

उत्तोग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अगाहरी प्रसाद यादव) (क) कपड़े धाने के साबून, टूथपेस्ट, सेफ्टी मार्बिस तथा चमड़े के जूतों का उत्पादन विकास के लिए केवल लघु लोह में पहले ही आरक्षित रक्त दिया गया है। स्टेनलैस स्टील के बहतों को अपरी तक आरक्षित नहीं दिया गया है। आरक्षित बस्तुओं की सरकार द्वारा सर्वीक्षा की जाती है ताकि लघु लोह में बनाये जा सकने वाले नये उत्पादों व नई प्रक्रियाओं का पता लगने पर ऐसी बस्तुओं की सूची में निरन्तर विस्तार किया जा सके।

(ब) और (ग) शोधेंगे नीति विवरण के पैरा 14 में यह ग्राट किया गया है कि जनता को बस्त सबधी आशयकाना खादी महित दृष्टकरण धैत जा बनवा के उत्पादन में लगे अनेक लोगों को रोजगार देना है। नरवार सरकार सरकार तथा विद्या कर्मान धैत की बनाई जानी में किसी प्रकार वा विस्तार करने का ग्रन्तमता नहीं देगी।

#### Investigation Re Fall in Price of Cotton

6661. SHRI BALASAHEB VIKHE PATIL: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state

(a) whether any investigation has been made by Government regarding fall in price of cotton though there has been increase in the cloth price, and

(b) if so, what results, indicating measures that have been taken by Government to ensure that neither textile industry nor the middle men take additional money at the cost of consumers?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) and (b). While no formal investigation has been made, it is found that during the period February, 1978 and February, 1979, the wholesale prices of cotton textiles have increased marginally by 2.9 per cent though the wholesale prices of cotton have fallen by about 9.4 per cent. The above increase in price of cotton textiles is attributed to the termination of sluggish demand for cloth during the three years 1975, 1976 and 1977 and to the increase in the cost of other inputs in making the cloth. The fall in prices of cotton does not appear to have created any additional money that could be taken by the textile industry or the middle men. Nevertheless, the price situation was discussed with the cotton textile industry who have been asked to devise steps to reduce the prices of cotton cloth.

M/s Porritts and Spencer (Asia) Ltd.

6662 SHRI ANANT DAVE: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to give the information asked for in Unstarred Question No 4147 on the 16th August 1978 in respect of M/s Porritts and Spencer (Asia) Ltd, Faridabad?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): The information asked for in Unstarred Question No. 4147 on 16th August, 1978 in respect of M/s Porritts and Spencer (Asia) Ltd, Faridabad, is as follows:—

(a) and (b) M/s Porritts and Spencer (Asia) Ltd was given an Industrial Licence for setting up a felt manufacturing unit in collaboration with its foreign principals. The collaboration agreement approved by Government in April, 1968 provided inter-alia that:—

(i) the authorised capital of the proposed company to be set up at

Faridabad, Haryana State, would be Rs. 2.5 crores with an initial paid up capital of Rs. one crore, in equity shares of Rs. 10 each at par.

(ii) 60 per cent of the initial paid up capital of Rs. one crore shall be allotted to M/s. Porritts and Spencer, U.K. out of which shares to the extent of paid up capital of Rs. 10 lakhs may be allotted for supply of technical know-how and the balance of Rs. 50 lakhs for the supply of capital equipment. Not more than 60 per cent of equity capital shall be held by non-Indians.

(iii) No royalty will be allowed to the foreign collaborator. The firm was issued an import licence on 26th August, 1968 for import of plant and machinery valued at Rs. 44,08,300. Major part of the machinery allowed was second-hand. Subsequently, the value of the import licence was enhanced to Rs. 47,98,300 in July, 1971.

(c) As reply to (a) and (b) above would indicate Rs. 50 akhs worth of share capital was allotted to the foreign collaborator against import of capital equipment. The repatriation of dividends linked with this equity, however, would be governed by the provisions of Foreign Exchange Regulation Act, 1973, which is administered by the Department of Economic Affairs.

#### Crisis faced by Small Scale Wax Industries, Kot Kapura, Punjab

6663. SHRI BALWANT SINGH RAMOOWALIA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether the manufacturers of small scale industry of wax are facing crisis in Punjab especially in Kot Kapura;

(b) whether the dealers of Kot Kapura are wandering with permits of wax but they had not got even a kilogram till now; and

(c) whether the dates of getting wax on permits have expired two to three times?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) There has been an overall short supply of wax against the requirements of units all over the country.

(b) No specific instance has come to notice of Director of Industries, Punjab.

(c) The validity of all permits issued in the first week of February, 1979 was extended only once in view of freezing of stocks with the dealers by the Ministry of Petroleum through a circular No. 19023 dated 31st January, 1979 pending fixation and finalisation of new sale price of wax. Validity of permits was accordingly extended upto 25th March on intimation of revised rates from M/s. Bharat Petroleum in the first week of March, 1979.

#### भारत का मानचित्र

(6664. श्री राहबी भट्ट : दया दिल्ली रेल्वे प्रैंसेंसिकी रक्षी रह दिनांक की हुया बदले कि :

(क) भारत का मानचित्र 'रेंट्रेडम' वर्तैयार बिया गया था, और

(ख) इसे वर पुनर्जित दिया दया आर्थर दया दनी दुटिया दूर बर दी गई है ?

रक्षा संस्थान से श्री रपराज डार्ड, इलेक्ट्रोनिक्स, दिल्ली बांगर प्रैंसेंसिकी दिल्ली के राष्ट्रीय इंस्टी (प्रैंसेर रिह) (क) भारत य इंडेक्षन में भारत का पहला मानचित्र 1881 में तैयार दिया गया था ।

(ख) भारतीय सर्वेक्षण भारत के मानचित्र में निरन्तर संशोधन करता रहा है, नवीनतम सरकारण, जिसे फटा सरकारण कहा जाता है 1972 में प्रकाशित दिया गया था ।

'रोड मैप भारत इंडिया' (भारत का सड़क मानचित्र) (फटा सरकारण) और 'रेलवे मैप भारत इंडिया' (भारत का रेल मानचित्र) (नवीन सरकारण) का प्रकाशन 1977 में किया गया ।

एक मानविक, सर्वेक्षण के समय में विद्यमान सांस्कृतिक (मानव-सिविल) विवरण और सांतिक विवेचनाओं को विवित करता है। प्रयोक्ता भवनकर्ता सर्वेक्षण से मानविकों की परिषुद्धता और रखना अन्तर्वर्तु में निरन्तर सुधार किया जा रहा है।

### Automobile Industry Units

6665. SHRI GANANATH PRADHAN: Will the Minister of INDUSTRY be

pleased to state the number of automobile industry units in the country and their manufacturing capacity of each of them?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI): The installed capacities of vehicle manufacturing units in the country are given in the statement attached.

### Statement

#### A. Commercial Vehicles:

Sr. No.	Name of the Unit	Installed capacity as on 1-4-1979 (Nos.)
1	M/s. Tata Engineering & Locomotive Co. Ltd., Bombay/Poona	36,000
2	M/s. Ashok Leyland Ltd., Madras	13,000
3	M/s. Hindustan Motors Ltd., Uttarpara (West Bengal)	15,000
4	M/s. Premier Automobiles Ltd., Bombay	6,000
5	M/s. Mahindra & Mahindra Ltd., Bombay	3,000
6	M/s. Bajaj Tempo Ltd., Poona	8,000
7	M/s. Standard Motor Products of India Ltd., Madras	3,000
<b>B. Jeeps:</b>		
1	M/s. Mahindra & Mahindra Ltd., Bombay	13,000
<b>C. Passenger Cars:</b>		
1	M/s. Hindustan Motors Ltd., Uttarpara (West Bengal)	30,000
2	M/s. Premier Automobiles Ltd., Bombay	18,000
3	M/s. Standard Motor Products of India Ltd., Madras	3,400
4	M/s. Sunrise Auto Industries Limited, Bangalore	1,000

### Utilisation of Jute Stock

(c) how much not utilised; and  
(d) what are the reasons for non-utilisation?

6666. SHRI SUSHIL KUMAR DHARA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government have any plan to utilise the jute-stock produced in abundance every year in the country and has been a waste for its non-utilisation;

(b) if so, the quantity of jute-stock produced every year in the country;

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) to (d). The normal annual production of Jute stock is estimated to be three million tonnes. At present most of this is put to use as fuel and for thatching and fencing purposes. Jute Technological Research Laboratories are conducting research to determine the feasibility of

utilising the jute stock for industrial purposes and they are reported to be already collaborating with a firm for manufacture of particle board from jute stock. Some of the small paper mills as well as Messrs India Paper and Pulp Ltd. are utilising jute stocks along with other raw materials. However, the exact quantity of jute stocks being put to such uses is not available. The main reasons which hinder the use of jute stocks for industrial purposes *inter alia* are difficulties in collection, transport, storage and its non-availability throughout the year.

**Promotion of a Deputy Director of I.B. as Joint Director**

6667. SHRI G. M. BANATWALLA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether a Deputy Director in the Intelligence Bureau has been promoted as Joint Director superseding seven other officers senior to him; and

(b) if so, the circumstances under which Government promoted a junior officer superseding his seniors?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL):

(a) No, Sir.

(b) Does not arise.

**Declaration of Koraput District as Hilly and Remote Area**

6668. SHRI BAIRAGI JENA: Will the Minister of PLANNING be pleased to state whether Government have considered the proposal of the State Government of Orissa to categorise Koraput district as one of the hilly and remote areas of the country?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING (SHRI FAZLUR RAHMAN): No such proposal has been received by the Planning Commission.

**Loss to Cement Factories for not lifting the Cement**

6669. SHRI G. NARSIMHA REDDY: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether certain factories had to reduce their production due to their storing capacity being full as cement could not be lifted;

(b) if so, the names of such factories and the loss of total quantity of cement production in tonnes, factory-wise and month-wise for last nine months;

(c) what action Government have taken to see that cement factories do not suffer production for want of storing capacity, what are the results;

(d) whether Government are prepared to allow all such cement factories who are losing production to sell the cement to persons or dealers who are prepared to lift cement immediately at factory upto the quantity which may create sufficient storing capacity to continue their full production; and

(e) if so, the details and how it will be implemented; if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) and (b). During the year 1978-79, some of the cement production units reported that their production was affected as their silos remained full due to inadequate availability of railway wagons or movement restrictions. Since capacity utilisation is also affected by a number of other factors including power restrictions, coal shortage, labour disputes etc., it is not practicable to determine the quantity lost due to silos remaining full.

(c) Government have taken a number of steps including liberalisation of rules for reimbursement of freight for movement of cement by road and general permission to the State Govts. in whose jurisdiction the concerned production units are situated for the immediate lifting of

cement in cases where the units reported that their silos were full. The Railways have also been requested in such cases to provide wagons on priority basis to the extent possible.

(d) No, Sir.

(e) Any general permission to the cement production units to sell cement to persons or dealers of their choice may lead to malpractices and will not be in accordance with the policy of the Government for controls on price and distribution of cement.

सरकारी क्षेत्र, गैर-सरकारी क्षेत्र तथा लघु उद्योग क्षेत्र के उद्योगों की तुलनात्मक विकास दर

6670. श्री राम सागर : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1976-77 से 1978-79 तक वित्तीय तथा कलेंडर वर्षों में कुल औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि की दर क्या है;

(ख) उक्त वर्षों में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि की दरें क्या हैं;

(ग) व्यापार तथा विकास महानिदेशक के अन्तर्गत आने वाले कारखानों और लघु क्षेत्र के कारखानों में उक्त अवधि में औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि की दर क्या थी; और

(घ) लघु क्षेत्र के उद्योगों के बारे में आंकड़ों के आधार क्या है और उसमें कितनी छूट दी गई?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख). औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक के माप (1970-100) के अनुसार वित्तीय वर्ष 1976-77, 1977-78, तथा 1978-79 के (अप्रैल से दिसम्बर) की विकास दर क्रमशः 9.5 प्रतिशत, 3.9 प्रतिशत तथा 8 प्रतिशत थी तथा कलेंडर (पंचांग) वर्ष 1976, 1977 तथा 1978 की विकास दर क्रमशः 9.8 प्रतिशत 5.2 प्रतिशत तथा 6.8 प्रतिशत थी। सरकारी तथा निजी क्षेत्रों के विकास दर विषयक तुलनात्मक सूचकांक प्रलग से उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) और (घ). तकनीकी विकास के महानिदेशालय की संबीक्षा के अन्तर्गत आने वाले एककों के बारे में लगाये गये अनुमानों के अनुसार

उत्पादन की विकास दर 1976-77 में 11.5 प्रतिशत, 1977-78 में 6 प्रतिशत तथा 1978-79 में 10 प्रतिशत बतायी गई है। तकनीकी विकास का महानिदेशालय (डी०जी०टी०डी०) क्षेत्र के लिये तीन कलेंडर वर्षों के आंकड़े क्रमशः 12 प्रतिशत, 8.5 प्रतिशत तथा 8.6 प्रतिशत हैं। लघु क्षेत्र के सम्बन्ध में विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय पंजीयित एककों के दो प्रतिशत के लघु नमूने के आधार पर उत्पादन का अनुमान लगाता रहा है। इस नमून के आधार पर लगाया गया अनुमान 1977-78 तथा 1978-79 में लगभग 16 प्रतिशत की विकास दर बताता है। इन आंकड़ों को और भी ठीक कर के तथा लघु क्षेत्र को समाविष्ट कर उसमें और भी सुधार करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

उत्पादकता सेवाओं के विकास के लिए प्रस्ताव

6671. श्री बागुन सुमित्रलाल : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा विचार विमर्श किये गये उत्पादकता सेवाओं के विकास सम्बन्धी नये प्रस्ताव क्या हैं; और

(ख) इस बारे में व्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख). राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद ने अपनी 15 मार्च, 1979 को हुई बैठक में अपनी गतिविधियों को सरकार की आर्थिक एवं औद्योगिक नीति विषयक उद्देश्यों के अनुरूप बनाने का निश्चय किया है। परिषद ने तत्काल ही कार्यवाही करने के लिये निम्नलिखित क्षेत्रों का पता लगाया है :—

(1) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, लघु उद्योगों के विकास आयुक्त तथा अन्यों के सहयोग से साबून तथा दियासलाई उद्योगों का विकास करना।

(2) विद्यमान एककों में लघु क्षेत्र उत्पादकता सुधार का विकास तथा विकास आयुक्त (लघु उद्योग) के सहयोग से आरक्षित वस्तुओं के लिये लघु एककों का विकास संवर्धन करना।

(3) सरकारी क्षेत्र के संगठनों में जहाँ उत्पादकता कम है अथवा रुग्ण समझी जाती है, उत्पादकता में सुधार तत्काल ही अव्ययन के लिये पता लगाये गये कुछ एककों/क्षेत्रों में राज्य विद्युत मण्डल, राष्ट्रीय वस्त्र निगम के रुग्ण एकक तथा इंजीनियरी उद्योग बंडल बंदरगाह, तथा मुगलसराय के रेलवे मार्ग आदि हैं।

(4) मजदूर सधो की रुचि जाग्रत करने हेतु उपयोग योजनाओं का संबंधित करना ताकि वे उत्पादिता को अपने आदानप्रदान का एक अविभाज्य ग्रंथ बना ले।

राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद साबून तथा लिप्पित उद्योगों का कृष्टीय/संषु केत में विकास करने हेतु विस्तार से प्रस्ताव बना चुकी है। अन्य शोकों के बारे में परिषद प्रस्ताव बना रही है।

आविधानियों की भूमि को आपस सोटाने के लिये संचाल परवाना में आन्दोलन

6672. श्री बडेश्वर हेमदाम : क्या यह ममी यह बनाने की कृपा करेंगे कि ।

(a) क्या यह सच है कि बिहार राज्य के परवाना संचाल परवाना जिसे मैं आविधानियों की भूमि को, जिसे अन्य व्यक्तियों को नाम कर दिया गया है और वह उनके कब्जे में बली गई है, उन्हें वापिस विलाने के लिये कई महीनों से आन्दोलन चला रही है और इस संबंध में हत्याएं और आगजनी की घटनायें हो रही हैं,

(b) क्या 2 दिसंबर, से 8 दिसंबर तक संचाल परवाना के मुख्यालय तुमका को आन्दोलन कारियों ने नाकाबन्दी की थी और राष्ट्रीय उत्पाद की भी मुख्यालय से उतारने का प्रयास किया था, और

(c) क्या इस आन्दोलन के परिणामस्वरूप अपनी जाति बाजार बाजा सुवरपहाड़ी में तीन व्यक्तियों की हत्यायें हुई और ग्राम पक्षदिया, बाजा पटवट बाजा, में हत्याएं और आगजनी की घटनायें हुई और बाज मकरमजूर, बाजा मतलिया, विला साला में हत्यायें हुई हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य बंडी (वी अधिक बाज अध्यक्ष) : (क) से (ग) अपेक्षित सुचना बिहार सरकार से मांगी गई है और बाह प्राप्त होती सदून के पटल पर रख दी जाएगी।

#### Inquiry against Director Electronics Testing and Development Centre

6673. SHRI BHAGAT RAM Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No 8259 on 26th April, 1978 regarding inquiry against Director, Electronics Testing and Development Centre and state:

(a) whether the Enquiry Officer has submitted his report;

(b) what are the findings of the Enquiry Officer and what action has been taken on the report;

(c) whether it is a fact that a committee has further been constituted to look into the same charges; and

(d) what is the justification for such a committee and why no action has so far been taken against the guilty officer in accordance with the findings of the enquiry officer?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI S. D. PATIL): (a) to (d). An enquiry was conducted into the allegations levelled against the Director of Electronics and Development Centre, Chandigarh:—

1. The Enquiry Officer in his report held as proved the following charges.—

(i) Misuse of Oxygen Gas Cylinder belonging to Electronics Testing and Development Corporation to benefit the industry owned by his wife.

(ii) Tampering with quotation of M/s Decent Furnitures in order to give him pecuniary benefits and drawing commission on account of this favour.

(iii) Claiming false T.A.

(iv) Changing of Joining Report of one Workshop Mechanic from afternoon to forenoon.

(v) Payment of daily wages to one Sweeper-cum-Chowkidar for the period when he was on leave.

(vi) Compelling a Glass Blower, A Class III employee to perform the duties of Sweeper-cum-Chowkidar

(vii) Termination of the services of a number of employees within a span of two years on account of their refusal to carry out his orders to do his private work.

(viii) Vindictive attitude towards the subordinate staff.

2. According to the report received from the Chandigarh Administration. The report was placed before the Appointing Authority, the Board of Directors of Chandigarh Small Industries Development Corporation. The Board of Directors decided that the enquiry report needed further scrutiny as it lacked clarity on some points and the Director, Electronics Testing and Development Corporation had not been afforded adequate opportunity by the enquiry officer to explain his position in respect of each charge. Therefore, a Sub Committee was appointed to analyse the enquiry report. The report of the Sub Committee is awaited.

#### Rise in Cloth Prices

6674. SHRI F. P. GAEKWAD: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government are aware that the Cotton cloth prices last year had risen in proportion to the fall in the cotton prices;

(b) whether the like in prices was due to the higher cost of inputs;

(c) if so, whether it a fact that the input cost had gone up ranging from one per cent to ten per cent whereas the rise in cloth prices at the consumer end was 25 per cent to 30 per cent; and

(d) in view of (c) above, what measures are proposed to be taken to arrest rise in cotton cloth prices immediately?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) to (d). The whole-

sale prices of cotton textiles have increased marginally by 2.9 per cent between February 1978 and February 1979 though the wholesale prices of cotton fallen by about 9.4 per cent during the same period. The increase of 2.9 per cent is attributed to the termination of sluggish demand for cloth during the three years 1975, 1976 and 1977 and to the increase in the cost of other inputs in making the cloth.

The cost of other inputs had gone up differently by 23 per cent to 14.6 per cent in December, 1978 over December 1977. Government have no information regarding increase in the prices of cloth at the consumers end.

The Minister of Industry recently discussed the matter with the industry, who were asked to devise steps to reduce prices of cotton cloth and the industry had responded with certain suggestions which are under consideration of Government.

#### महाराष्ट्र के विवाह उद्दोग केन्द्रों के लिए राजसंस्थान

6675. श्री नंगाधर शास्य बूराडे : क्या उद्दोग मंत्री यह बताने की हुपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के कितने जिलों में 15 प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान योजना कार्यान्वयन की जा रही है और उसका भावार क्या है;

(ख) क्या मरकार की महाराष्ट्र तरकारी की ओर से कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं यदि हाँ, तो उसका व्यौरा क्या है?

उद्दोग नंदालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) महाराष्ट्र के 3 जिलों प्रथम राज्यान्वयन, प्रोटोगावाड तथा बन्देश्वर में केन्द्रीय निवेश योजना कार्यान्वयन की जा रही है। केन्द्रीय निवेश राजसंस्थान योजना के पात्र बनाने हेतु जिलों/क्षेत्रों का चयन करने के लिए बनाई गई राज्यीय विकास परिषद की समिति के तिर्यक द्वारा अनुमति में यह निर्णय लिया गया था कि प्रौद्योगिक दृष्टि से पिछड़े पाये गए प्रत्येक राज्य

के 6 जिले/क्षेत्र तथा महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों 3 जिले/क्षेत्र रियायती वित्त सुविधाओं के पात्र बनने के लिए तथा कैन्ट्रीय लिंबेश राजसंस्थापना योजना के भी पात्र बनने के लिए शौक्यिक दृष्टि से पिछड़े धोपित विये गए जिलों में से चुने जाएं। महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव के आधारारं दर इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त 3 जिले चुने गये हैं।

(ख) योजना आयोग ने जो निर्देश राज्याधारा को बुनः सीमा निर्दर्शन करता है यहां पाया है कि महाराष्ट्र सरकार ने अग्रेस, 1974 में केंद्रीय सरकार को यह मुद्रावाह दिया था कि विशेष राज्याधारा योजना के पाय उनके के लिए चुने गए 3 विलों के मध्य पर रियायती विल गुविधा के लिए राज्य के चुने गए श्रीोपितक विल से विलडे 13 विलों में से 13 विकास विलों वाले 13 पचास समिति प्रछढ़ों का (13 विलों में से प्रत्येक में एक केन्द्र के दिमायबंग) चुना जाना चाहिए। चूंकि यह प्रस्ताव राज्य के मुद्रा संविधों की गण्डीय विकास परियद समिति के निर्णय के अनुच्छ नहीं पाया गया था अतएव इस प्रस्ताव के लिए सहमति देने में गहराई योजना आयोग की अत्यरिक्तता के बारे में सहमति द्वारा सरकार को 16-5-1974 की मूल्यवान दिवांगी दिया गया था।

महाराष्ट्र सरकार ने निवेदन राजसमाधायत के इन द्वितीयों का पुनः सोमा निर्धारण करने के लिए प्रत्रैल, 1974 के अपने पहले प्रस्ताव के लिए स्वाक्षरता प्राप्त करने हेतु 1975 में योजना यांगों से दावारा अनुरोध किया था। विस्तार से विचार करने के बाद योजना यांगों से 31 अगस्त, 1975 को राज्य को सूचना दी थी कि, चूंकि विद्यानन राजसमाधायत योजना के लिए राज्यीय विकास परिषद हाया स्वीकृति की गई थी, अतः इस नीति में किसी प्रकार के परिवर्तन के लिए उत्तरी समिति डारा सावधानीपूर्वक संवेदित की जानी चाहिए तथा स्वीकृति प्रदान की जानी चाहिए।

की दी० शिक्षारामन, सदस्य, योजना सामग्रेय की अध्यक्षता में पिछड़े लोकों की एक राष्ट्रीय समिति का हाल ही में गठन किया गया है। इस समिति के विचारार्थ विषयों में से एक विषय पिछड़े लोकों में धर्मानुग्रहिक विकास के बढ़ावा देने की विचारामन योजनाओं, जैसे रियायती नियन्त्रण राजसाहायता, परिवहन राजसाहायता, विद्यार्थीर में रियायत आदि कृषि वित्त संबंधित लोकों की इसी प्रकार की योजनाएं जैसे दी० पी०ए०पी० लक्ष्य पिछड़ापन इर करने के लिए पर्यावरी और बेरोजगारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए किए जाने वाले सामान्य उपायों की योजना के संचालन की संवेदीकरण करता है। केंद्रीय राजसाहायता योजना में यही कोई संकेतन करने पड़े ही उस पर इस समिति की रिपोर्ट जल्दी ही जारी के बाद ही विचार किया जा सकता है।

### Reserves of Rock Salt in Mandi

6676. SHRI GANGA SINGH: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) the areas and the estimated reserves of Rock Salt in Mandi (Himachal) Salt Mines:

(b) the daily discharge of Saline Waters from the rivulets of Drang, Maigal and Guma flowing adjacent to the Mandi Salt Mines;

(c) whether it is a fact that the production of both cattle lick and potable salt has fallen down in the above salt sources during the last ten years; and

(d) whether Government want to increase the production of salt and bye products from the above sources; if so, how?

THE MINISTER OF STATE IN  
THE MINISTRY OF INDUSTRY  
(SHRIMATI ABHA MAITI): (a) According to the report of the India Bureau of Mines, the area of, and estimated reserves of rock salt in Mandi Salt Mines are about 29,465 sq. metres and 8.52 million tonnes, respectively.

(b) While no authentic statistics are available about daily discharge of saline water from rivulets of Drang, Maigal and Guma, a report prepared by the National Industrial Development Corporation had estimated the discharge at 22.5 cu. metres of brine of 9 degrees (Be) per hour.

(c) and (d). The production of rock salt (cattle-lick) at Mandi has remained fairly stable around 4,000 tonnes during the last ten years. However, the production of pan and refined salt, which is produced in small quantities, has declined due to unfavourable weather conditions and shortage of coal. The production of rock salt is at present limited by its demand in the market and can be increased if there is more demand.

The salt produced at Mandi does not contain any important by-products for economic recovery.

**Research by Engineers and Architects of Engineering Unit of CSIR**

6677. SHRI T. S. NEGI:

DR. RAMJI SINGH:

Will the Minister of SCIENCE AND TECHNOLOGY be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2326 on 7th March, 1979 re: Engineers and Architects of engineering unit of CSIR and state:

(a) whether it is a fact that Engineers and Architects of Engineering Unit, CSIR are connected with research as they are implementing the works of SERC and CBRI;

(b) whether by virtue of their nature of job and technical qualifications the Engineers and Architects of this Unit are not primarily the technical persons;

(c) whether the persons like plumbers, masons, mates, polishers etc. working under them have been classified as Technical; and

(d) if so, how long it will take to review these categorisation and putting the Engineers and Architects in Technical Category?

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE AND IN THE DEPARTMENTS OF ATOMIC ENERGY, ELECTRONICS, SCIENCE AND TECHNOLOGY AND SPACE (PROF. SHER SINGH):** (a) The Engineers and Architects of the Engineering Unit, CSIR are essentially engaged in planning and construction of buildings and services. In doing so, they utilise some of the products and techniques developed by SERC and CBRI. They do not carry out any research as such themselves.

(b) The Governing Body of the CSIR felt that as the Engineering

and Architectural personnel of CSIR are not contributing towards research they may be classified as 'Administrative'. The work they are engaged in is however technical and they possess technical qualifications.

(c) The Governing Body of the CSIR took a decision to reclassify the staff of the CSIR into three categories namely, Scientific, Technical and Administrative against four categories of Scientific, Technical, Auxiliary Technical and Administrative, existing earlier. The posts of plumbers, masons, mates and polishers earlier included as 'Auxiliary Technical' have thus been classified as 'Technical'.

(d) The position is somewhat anomalous. The matter is therefore being reconsidered; no definite time limit can be given at this stage.

**Disposal of Cases of Offences by Police Personnel in Delhi**

6678. SHRI MOHAN LAL PIPIL: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have carried out any survey regarding the adequacy of police personnel in the face of growing cases of offences in the Union Territory of Delhi;

(b) the total number of cases presently under investigation of the Delhi Police for various offences which are pending for less than (i) one year (ii) three years (iii) five years (iv) eight years and (v) ten years;

(c) the total number of Enquiry Officers handling these cases and the average number of cases being investigated into by an enquiry officer; and

(d) whether there is any proposal under Government's consideration to augment the staff strength of police personnel for speedy disposal of cases?

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS**

(SHRI S. D. PATIL): (a) to (d) The requirements of the Delhi Police are constantly reviewed and measures necessary to promote their efficiency are taken subject to financial constraints. An Expert Committee has also been set up to formulate yardsticks for the manpower, transport and communication requirements of Delhi Police

The details of cases, presently, under investigation of the Delhi Police for the various offences are as below:—

Period	No. of cases pending investigation
One year	12105
Three years	650
Five years	38
Eight years	2
Ten years	Nil
Total	12795

394 Investigating officers are handling the above cases. There are approximately 32 cases with each investigating officer.

**Trouble in T.I. Cycles of India**

6679. SHRI C. N. VISVANATHAN: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether the factors behind the trouble in T.I. Cycles of India, Madras have been studied in depth;

(b) the causes for the trouble and the present position; and

(c) the positive steps proposed to ensure that retrenched employees are

reinstated and the production is resumed with vigour in the country's interest?

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY**

(SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) and (b). The management of M/s. T.I. Cycles of India Ltd., Madras suspended operations of the factory in January, 1978 on grounds of labour trouble. Negotiations were held by the management and an agreement was reached with the workers' representatives, with the assistance of the State Government of Tamil Nadu. The factory was reopened and production commenced in October, 1978.

(c) The State Government of Tamil Nadu has reported that some of the workers dismissed have raised industrial disputes which are pending disposal. The State Government has also reported that there has been increase in productivity after the re-opening of the factory.

**Working out of Plan by the Khadi and Village Industries Commission Re: Production of Matches**

6680. SHRI K. RAMAMURTHY: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) the details of the plan that has been worked out by the Khadi and Village Industries Commission at the instance of the Government which would enable the small and cottage industry sector to take over the entire production of matches in the country; and

(b) the places in which the new 18 raw material banks have been set up by the Commission to help the 2700 cottage match units?

(SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) The Khadi and Village

Industries Commission's programme for the rapid development of Cottage Match Industry envisages the following

outlays (besides institutional finance), production and employment targets:—

Year 1	Outlay (Grant and Loan) Rs. in Crores 2	Production Rs. in Crores 3	Employment Persons in Lakhs 4
1978-79	6.88	11.50	0.27
1979-80	14.61	21.64	0.54
1980-81	18.66	39.34	0.94
1981-82	11.50	60.23	1.49
1982-83	14.45	76.92	1.88

(b) The Commission has set up the following 16 Raw Material Banks/Depots:—

State	Place(s) where Raw Materials Banks/Depots set up	Number of Raw Material Banks/Depots set up
1. Andhra Pradesh	Hyderabad	2
2. Haryana	Ambala	2
3. Maharashtra	Bombay, Dahisar	3
4. Tripura	Agartala	1
5. Tamilnadu	Sattur Kovilpatti Sirivilliputhur	3
6. Uttar Pradesh	Kanpur Varanasi Meerut Chandrawal	4

**Working of Hindustan Photo Film Corporation**

6681. SHRI SHYAM SUNDAR GUPTA:

SHRI G. M. BANATWALLA:

DR. BIJOY MONDAL:

SHRI MUKHTIAR SINGH MALIK:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government of India have since inquired into the working of the Hindustan Photo Film Corporation of India since it was set up;

(b) if so, whether any irregularities have been found and if so, the nature thereof; and

(c) whether any action has been taken to uplift the working of this Corporation and if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) and (b). Based on the recommendations contained in the 55th and 70th reports of the Committee on Public Undertakings which had gone into the working of Hindustan Photo Films Mfg. Co. Ltd. (HPF) during 1974-75 and 1975-76, Government had appointed two inquiry Committees:

(i) Committee under the Chairmanship of Shri Bazle Karim, Adviser, Bureau of Public Enterprises, to examine the various lapses on the part of the management of HPF pointed out by COPU (in its 70 report) and to fix responsibility therefor. The Committee was also requested to make suitable recommendations for streamlining the administrative procedure so as to avoid recurrence of similar lapses.

(ii) A High Level Committee under the Chairmanship of Prof.

K. V. Subramanyam, Chairman-cum-Managing Director of Bharat Gold Mines, to investigate the entire matter of silver losses and to pin-point lapses on the part of the management of HPF and others concerned (in terms of COPU's 70th report).

The reports of both the Committees have been received. The findings and recommendations (summary attached herewith) of the Bazle Karim Committee have been accepted by the Government. The report of the Subramanyam Committee is still under examination.

(c) During the first 8 years of its working, HPF was incurring losses and did not achieve its rated capacity of 61.5 lakh sq. m. However, with improvements in its technological and managerial skills, the company has since turned the corner and for the first time in 1975-76, exceeded its rated capacity as well as made a profit of Rs. 16.06 lakhs. Since then, the company has been maintaining steady progress as is seen from the data given below:—

			lakhs sq.m.
Production	1975-76	.	70.17
	1976-77	.	91.80
	1977-78	.	92.23
			Rs. lakhs
Sales	1975-76	.	222.80
	1976-77	.	312.00
	1977-78	.	356.70
Profits	1975-76	.	16.06
	1976-77	.	142.63
	1977-78	.	164.10

During the year 1978-79 the company is expected to achieve a production of 94 lakhs sq. m., sales of Rs. 394 lakhs and profit of Rs. 210 lakhs.

**SUMMARY OF CONCLUSIONS/RECOMMENDATIONS MADE BY THE COMMITTEE CONSTITUTED UNDER THE CHAIRMANSHIP OF SHRI BAZLE KARIM, ADVISER, BUREAU OF PUBLIC ENTERPRISES**

**CONCLUSIONS**

1. The present location and site were chosen with due care and attention. Excellent atmospheric conditions, availability of good water and other favourable factors tended to favour Ootacamund as the location. Before choosing the site, soil and water analyses and trial borings were done by appropriate agencies.

2. The delay in commissioning the project was due to multiplicity of factors. The management of HPF were operating under highly trying situation, due to construction delay, claim for compensation from foreign collaborator, for delay in construction, change in management of collaborating firm and inadequacies in the collaboration agreement leading to protracted negotiations.

3. The management could not invoke penalty clauses for non-fulfilment of certain obligations by the foreign party due to various reasons. Invoking penalty clause would have led to litigation to be carried through French courts adding further delay and uncertainty.

4. The collaboration agreement was not of a turn-key nature whereby responsibility could be pin-pointed on the collaborators.

5. The Company management were constantly seized of the problem of delay and sought directions from the Board of Directors from time to time to overcome difficulties.

6. The collaborators had no managerial control and holding them responsible for achieving or non-achieving a certain production level would not have been of much help in such

a highly sophisticated industry as manufacture of photo films. With the rapid change in demand for types of photo films, incorporation of capacity build-up would hardly have served as a useful guidance to HPF management for watching progress.

7. There was tacit understanding between MACC and HPF for supply of cellulose triacetate for manufacture of photo films MACC, which is a semi-Government Company promoted by Mysore Sugar Co. (Karnataka State Government Company) was headed by a senior officer of IAS from Karnataka State Cadre. The question of seeking compensation from MACC was considered by the Board of Directors of HPF, which decided to drop the issue.

MACC was itself in a difficult financial situation due to poor off take of its product and was not in a position to meet loan commitments entered into with IDBI, ICICI, etc. In such circumstances, the question of recovering any portion of the cost of modifications would not have been of help.

8. The problem of losses of solvent and the need for designing a system to improve the efficiency of recovery engaged the attention of HPF management sufficiently early. The services of Indian consultancy firm (Dasturco) were engaged by the management in April, 1970 to study *inter alia* the solvent recovery system. Global tenders were floated by the management in November, 1971, an offer received in response from a Dutch firm was accepted in 1972 and the recovery plant received in June, 1973 was commissioned in August, 1973. There has been no lapse of management in this regard.

9. It is a commendable effort on the part of HPF that they on their own efforts without the benefit of foreign collaborators, developed process technology for manufacture of silver nitrate. The design of the

plant was provided by HPF technicians and the plant totally fabricated in India is operating since 1969-70 with very little modifications.

10. The assumption at the time of setting up Silver Nitrate Plant that all the silver used in process could be recovered was an unrealistic estimate, according to Bauchot and Co., the average yield of recovery was not more than 50 per cent of silver used in preparation section.

11. Silver loss accounting is suited only to Accounts Department, in as much as theoretically there should be no silver loss in the Emulsion and Coating Section, as all Waste material is sent to silver recovery system; yet in reality there is loss.

12. Silver from all silver bearing materials, except samples drawn for quality control and slag arising during conversion of sludge into silver and photographic clippings and waste paper was being recovered on a regular basis from January, 1971. Upto December, 1970, the quantity of silver recovered was about 1000 kgs. reckoning the first year of operation of the plant as 1968-69.

13. Slag arisings are being sent to BGML from October, 1972 due to lack of facility within HPF. Earlier to this period, the slag was allowed to accumulate with the expectation that HPF technicians themselves would find a solution.

14. Transportation of bulk quantity of slag to a distance of about 250 km. away from Coton and traversing back the same distance the recovered silver with all the security precautions necessary in one of the less frequented roads, is not a very satisfactory arrangement.

15. The rejection levels of main film products were in such a high range as 65 per cent to 152 per cent

for cine film (positive) 176 per cent to 444 per cent for X-ray, between the years 1968-69 to 1971-72. In such a situation, the natural concern of management would be to contain these rejections and make attempts to turn out acceptable quality of products. The question of recycling of wastes is of secondary importance; nevertheless, considerable attention had been paid by management to the aspects of recovery of silver within the constraints of available know-how. There was, however, scope for improvements.

16. With know-how maturity, production stabilisation capital improvements made in the manufacturing sections, and in silver recovery plant and improved management practices, there has been improvement in the recovery of silver from 1971-72. Over the last few years, there has been substantial increase in output of photo-sensitised materials.

#### Recommendations:

1. HPF is in a unique position holding monopoly in the manufacture of photographic goods in the whole of Asia, barring Japan. A special responsibility is cast on it to keep a careful watch on the improvements/developments in technology/know-how taking place in the leading countries of photographic manufacture so as to avail of improved facilities through fresh collaboration schemes.

2. The role of foreign collaborator should be clearly spelt out to avoid any ambiguities in the interpretation of agreements with foreign parties.

3. In photographic goods, leading manufacturers have specialised in different types of products (X-ray, Roll film, Colour Film, etc.). Future agreements should be split up into separate schemes for individual products so as to ensure that the most suitable manufacturer is chosen for collaboration. Such agreements

should incorporate clauses insisting on foreign parties to supply detailed design sheets and specifications in time.

4. Any future agreement should provide for pre-shipment inspection/testing by independent inspection agencies before shipment of equipment and materials for use in HPF factory.

5. Further agreement should also ensure that before accepting any equipment or process from abroad, its performance should be thoroughly tested regarding capacity, quality and suitability of process. Any performance guarantee should cover performance over a fairly long period.

6. The collaboration agreement should include provision for arbitration in case of dispute between the Indian party and foreign collaborator to be settled in India, as far as possible.

7. Slag arisings in the process of conversion of sludge into silver are sent to a distance of 250 kms. to Bharat Gold Mines, with all security risk, for recycling. HPF has also no arrangement for recovery of silver from photographic paper clippings and wastes. Silver from waste water drawn for laboratory purposes is also not recovered. HPF management should, therefore, make a study of practices abroad in all the above three areas and come forward to Government with proposals for creating suitable facilities.

8. Silver loss accounting should be in the form of material balance after establishing input-output relationships at various stages of recovery.

9. With product stabilisation know-how maturity and improved management practices, the HPF plant is now poised for product diversification and growth. The photographic plant has withstood many vicissitudes. The

scientists and engineers of HPF have by their own efforts, solved many of their problems. The need for continuous upgradation of knowledge and techniques in photo film manufacture is born out by our study.

#### Sale of Bajaj and Priya Scooters

6682. SHRI SHRIKRISHNA SINGH: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) the total number of various types of scooters, such as Bajaj 150 and Priya, etc. sold by M/s. Bajaj Auto Ltd. to the persons registered in general and against Government quota, separately, in the country and Delhi/New Delhi in particular immediately preceding one year (month-wise) of decontrol of scooters by Government and the number of scooters sold in the corresponding months thereafter against general list and others separately;

(b) whether there has been any fall in the number of scooters sold after decontrol; if so, the reasons therefor with reference to their manufacturing capacity; and

(c) the total number of persons in general waiting list for Bajaj 150 and Priya Scooters and the approximate time to be taken to meet the requirement?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI): (a) M/s. Bajaj Auto Limited, Poona are manufacturing Bajaj Super and Bajaj Chetak scooters. 'Priya' scooters are being manufactured by M/s. Maharashtra Scooters Limited, Satara, under sub-licensing arrangements with M/s. Bajaj Auto Limited, Bajaj Chetak scooters are being allotted against inward remittances of foreign exchange. The Statutory Control on distribution and sale of all makes of scooters, which was last applicable only to Bajaj and Priya makes of

scooters, was rescinded on 1st January, 1978. There are, therefore now no quotas for allotment of scooters at the disposal of Government authorities. Deliveries, however, in 1978 were made against quotas during the period of control. On the basis of the information reported, (which is not available month-wise) the data in respect of sales of scooters during the year 1977 and 1978 is given in the statement attached.

(b) Supplies effected in 1978 were less than in 1977, mainly because of disruption in production due to strike in the unit of M/s. Bajaj Auto Ltd. for about 1½ months.

(c) The total number of orders booked with various dealers in the country for Bajaj-150/Bajaj Super and Priya scooters stood at 3.70 lakhs and 1.14 lakhs respectively as on 1st January, 1979. The manufacturing capacity of M/s. Bajaj Auto Limited is being increased. The industry, as a whole, including the public sector organisation—Scooters India Limited—is also being developed so that consumer demand for scooters is met both qualitatively and quantitatively. It is expected that with this development in the industry, imbalanced preferences for a particular brand of scooter would be corrected expeditiously.

#### Statement

Bajaj/Chetak/Priya	1977		1978	
	Against quotas	Public booking/ Foreign exchange	Against quotas prior to de-control	Public booking/ Foreign exchange
Delhi	3,026	14,809	1,086	11,485
Other than Delhi	11,395	60,687	2,511	50,973
Total	14,421	75,496	3,597	71,468

#### Strike in Cement Companies

6683 SHRI NIHAR LASKAR-

SHRI M. V. CHANDRA-SHEKHARA MURTHY:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether the Associated cement company is facing an indefinite strike from 20th March following failure of talks of Bonus for 1977-78 with the Indian National cement and allied workers federation;

(b) if so, whether there will be a great loss due to strike; and

(c) whether Union Government have intervened in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SIIRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) to (c) The Indian National Cement and Allied Workers' Federation had given notice of strike to the Associated Cement Companies from 20th March, 1979 on the bonus issue. The strike was averted as both the parties reached a settlement on the 19th March, 1979. The strike notice was consequently withdrawn.

#### Concessions to SC & ST in Lakshadweep

6684. SHRI P. M. SAYEED: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether concessions granted to the Scheduled Castes and Scheduled

Tribes in Lakshadweep by the Union Government have not been implemented by the Administration of the Union Territory so far;

(b) if so, whether the periodic instructions from the Department of Personnel and Administrative Reforms, Cabinet Secretariat to the Lakshadweep administration for the speedy implementation of the concessions and relaxations had no effect on them;

(c) if so, how many of the concessions have so far been implemented in the Union Territory with details thereof and how many are still left, and

(d) the schemes and concessions that during the current financial year for the welfare of the Scheduled Tribes are proposed to be implemented during the current financial year for

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL):  
(a) There are no Scheduled Castes in Lakshadweep. All orders relating to Concessions to Scheduled Tribes in service matters are implemented by the Lakshadweep Administration

(b) and (c). Does not arise.

(d) A statement is attached.

#### Statement

The entire plan funds of the territory are for the benefit of the local inhabitants who are Scheduled Tribes. Some of the important concessions/schemes being implemented under the current Annual Plan are:—

1. Free distribution of coconut seedlings to farmers affected by the cyclone.

2. Distribution of fertilisers with 50 per cent subsidy.

3. Distribution of power tillers with 50 per cent subsidy.

4. Distribution of milch cows with 50 per cent subsidy.

5. Supply of seeds and plants, agricultural implements, cattlefeed, sewing machines etc. under community development programme with 50 per cent subsidy.

6. Subsidised issue of mechanised fishing boats with 50 per cent subsidy on engine and 25 per cent subsidy on hull.

7. Issue of fishing gear with 33-1/3 per cent subsidy.

8. Issue of subsidy at the rate of Rs. 1875/- per dwelling unit.

#### बेरोजगारी दूर करना

6685. श्री राम कंवार बेरवा क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश से बेरोजगारी दूर करने का है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसमें गजस्थान को किस सीमा तक लाभ मिला है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रकाश्नाथ रहमान) : (क) : योजना के प्रारूप (1978-83) में यह बताया गया है कि योजना के प्रवान उद्देश्यों में से एक उद्देश्य होना चाहिए 10 वर्ष की अवधि में बेरोजगारी और पर्याप्त अप्ल-रोजगार का दूर करना।

(ख) यह अनुमान लगाना इस समय संभव नहीं है कि बेरोजगारी को कम करने के लिए वर्तमान योजना में परियोजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन द्वारा राजस्थान को कहाँ तक लाभ हुआ है।

छठी पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप से तैयार करना

6686. श्री केशव राव घोडगे : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि :

(क) क्या छठी पंचवर्षीय योजना इस बीच अन्तिम रूप से तैयार की जा चुकी है;

(ख) दिल्ली में राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक के बारे में तैयार की गई नीति का घोरा क्या है; और

(ग) यदि हाँ, तो उसकी व्यापकता क्या है?

योजना मंत्रालय ने राज्य मंत्री (श्री कलन्तुर-रहमान) . (क) से (ग) छठी पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप देने का वापस चल रहा है और जर्दी ही पृग हो जाने की आशा है। राष्ट्रीय विकास परिषद ने, जिसकी बैठक नई दिल्ली में 24-25 फरवरी, 1979 को हुई थी, सरकारी लेन की योजना के बुल आकार को अनुमोदित किया और योजना के अगले चार वर्षों के लिए राज्यों को दी जाने वाली केंद्रीय योजना सहायता की मात्रा के सबध में भी निर्णय किया।

परिषद का निर्णय यह था कि अगले चार वर्षों के लिए केंद्रीय सहायता के रूप में उपलब्ध होने वाली सभावित कुल धनराशि में से 1800 करोड़ रु० विशेष श्रेणी राज्यों के लिए और 600 करोड़ रु० राज्यों की विशेष समस्याओं के लिए आरक्षित रखे जाने चाहिए; तथा 4200 करोड़ रु० विशेष श्रेणी के इतर 14 राज्यों के बीच में, विशेष समस्याओं से सबधित मापदण्ड के प्रलाप कार्यसे में विर्भारित किए गए जिभिक मापदण्डों के आधार पर वितरित किए जाने चाहिए। इनके आलावा केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों में कुल आयोजनों को करके अगले चार वर्षों में दी जाने वाली 2000 करोड़ रु० की राशि को हेक्टर राशि की 1.14 रु० में पितृ कुल 5.52 रु० के आधार पर, अर्थात् जनसंख्या द्वारा गुणित राज्य की प्रति व्यवित्र प्रायम के दिल्लीम के आधा पर, विशेष श्रेणी से इतर 14 राज्यों के बीच में वितरित किया जाना चाहिए।

### Strength of SC/ST Officers in Central Police Organisations

6687. SHRI R. L. KUREEL: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) what is the total strength of the following categories of officers in the Central Police Organisations and Union Territories separately (i) Director Generals (ii) Inspector Generals of Police (iii) Deputy Inspector Generals of Police (iv) Superintendents of Police (v) Commandants (vi) Deputy Supdts./A.S.P./Assistant Commandants (vii) Police Officers posted in the Central Secretariat or other allied organisations in the above mentioned ranks; and

(b) what is the percentage of S.C. and S.T. in each rank?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL): (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the House on receipt.

### Amount sanctioned to National Federation of Industrial Cooperatives Limited by Ministry of Finance

6688. SHRI BIRENDRA PRASAD: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a large amount has been sanctioned to the National Federation of Industrial Cooperatives Limited, New Delhi by his Ministry from time to time during the last four years;

(b) has the objectives stipulated in the Grants been fully achieved;

(c) what is the maintenance expenditure of the N.F.I.C. on Salaries, Rent and also TA/DA of the Chairman for the last three years;

(d) whether it is a fact that N.F.I.C. has failed to submit the Audited Re-

ports of Accountant General as per conditions of Grants sanctioned for the last several years; and

(e) if so, how Government nominated Directors kept proper watch over the Government funds entrusted to this organisation and how further funds are being released to it?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) During the last four years following amounts (Share capital investments and grants) were released to National Federation of Industrial Cooperatives for different

approved schemes by the Ministry of Industry.

Year	Grants (Rs. in Lakhs)	Share Capital Invest- ment (Rs. in lakhs)
1975-76 . . . . .	3.62	..
1976-77 . . . . .	5.76	6.00
1977-78 . . . . .	4.07	5.00
1978-79 . . . . .	2.22	..

(b) The Federation has helped in marketing the goods produced by the Industrial Cooperatives which comprise the weaker sections of the society.

(c) The yearwise details are given below:

Heads	1975-76	1976-77	1977-78
(i) Salary . . . . .	3,43,979.54	4,52,344.69	5,23,164.46
(ii) Rent . . . . .	74,235.40	2,33,630.23	3,09,034.71
(iii) TA & DA to Chairman . . . . .	11,310.00	3,774.00	12,411.45

(d) The Statutory Auditors have completed the audit for the year 1974-75 but the audit report is awaited. Statutory Auditors for conducting the audit for subsequent years have yet to be appointed.

(e) An enquiry into the working of the Federation was conducted. A time-bound programme is being formulated for implementation by the Federation so that it is revitalised and is able to serve the objects for which it has been established. In the meanwhile funds were released only to meet committed expenditure.

#### Cars in American Cell of the C.I.B

6689. SHRI RAJ NARAIN: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether there are 6 cars in American Cell of the Central/Intelligence Bureau (I.B.);

(b) if so, the purpose for which these cars are used;

(c) whether it is a fact that a car of I.B. was stolen from the residence of the chauffeur; and

(d) if so, the reasons for which this car was taken to Driver's house instead of being parked in the garage for staff cars?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL): (a) and (b). It would not be in public interest to disclose any information on this matter.

(c) and (d). A car was stolen from the residence of a driver on 10-9-78 and was recovered five days later. Disciplinary action has been initiated against the driver for lapses on his part.

**Promotion Opportunities to Upper Division Clerks**

**6690. SHRI SUKHENDRA SINGH:** Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether certain Upper Division Clerks of Central Secretariat Service have been stagnating for a number of years for lack of promotion opportunities;

(b) whether they have not been promoted despite the fact that they have rendered over 25 years of service;

(c) whether Central Secretariat Service rules provide a small percentage for inclusion of Upper Division Clerks to grade of Assistants; and

(d) what steps are being taken to provide (i) incentives and (ii) relieve stagnation?

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI S. D. PATIL):** (a) and (b). The Central Secretariat Clerical Service is a decentralised service, each Ministry/Department administering its own cadre. However, in order to remove imbalances in promotion as between the cadres the Department of Personnel and Administrative Reforms fixes annually zones i.e. range of seniority for promotion from the grade of Upper Division Clerk to that of Assistant. In accordance with the zone now prescribed, U.D. Cs. with approximately 9 years of service in the grade are within the zone for promotion. According to the Central Secretariat Service Rules, 1962, U.D.Cs. with 5 years of approved service in the grade are eligible for promotion to the Assistants' grade. There is hardly any U.D.C. with 25 years service in the grade who has still not been promoted to the Assistants' grade.

(c) Percentage of posts for promotion of Upper Division Clerks to Assistants' Grade is not small because

50 per cent of permanent vacancies and all temporary vacancies in the grade of Assistant are available for promotion of Upper Division Clerks.

(d) In view of the position explained above, the question of providing incentives and relieving stagnation does not arise.

रेस्टर्डियो द्वारा सीमेट हास है बरमे में कठिनाई

**6691. श्री कबहसाल हेमराज जीव :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह मत है कि देश के विभिन्न राज्यों में रेस्टर्डियो द्वारा सीमेट संस्लाइ करने के सम्बन्ध में कठिनाई अनुभव की जा रही है, और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और मरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किये जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदामी प्रसाद यादव) (क) जी, हां।

(ख) प्रधार्याल रेस्टर्डियो तथा रेस्लेबे द्वारा समय-समय पर कुछ रिशाप्स में लगाये गये दुलाई सबधी प्रतिवर्षों से सीमेट की दुलाई पर प्रतिकल प्रभाव न पढ़े इसका सुनिश्चय करने की दृष्टि से मार्गकर्ताओं से अनुरोध किया गया है कि वे यथासम्भव सड़क के द्वारा सीमेट उठाना तथा इस प्रयोजन के लिये सड़क माड़े की प्रतिपुर्ति को उठाना बना दिया गया है। रेस्लेबे बोईं से भी सीमेट की दुलाई करने के लिये रेस्लेबे के माल डिव्हो की संस्लाइ पर विशेष ध्यान देने का अनुरोध किया गया है।

**Putting Hindustan Levers "Lifebuoy" in Category of Carbolic**

**6692. DR. BAPU KALDATE:** Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether IDR Act has classified soaps in three different categories;

(b) whether Life Buoy a product of Hindustan Lever has been put in the category of "Carbolic";

(c) the reasons for putting Life Buoy a hard washing soap in the category of "carbolic";

(d) whether Government are aware of the fact that Hindustan Lever has changed the chemical composition to suit the category of carbolic; and

(e) whether Government propose to examine this issue?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) : (a) No, Sir.

(b) and (c). There is no separate Indian standard specification for Carbolic soap. A Carbolic soap should comply with the specifications for laundry soap if it is meant to be used as laundry soap or with the specifications for toilet soap if it is to be used as a toilet soap.

(d) and (e). M/s. Hindustan Lever Ltd. have not applied to ISI for grant of a licence for their brand of carbolic soap. Government is, therefore, not aware of any change in the chemical composition of Life Buoy by the Company.

#### राष्ट्रीय आग में धूंदि

6693. श्री सुरेन्द्र ज्ञा मुख्य : क्या योजना मंत्री यह बनाने की कृपा करेंगे कि

(क) वर्ष 1976-77, 1977-78 और 1978-79 के दीर्घन प्रचलित मूल्य के प्राधार पर इन लीन वर्षों में वर्षेवार राष्ट्रीय आग किसी भी दोष ; और

(ख) इस वर्ष किसी राष्ट्रीय आग होने का अनुमान है ?

योजना मंत्रालय में राय मंत्री (श्री कल्याण रहमान) : (क) और (ख). वर्ष 1976-77 व 1977-78 के लिए प्रचलित मूल्यों के प्राधार पर राष्ट्रीय आग क्रमांक 66561 करोड़ रुपये तथा 73157 करोड़ रुपये अनुमानित की गयी है। वर्ष 1978-79 के लिए ऐसे ही अनुमान भी तैयार किये जाने हैं।

#### Synthetic Detergents

6694. DR. BAPU KALDATE : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that synthetic detergents were classified as a core sector industry in the initial stages;

(b) whether there is any proposal to declare the field of synthetic detergents as reserved for small scale sector and to take synthetic detergents out of the core sector; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) : (a) Synthetic detergents are included in Appendix I to the Industrial Policy Statement of 2-2-1973.

(b) and (c). The question of reservation of manufacture of detergents for the small scale sector is under consideration.

#### Memorandum from Nagrik Sangha-rasha Samiti, Gangtok

6695. SHRI AMAR ROY PRADHAN :

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI :

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have received a Memorandum from the Nagrik Sangha-rasha Samiti, Gangtok, on denial of full citizenship rights to the non-Sikkimite Indians in Sikkim in 1977; and

(b) if so, the details thereof and action taken so far in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS : (SHRI DHANIK LAL MANDAL) : (a) Yes Sir.

(b) The Samiti mentioned that all the seats in the 32-member Legislative Assembly of Sikkim were reserved for Bhutia-Lepcha communities, Nepalis of Sikkimese origin, Scheduled Castes and Sanghas of monastics and consequently Indian citizens not belonging to the above mentioned four categories were not entitled to contest elections to the Legislative Assembly. The demand of the Samiti was that every Indian citizen in Sikkim, who had the right to vote, should also have the right to contest election to the Assembly.

The matter has been under the active consideration of the Government and appropriate legislation in this regard is likely to be introduced in Parliament before long for consideration.

#### बंगाल नागपुर काटन मिल

6646. श्री हुकम चन्द कछायाः क्या उद्देश मंत्री 16 अगस्त 1978 के नागरिक प्रश्न संख्या 437 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की हुपा चारों कि

(क) क्या यह मत है कि बंगाल नागपुर काटन मिल पर जनवरी, 1976 से प्रकृत्वर, 1978 के प्रवधि से सम्बन्धित राशि बताया है और अब तक कितनी राशि जमा कराई गई है तथा कम्चारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत जमा करवानी है और क्या इन दोनों राशियों को बूल करने के लिए उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध कायांवाही की गई है ; और

(ख) क्या उक्त मिल में ऐसे प्रमुख अविकृत हैं जिनके अपार सम्बन्धी अन्य बहुत से हित भी हैं ?

उद्देश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी, नहीं। इस समय जनवरी, 1976 से प्रकृत्वर 1978 की प्रवधि विषयक नर्मचारी राज्य बीमा (ईंग्लॉस-आई) श्री कोई भी देश बकाया राशि बंगाल नागपुर काटन मिल की ओर नहीं निकलती है।

(ख) जी नहीं।

#### Setting up of Paper Mills in Hoshiarpur

6697 CHOWDHRY BALBIR SINGH: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether two paper mills have since been sanctioned in the Hoshiarpur District;

(b) the total production target per month likely to be done by these mills; and

(c) when these mills will start production of paper?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) : (a) Approval has been given to three units for setting up paper mills in Hoshiarpur District.

(b) The total installed capacity of those units is about 2800 tonnes per month.

(c) One of the units is likely to commence production by the middle of 1979. The other two units are expected to commence production in 1980.

#### Loss to Jute Mills in Public Sector

6698 CHOWDHRY BALBIR SINGH: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the almost all the Jute Mills in Public Sector are going in loss since long;

(b) if so, the total loss suffered by all the jute mills in the country during 1978-79; and

(c) the steps Government have taken to stop this loss and the planning for future to stop such loss?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) : (a) No jute mill has been commissioned in public sector so far.

(b) The figure of profit/loss of all the jute mills in the country during 1978-79 is not available as the year has just ended.

(c) The following are the important steps taken to restore the viability of jute industry:—

(1) To promote exports, which came down drastically, export duty on all jute products has been abolished.

(2) Cash Compensatory Support has been given on export of selected jute goods

(3) Cess has been levied on jute manufacturers to finance R&D activities through the Development Council constituted for the jute industry.

(4) A soft loan scheme has been introduced to enable the industry to modernise the plants and machinery at a concessional rate of interest etc., so as to improve productivity and make their products competitive.

**Subversive activities by Chinese trained Nagas coming to Nagaland from Burma**

6699. SHRIMATI MOHSINA KIDWAI: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Chinese trained Nagas who have sneaked into the State of Nagaland from the Burma border in large numbers have indulged in blowing up of a power station and other serious works of sabotage; and

(b) if so, the number of arrests made in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANADL): (a) and (b). Recently, some violent incidents have taken place in Mon

and Tuensang Districts of Nagaland. These include an attack on the power house at Mon by some unknown miscreants. No damage was caused to the power house. Although the identity of the persons involved in the attack has not yet been established, it is however suspected that members of the China-returned gang who are staying across the border may be behind the incidents. No arrests have been made so far in this regard.

**Increase in Central Plan Aid**

6700. SHRI M. RAM GOPAL REDDY: Will the Minister of PLANNING be pleased to state:

(a) whether many State Governments have asked for increase in the Central Plan Aid; and

(b) if so, the names of these States and additional amount asked for each State?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING (SHRI FAZLUR RAHMAN): (a) and (b). The National Development Council in its meeting held on February 24 and 25, 1979 has determined the quantum of Central assistance for State Plans for 1979-83 and decided the principles on which this should be distributed among the States. The State-wise allocations are yet to be finalised. The question of any State asking for increase in the Central Plan aid, therefore, does not arise.

**Cases of Murder and Rape in Delhi**

6701. SHRI M. RAM GOPAL REDDY: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the number of cases of murder and rape reported in Delhi during 1978; and

(b) the number of cases that have been solved and the details thereof?

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS**

**(SHRI S. D. PATIL) :** (a) and (b). The details of the number of cases of murder and rape reported in Delhi during the year 1978 are as under--

	Reported	Cancelled	Admitted	Solved
<b>Murder</b>	185	4	181	135
<b>Rape</b>	80	4	76	71

**Recruitment of SC/ST Members to Junior Posts in Central and State Services**

**6702. SHRI MADHAVRAO SCINDIA :** Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether a two days conference of the officials of U.P.S.C., State P.S.C., Ministry of Education, Social Welfare and Culture and his Ministry and Labour was to be held during the last week of March, 1979 to discuss the matter with regard to promotion recruitment of SC/ST members to junior posts in the Central and State services; and

(b) if so, outcome thereof?

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI S. D. PATIL) :** (a) Yrs Sir A two-day conference of Recruiting Agencies like State Public Service Commissions etc. was organised by Staff Selection Commission on 24th and 26th March, 1979.

(b) The conference concluded with several recommendations. Some of the main recommendations of the conference are as follows:--

(i) to make up the shortfall in recruitment against vacancies reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, special recruitment may be held exclusively for them.

(ii) Where necessary and possible, additional examination centres may be set up in areas where Scheduled Castes and Scheduled Tribes population is concentrated.

(iii) Adequate number of pre-examination training centres may be set up for providing coaching facilities to candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

(iv) Facilities like hostel accommodation, typewriters etc. should also be made available.

(v) Extensive publicity may be given about examinations and recruitments in which reservations for Scheduled Castes/Tribes exist.

(vi) Recruiting agencies may be vested with the discretion of relaxing to the extent necessary, qualifications relating to experience prescribed for recruitment to various posts and services reserved for Scheduled Castes/Tribes.

**Meeting of National Productivity Council**

**6703. SHRI MADHAVRAO SCINDIA :** Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a meeting of National Productivity Council was held recently in Delhi;

(b) if so, whether Government have advised the Committee to reorient

its activities to new economic and industrial policy;

(c) if so, details of discussions therein; and

(d) outcome thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) : (a) and (b). Yes, Sir

(c) The National Productivity Council at its meeting held at New Delhi on 15th March, 1979, identified the following areas for immediate action :—

(i) Development of soap and match industries in collaboration with Khadi and Village Industries Commission, Development Commissioner for Small Scale Industries and others.

(ii) Development of small-scale sector-productivity improvement in the existing units and promoting growth of small scale units for the reserved items in collaboration with DCSSI.

(iii) Productivity improvement in public sector organisations where productivity is low or are considered sick. Some of the units/areas identified for immediate studies are State Electricity Boards, sick units of the National Textile Corporation and Engineering Industry, Bombay, Port, Railway Yard in Mughalsarai, etc.

(iv) Promoting appropriate schemes for securing involvement of Trade Unions to enable them to adopt productivity as an integral part of their movement.

(d) The National Productivity Council has already worked out detailed proposals for development of soap and match industries in the cottage/small sector. Proposals in respect of other areas are being worked out by the Council.

कास्याय मिल हारा वस्तुओं की विक्री

6704. श्री हुक्म चन्द कठबाय : क्या उद्योग मंत्री 16 अगस्त, 1974 के गारंकित प्रश्न संबंध 437 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या कास्याय मिल जनवरी, 1976 से अक्टूबर, 1978 के बीच कुछ पार्टियों द्वारा मिल में बने धारे, कपड़ों कटपीसों करतानों तथा अन्य लोकों एवं भवशिष्टों आदि जैसे अनेक वस्तुओं की विक्री करता रहा था, यदि तो, तो प्रत्येक वर्ष कितने मूल्य की तर्जी वस्तुएँ बेची गईं और किन किन पार्टियों को बेची गईं,

(ख) किन विन पार्टियों का बेचे गये माल की कितनी गारंज की अदायगी प्रभी प्राप्त नहीं हुई है, कब तक उसे बमूल कर लिया जायेगा और उसका सामान सामान्यता के लिये कितनी पर देचा जाता है, और

(ग) क्या अदायगी प्राप्त करने के लिये भूगतान न करने की दोषी कर्मों की कोई नोटिस जारी किये गये हैं और यदि हाँ, तो उन्हें किननी वार नाटिम दिये गये, इस प्रयोजन के लिये किननी कर्मों के विरुद्ध मुकदमे दायर किये गये और किनने मुकदमे दायर किये गये,

उद्योग मंत्री (को जार्ज फर्नन्डो) :

(क) मे (ग) अधिकार जानकारी उन जिलों में प्राप्त है जो दिनांक 19-5-79 और 10-5-78 को पूछे गये प्रश्न संबंध वर्ष 7460 और 9827 संबंधी आवासनों को प्राप्त करने हेतु सम्बद्ध पुरतकालय में रखी जायेगी। यह समस्या जाता है कि इस जानकारी को एकल करने में लगने वाले परंपराम के अनुकूल कल नहीं निकलेगा।

#### Formation of Reception Committees to Freedom Fighters at Port Blair

6705 SHRI MANORANJAN BHAKTA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that during the inauguration of Cellular Jail as a National Memorial at Port Blair by the Prime Minister of India when large number of freedom fighters were present two reception committees to freedom fighters, one official committee and other citizens committee were formed if so, the details thereof, and

(b) whether the Chief Commissioner, Andaman and Nicobar Islands, Shri S. M. Krishnayya had issued special instructions in spite of the request made by ex-Andaman Political Prisoners Fraternity Circle, to have a official, non-official joint reception committee, to keep away the non-officials if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL). (a) In connection with the inauguration ceremony of the Cellular Jail Memorial at Port Blair held in February, 1979, the Andaman and Nicobar Administration had constituted a Reception Committee consisting of both officials and non-officials. It is learnt that the local political parties, cultural institutions and other organisations had also formed a Citizens Committee, the details of which are not available with the Andaman and Nicobar Administration.

(b) No such instructions were issued.

**Schemes for Rural Development in Andaman and Nicobar Islands**

6706 SHRI MANORANJAN BHAKTA: Will the Minister of PLANNING be pleased to state:

(a) whether the Planning Commission has gone through the details of Sixth Five Year Plan Schemes of Andaman and Nicobar Islands; if so, details of the schemes of rural development and the total percentage of plan outlay;

(b) whether it is fact that there is a huge cut in the rural road sector which shall cause setback in the rural development in the outlying and remote areas if so, the details thereof; and

(c) whether the Planning Commission will reconsider the urgent need for construction of rural roads in the Union Territory of Andaman and

Nicobar Island; if so, whether Government will like to send a senior personnel to examine the whole case?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING (SHRI FAZLUR RAHMAN) (a) to (c). The Sixth Five Year Plan 1978-83 of Andaman and Nicobar Islands is under finalisation.

**Production of Keyboard for Hindi Typewriters**

6707 SHRI VASANT SATHE: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have taken a decision to encourage production of indigenous Hindi typewriters in the country as part of the programme for popularising the use of Hindi in Government and semi-Government organisation;

(b) if so, the present annual production of the Hindi-typewriters in the country, production unit-wise for the last three years, year-wise;

(c) whether Government have received a proposal sometime back from Shri S. N. Nilakhe of Akola, a World Typewriting Wizard and Research Scholar regarding his improved keyboard of Devnagri script and details of the proposal made by him for production of his keyboard as a media for popularising Hindi; and

(d) what action Government have taken to provide incentives to the said scholar and small scale entrepreneur like Mr. Nilakhe to manufacture his keyboard on a larger scale and the reaction of Government to the keyboard devised by him?

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL):**

(a) and (b). The Government are making efforts for the production of more Devnagri Typewriters than the requirement. The various companies have produced the Devanagri

Typewriters in the following number during the last three years.

	1976	1977	1978
Godrej, Bombay .	2723	2260	3104
Remington Rand Calcutta .	3019	5311	4720
Remington Rand Faizabad .	..	1059	1302
Royal, Madras .	1115	732	1066
	6857	9362	10192

(c) and (d). Some time back Sh. Nilakhe suggested for manufacturing a key board for Devnagri script Typewriter based on the Key Board of Roman script Typewriter. He was requested to make available his machine for some time for trial. He did not do so. Under these circumstances it is not possible for Government to frame any opinion about the said Key Board without making a thorough trial.

#### Study of Labour Intensive Nature Schemes

6708. SHRI VIJAY KUMAR N PATIL: Will the Minister of PLANNING be pleased to state:

(a) whether the Planning Commission have carried out some studies of the job oriented centrally sponsored central sector schemes of labour intensive nature during the 5th plan period and important findings regarding the programme Planning, programme content, administrative and other arrangements made at the Central/State and field level in the project areas, technical viability of the schemes executed and the results achieved on completion of schemes *vis-a-vis* the targets set; and

(b) if so, important findings thereof and how far these observations/find-

ings have been taken into account for formulation of new schemes?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING (SHRI FAZLUR RAHMAN): (a) and (b). The Programme Evaluation Organisation of the Commission has carried out evaluation studies of the Crash Scheme for Rural Employment and the Special Employment Programme for the Educated Unemployed implemented during the Fifth Plan period. Summaries of the findings of these studies are laid on the Table of the House. [Placed in Library. See No LT-4283/79] No such scheme is either in operation or under the consideration of the Government at present.

#### Special Assistance to Artisans, and Small Scale Industries

6709. SHRI NATHU SINGH: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is proposed to provide special assistance to the artisans, village and cottage industries and small scale industries and reduce the rate of interest in the backward districts, and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) Yes, Sir

(b) According to the instructions issued by the Reserve Bank of India to all commercial banks on the 12th December, 1978, bank credit for artisans and village and cottage industries and small scale industries in the tiny sector would be treated as composite term loan for equipment finance or working capital or both upto Rs 25,000/- In respect of credit limits for working capital above Rs. 25,000/- but less than Rs. 1 lakh

granted to artisans, village and cottage industries and small scale industries in the tiny sector, bank may charge at a rate not exceeding 12½ per cent per annum (except for small banks with aggregate demand and time liability of less than Rs. 25 crores, it may charge interest at a rate not exceeding 13½ per cent per annum)

The Reserve Bank of India has also issued guidelines to all scheduled banks on the 12th December, 1977 advising the banks to charge rate of interest not exceeding 11 per cent to small scale units covered under the Credit Guarantee Scheme and units promoted by technical entrepreneurs in order to stimulate capital investment in the small scale sector.

For promoting the development of industries in backward areas, the scheme of charging low rate of interest as also extending longer amortisation facilities in respect of projects located there will continue. The District Industries Centres which include all erstwhile areas declared industrially backward will continue to operate these schemes. The maximum rate of interest on loans refinanced by IDBI in backward districts is 9½ per cent per annum for primary lenders.

#### Setting up of a Mini Cement Factory in Orissa

6710. SHRI D. AMAT. Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether the Minister of Industry, Government of Orissa has proposed that a mini cement factory should be set up in Sundergarh district of Orissa under the expansion programme of Industrial Development Corporation; and

(b) if so, in which particular place it will be set up and by when the work of construction will start and at what cost?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) and (b). A scheme of the State Industrial Development Corporation of Orissa Ltd. (Bhubaneswar) has been registered on 23rd August, 1978 with D.G.T.D. for setting up of a mini-cement plant with a capacity of 33,000 tonnes per annum at Kiringsera, District Sundergarh, at a cost of Rs. 172 lakhs (estimated): It is too early to state when the work of construction will start.

#### Reservation of Posts for SC/ST in CSIO, Chandigarh

6711. DR SARADISH ROY: Will the Minister of SCIENCE AND TECHNOLOGY be pleased to state:

(a) how many posts have been filled up in the Central Scientific Instruments Organisation (CSIO) Chandigarh during the last five years (vacancies and newly created posts) category-wise;

(b) how many of the e posts were reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, category-wise;

(c) how many Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates applied and how many of them were selected; and

(d) how many Scheduled Castes/Scheduled Tribes employees are working in CSIO at present in Class I, Class II, Class III and Class IV categories and what is the total strength of staff in each category of staff?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE AND IN THE DEPARTMENTS OF ATOMIC ENERGY, ELECTRONICS, SCIENCE AND TECHNOLOGY AND SPACE (PROF. SHER SINGH): (a) to (d). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

**Persons Working Under Engineers and Architects of CSIR:**

6712. SHRI RAM VILAS PASWAN:

SHRI SHYAMLAL  
DHURVE:

Will the Minister of SCIENCE AND TECHNOLOGY be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question Nos. 2326 and 2346 on 7th March, 1979 and state:

(a) whether persons like plumbers, masons, welders, working directly under Engineers and Architects of CSIR have been declared as 'Technical' and the later category have been singled out;

(b) if so, the reasons thereof;

(c) whether by virtue of their qualifications and nature of work, the Engineers and Architects of CSIR are technical persons;

(d) whether it is a fact that Engineers and Architects of Headquarters are implementing research works of CBRI and SERC in planning and execution and as such are a coordinating link;

(e) whether Vardarajan Committee report on staff categorisation was based on some inbuilt prejudices to deprive Architectural and Engineering personnel of some consequential benefits like 5 years assessment and retirement age; and

(f) if so, by when these anomalies are likely to be removed?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE AND IN THE DEPARTMENTS OF ATOMIC ENERGY, ELECTRONICS, SCIENCE AND TECHNOLOGY AND SPACE (PROF. SHER SINGH):

(a) to (c). The Governing Body of the CSIR took a decision to reclassify the staff of the CSIR into three categories namely, Scientific Technical and Administrative against

four categories of Scientific, Technical, Auxiliary Technical and Administrative existing earlier. The posts of plumbers, masons, welders earlier included as 'Auxiliary Technical' have thus been classified as 'Technical'. At the same time, the Governing Body of CSIR felt that as Engineers and Architects of the CSIR are not contributing towards research, they may be classified as 'Administrative'. It is true that the Engineers and Architects of the CSIR are engaged on technical work and possess technical qualifications.

(d) The Engineers and Architects of the Engineering Unit, CSIR are essentially engaged in planning and construction of buildings and services. In doing so, they utilise some of the products and techniques developed by SERC and CBRI.

(e) No, Sir.

(f) The position is somewhat anomalous and the matter is therefore being reconsidered; no definite time limit can be given at this stage.

**Import of Computer by Glaxo Industries**

6713. SHRI A. K. ROY: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether permission has been given to a multi-national pharmaceutical company Glaxo Laboratories (India) Ltd. Bombay to import a giant computer throttling the employment potential in the industry; if so, facts in detail;

(b) whether this is against the policy of job oriented industrialisation of the country declared by Government; and

(c) if so, whether Government propose to withdraw permission; if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) : (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

**Senior Executives of Central Government Serving in Private Enterprises after Retirements**

6714. SHRI A. K. ROY: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state the number of Senior Executives of the Central Government now serving the private enterprises after retirement?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI S. D. PATIL) : This information is not monitored by the Department of Personnel and Administrative Reforms.

**Finding of the Study Group**

6715. SHRI A. K. ROY: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether his attention has been drawn to the findings of the Study Group of the Ministry of Industry that Senior Executives of Central Government serving the private enterprises after retirement are often used for their old contacts to take undue benefit from Government machinery; and

(b) if so, steps taken thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) : (a) The Study Group of the Ministry of Industry on Industrial Regulations and Procedures has

made a number of recommendations. However, this Group has not given any finding about the employment of senior officers of the Central Government after retirement by private enterprises and the use of their old contacts for undue benefits.

(b) Does not arise.

**Trade Fair in Purnea Distt. (Bihar) for Development of Jute Products**

6716 SHRI HALIMUDDIN AHMED: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government propose to arrange any trade fair in the Purnea District of Bihar for the development of Jute and its products;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor and the steps proposed to be taken by Government to promote Jute Production there?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) : (a) to (c). Government of India have no proposal to hold any trade fair in Purnea District of Bihar for the development of jute and its products. However, a Centrally Sponsored Scheme of Intensive Jute District Programme was initiated in 1972-73 in that district to raise the unit yield and production. This scheme is being continued during 1979-80 also. Under the scheme, the Government of India is providing cent per cent financial assistance for the development of jute in Purnea District. 80,000 hectares of the district have been covered by IJD programme and the production of jute in Bihar has increased from 516,000 bales in 1974-75 to 881000 bales in 1978-79.

1 Import of Bivoltine Silk

6717. SHRI A. R. BADRI  
NARAYAN:

SHRI M. V. CHANDRA  
SHEKHARA MURTHIY:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Union Government have decided to import 100 tonnes of Bivoltine silk which is roughly equal to the entire Bivoltine production in Karnataka:

(b) if so, whether this import of Bivoltine silk will reduce the prices of Karnataka's Bivoltine silk;

(c) if so, to what extent the prices will be reduced;

(d) whether the price decrease will result in Karnataka Growers continuing to produce low quality multivoltine only;

(e) if so, whether Karnataka growers have objected to the import of 100 tonnes of Bivoltine silk; and

(f) if so, the reaction of the Government?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) No, Sir. Import of bivoltine raw silk is, however allowed under replenishment scheme against export of natural silk goods as an export promotion measure. There is also a provision for import of a very limited quantity of raw silk for operating the mulberry price stabilisation scheme.

(b) No, Sir.

(c) to (f). Do not arise.

Use of Max Factor Trade Mark in India

6718. SHRI DHARMASINHBHAI PATEL: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state.

(a) whether Government are aware that Max Factor trade mark is used in India;

(b) the basis under which the trade Mark is permitted to be used; and

(c) whether Government have checked if there is an indirect consideration?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) Yes, Sir.

(b) "Max Factor" trade mark is being used in India by M/s. Swastik Household and Industrial Products (Division of Ambalal Sarabhai Enterprises Pvt. Ltd.) on the basis of the Registered User Agreement with M/s Max Factor & Co., U.S.A.

(c) The Reserve Bank of India has undertaken an investigation to check if the use of Max Factor trade mark involves any indirect consideration.

राजस्वान में आदिवासीय लोकों के विकास के लिए योजना

6719. श्री नाथ सिंह :

श्री चतुर्भुज :

क्या यह मंत्री यह बताने की हुपा करेंगे कि :

(क) राजस्वान में आदिवासी लोकों के विकास के लिये बनायी गई योजनाओं का ध्यारा क्या है और आप उन्हीं पंचवर्षीय योजना में आदिवासीयों कि स्थिति में सुधार करने के लिये किये जाने वाले उपायों का ध्यारा क्या है ; और

(ख) यह इसके लिये लोकों का वयन कर लिया गया है और यदि हाँ, तो उनके नाम क्या हैं ?

श्री चतुर्भुज में राज्य मंत्री (श्री अधिकारी वाल चतुर्भुज) : (क) और (ख) . एक उप-योजना, 50 प्रतिशत या उससे अधिक आदिवासी जनसंघों वाले लोकों के लिये बनाई गई है । ये अनुसन्धान में दिए गए हैं ।

इन योजनाओं के लिए परियोजनाओं में विकास के सभी क्षेत्र सम्मिलित है अबात् :—

1. कृषि और सम्बद्ध क्षेत्र ।
2. सहकारिता ।
3. जल और विज्ञानी विकास ।
4. उद्योग ।
5. संचार ।
6. सामाजिक और सामुदायिक सेवायें ।
7. आर्थिक सेवायें और
8. केन्द्रीय सेवायें ।

विभिन्न प्रकार के योजना अध्यात् भूमि हस्तांतरण, जलप्रदर्शन आदि को रोकने के लिए भी उपाय किए गए हैं ।

मध्यम-झवाड़ी योजना 1978-83 में इन योजनाओं पर जोर दिया जा रहा है ।

#### विवरण

#### राजस्वान

#### आविष्कारी उप-योजना क्षेत्र

जिले का नाम	क्षेत्र
आंतरिक	थाटोल गढ़ही तालाबा पिपलबूट कुतालग़ सज्जनगढ़ भुकिया बागीडोरा
झंगरपुर	झंगरपुर बीचीबाड़ा आसपुर संपदाड़ा सिमलबाड़ा
चित्तोड़गढ़	प्रतापगढ़ झरोड़
उदयपुर	कलासिया, बोरवाड़ा, लसादिया, सालम्बर, सारदा, कांडाडा, गिरी चम्प (पुर्णर्वित)
तिरहोड़ी	पावुरोड (पुर्णर्वित)

Cooperation agreement with Yugoslavia for peaceful uses of Atomic Energy

6720. SHRI NATHU SINGH:

SHRI SHANKER SINHJI VAGHELA:

SHRI MUKHTIAR SINGH MALIK:

SHRI G. M. BANATWALLA:  
DR. BIJOY MONDAL:  
SHRI BAGUN SUMBRUI:

Will the Minister of ATOMIC ENERGY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that India and Yugoslavia had entered into an agreement for cooperation in the utilisation of atomic energy for peaceful purposes; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE AND IN THE DEPARTMENTS OF ATOMIC ENERGY, ELECTRONICS, SCIENCE AND TECHNOLOGY AND SPACE (PROF. SHER SINGH). (a) and (b). An agreement between India and Yugoslavia on cooperation regarding the utilization of atomic energy for peaceful purposes was signed in Bombay on March 16, 1979. The Agreement provides for fellowships for training of scientists, exchange of unclassified information, exchange of scientific visits, lease or sale of material and equipment and carrying out of collaborative programmes as may be mutually agreed upon from time to time. Work programmes for carrying out joint activities under the agreement are being drawn up.

#### Growth rate of various Industries

6721. SHRI DHARMAVIR VASISHT: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) the overall performance of Heavy Industries and Engineering Industries during 1978-79;

(b) the production and growth rate achieved in Industrial Machine boil-

vers, cement machinery, tractors, cranes, machine tools, motor cars, commercial vehicles, motor cycles, electrical equipment and drycells; and

(c) the exportable surpluses, if any?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV):

(a):- The rate of growth of industries which can be classified as 'Engineering Industries' (which covers industry groups such as basic metal industries, metal products, non-electrical machi-

nery, electrical machinery, transport equipment, etc.) during the first nine months (April-December) of 1978-79 was 7.2 per cent according to the general index compiled by the CSO. No comparable estimate for "Heavy Industries" is available.

(b) A statement is attached.

(c) For most of the engineering industries, export targets are fixed by Export Promotion Council/Ministry of Commerce. No estimates of exportable surpluses as such, are available.

#### Statement

*Production and growth rates of selected Engineering Industries during April, 1978—January 1979.*

Industry	(A/c Unit)	April, 1977— Jan 1978	Apr. '78	Rate of Growth %
			Jan. '79	
1. Boilers: . . . . .	Rs. crores	156.6	170.8	+9.1
2. Cement Machinery . . . . .	Do.	16.88	31.69	+87.7
3. Tractors . . . . .	Th. Nos.	31.8	44.9	+41.2
4. Cranes . . . . .	Th. Tonnes	14.6	15.1	+3.4
5. Machine tools . . . . .	Rs. crores	81.3	100.9	+24.1
6. Cars . . . . .	Th. Nos.	30.2	29.8	-1.3
7. Commercial vehicles: . . . . .	Do.	32.7	45.8	+40.1
8. Motor cycles . . . . .	Do.	55.2	74.9	+35.7
9. Dry cells . . . . .	Mil Nos.	522	684	+31.0

NOTE:—Figures are provisional.

#### Ban on Expansion of Multinationals

6722. SHRI DHARMAVIR VASISHT: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) the steps taken to limit the activity of large industrial houses and to bring them in line with the country's socio-economic goals; and

(b) in what specific areas, with details the large houses had been prevented from expansion and with what results?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) and (b). Government have in the Industrial Policy Statement (f December, 1977 stated that where large scale units are already engaged in the manufacture of items reserved for small scale sector, there will be no expansion in their capacity. On the other hand, the share of these units in the total capacity for these items will be steadily reduced and that of the small scale and cottage sector increased. This policy is being strictly enforced.

**Reduction of Import Duty on Leather Chemicals and Footwear Accessories**

6723 SHRI DHARMAVIR VASISHTH: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether the reduction of import duty on certain leather chemicals and footwear accessories has achieved the objects in view;

(b) the detailed list of the identified chemicals; and

(c) the expected target during the Sixth Plan of finished leather goods export?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a)

Since the reduction in Customs duty on certain leather chemicals and footwear accessories/Components has been notified only on 10th Feb, 1979, it is too early to assess whether it has achieved the desired objective.

(b) A statement containing the list of chemicals for leather industry and the components/accessories for footwear industry where reduction in Customs Duty has been effected, is attached.

(c) The value of exports of finished leather and leather goods by 1982-83 is expected to be of the order of Rs. 423 crores at current prices.

**Statement**

S. No.	Description
1	Sulphonated cod oil or sulphated cod oil or oxidised cod oil or chlorinated cod oil or sulphonated neat's foot oil or sulphated neat's foot oil or oxidised neat's foot oil or chlorinated neat's foot oil or sulphonated fish oil or sulphated fish oil or oxidised fish oil or chlorinated fish oil or mixtures thereof.
2	Syntans.
3	Pigment finishes for leather.
4	Synthetic fat liquors (with or without hydrocarbons) Non-ionic fat liquors and mixture thereof.
5	Self blackening chrome tanning agents, Aluminium tanning agents, Oil tanning agents, resin tanning agents, zirconium tanning agents.
6	Sole Leather from ox hides and cut soles and units thereof.
7	Polyurethane Soles cut to size.
8	Steel reinforced in soles.
9	Leather and Plastic Heels.
10	Thermoplastic toe caps and counters.
11	Welts made from leather or plastic.
12	Buckles and other embellishments for footwear.
13	Shoe eyelets.
14	Shoe finishing polishes in solution or in blocks.

15. The following solvent soluble dyes:—

Number	Dyes	Hue No.	Colour Index Number
(1) Direct brown	.	214	..
(2) Acid Brown	.	150	..
(3) Acid Brown	.	52	..
(4) Acid Brown	.	238	..
(5) Acid Brown	.	151	..
(6) Acid Brown	.	239	..
(7) Acid Brown	.	147	..
(8) Acid Brown	.	188	..
(9) Acid Brown	.	189	..
(10) Acid Brown	.	314	..
(11) Acid Brown	.	235	..
(12) Acid Brown	.	191	..
(13) Acid Brown	.	192	..
(14) Acid Black	.	162	..
(15) Acid Black	.	67	..
(16) Acid Black	.	169	..
(17) Acid Brown	.	143	..
(18) Direct Blue	.	59	..
(19) Acid Brown	.	321	..
(20) Acid Brown	.	290	..
(21) Acid Brown	.	322	..
(22) Acid Green	.	93	..
(23) Acid Brown	.	127	..
(24) Acid Black	.	82	20265
(25) Acid Brown	.	145	20260
(26) Acid Brown	.	265	13230
(27) Acid Green	.	49	..
(28) Acid Black	.	83	..

Number	Dyes	Hue No.	Colour Index Number
(29) Acid Brown	.	144	14295
(30) Acid Brown	.	146	26531
(31) Acid Yellow	.	86	23310
(32) Acid Blue	.	133	..
(33) Acid Red	.	234	..
(34) Acid Red	.	235	..
(35) Acid Red	.	236	..
(36) Acid Brown	.	159	..
(37) Acid Brown	.	160	..
(38) Acid Brown	.	161	..
(39) Acid Brown	.	162	..
(40) Acid Brown	.	163	..
(41) Acid Green	.	48	—
(42) Acid Brown	.	311	..
(43) Acid Brown	.	126	..
(44) Acid Brown	.	236	..
(45) Acid Brown	.	276	..
(46) Acid Brown	.	188	..
(47) Acid Brown	.	277	..
(48) Acid Brown	.	130	..
(49) Acid Brown	.	303	..
(50) Acid Brown	.	237	..
(51) Acid Black	.	76	..
(52) Acid Black	.	94	30336
(53) Acid Brown	.	279	..
(54) Acid Brown	.	165	..
(55) Acid Blue	.	134	..
(56) Acid Green	.	26	..

Number	Dyes	Hue No.	Colour In dex Number
(57) Acid Orange	.	78	..
(58) Acid Violet	.	80	..
(59) Acid Yellow	.	96	..
(60) Direct Brown	.	206	23010
(61) Acid Black	.	84	17560
(62) Acid Brown	.	103	10415
(63) Acid Brown	.	75	34905
(64) Acid Brown	.	85	34900
(65) Acid Brown	.	84	20255
(66) Acid Brown	.	325	..
(67) Acid Black	.	173	..
(68) Acid Brown	.	92	36020
(69) Acid Brown	.	324	..
(70) Acid Brown	.	86	17595
(71) Acid Brown	.	87	17596
(72) Acid Brown	.	92	36020
(73) Acid Brown	.	86	34900
(74) Acid Black	.	69	30460
(75) Acid Blue	.	36	29115

**Recommendations of Committee on  
Kanjhawala Land Dispute**

6724. SHRI DHARMAVIR VASISHTH:  
Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state the detailed recommendations of the nine-Member Committee constituted in September, 1978 by the Delhi Administration to go into dispute and suggest a solution to the Kanjhawala land dispute between villagers and allottees?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI S. D. PATIL): Delhi Administration have reported that no such Committee was constituted by them.

**Charging of High Rates on Papers by  
Shopkeepers ..**

6725. SHRI SHANKERSINHJI VAGHELA:

SHRI MUKHTIAR SINGH MALIK:

DR. BIJOY MONDAL:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state;

(a) what are the rates at which the various kinds of paper is supplied to the shopkeepers by the mills in the country;

(b) whether it has come to the notice of Government that shopkeepers have been selling the paper by charging Rs. 150/- to 200/- per

quintal over and above the rates specified by Government for which they do not issue any receipt; and

(c) whether Government propose to set up an inquiry committee or get it probed through C.B.I. as to why the paper is sold in the black market in such a manner and action taken or proposed to be taken in the matter?

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV):** (a). There is a chain of intermediaries in the paper trade, and the retail price takes into account the ex-mill rate, excise duty, freight, local taxes and distributors' margin. As there are also a large number of varieties and qualities of paper, the rates are not uniform.

(b) and (c). As there is no statutory control on prices of paper, the question of legal action does not arise. Govt. are however taking various steps to increase production and are also planning to import paper to ensure that the marginal imbalance between demand and supply does not result in speculative increase in price of paper.

**Report on Institute of Applied Man-power Research**

6726. SHRI SHANKERSINHJI

VAGHELA:

SHRI G. M. BANATWALLA:

DR. BIJOY MONDAL:

Will the Minister of SCIENCE AND TECHNOLOGY be pleased to state:

(a) whether Government have since received the report of Professor P. R. Sengupta on the Institute of Applied Manpower Research;

(b) if so, the recommendations made;

(c) whether Government have since contemplated any action to implement the recommendations; and

(d) if so, the details thereof?

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE AND IN THE DEPARTMENTS OF ATOMIC ENERGY, ELECTRONICS SCIENCE AND TECHNOLOGY AND SPACE (PROF. SHER SINGH):** (a) Yes, Sir. The Report has been prepared by the Institute of Applied Man Power Research in response to a request made by the National Committee on Science and Technology.

(b) The salient features of the recommendations are given in the enclosed statement.

(c) and (d). The reports are under study.

**STATEMENT**

The report brings out the pattern of employment and characteristics of scientific manpower, and also a norm for assessing future requirement of manpower for R&D on the basis of proposed outlay.

Although the report is mainly in the form of a status report, there are few general recommendations. The Report covers (i) the Institutional Sector covering the CSIR chain and a few large public sector industries such as FCI; (ii) Industrial Sector covering R&D labs. in the public and private sector on a sampling basis; and (iii) University Sector (of some Universities and IITs) but largely based on the IIT system.

The main recommendations are:

**1. Industrial Sector:**

(1) In a free market situation, every industry has to take enough precaution against obsolescence, so that it may not suffer in competition against more sophisticated technology or by the introduction of a more attractive product.

(2) As regards functional distribution of S&T personnel, it is stated

that, as the purpose of R&D in the industrial sector is to develop marketable technology and technical innovation, R&D programme in the industry should be design and development oriented. An overall functional ratio of 1:1 of the R&D and Auxiliary personnel, is fairly reasonable.

(3). The poor utilisation pattern of post-graduates in Science & Technology in industrial R&D is a matter of great concern, and calls for in-depth study for ascertaining the reasons for this.

(4) R&D in the industrial Sector should include mainly (a) design and development and (b) marketing.

For every rupee spent on the R&D part, the economy should be prepared to invest five to ten times as much, depending on the nature of the industry, for successfully marketing the product or innovation.

(5) The manufacturing industries should spend matching amount to utilise the R&D results of the various Institutions, on developmental or technical R&D. Industry should be committed to industrial growth through technological development.

## ***H. Industrial Sector***

(1) There should be an interdisciplinary approach with regard to technology and better utilisation of professionals.

(2) The pattern of distribution of S&T personnel, by salary, needs to be examined thoroughly in order to make R&D more productive and to draw more young brilliant scholars to it. A cylindrical pattern is preferred to a pyramidal pattern.

(3) Technical services should constitute a more important wing of R&D than administration and clerical functions.

## ***Increase in Price of Cloth***

6727. SHRI SHANKERSINHJI VAGHELA:

DR. BIJOY MONDAL:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether there has been considerable increase in the prices of cloth in the country after the presentation of Finance Budget and if so, to what extent;

" (b) whether it is also a fact that the prices of cotton have gone down by 13.8 per cent at present as compared to the last year; and

(c) whether any steps have been taken by Government to check the prices of cloth in the country and if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) No, Sir. In fact, the wholesale price index for cotton textiles has fallen from 185.7 for the week ending 24-2-1979 to 185.4 for the week ending 24-3-1979.

(b) The wholesale prices of cotton decreased by about 94 per cent between February, 1978 and February, 1979.

(c) There is no statutory control on the prices of cloth. The price movement is conditioned by a multiplicity of factors, important of which are production costs and demand and supply. Nevertheless, the Minister of Industry has recently discussed the matter with the industry, who have been asked to devise steps to reduce prices of cotton cloth.

६. नियन्त्रित कपड़े का निर्माण और उत्तर के मूल्य में बढ़ि

6728. श्री अमल राम कायसवाल : क्या उत्तर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 अप्रैल 1978 से 31 मार्च, 1979 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय बस्त नियम के अधीन संचालित निलों द्वारा गैर-नियन्त्रित कपड़े के मूल्यों में बढ़ि की गई थी, जबकि ऐसी प्रबंधि के दौरान वही की कीमतों में कमी हुई थी।

(ब) वर्ष 1978 के दौरान उपर्युक्त निलों द्वारा अनियन्त्रित कपड़े का कितनी भावा में उत्पादन किया गया और ऐसे कपड़े के मूल्यों में प्रत्येक निल द्वारा कितनी भीतर बढ़ि की गई ; और

(ग) क्या वर्ष 1978 और 1979 की प्रबंधि नियमितों के दौरान इन निलों को अपनी मूल्य नियन्त्रित नीति के बारे में सरकार ने कुछ भारत-दर्शक सिद्धान्त जारी किये थे और यदि हाँ, तो उत्तराधिकारी भीरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तोग अंतरालमध्ये राष्ट्र लोकी (श्री अमलस्वामी असाध यादव) : (क) जी हाँ, हई के मूल्य में कमी होने के बावजूद, वर्ष, 1978-79 के दौरान अन्य नियन्त्रितों की लागत में बढ़ि हो जाने के कारण राष्ट्रीय बस्त नियम की निलों द्वारा उत्पादित अनियन्त्रित किस्म के कपड़े के निल से निकलते सबवय के लागत मूल्य में कुछ बढ़ि हुई है।

(ब) 1978 के कलंडर वर्ष में राष्ट्रीय बस्त नियम की निलों में लगभग 7771.70 लाख भीटर गैर-नियन्त्रित कपड़े का उत्पादन किया। उत्पादित कपड़े की निल से निकलते सबवय की कीमत में भीतर 2 प्रतिशत की बढ़ि हुई है।

(ग) जी, नहीं। कपड़े की गैर-नियन्त्रित किस्मों के मूल्यों पर कोई भी कानूनी नियंत्रण नहीं है।

बस्तों और ढुकों का आवात

6729. श्री राम किलाल पालवाल : क्या उत्तोग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बस्तों, ढुकों प्रबंधि उनके चेतिस का आवात करने से रोजगार के अवसर प्रदान करने में और वित्तीय लाभ प्राप्त करने में सहायता प्रियेती ;

(ब) क्या वर्तमान कारखानों की उत्पादन अवसरा में बढ़ि करके उनके उत्पादन में तकली बढ़ि नहीं की जा सकती ; और

(ग) इनके स्वदेशी उत्पादन और इनके आवात के पश्च और विषय में क्या मार्गिक कारण हैं ?

उत्तोग अंतरालमध्ये राष्ट्र लोकी (श्रीमती आमा लाहौंस) : (क) प्रतिक परिवहन और माल का परिवहन, जिसमें बस्तों और ढुकों का परिवहन अन्तर्भृत है, एक प्राविनिकता श्राव्य उद्योग है, जिसकी रोजगार अवसरा भी पर्याप्त है।

(ब) 1979-80 में माल में प्रत्याक्षिप्त बढ़ि के अनुरूप वाणिज्यिक गाड़ियों के स्वदेशी निर्माण में बढ़ि करने के लिए अनेक उपयोग जारी हैं। इन उपयोगों के परिमाणमत्त्वरूप बहुत ही इस वर्ष 1978-79 में देश में निर्मित वाणिज्यिक गाड़ियों की संख्या गत वर्ष 1977-78 की प्रबंधि में 41,244 की तुलना में 58,255 हो गई है। अतः माल में बढ़ि को पूरा करने के लिए इस वर्ष उत्पादन में स्पष्ट रूप से बढ़ि हुई है।

(ग) ढुक/बस चेतिसों का बास्तव में कोई आवात नहीं हो रहा है। आवात के विषय में मुख्य कठिनाई यह है कि आवातित गाड़ियों जिसकी तुलना भारत में निर्मित वाणिज्यिक गाड़ियों की विकसितियों और काम से की जा सकती है, की कीमतें सीमांगूत्क जोड़े बिना भी काफी अधिक हैं।

#### Aid to Handloom Intensive Development Projects in Karnataka

6730. SHRI C. K. JAFFER SHARIEF: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Central Government have given assistance for handloom intensive development projects in the State of Karnataka during the current financial year; and

(b) if so, the district-wise details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) and (b). Central assistance is given according to prescribed pattern for projects. For the Ilkal intensive handloom development project (covering parts of Bihar, Gulbarga and Bijapur districts), a sum of Rs. 22.50 lacs was released by the Central Government during 1978-79.

**Indo-Soviet Cooperation in Fast  
Neutron Breeders**

6731. SHRI EDUARDO FALEIRO: Will the Minister of ATOMIC ENERGY be pleased to state:

(a) whether Government have taken steps towards Indo-Soviet Cooperation in the field of "fast neutron breeders" for operating the next generation of nuclear power plants; and

(b) if so, the details thereof?

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE AND IN THE DEPARTMENTS OF ATOMIC ENERGY, ELECTRONICS, SCIENCE AND TECHNOLOGY AND SPACE (PROF. SHER SINGH):** (a) and (b). A new agreement between India and USSR has been signed on January 22, 1979 which *inter alia* includes cooperation in the field of fast breeder reactors. Work programmes for carrying out joint activities in accordance with the new agreement are being worked out.

**Resumption of Dialogue with Naga Rebels**

6732. SHRI CHITTA BASU: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government contemplate any possibility in near future to resume dialogue with the rebel Nagas and adopt a policy of conciliation rather than confrontation;

(b) whether there are some moves to arrange for a fresh dialogue between Government and Naga rebels; and

(c) if so, the reaction and attitude of the Government thereto?

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL):** (a) to (c). Government have all along been following, and continue to follow a policy of reconciliation. It was in pursuance of this policy that the talks were held with the ex-underground Nagas and an Agreement

reached in November, 1975. Representatives of the ex-underground who were signatories to this Agreement have been in contact with underground Nagas staying across our border in Burma with a view to persuading them to accept the Shillong Agreement. Talks between them are to continue. Besides, at present there is no other proposal for any dialogue between the Government and underground Nagas.

**Meeting of D.I.G.s of Police in Delhi**

6733. SHRI K. A. RAJAN: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether a meeting of Deputy Inspectors General of Police was held in Delhi on 8th March, 1979;

(b) if so, the details and where the meeting was held;

(c) total amount spent for the meeting;

(d) whether it is a fact that Rs. 6600/- was spent on dinner attended by these 120 D.I.G.s.; and

(e) if so, whether this is in keeping with the policy of Government?

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL):**

(a) Yes, Sir

(b) This is an Annual Conference which is held at New Delhi and was attended by D.I.G.s and other senior police officers from all State Governments and Union Territories.

(c) A sum of Rs. 33,124.70 was spent in connection with the Conference.

(d) An expenditure of Rs. 12,358/- was incurred on the dinner which was attended by these delegates and some other officers.

(e) It is a usual practice to host dinner on such occasions to provide an opportunity to the delegates for greater informal discussions.

**Criminal Cases Filed for Demonstration against Simla Pact**

**6734. SHRI RASHEED MASOOD:** Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether certain criminal cases were filed against some persons when they demonstrated in Delhi against Simla Pact with Pakistan; and

(b) if so, what has happened to those cases?

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI S. D. PATIL):** (a) and (b). Delhi Administration have reported that eight cases were registered in connection with the demonstration held in Delhi against Simla Pact. Out of these, 5 cases were decided by the Court. The accused were sentenced till rising of the Court in 4 of these cases and discharged in the 5th case. The other cases were withdrawn by the Delhi Administration.

मध्य प्रदेश के आदिवासियों के जीवन यापन की पद्धति का सर्वेक्षण

**6735. श्री इसपत्र रिह परस्ते :** क्या यह मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के आदिवासियों (प्राचीन जातियों) के जीवन यापन की पद्धति और उनकी संभाव्य के बारे में पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है ?

यह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनिल लाल महेश्वर) : (क) और (ख). संभवतः सदस्य का आकाश उन आदिवासीय जनजातीय समुदायों से है जो पूर्व कृषि स्तर तकनीक के अनुसार रह रहे हैं। इन वर्गों को परिवासनने के लिए तीन महत्वपूर्ण अभियान लिए गए हैं, अर्थात् :-

(i) वर्ग पूर्व कृषि स्तर तकनीक का होना चाहिए, स्थानान्तरित वेरी विभाजन रेखा के स्पर्श में आगी जा रही है ?

(ii) वर्ग पूर्व-साकरता या 5 प्रतिशत साकरता से कम का होना चाहिए, तथा

(iii) वर्ग के विकास की दर स्थिरता के निकट या कैबल सीमान्त की होनी चाहिए।

उपरोक्त आधार पर, मध्य प्रदेश सरकार ने प्रभुज-जारियां, बेग़ल, भरियास, पहाड़ी कोरियास तथा साहुर्दियास आदिय जनजाति समुदायों का पता लगाया है।

इन समुदायों के विकास के लिए विशेष कार्यक्रमों को शुरू करने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य के लिए राज्य उत्तरकार प्रत्येक समुदाय के लिए परियोजना रिपोर्ट तैयार कर रही है। इन रिपोर्टों को, विस्तृत सर्वेक्षण करने के बाद तैयार करने की आवश्यकता है।

**Recommendations of the Working Group on Automotive Industry**

**6736. SHRI SUBHASH CHANDER BOSE ALLURI:**

**SHRI K. RAMAMURTHY:**

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a high level working group appointed by Government on the automotive industry has submitted its report to Government;

(b) if so, what are the main recommendations of the group; and

(c) whether Government have examined the report, what are the recommendations that Government have accepted and implemented?

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI):** (a) and (b). The Working Group on Transport, Earth Moving Equipment and Agricultural Machinery set up to formulate programmes of development for the Five Year Plan Period 1978-83 has submitted its report recently. The recommendations cover the main sectors of the Automotive Industry comprising commercial vehicles, jeeps, cars, 2-wheelers, agricultural tractors, earth-moving equipment, diesel engines, automotive ancillaries and railway equipment. The main

recommendations relate to augmenting and upgrading, where necessary, productive capacities and capabilities in the country for meeting the demand, particularly with reference to national priorities, concerning increased employment opportunities, public transportation, movement of goods and capital inputs for projects concerning power, mining, rural development, etc. Besides outlining the industry status and future trends of each of these sectors of automotive industry, the report of the Working Group also indicates long-term production projections, investments required to achieve the projected production employment potential, rationalisation and technological upgradation.

(c) The main thrust of the report has been accepted by the Government. The modalities, direction and progress of implementation will depend on several factors including the response of the Industry, the actual growth of demand and resources available.

#### Inquiry into Alleged Atrocities on Harijans in Muzaffar Nagar

6737. SHRI CHITTA BASU: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Commission have enquired into the alleged atrocities on the Harijans in Muzaffar Nagar recently;

(b) whether the commission has since submitted its report; and

(c) if so, the essential findings of the Commission and their specific recommendations on this particular issue?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL): (a). Yes, Sir.

(b). No, Sir.

(c). Does not arise.

'सो कास्ट स्वामी कार' शीर्षक से समाचार

6738. श्री हुकम बहादुर कछवायः

श्री दलाल शास्त्रीः

क्या उद्घोग मंत्री यह बताने की हुआ करेंगे कि :

(क) क्या 6 मार्च, 1979 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में कल कीत पर छोटी कार के बारे में समाचार प्रकाशित हुआ है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उक्त छोटी कार का निर्माण करने के लिये किस कम्पनी को आशय पत्र आई किया गया है और देश में इस कार का निर्माण किस स्थान पर होगा और इसकी लागत निर्माण प्रादि का पूर्ण व्यौरा क्या है ?

उद्घोग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आमा नारी) : (क) और (ख). 6 मार्च, 1979 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में भोटराली उद्घोग के उल्लंगन के प्रस्तावों का उल्लेख है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ देश में विद्यमान यात्री कारों की तुलना में ईंधन लम्ता आदि की दृष्टि से एक और अच्छी कार का निर्माण की अवस्था है। इन प्रस्तावों का अध्ययन किया जा रहा है और रिपोर्ट में यह कहा गया है कि प्रस्तावित कार के निर्माण के संबंध में समय और खूब के बारे में बताना सम्भव नहीं है। इस परियोजना के लिए किसी कम्पनी को आशय पत्र नहीं दिया गया है।

राजस्थान में एच० एम० टी० की बता कारखाना स्थापित करना

6739. श्री नालू कुमार शास्त्रीः क्या उद्घोग मंत्री यह बताने की हुआ करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में एच०एम०टी० की बता बनाने का कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव मंत्रालय के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस कारखाने की स्थापना कब तक की जायेगी ?

उद्घोग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आमा नारी) : (क) और (ख). राजस्थान शीर्षोंग्रन्थ एवं कलिङ्ग विकास विभाग द्वारा बतावेर में एच० एम०टी० सहायता प्राप्त राजस्थान की बाज़ असेम्बली यूनिट की स्थापना की जा रही है। कर्मचारियों की प्रतिक्रिया दिया जा रहा है तथा द्वारात का विभाग कार्य चल रहा है। नालू वर्ष में एक के कार्य शुरू कर देने की आशा है।

भारत ही ईलेक्ट्रिकल लिमिटेड में आयुर्वेदिक चिकित्सा पट्टरि को आव्याता देता।

6740. श्री भानु कुमार शास्त्री : क्या उच्चोग मंत्री यह बताने की हुया करेंगे कि भारत ही ईलेक्ट्रिकल लिमिटेड में आयुर्वेदिक चिकित्सा पट्टरि को आव्याता न देने के क्या कारण हैं ?

उच्चोग मंत्रालय में राज्य अंगी (श्रीमती आमा शाहीत) भारत ही ईलेक्ट्रिकल लिमिटेड के कर्मचारियों को डाकटरी उपचार तथा चिकित्सा की उदार व पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। कल्पनी के भोपाल स्थित एक एवं कर्मचारी आयुर्वेदिक पट्टरि के अन्तर्गत श्री डॉक्टरी ईलाज देने के हकदार हैं। सरकारी नीति के मनरूप अन्य प्रभागों में भी देशी चिकित्सा पट्टरियों के अन्तर्गत चिकित्सा सुविधाएं बढ़ाव करने के सवाल पर श्री एच.ई.एल. विचार कर रहा है।

राजस्थान में सीमेंट उच्चोग स्थापित करने के लिये आवेदन पत्र

6741. श्री भानु कुमार शास्त्री : क्या उच्चोग मंत्री यह बताने की हुया करेंगे कि :

(क) राजस्थान में सीमेंट उच्चोग स्थापित करने के लिये सरकार को किनने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) उनमें से स्वीकृत प्रधना अस्तीकृत किये गये आवेदन-पत्रों की संख्या अलग-अलग कितनी है, और

(ग) आवेदनों को अस्तीकार करने के मुख्य कारण क्या हैं ?

उच्चोग मंत्रालय में राज्य अंगी (श्री जगद्वीप प्रसाद बाबू) : (क) और (ख). राजस्थान में सीमेंट संयंक स्थापित करने के लिए 1 प्रस्ताव, 1977 से श्रीमती लाइसेंसों/आशय पत्रों के लिए 22 आवेदन तथा तकनीकी विकास के हानिदेशालय में पंजीकरण हेतु 12 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उनमें से 15 प्रस्ताव स्वीकृत कर दिये गये हैं। 8 प्रस्ताव रद्द कर दिये गये हैं तथा 11 प्रस्तावों की जांच की जा रही है।

(ग) राजस्थान में सीमेंट संयंकों की स्थापना क्षमती आवेदन रद्द होने के मुख्य कारण रेत परिवहन की अपर्याप्ति सुविधा का होना तथा जिन कंतों के के लिए आवेदन किया गया है, उनमें सीमेंट ग्रेड के बूने पत्थर का न होना है।

#### Coir Production in Coimbatore

6742. SHRI R. KOLANTHAIVELU: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) the quantity of coir fibre produced in Coimbatore and Salem districts of Tamil Nadu;

(b) whether Government have studied the feasibility of starting a rubberised coir unit in Tamil Nadu making use of the immense quantity of coir fibre available there; and

(c) if so, the results of the study and the further steps proposed to be taken for developing the industry?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a). The estimated production of fibre during 1977-78 is 880 tonnes in Coimbatore and 350 tonnes in Salem districts of Tamil Nadu.

(b) and (c). The Government of Tamil Nadu have prepared a scheme for setting up of a rubberized coir unit in Thanjavur district for the consideration of the Coir Board. The Coir Board after due consideration will send a viability report to the Government of Tamil Nadu taking into account the existing installed capacity of the rubberized coir manufacturing units. The actual implementation of developmental programmes in respect of coir industry the responsibility of the State Governments under their respective Plan Schemes.

#### Launching of Geosynchronous Satellite

6743. SHRI R. KOLANTHAIVELU: Will the Minister of SPACE be pleased to state:

(a) whether Government propose to launch geosynchronous satellite in 1981;

(b) if so, the particulars thereof; and

(c) whether such a satellite is considered to be of great importance for Tamil Nadu which has to depend mostly on monsoon rains?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE AND IN THE DEPARTMENTS OF ATOMIC ENERGY, ELECTRONICS, SCIENCE AND TECHNOLOGY AND SPACE (PROF. SHER SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) The geosynchronous satellite, called the INSAT-I, is a multi-purpose domestic satellite system for telecommunications, TV and Meteorology. Its telecommunications and TV coverages are designed for national coverage. However, its Very High Resolution Radiometer (VHRR) for meteorological earth imaging is designed to cover about 25 per cent of the world area directly below the satellite.

(c) The satellite will be of prime importance to the whole country, as the meteorology components of INSAT-I system will significantly improve the country's weather forecasting capability which will benefit, in particular, agricultural operations, aviation, port and shipping operations, hydro-electric power generation planning, and cyclone and flood disaster warning.

**Issue of Licences for increasing production of items reserved for Small Scale Industries**

6744. SHRI S. R. DAMANI: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government have issued fresh licences or allowed to increase the production capacity with regard to the production of items reserved for small scale sector on the consideration of 100 per cent exports on a continued basis, during the course of the year;

(b) if so, the names of the companies who were allowed to increase the production capacity or given fresh licences in this regard; and

(c) the items for which the fresh licences were issued or allowed to increase the production capacity?

**THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI GEORGE FERNANDES):** (a). Yes, Sir.

(b) and (c). Under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, the following 2 Industrial Licences and 5 Letters of Intent were issued during 1978 for the manufacture of items reserved for the Small Scale Sector subject to the conditions that they would export 100 per cent of their annual production on a continuing basis.

Name of the Company and Location of the Undertaking	Item of Manufacture
<b>A. Industrial Licences</b>	
1. M/s. Anspa-Knit (Pvt.) Ltd., (Kandla Free Trade Zone, Gandhidham, Kutch, Gujarat)	Pullovers, Cardigans, Ladies Blouses. (New Undertaking)
2. M/s. Pentagon Screws & Fasteners Ltd., (Sahibabad, Ghaziabad, U.P.)	Wood Screws, M.S. Screws etc. (New Undertaking)
<b>B. Letters of Intent</b>	
1. Shri Darshanji Singh . . . . . (Ghaziabad—U.P.)	M.S Screws, Wood Screws, etc. (New Undertaking)
2. M/s. Britania Biscuit Co. Ltd. . . . . (Nadia—West Bengal)	Leather Footwear (New Article)
3. Shri M. Syed Mohamed . . . . . (Pudukkottai—T.N.)	Shoe Uppers (New Undertaking)
4. M/s. Farida Shoes Pvt. Ltd. . . . . (North Arrol—T.N.)	Leather Shoe Uppers, Leather Footwear (New Undertaking)
5. M/s. Gedore Tools India Pvt. Ltd., . . . . . (Maharashtra)	Cast Tools—Vices of different sizes (New Articles)

**Reduction in Capacity of Multinationals Manufacturing Items Reserved for Small Scale Industries**

6745. SHRI S. R. DAMANI: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government have reduced the capacity of production while fixing capacities in the C.O.B. licences with regard to the Multinational Companies which are manufacturing consumer goods which have been reserved for small scale sector during the course of the year;

(b) if so, the names of the companies and items thereof; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV):

(a) to (c). Following criteria are taken into account while fixing capacities in COB licences.

(i) Where production has been established and reported for a period of more than one year prior to the specified date, the capacity may be fixed at the level corresponding to the highest annual production, subject to a minimum economic capacity to be determined in respect of the concerned industries/products, whichever is higher. There may, however, be cases where it may not be practicable to fix a minimum economic capacity. In such cases, the capacity will be fixed provisionally on the basis of peak production in any of the previous years.

(ii) Where production had commenced within less than one year before the specified date or the undertaking has not yet gone into production, the capacity may be provisionally determined on the basis of the minimum economic capacity. But in cases where it is not practicable to fix the minimum economic capacity, the capacity may be provisionally determined on the basis of

the capacity claimed or the computation based on plant and equipment installed.

(iii) Where a minimum economic capacity or a provisional capacity is fixed, this capacity will have to be fixed finally on the basis of the highest annual production, after the unit has been in production for a period of three years.

The above criteria are uniformly applied in all cases including multinationals.

**Policy to Attract Investment and Foreign Entrepreneurial Talent**

6747. DR. VASANT KUMAR PANDIT: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government of India announced a policy to attract investment and foreign entrepreneurial talent from non-resident industrialists willing to set up industries in the country;

(b) if so, how many applications and for what type of industries have been received so far and out of which how many have been cleared;

(c) how many applications are pending for import of texturising and crimping machines; and

(d) what decision Government had taken in the above applications?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV):

(a) to (d). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

**Permit for Soda and Oil Used in Soap Manufacture**

6748. SHRI G. Y. KRISHNAN: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) what are the details regarding the big chunk of quotas and permits

for soda and oil used in soap manufacture and imported from foreign countries granted to the large houses;

(b) whether Government are aware that small scale soap industry is facing hardship as a result thereof;

(c) whether Government have received complaints in this regard and if so, the details thereof; and

(d) the steps Government propose to take to help the small scale soap industry?

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV):**

(a) None of the large industrial houses was recommended for grant of quota and licence for soda and oil for preparation of soap. In 1978, release orders were issued for about 10,000 tonnes of mutton tallow to DGTB registered users for the manufacture of fatty acids used in soap manufacture. At present, import of soda is under open general licence and import of oil is canalised through STC. Details of licences granted are published in Weekly Bulletins issued by the Chief Controller of Imports and Exports, copies of which are available in the Parliament Library.

(b) During the calendar year 1978, against an allocation of 20,158 tonnes of imported tallow/fatty acids, only 12,416 tonnes had been lifted. It would, therefore appear that small scale units are able to get their requirements of oil for soap manufacture. Soda ash is used in the manufacture of soap to a small extent. Due to scarcity of indigenous soda ash, however, some units did experience difficulties.

(c) Some complaints have been received in regard to supplies of soda ash and they are from units who are not eligible for supplies of indigenous soda ash according to the guidelines of the Department of Chemicals and Fertilizers. These guidelines state that indigenous soda is to be supplied on the basis of off-take of 1977.

(d) It has been decided to supply 18,000 tonnes of tallow/fatty acids to small scale soap industries during the year 1979 through State Governments. Keeping the 1978 performance in view it is considered that this quantity would be adequate to meet anticipated demand.

Government have recently issued guidelines to all manufacturers to supply soda ash to individual units based on off-take. Further, imports of soda ash are allowed under open General Licence and import duty has also been reduced.

#### **Percentage of Population engaged in Industry**

**6749. SHRI DURGA CHAND:** Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government have made any survey regarding the percentage of population engaged in industry in the country at present;

(b) if so, what is the percentage;

(c) what is the percentage of people engaged in industry in each state;

(d) whether Government have formulated any scheme to shift people from agriculture to non-agricultural occupations;

(e) if so, what are the details thereof; and

(f) whether the State Government and voluntary organisations are consulted in this regard; if so, what are the details and what is the response of the State Governments and voluntary agencies in this regard?

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV):**

(a) and (b). While comprehensive data

on employment in factories covered by the Factories Act, 1948 are available from year to year on the basis of Annual Survey of Industries no such data are, however, available in respect of non-factory manufacturing sector as a whole. The National Sample Survey Organisation in its 20th Round covering the period July 1974—June 1975 undertook a household enquiry of self employment in non-agricultural enterprises which *inter alia* included the non-factory manufacturing sector also. The sample number of non-household non-factory reporting units was, however, so small that no analysis of these data have been carried out. Recently in 1977 the Central Statistical Organisation had conducted an Economic Census of all establishments employing at least one hired worker on a fairly regular basis in the non-agricultural sector of the economy, including, *inter alia*, the manufacturing sector. The data collected in the course of the Census is under tabulation. In addition to the above, presently the National Sample Survey Organisation and the CSO are also conducting surveys on non-factory manufacturing sector. The surveys are in progress.

(c) Information on persons returned as workers for their main activity and classified into nine broad industrial categories as per 1971 Population Census is given in the statement laid on the Table of the House. [Placed in Library. See No. LT-4284/79].

(d) to (f). In pursuance of the policy of Government to promote the development of rural areas licences for new undertakings or for substantial expansions would not be given for industries in standard urban areas of metropolitan cities and industries within the municipal limits of cities with a population of 5 lakhs or more. The only exception would be in the case of sick units which cannot be revived except through expansion and diversification and in the case of uneconomic units which needed expansion or diversification to avoid sickness.

The District Industries Centre programme is a totally new effort in promoting rural industrialisation and taking industry to rural areas. Periodic review meetings are being held with the State Governments to clarify doubts remove impediments and generally to speed up the implementation of the programme.

#### Ex-Factory Price of Car

6750. SHRI DURGA CHAND: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

- (a) what is the ex-factory price of car of each make separately manufactured in the country;
- (b) what is the amount of excise duty and other taxes on car of each make separately;
- (c) what is the progress so far made in the manufacture of small car; and
- (d) by when the small car will come in the market?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI-MATI ABHA MAITI). (a) and (b). A statement is attached indicating the prices as reported by manufacturers.

(c) and (d). In comparison to the wide-range configuration of passenger cars manufactured in developed countries, the passenger cars manufactured in India are considered small cars. The objectives are to upgrade the Automobile Industry particularly in the interest of improving fuel efficiency and reliability for the end users. Government are presently considering various proposals, including the participation of the Public Sector for upgradation of the passenger car industry.

## Statement

Sl. No.	Name of the manufacturer	Make of Car	Ex-factory/ Net Dealer price of Car (Rs.)	Excise duty (Rs.)
1.	M/s. Hindustan Motors Ltd., Ut- tarpara (W.B.)	(a) Ambassador Mark-4 (Petrol)	30,362.00	7,590.00
		(b) Ambassador Mark- 4* (Diesel)	41,362.00	10,341.00
2.	M/s. Premier Automobiles Ltd., Bombay.	Premier	126,991.00	6,747.75
3.	M/s. Standard Motor Products of India Ltd., Madras.	Standard Gazel,	19,727.00 (As in Feb., 1979)	3,744.28
4.	M/s. Sunrise Auto Industries Ltd., Bangalore.	BADAL	15,500.00	3,100.00

NOTE: The actual price to be paid by the customer will include dealer's margin. It will also include Sales Tax, Octroi Duty, Transportation Charges, etc., which differ from State to State.

**Number of cars in the Ministry and  
Attached and Subordinate Offices**

6751. **SHRI DURGA CHAND:** Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) what is the number of cars of each make in the Ministry of industry, attached and subordinate offices and public undertakings under the Ministry, separately;

(b) whether there is any proposal to reduce the number of cars in the Ministry and other offices;

(c) if so, the details thereof; and

(d) what is the expenditure on maintenance of these cars during the last 3 years year-wise?

**THE MINISTER OF STATE IN  
THE MINISTRY OF INDUSTRY  
(SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV):**  
(a) to (d). The information is being collected and will be placed on the Table of the House.

**Nuclear Power Plant in Coastal  
Region of West Bengal**

6752. **PROF. SAMAR GUHA:** Will the Minister of ATOMIC ENERGY be pleased to state:

(a) whether the question of setting up a Nuclear Plant in the coastal region of West Bengal was under consideration of the earlier Government;

(b) whether the matter was discussed earlier with the representatives of the West Bengal Government and the Atomic Energy Commission several times; and

(c) if so, the latest position in regard to finalisation of the plan for setting up a Nuclear Power Plant in the coastal region of West Bengal?

**THE MINISTER OF STATE IN THE  
MINISTRY OF DEFENCE AND IN  
THE DEPARTMENT OF ATOMIC  
ENERGY, ELECTRONICS, SCIENCE  
AND TECHNOLOGY AND SPACE  
(PROF. SHER SINGH):** (a) No Sir.

(b) and (c). Yes Sir. The question of setting up a nuclear power plant in Eastern Region was raised during discussions held in November 1974 with the West Bengal State Planning Board. The Board was advised that a detailed study may be conducted to determine the most desirable and optimal mix of thermal hydel and nuclear power to cater to the demands of the Region in the context of the overall regional and national energy policy and to approach the Ministry of Energy in case the study revealed that a nuclear power station was economically viable in the Eastern Region.

**Supply of Uranium by USA for T.A.P.S.**

6753. PROF. SAMAR GUHA: Will the Minister of ATOMIC ENERGY be pleased to state:

(a) whether the issue of supply of uranium by USA for Tarapur Atomic Power Plant has been finalised;

(b) whether Government have received any communication from the Government of USA in this regard; and

(c) if so, facts thereabout?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE AND IN THE DEPARTMENTS OF ATOMIC ENERGY, ELECTRONICS, SCIENCE AND TECHNOLOGY AND SPACE (PROF. SHER SINGH): (a) One of the pending export licence applications for 16.8 tonnes of enriched uranium for the Tarapur Atomic Power Station has been cleared by the U.S. Nuclear Regulatory Commission on March 23, 1979

(b) and (c). The U.S. Authorities have informed Government of the recommendation of the Executive Branch of the U.S. Government to the U.S. Nuclear Regulatory Commission regarding the pending export licence application for 19.8 tonnes of enriched

uranium for the Tarapur Atomic Power Station. This application is presently under the consideration of the U.S. Nuclear Regulatory Commission.

**Production of Cement in Bokajan Factory, Assam .**

6754. SHRI BEDABRATA BARUA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) what is the total quota of cement allotted to Assam in one year;

(b) what is the total cement produced in the Bokajan Cement Factory in Assam;

(c) what is the full capacity of the Bokajan Factory; and

(d) what are the reasons for the Bokajan factory not producing upto full capacity?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV):

(a) The state of Assam was allotted 2.35 lakh tonne of cement during the year 1978.

(b) The production of the Bokajan Cement Factory was 1.23 lakh tonnes during 1978-79.

(c) The annual installed capacity of Bokajan Cement Factory is 2 lakh tonnes.

(d) The capacity utilisation at Bokajan was about 61.5 per cent during the year 1978-79 mainly due to constraints on limestone raising and transport.

**Central Assistance for Rural Roads in N.E. Region**

6755. SHRI AHMED HUSSAIN: Will the Minister of PLANNING be pleased to state:

(a) the quantum of Central assistance/loans/grants given by the Cen-

tre and allotted to each State each year during the last five years ending 31st March, 1979 and earmarked for 1979-80 for the purpose of providing Rural Roads/Rural Link Roads in the N.E. Region;

(b) whether any specific proposal request has been received from the Government of Assam under the minimum needs programme to assist in providing and repairing rural roads/link roads in Assam; and

(c) if so, the details therefor alongwith the action taken or proposed to be taken thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING (SHRI FAZLUR RAHMAN): (a) Central assistance for State Plan outlays is given in the shape of block loans and grants and is not linked to specific projects. The allocations earmarked for rural roads under the Minimum Needs Programme in the N.E. Region for 1974-1979 and proposed for 1979-80 are given in the Statement enclosed.

(b) No proposal has been received from the Government of Assam for extra assistance under the minimum needs programme.

(c) Does not arise.

#### Statement

##### *Allocations for Rural Roads under M.N.P. in the N.E.C. Region*

(Rs.lakhs)

State	1974-75	1975-76	1976-77	1977-78	1978-79	1979-80 (Provi- sional)
Assam . . . .	110	190	252	350	535	460
Manipur . . . .	50	80	88	100	130	200
Meghalaya . . . .	30	56	35	50	55	60
Nagaland . . . .	45	60	70	71	95	130
Tripura . . . .	40	40	50	75	130	180
Arunachal Pradesh . . . .	..	..	..	..	..	25
Mizoram . . . .	10	30	35	42	46	125

#### Change of Name of "Bombay" to "Mumbai"

6756. SHRI R. K. MHALGI: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Maharashtra Government have submitted a proposal to change the name of Bombay as Mumbai; and

(b) if so, when such proposal was received and decision taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL): (a) Yes, Sir.

(b) The proposal was received from the Government of Maharashtra in December, 1977. It is still under consideration.

सरकारी उपकरणों में प्रधार के लिये बच्चे की गई अनुरागिका

6757. श्री सचिव लाल लिखा :

श्री एम० ए० हुमायूं अलहाबाद :

क्षमा विज्ञान और ग्रीष्मोनिकी मंत्री यह बताने की छूपा करेंगे कि :

(क) उनके बंकालय के अतर्गत आने वाले सरकारी उपकरणों के नाम क्या हैं,

(ख) एकको के एककावार प्रधार ढाँचे का व्यूपा क्या है और यह तीन वर्षों में बर्चावार, एककावार कितनी अनुरागिक प्रधार पर बच्चे की गई,

(ग) यह तीन वर्षों में इन एकको द्वारा एककावार, बर्चावार विज्ञान किन दैनिकों को दिये गये

(घ) इन एकको का छोटे और मध्यम दर्जे के भावाग्नी दैनिकों के प्रति इस का व्यूपा क्या है, और

(ङ) इन एकको द्वारा एककावार आज तक की गई कार्यवाही का व्यूपा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में और परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रोनिक्स, विज्ञान तथा ग्रीष्मोनिकी और इंस्ट्रियल विज्ञानों में राज्य मंत्री (एम० ए० लैर लिह) (क) (१) नेशनल रिसर्च डिवेलपमेंट कार्पोरेशन आफ इंडिया (एन० आर०डी० सी०) नई दिल्ली, और

(२) सेन्ट्रल इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड (सी०ई० एल०), साहिकावाद (उ० प्र०) संस्थान बक्तव्य में दी गई है।

### विवरण

१. नेशनल रिसर्च डिवेलपमेंट कार्पोरेशन आफ इंडिया (एन० आर०डी० सी०) :

भाग (क) —एन० आर०डी० सी० के प्रधार एक में एक शैक्षणिक संपर्क और यूचना प्रविकारी, एक यूचना और प्रधार प्रशिकारी, एक उच्च श्रेणी सिपिक और एक कनिष्ठ आशुलिपिक शामिल है। विगत तीन वर्षों के दौरान एन० आर०डी० सी० के प्रधार पर किया गया व्यय नीचे दिया गया है—

1975-76 . . . 1,30,138/-००

1976-77 . . . 1,65,210/-००

1977-78 . . . 1,75,582/-००

भाग (ग) विगत तीन वर्षों के दौरान एन० आर०डी० सी० द्वारा निरूपित विज्ञानों के लिए प्रयुक्त दैनिक समाचार वस्तों की सुधी अनुकूल्य-१ में दी गई है।

भाग (च) और (इ) जहाँ कही भी सम्बन्ध होता है, विज्ञान छोटे और मध्यम दर्जे के भारतीय भावाग्नी के दैनिकों को लिए जाते हैं और यक्षात्तर्पण ऐसे समाचार पत्रों की सेवाओं का उपयोग किया जाता है।

२. सेन्ट्रल इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड सी० ई० एल० :

भाग (क) सी० ई० एल० नई कम्पनी है जो कि अपनी निर्माण प्रबन्धन में है और सी० ई० एल० के लिये प्रबन्ध कर्प से इस प्रकार की कोई प्रधार संस्थान नहीं है। विपणन दृप भावी उत्पादों के बारे में जानकारी प्रदान करने और उन्हे लोकप्रिय बनाने के लिए विज्ञान देता है। विगत तीन वर्षों के दौरान किया गया वर्ष वार व्यय नीचे दिया गया है—

		इ
1975-76	.	30,386
1976-77	.	39,710
1977-78	.	33,462

भाग (ग) —विगत तीन वर्षों के दौरान विए गए विज्ञान अधिकारी उन तकनीकी परिकार्यों और प्रकाशनों तक ही सीमित वे विनामा इलेक्ट्रोनिक्स ट्रेन में परिचालन किया जाता है यथा

१ इलेक्ट्रोनिक्स कार य

२ इलेक्ट्रोनिक्स रिम्यू

३ जनेल आफ इन्स्टीट्यूशन आफ इलेक्ट्रोनिक्स एड टेलिकम्युनिकेशन इंजीनियर्स

४ इलेक्ट्रोनिक्स ट्रेने

५ माइक्रो ट्रेन, और

६. साइंस रिपोर्टर

भाग (घ) और (इ) —कम्पनी मुख्यतः परिकृत इलेक्ट्रोनिक संचाटको और प्रधारितो का निर्माण करती है और इसके बारे में विज्ञान इलेक्ट्रोनिकी से सम्बद्ध तकनीकी परिकार्यों और प्रधारितों में स्वीकृत रखने वाले उपभोक्ताओं, नामतः इलेक्ट्रोनिकी उद्योगों, अनुसंधान और विकास संगठनों, आदि तक पहुच करती है। किलहाल इस प्रकार के उत्पादों के लिए लघु और मध्यम दर्जे के विभिन्न भाष्यों भावाग्नी के दैनिकों को विज्ञान देने की बहुत अधिक गुजारात नहीं है।

मेहमान विरह दिल्ली, बाललेला भाऊ इंदिया द्वारा निमुक्त वित्तापर्णी के लिए प्रयोग वेताए द्वारा वारे विविध स्थानों पर्यावरण की तृप्ति

1. इंडियन एक्सप्रेस	नई दिल्ली
2. इंडियन एक्सप्रेस	बम्बई/महाराष्ट्रावाद
3. इंडियन एक्सप्रेस	दिल्ली संस्करण, मद्रास
4. अमृत बाजार पत्रिका	कलकत्ता/इसाहाबाद
5. ट्रिप्प्ला	बंडीगढ़
6. फाइनेंशियल एक्सप्रेस	दिल्ली/बम्बई
7. हिन्दू	मद्रास
8. इंडियन टाइम्स	बम्बई/दिल्ली
9. देशानन्द प्रोग्रामिक्स	सिक्किमदराबाद
10. इंडियनहैथल्ड	हैदराबाद
11. नवभारत टाइम्स (हिन्दी)	दिल्ली/बम्बई
12. वि भेत्र	मद्रास
13. हिन्दुस्तान (हिन्दी)	नई दिल्ली
14. नवजयोति (हिन्दी)	जयपुर/शजहार
15. दाहम्स भाऊ इंदिया	दिल्ली/बम्बई/महाराष्ट्रावाद
16. विजेन्स स्टैंडर्ड	कलकत्ता
17. स्टेट्सर्न	दिल्ली/कलकत्ता
18. इंजीनियरिंग टाइम्स	कलकत्ता
19. भासाम ट्रिप्प्ला	पौहाटी
20. फी फ्रैंस बनरल	बम्बई
21. नागपुर टाइम्स	नागपुर
22. इंडियन नेशन	पटना
23. रेनिक भाऊ (हिन्दी)	वाराणसी/कानपुर
24. राजस्थान पत्रिका	जयपुर
25. भानुद बाजार पत्रिका	कलकत्ता
26. इन्डियायर्स न्यूज़	नई दिल्ली
27. प्रेट्रिवट	नई दिल्ली
28. दीनमनी (तमिल)	मद्रास/मुम्बई
29. भानुष्ठ प्रभा (तेलुगु)	विजयवाड़ा/बगलौर/हैदराबाद
30. भातुभूमि (मलयालम)	कालीकट/कोचीन
31. रोजाना भाजीत (पंजाबी)	बंगलूर
32. रेनिक जागरण (हिन्दी)	कानपुर/गोरखपुर
33. सर्वे स्टैंडर्ड	नई दिल्ली

Manufacture of Paper by Sehgal Paper Ltd.

6758. SHRI JYOTIRMOY BOSU: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Sehgal Papers Ltd., a new company engaged in the manufacture of various kinds of paper,

has entered the capital market on February 5, 1979;

(b) if so, what are the facts thereof;

(c) whether this company has been allowed to enter into technical and financial collaboration agreements with two U.S. multi-nationals;

(d) if so, what are the terms of agreements; and

(e) the reasons why foreign collaboration is being allowed in the paper industry?

**THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI GEORGE FERNANDES):** (a) and (b). Yes, Sir. M/s. Sehgal Papers Ltd. were granted consent on 13-7-77 under the Capital Issues Control Act 1947 for the issue of capital of Rs. 565 lakhs in the form of equity shares of Rs. 10 each. Out of this, shares worth Rs. 639 lakhs were to be offered to the public by prospectus and the balance of Rs. 226 lakhs were to be issued to the promoters, Directors of the company, their friends and relatives. The company entered the capital market on 5-2-1979 with a public offer of shares worth Rs. 339 lakhs and the issue was closed on 12th February, 1979.

(c) to (e). M/s. Sehgal Papers have been permitted to enter into a technical collaboration with an American firm for the manufacture of Carbonless Copying Paper. The approval of collaboration is for a period of five years and involved the payment of a technical fee of US \$400,000 and royalty at the rate of 3 per cent of net ex-factory sale price on internal sale and 5 per cent of net ex-factory sale price on exports. Foreign technical collaboration is permissible on merits for the manufacture of special grades of paper.

**Subsidy Grant to Jhalawar District of Rajasthan**

6759. **SHRI CHATURBHUJ:** Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government propose to formulate a definite short term plan for bringing about faster economic development of the most backward district of Jhalawar in Rajasthan without involving heavy capital outlay;

(b) whether the Central Government propose to grant all facilities including loans and subsidies for such a plan and would advise the State Government to do the same; and

(c) if so, the details thereof?

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV):**

(a) There is no proposal with the Ministry of Industry to formulate any separate plan for the faster economic development of Jhalawar district in Rajasthan. However, as part of a national scheme to set up District Industries Centres to provide all service and support required by the small and village entrepreneurs under one roof, one such DIC has been set up at Jhalawar. The Centre has so far identified 334 entrepreneurs and have assisted 148 artisans/small scale units.

(b) and (c). Jhalawar District has already been identified as an industrially backward district making it eligible for the following incentives for eligible entrepreneurs, who desire to set up industries there:

(i) concessional finance facilities by All India Term Lending institutions

(ii) tax concessions

(iii) hire purchase of machinery of small scale units

(iv) consultancy for technical service

(v) interest subsidy

(vi) special facilities for import of raw-materials.

This scheme is operated in association with State Government.

**Production of Controlled cloth for the  
Poor**

6760. SHRI K. S. VEERABHADRAPPĀ: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) what are the details regarding the quantity and value of controlled cloth for the poor produced in the Mills controlled by the National Textile Corporation during the last two years; and

(b) the reasons for the shortfall in the production of cloth during the current year and what measures Government have taken to improve the situation?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV):

(a) Production and value of controlled cloth produced in mills under the management of National Textile Corporation is as under:—

Year	Quantity (Million Sq. Metres)	Value (Rs. in Crores)
(1)	(2)	(3)
1977-78 . . .	64.02	11.84*
1978-79 . . .	204.00	37.74*

\*These are calculated at the ex-mill price at consumer level.

(b) There has been no short fall in production in the current year.

**News Item "Tarapur Killing Softly"**

6761. SHRI VASANT SATHE: Will the Minister of ATOMIC ENERGY be pleased to state:

(a) whether attention of Government has been drawn to the exclusive investigative story on the total

criminality involved in all aspects of Tarapur Atomic Plant appearing in "This Fortnight" news magazine dated March, 8—March 21, 1979 under the Caption "Tarapur Killing softly";

(b) if so, the reaction of Government to the various observations of serious nature, observation-wise made therein; and

(c) the details regarding facts of the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE AND IN THE DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY, ELECTRONICS, SCIENCE AND TECHNOLOGY AND SPACE (PROF. SHER SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) and (c). The main allegations made in the article of dangerous over exposure to personnel at Tarapur is incorrect. While this reactor built on a turn-key basis and commissioned in 1969, has given rise to problems like other reactors of this design and vintage, these problems have been successfully tackled and the reactor has been operated in complete consonance with international safety regulations. There is an integrated system of comprehensive radiation protection for the workers at Tarapur which is in line with the accepted international standards and it is as a part of this integrated system that workers from outside Tarapur have been drafted for occasional jobs in Tarapur. However, all appropriate records of radiation exposure in respect of these workers including casual workers have been maintained and there has not been even a single case of radiation sickness.

**Functioning of Artificial Limbs Manufacturing Corporation**

6762. SHRI P. RAJAGOPALA NAIDU: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether artificial limbs manufacturing Corporation of India, Kanpur is functioning; and

(b) the work done by it till now?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) Yes, Sir.

(b) The Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India, Kanpur was for the setting up of a modern The main objective of the company was for the setting up of a modern plant for the manufacture of a wide range of Orthotics, Prosthetics and Rehabilitation Aids.

With the commissioning of ALIMCO, a wide range of Artificial Limbs etc., have been introduced into the Indian Market for the first time.

The production and sales of the Corporation has so far been as follows:-

	Production	Sales
(Figures in Rupees lakhs)		
(i) 1976-77 (six months operation)	13.58	4.98
(ii) 1977-78	40.98	15.36
(iii) 1978-79 (upto Jan. 1979)	37.93	16.97

Considering that the nature of the products is such that these cannot be brought and fitted by the patient himself ALIMCO has undertaken to establish a chain of limb fitting centres all over the country in collaboration with the respective State Governments. At present five Regional Limb Fitting Centres and 12 Peripheral Limb Fitting Centres are functioning in our country.

**Demand for Democratic set up in Andaman and Nicobar Islands**

6763. SHRI MANORANJAN BHAKTA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government of India are aware of continuous demand by the people of Andaman and Nicobar Islands for providing them demo-

cratic set up in the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands on the pattern of Arunachal Pradesh and whether any agitation was launched in the territory

(b) if so, details thereof;

(c) whether Government have agreed to have a democratic set up there in the near future; if so, when; and

(d) what shall be the pattern of Government in the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands in the new system?

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL):**

(a) to (d). A demand for providing democratic set up in the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands has been raised both in the Parliament and outside. Meetings and processions in support of these demands were organised during the month of February, 1979. The Government have decided to constitute a Pradesh Council in these Islands and to appoint 3 Counsellors from among the members of the Council, whom the Administrator may consult on any matter. The pattern is similar to the one that obtained in Arunachal Pradesh before a Legislative Assembly was constituted in that Union Territory. The details of the proposal were announced in the Lok Sabha by the Minister of Home Affairs on 6.4.1979 during his reply to the debate on the demands for grants of the Ministry of Home Affairs. A Regulation to give effect to this decision will be promulgated under article 240 of the Constitution.

**Industrially backward Taluks in Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Karnataka**

6764. SHRI K. LAKKAPPA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government have received any proposals from Tamil

Nadu, Andhra Pradesh and Karnataka to declare specific taluks as industrially backward, instead of considering entire districts as industrially backward so that the objective of spreading industries could be better achieved; and

(b) if so, whether those proposals have been agreed to and grants/subsidies have been given for new industries to be set up in these taluks?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) Yes, Sir.

(b) The proposals were examined in consultation with the Planning Commission. The schemes of backward area development and the selection of districts/areas, both for concessional finance and capital investment subsidy were formulated and finalised in accordance with the norm laid down by the NDC Committee and in consultation with the State Governments concerned. As the proposals received from the State Governments of Andhra Pradesh, Tamil Nadu and Karnataka were in respect of districts/areas which had not been selected earlier under accepted identified norms, it has not been possible to accede to their request.

Government have recently constituted a National Committee on Backward Areas under the Chairmanship of Shri B. Shivaraman former Member, Planning Commission to examine the validity of the various concepts of backwardness underlying the definitions in use for present policy purposes and recommend the criteria by which backward areas should be identified.

The Committee is expected to submit its Final Report by 31st December 1979.

A view on the modification of the present subsidy scheme would be taken after the recommendations of this Committee become available.

### Issue of Licences for Cement Industries

6765. SHRI K. LAKKAPPA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) how many letters of intent and Industrial licences were issued for expansion of or starting new cement projects from 1974-75 upto March, 1977 and for what capacity; and

(b) how many letters of intent and Industrial licences were issued since April, 1977 and for what capacity?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) Seven Letters of Intent and eleven Industrial Licences for a total capacity of 84.60 lakh tonnes were issued from 1st April, 1974 upto 31st March, 1977.

(b) Thirty-five letters of intent and seven industrial licences for a total capacity of 150.50 lakh tonnes were issued from 1st April, 1977 upto the 7th April, 1979.

### Capital Cost and Number of Employees of mini Cement Plants

6766. SHRI K. LAKKAPPA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) what is the capital cost per tonne of a mini cement plant as compared with that of a bigger plant; and

(b) what is the number of persons employed for the same unit of investment between mini cement plants and bigger cement plants?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) According to the Cement Research Institute, the fixed capital cost of a mini cement plant

based on vertical shaft kiln technology with a capacity of 100 tonnes per day would be about Rs. 420 per tonne of installed annual capacity as against the standard cost of Rs. 650 per tonne for a larger sized cement plant with a capacity of 1,200 tonnes per day.

(b) The estimated employment potential in different sizes of cement plants is given below:-

Size of Plants (tonnes per day)	Manpower per tonne of cement
Up to 100 . . .	4-4.55
101-300 . . .	1-4.5
301-1,000 . . .	0.29-2.32
above 1,000 . . .	0.18-2.26

**Schemes for utilisation of Indian Scientists Trained Abroad**

6767. PROF. P. G. MAVLANKAR:  
SHRI CHITTA BASU:

Will the Minister of SCIENCE AND TECHNOLOGY be pleased to state:

(a) whether Government have one or more schemes for utilising the talents of young Indian Scientists who have had an experience of training and laboratory work abroad for some years;

(b) if so, broad details thereof;

(c) how are the said young scientists attracted, employed and absorbed in various departments/laboratories in the country; and

(d) whether Government's steps in this regard so far have been found adequate and helpful, and if not, why not?

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE AND IN THE DEPARTMENTS OF ATOMIC ENERGY, ELECTRONICS, SCIENCE AND TECHNOLOGY AND SPACE (PROF. SHER SINGH):** (a) Yes, Sir.

(b) and (c). Measures undertaken for utilising the talents of young Indian Scientists trained abroad and to attract and employ them in the country are as under:

(i) A special section titled "Indians Abroad" section of the National Register is maintained for enrolment of Indian Scientists and Technologists abroad; and for the circulation of their particulars, in the form of classified directors, to all Ministries/Departments of the Government of India, State Governments, Union and State Public Service Commissions, Public Sector Industries and large private sector establishments. Particulars of such personnel are also published in the monthly "Technical Manpower" Bulletin (CSIR), which is distributed free to about 2,500 organisations all over India.

(ii) The Union Public Service Commission and some of the State Public Service Commissions have agreed to treat scientific and technical personnel, whose particulars are in the Indians Abroad section of the National Register, as 'Personal Contact' candidates for posts advertised by them.

(iii) The Scientists' Pool operated by CSIR, provides temporary placement for well-qualified Indian Scientific and Technical personnel who return from abroad without an assured job.

(iv) Supernumerary posts can be created in approved scientific institutions, to which temporary appointments can be made quickly from

among the scientists working and studying abroad.

(v) A 'Package Scheme' has been approved to attract Indian Scientists working in production units abroad to come back and start their own industries in this country, particularly in spheres where they may have acquired skills in production technology.

(vi) CSIR have introduced a scheme for appointment of Research Associates' or 'Visiting Scientists' under which Indian Scientists, etc., visiting India for a short period, can be offered such appointments in CSIR Organisations, in cases where their background fits the requirements of the organisation.

(vii) The University Grants Commission has introduced a scheme under which Indian scholars abroad can be offered shortterm appointment in Indian Universities during their sabbatical leave.

(viii) A scheme for utilisation of talented Indian Scientists and technologists settled abroad, for the development programme of the country was introduce by the Department of Science and Technology.

(d) The steps taken by the Government (as listed above) are considered adequate and have been helpful in placement of many trained persons. There has been a limitation in terms of adequate (appropriate and satisfying) employment opportunities to absorb the large number of Indian Scientists who are produced by our educational system as well as those returning from abroad; the best amongst the later have to be persuaded to return to work in India by their friends in the scientific community already working in India with some degree of success and satisfaction.

#### Steps taken to Improve Police-Community Relations

6768. PROF. P. G. MAVALANKAR: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government take any concrete and continuous steps at improving the Police-community relations in the country;

(b) if so, what are these and how are these productive;

(c) whether any studies cum research take place in this regard; and

(d) if so, broad outline thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL): (a) and (b). From time to time State Governments have been issuing instructions to its district and lower police officials in this regard. The subejct have been given more and more importance in the training programmes for the police officials in most of the states. This subject also forms a part under item 11 of the Terms of Reference given to National Police Commission who will deal with this item in great depth and detail while forwarding their report. The said Term of Reference under NPC reads as follows:

"Examine the manner and extent to which police can enlist ready and willing co-operation of the public in the discharge of their social defence and law enforcement duties and suggest measures regarding the institutional arrangements to secure such co-operation and measure for the growth of healthy and friendly public-police relationship."

(c) and (d). Bureau of Police Research and Development had undertaken a study in 1973 on the subject "Reluctance of the Public to Aid the Police in the Detection of Crime and

Crime Reporting at Police Stations". They have also another study in hand entitled "Image of the Police in India". Parts of this subject are being covered in these studies undertaken by the BPR&D.

सीमेंट के उत्पादन में बढ़ करने के लिए आरी किये गए लाइसेंस

6769. श्री अर्पणसिंह भाई पटेल : क्या उच्चोग मर्ती यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) सीमेंट का उत्पादन बढ़ाने के लिए अब तक कितने लाइसेंस दिये गये हैं तथा कितने लाख टन की कमता के लिए लाइसेंस दिये गये हैं ;

(ब) इस समय सीमेंट उत्पादन की कुल अधिकारित कमता कितनी है तथा 1979 और 1980 में इस कमता में कितनी वृद्धि होगी ;

(ग) इस समय कितने लाख टन की कमता के लिए आवश्यक पत्र दिये गये हैं तथा कितने लाख टन सीमेंट के उत्पादन के लिए आवेदन पत्रों की जांच की जा रही है ;

(घ) सीमेंट के मामले में देश कब तक आत्मनिर्भर हो जायेगा ; और

(ङ) इस समय देश में कुल कितने टन सीमेंट की आवश्यकता है तथा देश में कितने टन सीमेंट का उत्पादन होता है तथा इसमें से कितनी सीमेंट का आयात किया जाता है ?

उच्चोग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद शास्त्री) : (क) और (ग). 1 अप्रैल, 1977 से लेकर 31 मार्च, 1979 की अवधि में 24.73 लाख मी०ट० की कमता के लिये 7 अधिकारिक लाइसेंस तथा 115.47 लाख मी०ट० की कमता के लिये 33 आवश्यक जारी किये गये हैं। इस समय कुल मिलाकर 116.42 लाख मी०ट० की कमता के लिये अधिकारिक लाइसेंसों आवश्यकों के 29 आवेदनों की जांच की जा रही है।

(ब) इस समय सीमेंट उच्चोग की कुल अधिकारित कमता 230 लाख मी०ट० है। 1979-80 तथा 1980-81 में कमता : 46.5 लाख मी०ट० टन तथा 21.6 लाख मी०ट० टन की आनुमानित अनियन्त्रित कमता उत्पन्न हो जाने की आशा है।

(घ) देश के लगभग 3 बड़ों में सीमेंट के मामले में आत्मनिर्भर हो जाने की आशा है।

(ङ) देश की सीमेंट की विद्यमान आनुमानित संग्रह 240 लाख मी०ट० है। वर्ष 1978-79 की अवधि में सीमेंट का उत्पादन लगभग 196 लाख मी०ट० है तथा अप्रैल, 1978, से मार्च, 1979 (19 मार्च, 1979 तक) में 15.5 लाख मी०ट० सीमेंट का आयात किया गया है।

#### Request from West Bengal Jute Industry

6770. SHRI BALASAHEB VIKHE PATIL : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether he has received recently any request by the West Bengal Government for paying more attention to the R and D efforts in the Jute Industry; and

(b) if so, what are the suggestions of the State Government in this regard and what is the reaction of the Central Government to those suggestions?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

#### Big Houses taking smaller shapes

6772. SHRI SURENDRA BIKRAM : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) based on a news item published in Economic Times, New Delhi, dated March 10, 1979, is it a fact that big industrial houses of the country are splitting and taking shapes of several smaller houses as a reaction to "Janata Government's" declaration to disallow concentration of economic power in few hands of the country;

(b) if so, which major houses have so far splitted into several groups and how; and

(c) whether such splitting of big houses will lead to any problems in

managing these industrial houses or normalacy will prevail and whether the Government is keeping an eye on such activities by big houses?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) : (a) to (c). In the news item appearing in the Economic Times, New Delhi dated 10th March, 1979, reference has been made to the splitting up of the industrial houses of Jaipurias, Mafatlal and Rohitt. In the context of the MRTP Act, information about any splitting up of a large industrial house is likely to come to the notice of the Department of Company Affairs only when an application is made by an undertaking which has already registered under section 26 of the MRTP Act as one to which section 20(a) of the Act is applicable, for cancellation of its registration on the grounds of a split up of the concerned house and consequent inapplicability of the provisions of Section 20(a) of the undertaking. No such indication is seen in the applications for cancellation which

have been received in the Department of Company Affairs in recent months.

#### स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन

6773. श्री लालकी भाई : क्या यह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) देश में गत तीन वर्षों में राज्यवाहार, कितने कितने स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन भंजूर की गई ; और

(ख) आखंक वर्ष में कितने व्यक्तियों को पेंशन देने का विवरण है ?

गृह मंत्रालय ने राज्य भंजी (श्री अग्रिम लाल मच्छर) : (क) अपेक्षित सूचना का विवरण संलग्न है ।

(ख) यह सूचना देना संभव नहीं है क्योंकि आखंक वर्ष के दौरान अपेक्षी स्वीकृतियों आवेदकों द्वारा स्वीकार्य वस्ताविकी साध्य प्रस्तुत करने पर आधारित होती जिन के मामलों को अपेक्षी संतिम रूप नहीं दिया गया है तथा/अथवा जिन के मामलों में राज्य सरकारों की विशिष्ट सिफारिशें प्राप्त नहीं हुई हैं ।

#### विवरण

पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1976-77, 1977-78 तथा 1978-79 के दौरान उन व्यक्तियों की संख्या जिनको पेंशन भंजूर की गई है, का विवरण (राज्यवाहार) ।

राज्य	1976-77	1977-78	1978-79
अन्धमान और निकोबार	—	—	—
आण्ड्र प्रदेश	38	1007	723
असम प्रदेश	—	—	—
आसम	8	11	35
बिहार	49	129	670
चंडीगढ़	—	—	2
दिल्ली	1	3	20
जौनपुर	1	28	30
गुजरात	1	18	184
हरियाणा	—	2	7

राज्य	1976-77	1977-78	1978-79
हिमाचल प्रदेश	—	2	13
जम्मू व काश्मीर	—	2	45
केरल	31	56	205
कर्नाटक	6	99	290
मध्य प्रदेश	8	18	35
महाराष्ट्र	23	202	587
मणिपुर	—	—	1
मेघालय	—	—	—
मिश्रोरम	—	—	—
नागालैंड	—	—	—
उड़ीसा	11	6	22
पाहिंजेरी	—	4	21
पंजाब	13	16	120
राजस्थान	—	7	12
समिलनाडू	22	30	83
त्रिपुरा	1	2	15
उत्तर प्रदेश	8	34	245
पश्चिम बंगाल	181	370	870
कुल स्वतंत्रता सेनानी	402	2046	4235
भूतपूर्व धाराद हिम्म कोष के जबान	297	171	1347
कुल जोड़	699	2217	5609

**Setting up of H.M.T. Unit in Hoshiarpur**

**6774. CHOWDHRY BALBIR SINGH:** Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether there is an outstanding demand since long by the masses of Punjab that a H.M.T. Unit be installed at the backward district of Hoshiarpur (Punjab);

(b) if so, the action taken by Government so far;

(c) keeping in view the cheap labour and other facilities there, whether Government will open a HMT Unit there; and

(d) if so, when and if not, the reasons therefor?

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI):** (a) to (d). It is not possible for HMT to set up units in several backward districts of the country. However within the constraints of finances and the production lines of HMT, HMT have to the extent possible been developing linked production lines in several parts of the country. In so far as Punjab is concerned, HMT is assisting towards the establishment of a watch assembly unit at a location decided in consultation with the Government of Punjab. This location is at Sahibzada Ajit Singh Nagar near Chandigarh.

हिन्दी भाषीपरिचय और स्टेनोग्राफरों की भर्ती

6775. श्री रामानन्द तिवारी : क्या मूह भंडी यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजभाषा विभाग को पता है कि देश में हिन्दी टाइपिस्टों और स्टेनोग्राफरों की बहुत कमी है;

(ब) क्या केन्द्रीय हिन्दी समिति हिन्दी स्टेनोग्राफरों तथा हिन्दी टाइपिस्टों की सीधी भर्ती करने के लिये सहमत है परन्तु मंत्रालय ने अभी तक कोई शोधपारिक आदेश नहीं दिये हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार हिन्दी टाइपिस्ट और हिन्दी स्टेनोग्राफर सीधे भर्ती करना काहती है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो सीधी भर्ती करने में क्या कठिनाइयां हैं?

मूह मंत्रालय में राज्य भंडी (वी बैंकिंग लाल मकान) : (क) से (घ). देश में हिन्दी टाइपिस्टों और शास्त्रियों की कमी को बारे में सरकार को कोई निर्विचल जानकारी नहीं है। वहां तक केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों में स्टेनोग्राफरों और टाइपिस्टों का प्रश्न है, हिन्दी टाइपिस्टों और हिन्दी स्टेनोग्राफरों के कोई अलग पद नहीं है और प्रत्याशी हिन्दी या अंग्रेजी किसी भी माध्यम से परीका देकर सेवा में द्या सकते हैं। भर्ती के बाद स्टेनोग्राफरों को दूसरी भाषा का शास्त्रियिका प्रशिक्षण देने की अवस्था है।

केन्द्रीय हिन्दी समिति ने हिन्दी शास्त्रियों की भर्ती के लिए केवल हिन्दी शास्त्रियों और टाइपिंग की परीका देने जाने की संस्तुति की थी और यह भी कहा था कि जो उच्चीविद्वार इसके अतिरिक्त अंग्रेजी शास्त्रियों और टाइपिंग का ज्ञान रखते हों उन्हें प्रायोगिकता थी जाए। इस पर धारा विचार किया जा रहा है।

भोजपुर में गता (दफ्तरी) कारबाना स्वतंत्रता विभाग बाजार

6776. श्री रामानन्द तिवारी : क्या उद्योग भंडी यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के भोजपुर जिले में कुटीर तथा लघु उद्योगों का विकास करने के लिए सरकार ने कब तक क्या कार्यालयी की है;

(ख) क्या यह सच है कि भोजपुर जिले में जन के पुराल का गता (दफ्तरी) बताने का कारबाना स्थापित किया जा सकता है; और

430 LS-8

(ग) यदि हां, तो सरकार इह पर कौन से कदम उठाने जा रही है विस्तृत प्रवित्रम् कार्य प्रारम्भ हो?

उद्योग मंत्रालय में राज्य भंडी (वी बैंकिंग लाल मकान) : (क) बिहार राज्य के भोजपुर जिले को 1977-78 तक केन्द्र द्वारा प्रायोगिक शास्त्रिय उद्योग परियोजना कार्यक्रम की योजना में सामिल कर लिया गया था। कुटीर तथा लघु उद्योगों के विकास को व्यापक रूप से प्रोत्साहित देने सम्बन्धी सरकार की बोर्ड के अनुरुप में भोजपुर जिले को 1978-79 में केन्द्र द्वारा प्रायोगिक विला उद्योग केन्द्रों की ओर अधिक व्यापक योजना के अन्तर्गत लाया गया है।

(घ) और (ग). कैंक जेल में धान की भूसी उपलब्ध है, यह भर्ती धान की भूसी से काढ़ बोढ़ बनाने के लिए एक कारबाने की स्थापना अवधारिक हो सकती है। विला उद्योग केन्द्र भोजपुर द्वारा विस्तृत कार्यालयी योजनाएं तैयार की जा रही हैं तथा इन योजनाओं को अंतिम रूप दिये जाने के पश्चात ही स्वित स्पष्ट हो सकती है।

वैज्ञानिक अनुसंधान-संस्था पर वर्च की गई घवराति

6777. श्री रामानन्द तिवारी : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी भंडी यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दस वर्षों के दौरान, वर्षभार, वैज्ञानिक अनुसंधान-कार्य पर कितनी राशि खर्च की गई है; और

(ख) क्या सरकार सन्तुष्ट है कि यह अनुराति राष्ट्रीय विकास के कार्य के लिये उचित तरीके से उद्योग में लाई गई है?

राज्य मंत्रालय में और परमाणु कला, इलेक्ट्रोनिक्स, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक विभागों में राज्य भंडी (ओरो और लिंग). (क) 1977-78 को समाप्त वर्षों के दौरान वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य पर अवय की गई राशि नीच दी गई है:—

वर्ष	अवय	(करोड़ रुपयों में)
1968-69	.	.
1969-70	.	107.56
1970-71	.	116.62
1971-72	.	139.64
1972-73	.	151.64
1973-74	.	194.67
1974-75	.	216.01
1975-76	.	291.60
1976-77	.	356.69
1977-78	.	402.25
		460.00
		(अनुमान)

उपरोक्त व्यवस्था अनुसार 8 प्रमुख वैज्ञानिक धर्मिकरणों द्वारा, परमाणु ऊर्जा विभाग, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक अनुसंधान परिषद, रक्त अनुसंधान और विकास संगठन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, विभाग और प्रौद्योगिक विभाग, अन्तर्राष्ट्रीय विभाग, इंजीनियरिंग विभाग और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् द्वारा किया गया था। इन धर्मिकरणों को आर्द्ध-व्यावसायिक और प्रौद्योगिक संबद्ध परियोग्यताओं को कामगिरीत करने के साथ-साथ अनुसंधान और विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आगे बढ़ते समय-बदू कार्यक्रमों का नियावेदन करने के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है। सही शीर्षों के अनुसार, जिनके अन्तर्गत व्यवस्था की विभिन्न घटें सामिल की गई हैं, विए गए आकारों में कुछ विभिन्न हो सकती हैं।

(ब) जी, हा।

### Short fall in Plan Outlay

6778 SHRI K. T. KOSALRAM: Will the Minister of PLANNING be pleased to state:

(a) the details of sectors in which a shortfall of Rs. 230 crores has occurred in the Plan Outlay for 1977-78, as pointed out by the National Council of Applied Economic Research in its recent study; and

(b) steps taken to remove the deficiencies so that there is full utilisation of the Plan Outlay in future?

#### Statement

#### Budgetary support for Central plan by Ministries/Departments

(Rs. crores)

S. No.	Ministry/Department	Budget Estimates 1977-78	Revised Estimates 1977-78
		3	4
1			
1	Agriculture . . . . .	198.26	159.92
2	Food . . . . .	45.76	40.53
3	Rural Development . . . . .	168.47	198.44
4	Agricultural Research & Education . . . . .	36.74	38.60
5	Irrigation . . . . .	24.16	21.82
6	Commerce . . . . .	8.14	7.69

“भरतीय धर्मिकरणों के हिताव में कुल व्यवस्था अनुमति 85% आता है।

1	2	3	4
7	Civil Supplies & Cooperation	31.96	29.58
8	Communication (excluding P&T)	20.57	20.39
9	Posts & Telegraphs	42.35	25.71
10	Education	85.67	82.01
11	Social Welfare	12.87	12.84
12	Power	130.58	113.91
13	Coal	226.66	240.05
14	Economic Affairs	119.91	135.24
15	Revenue	0.62	0.20
16	Health	83.14	96.02
17	Family Welfare	98.61	90.38
18	Home Affairs	24.88	24.79
19	Personnel & Administrative Reforms	0.20	0.20
20	Industrial Development	232.32	226.72
21	Heavy Industry	56.81	61.10
22	Information & Broadcasting	24.62	21.07
23	Labour	4.65	3.64
24	Petroleum, Chemicals & Fertilizers	713.30	590.08
25	Planning	7.39	6.10
26	Shipping & Transport	301.73	297.58
27	Steel	510.85	453.04
28	Mines	79.63	84.05
29	Supply	0.60	0.28
30	Rehabilitation	21.23	25.64
31	Tourism & Civil Aviation	36.04	30.77
32	Works & Housing	175.14	110.91
33	Atomic Energy	129.79	121.55
34	Culture	5.97	4.45
35	Electronics	10.64	10.49
36	Space	30.20	28.65
37	Science & Technology	35.00	33.69
38	Railways	302.15	300.10
<b>Total</b>		<b>3,977.61</b>	<b>3,748.17</b>

### Scheme to produce Salt

6779. SHRI K. T. KOSALRAM : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether any scheme has been formulated to utilise coolant water from Kalpakkam Atomic Energy Plant for producing salt, instead of letting the water into the sea and if so, the salient features of the scheme;

(b) whether it is being implemented now and if so, the details of the same; and

(c) if not, the reasons for the delay in implementing it?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI): (a) to (c). The Government of Tamil Nadu have formulated a scheme for diverting 50 cusecs of discharged coolant water from the Atomic Power Plant at Kalpakkam to the Buckingham Canal in order to ensure adequate availability of brine in the Canal for salt production. The scheme will be considered by the Central Advisory Board for Salt at its next meeting for grant of assistance out of the salt cess proceeds.

### Setting up of a Cement Factory at Koraput, Orissa

6780. SHRI BAIRAGI JENA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether the Cement Corporation of India has reviewed the position for setting up the Cement Plant in the district of Koraput, Orissa, which was proposed to be Joint Venture Project between Cement Corporation of India and Industrial Development Corporation, Orissa Ltd.; and

(b) a detailed report thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) : (a) and (b). The Cement

Corporation of India Ltd., had examined the feasibility of setting up of a cement plant in District Koraput in Orissa. This site is connected by the Kottayalasa-Kirandul broad-gauge railway line, which is exclusively reserved for transportation of iron ore from Bailadila to Visakhapatnam and is not open to other goods traffic. This project is therefore not feasible till either Dantewada-Sukhma-Rajmundry rail line comes up or Kottavalse-Kirundal railway line is thrown open to general goods traffic.

### Promotions in Palm Gur Industry

6781. SHRI K. A. RAJAN: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that under the Palm Gur Industry, Khadi and Village Industry Commission, except for few cases of promotions, no promotion of the staff has been made during the last ten years;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the details of the posts either surrendered or allowed to lapse since 1967?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) : (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

### Functions of Central Palm Gur and Palm Products Institute, Madras

6782. SHRI K. A. RAJAN: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) the objectives and functions of the Central Palm Gur and Palm Products Institute, Madras of the Khadi and Village Industry Commission;

(b) its achievements, if any; and

(c) future programme?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) The objectives and functions of the Central Palm Gur and Palm Products Institute, Madras are as follows:—

(1) To conduct field trials, undertaken research and experiments for technical problems faced in development programme of the Industry and improvement in equipment to raise productivity.

(2) To undertake extension activities, to study cost structure of various Palm Products, to organise demonstration and exhibition to disseminate Technical and Organisational progress, to render on the spot Technical guidance to implementing agencies and to do monitoring work in respect of development schemes as and when required.

(3) To impart specialised training to supervisory and technical staff.

(4) To undertake working of model trading activity for assessment of economic viability of the Schemes/Projects.

(b) (1) The Institute is in a position to standardise recipes/formulae for certain palm sweets and other edible products under its research and experimentation programme.

(2) A process for making palm sugar using simple appropriate technology has been evolved.

(3) Simple manually operated equipment have been evolved for cutting of palm leaves and weaving the same.

(4) New designs for palm leaf and palm fibre utility articles have been worked out.

(5) Use of simple climbing tools have been experimented and optimum condition worked out.

(6) A scheme on palm candy manufacture under NCST programme is in progress at the Institute.

(7) Cost structure of various palm-products from different parts of the country have been studied under extension programme Model Training-cum-Demonstration centres are in operation, introduction of improved furnaces and pans at selected societies has been undertaken.

(8) A specialised training course in sugar making is in progress

(9) The Institute runs a model trading operation dealing with various edible and non-edible products.

(c) The future programme of the Institute envisages:—

(1) Intensification of training programme and extension activity.

(2) Introduction of regular course in palm gur technology for the benefit of supervisory staff under implementing agencies.

(3) Rendering promotional assistance through spot assessment of various schemes in operation by implementing agencies.

(4) Intensification of research and experiment work under NCST programme.

#### Introduction of selection Grade in the Khadi and Village Industry Commission

6783. SHRI K. A. RAJAN: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether the Khadi and Village Industry Commission has decided to introduce Selection Grade for all the posts;

(b) if so, the details of the scheme; and

(c) the probable date by which the Selection Grade system is to be implemented and completed?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) to (c). No, Sir. In conformity with the guidelines issued by the Government from time to time Khadi and Village Industries Commission is introducing Selection Grade for Group 'D' posts with effect from the 1st April, 1978. Orders are under issue. For other categories of posts a Committee constituted by the Khadi and Village Industries Commission has recommended that in all groups of posts where there is acute stagnation, 10 per cent of the total number of posts may be converted into selection grade posts. The recommendations of the Committee are being processed further.

#### Entry of Multinational into Soyabean Industry

6784. SHRI VIJAY KUMAR N. PATIL: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government have received a memorandum from small Soya Processors Association Nagpur regarding the reported back door entry of multinationals/large house in the field of Soyabean Processing;

(b) if so, the important details of the memorandum and allegations made therein; and

(c) what is the reaction of Government thereto and action taken in the matter?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI GEORGE FERNANDES): (a) and (b). Government have received a memorandum from Small Soya Processors Association, Nagpur, against the entry of large houses and multinationals in the field of soyabean processing on the ground that the existing small-scale units would not be

able to withstand competition from large houses/multinationals. It has also been stated in the memorandum that there is no need for foreign collaboration and/or import of capital goods for the manufacture of soya products.

(c) Government have decided to permit the entry of large houses in the soyabean industry as the manufacture of textured protein, isolates and concentrates cannot be undertaken economically in the small scale sector and most of the entrepreneurs in the medium sector could not implement the Letters of Intent given to them. Prohibition of entry of large houses in this industry would cost considerable distress to the growers of soyabean.

भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा/भारतीय/वन सेवा संघर्ष में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के लिए भारकण कोटा

6785. श्री राम साहब : क्या यह मंत्री यह बताने की हुपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रशासनिक सेवा/पुलिस/वन सेवा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों का कोटा केवल परीका के समय ही भरा जाता है तथा उच्च पदों पर नहीं;

(ख) क्या भारतीय प्रधं सेवा में उच्च दो (1500-1800-2000) में कोटा रखा गया है तथा भरा गया है;

(ग) क्या संविधान के उपबन्धों के लिए यह में भरा गया है; यदि हाँ, तो इस में उपबन्ध को दूर करने के लिए सरकार क्या ठोक करम उठा रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो भारतीय प्रशासन सेवा/भारतीय पुलिस सेवा/भारतीय वन सेवा में उप सचिव तक उससे ऊपर के पदों में भारकित कोटा न भरे जाने के क्या कारण हैं ?

यह मंत्रालय में तथा विधि, व्याय और कानूनी वार्ष भारतावध में राज्य भर्ती (श्री एस० श्री० शाहिल) : (क) भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लिए भारकण की व्यवस्था केवल प्रतियोगी परीका के सावधान से इन सेवाओं में सीधी भर्ती के स्तेज पर ही है।

(क) सीधी भर्ती से भरी जाने वाली भारतीय भारत सेवा के शेड-I (वि 1800-2000) और शेड-II (वि 1500-1800) को रिक्तियों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए भारकरण की व्यवस्था है। अनुसूचित जनजातियों के लिए शेड-I में भारकरण एक रिक्तित तथा शेड-II में अनुसूचित जातियों के लिए भारकरण एक रिक्तित को उपयुक्त उम्मीदवारों से न मिलने के कारण नहीं भरा जा सका। सच लोक सेवा योग्य द्वारा इन रिक्तियों को पुन विज्ञापित किया जा रहा है।

(ग) जी नहीं श्रीमान्।

(घ) चूंकि उप-सचिव और उससे ऊपर के पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई भारकरण नहीं है, इसलिए प्रश्न नहीं उठता।

#### Scheme for Development of Adivasi areas in Bihar

6786. SHRI BAGUN SUMBRUI: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state

(a) the details of the scheme formulated for bringing improvement in the position of Adivasi and for the development of Adivasi area in Bihar; and

(b) the names of the areas to be covered by this scheme and the amount of expenditure to be incurred thereon during the Sixth Five Year Plan?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL): (a) and (b). A sub-Plan has been drawn up for areas having 50 per cent or more tribal population. The areas covered by the Tribal sub-Plan in the State of Bihar are given in the Annexure.

The schemes for these areas include all sectors of development viz. (1) Agriculture and Allied sectors (2) Co-operation (3) Water and Power Development (4) Industries and Minerals (5) Communication (6) Social and

Community Services (7) Economic Services and (8) General Services.

The Medium Term Plan (1978-83) has not so far been finalised.

#### Statement

#### STATEMENT SHOWING THE AREAS UNDER TRIBAL SUB PLAN IN BIHAR.

1. RANCHI district.

2 SINGHBHUM district.

3 Latehar sub-division, and Bhandaria block of Garhwa sub-division, in PALAMAU district.

4 Dumka, Pakur, Rajmahal and Jamtara sub-division, and Sundar Pahari and Boarij or blocks of Godda sub-division in SANTHAL PARAGANAS district.

#### Salt cess proceeds from Gujarat

6787. SHRI F. P. GAEKWAD: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state

(a) the amount the Centre had been collecting from Gujarat by way of salt cess during the last three years;

(b) whether it is a fact that Gujarat is a major contributor to this fund;

(c) if so, how this fund is being utilised at present;

(d) whether it is a fact that the Gujarat Chamber of Commerce recently complained before the Salt Enquiry Committee about effective steps not being taken to utilise the fund either for development of salt industry or for welfare of labour; and

(e) if yes, steps proposed to be taken in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI-MATI ABHA MAITI) (a) The amounts

of salt cess collected from Gujarat State during the last three years were:

(in lakhs of rupees)

1975-76 . . . . .	78.20
1976-77 . . . . .	75.99
1977-78 . . . . .	83.97

(b) Yes, Sir.

(c) The proceeds of salt cess reduced by the cost of collection are to be utilised on all or any of the following objects as provided in section 4 of the Salt Cess Act, 1953:—

(1) meeting the expenditure incurred in connection with the salt organisation maintained by the Central Government,

(2) meeting the cost of measures taken in connection with the manufacture, supply and distribution of salt by Union agencies and the regulation and control of the manufacture, supply and distribution of salt by other agencies; and in particular, measures for—

(i) the establishment and maintenance of research stations and model salt farms;

(ii) the establishment, maintenance and expansion of salt factories;

(iii) fixing the grades of salt;

(iv) promoting and encouraging co-operative effort among manufacturers of salt; and

(v) promoting the welfare of labour employed in the salt industry.

(d) and (e). The Gujarat Chamber of Commerce presented a memorandum to the Salt Enquiry Committee suggesting several measures for the better utilisation of Salt Cess proceeds and for the development of Salt Industry and welfare of labour employed in the Industry. These suggestions would be considered by the Salt Enquiry Committee.

**Memorandum regarding growth of small scale Industries**

6788. SHRI VIJAY KUMAR N. PATIL: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government have received any memorandum from Shri Prahm Vasudeva, President Small and Developing Industries Association of India P.O. Box 1542 Bombay regarding growth of small scale industries;

(b) if so, important details thereof; and

(c) the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) Yes, Sir

(b) The representation has referred to the criteria announced through Press Notes of 3rd and 5th Jan. 1979 regarding endorsement of capacity on registration certificates of undertakings pertaining to all industries included in the first schedule of the IDR Act. It has also been pleaded in the representation that small scale units which have crossed investment limit of Rs. 10 lakhs in plant and machinery may be allowed to grow atleast upto Rs. 3 crores investment which is the current level for general exemption in the industrial Licensing Policy.

(c) The Government has stipulated in the above mentioned Press Notes that in respect of items reserved for the small scale sector, the production capacity for the non-small scale units producing these items would be determined with respect to the highest production achieved by the undertakings in the three years prior to the date of reservation of the item for production in the small scale sector or the level of production existing on 29th August.

1973, whichever is earlier, subject to a few additional conditions. This stipulation has been made applicable to all units which are not in the small scale sector. While it has been stipulated that no undertaking should exceed the maximum production levels achieved prior to 31-12-1978, it has been provided that where an undertaking is producing in excess of the capacity as determined above, it would bring down its production to the registered capacity as endorsed on the registration certificates within a period of two years from 1-1-1979. However, if the undertaking agrees to buy and market the same or similar products of small scale industries, its capacity determined according to the above criteria will be enhanced to that extent. However, the representation is receiving further attention.

#### Production of Bread and Biscuits Industries

6789. SHRI VIJAY KUMAR N. PATIL: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government have decided to allow bread and biscuits production to Small Scale Industries; and

(b) if so, what measures will be taken to ensure hygienic production of these articles as is done in Britania or Modern Bakeries?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) Yes, Sir. Manufacture of bread and biscuits has been carried on in the small scale sector for a long time. In December 1977 bakery products, including bread and biscuits, were reserved for exclusive development in the small scale sector.

(b) Small scale industries engaged in the production of bread and biscuits are subject to the norms of

hygienic production prescribed by the health authorities in the same way as the units in the organised sector.

#### महाराष्ट्र में सीमेट का जिलावार आवंटन

6790. SHRI गंगाधर खप्पा भूराहे : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि :

(क) जनवरी से मार्च, 1979 तक की अवधि में महाराष्ट्र के लिए सीमेट का किनना कोटा जिलावार, दिया गया और सीमेट एजेन्सियों के नाम क्या हैं,

(ख) 15 मार्च, तक उन जिलों को वास्तव में किननी मावा में सीमेट गप्पाई किया गया; और

(ग) क्या उनको मागे पूरी करने के लिए सम्पादित हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख). सीमेट के वितरण की विधान प्रणाली के प्रनुसार सीमेट का इकट्ठा आवंटन प्रयोक तिमाही के आधार पर प्रत्येक राज्य/संघ जातित प्रदेश के अधीन विभिन्न श्रेणियों जैसे नरकारी उपभोक्ताओं गैर-नरकारी इकट्ठे खपत वाले उपभोक्ताओं तथा आम जनता में विकी के लिये किया जाता है। जनवरी-मार्च, 1979 की तिमाही के लिए महाराष्ट्र को किया गया इकट्ठा आवंटन 50,000 मी० टन के अनिवार्य तरदद आवंटन का मिलाकर 5.45 लाख मी० टन है। सीमेट का जिलेवार आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। जनवरी-मार्च, 1979 की तिमाही के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रधिक जिलों को दी गई सीमेट की मावा, प्रयोक जिले को सीमेट संभरण कर रही सीमेट फैबरियों के नाम तथा फरवरी के इन तक भेजी गई सीमेट की मावा बनाने वाला एक विवरण सलग है :

(ग) राज्य सरकार ने 54.95 लाख मी० टन के मूल आवंटन के प्रनाला प्रति तिमाही में 1.00 लाख मी० टन के अनिवार्य आवंटन के लिए प्राप्त रोध किया था। महाराष्ट्र राज्य की भव्यांग माग पूरी करना समझ नहीं हो सका है क्योंकि देश में सीमेट की उपलब्धता सारे राज्यों तथा केन्द्रीय सरकार के विभागों की कृत माग से कम है।

## विवरण

जनवरी—मार्च, 1979 की अवधि के दौरान महाराष्ट्र में विविध जिलों को किये गये सीमेंट का आवंटन तथा भेजी गई मात्रा

क्र०	जिले का नाम	सीमेंट फैक्टरियों के नाम जिनसे आवंटन तथा प्रेषण किया जाता है	जनवरी—मार्च 1979 की तिमाही के लिए सीमेंट का आवंटन	जनवरी और फरवरी 79 में किए गये प्रेषण
1	2	3	4	5
1.	आहमद नगर	केसोराम, शाहाबाद, बाडी (इम्प)*	5304	686
2.	अंकोला	शाहाबाद बाडी, चांदा, केसोराम	4170	1914
3.	अमरावती	चांदा (इम्प)*	4364	1888
4.	झोरंगाबाद	बाडी, चांदा, पण्यम, भर्मासान्द्रा, केसोराम	4314	430
5.	भंडारा	चांदा, केसोराम	2808	905
6.	बुलडाना	चांदा, केसोराम (इम्प)*	3300	526
7.	भोर	शाहाबाद, बाडी, पण्यम, भर्मासान्द्रा (इम्प)*	2560	575
8.	चन्द्रपुर	चांदा	2485	1233
9.	छूलियां	चांदा, केसोराम (इम्प)*	3860	934
10.	जलगांव	चांदा, केसोराम (इम्प)*	5012	782
11.	कोल्हापुर	बाडी, बगलकोट, भर्मासान्द्रा (इम्प)*	6880	2162
12.	कोलाबा	शाहाबाद, बाडी, कुरकुन्ता (इम्प)*	3188	1592
13.	नांदेड़	पन्दा, भर्मासान्द्रा (इम्प)*	2832	414
14.	नागपुर	चांदा, केसोराम	12892	4488
15.	नासिक	चांदा, केसोराम (इम्प)*	5368	1678
16.	उत्तमानाबाद	शाहाबाद, बाडी, कुरकुन्ता (इम्प)*	2962	702
17.	परमनी	बाडी, पण्यम, भर्मासान्द्रा (इम्प)*	3100	240
18.	पुणे	शाहाबाद, बाडी (इम्प)*	20715	8477
19.	रत्नागिरि	शाहाबाद, बाडी, बगलकोट, भर्मासान्द्रा कुरकुन्ता (इम्प)*	3338	1342
20.	सतारा	शाहाबाद, बाडी, बगलकोट, कुरकुन्ता (इम्प)*	4360	1441
21.	सांगली	बाडी, बगलकोट (भर्मासान्द्रा) (इम्प)*	4796	1034
22.	शोलापुर	शाहाबाद, बाडी, कुरकुन्ता (इम्प)*	6220	2621
23.	थाना	शाहाबाद, बाडी, कुरकुन्ता (इम्प)*	11984	7020
24.	वर्धा	चांदा, केसोराम	3204	1220
25.	यवतमाल	चांदा, पण्यम, केसोराम	3480	2165
26.	बहुत शम्बरी	शाहाबाद, बाडी, चांदा, सेवरिया तथा आयातित सीमेंट	66050	33183
			200294	79657

\*इम्प—महाराष्ट्र में मैं १० सी० सी० द्वारा अपनी शाहाबाद तथा बाडी सीमेंट फैक्टरियों में भंडारों (इम्पों) को चलाया जा रहा है।

**News-item captioned "Giant's Threat"**

6791. SHRI VASANT SATHE: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether attention of Government has been drawn to the news report appearing in the *Economic Times* dated the 21st March, 1979 at page 4 under the caption "Giant's threat";

(b) if so, what is the reaction of Government to the various observations of serious nature made therein; and

(c) details of action taken/proposed in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) Yes, Sir.

(b) and (c). The decision to permit the entry of the large units in the Soyabean processing industry has been mainly based on the following considerations:

(i) Most of the medium entrepreneurs who had been given letters of intent in the past had not yet implemented those letters of intent.

(ii) The manufacture of textured protein, protein isolates and concentrates do not generally lend themselves to economical processing in the small scale sector

(iii) It also requires market promotional effort on a large scale, in which the established market outlets of the large units act as an asset.

(iv) The poor performance of the small and medium scale entrepreneurs, coupled with prohibition of entry of large units, would have caused considerable distress to the growers of Soyabean. The States where this crop has been produced on a big scale are finding it difficult to ensure raw remunerative prices to

the farmer. Its cultivation was promoted to strengthen the protein content in the Indian diet.

(v) It has been made clear in the Ministry of Industry's Press Note dated the 29th January, 1979 that preference will be given to proposals received from non MRTP and non FERA companies. The decision to permit the entry of large units had been taken in consultation with the authorities concerned with protection of the interest of the small scale units, including DC(SSI) and CSIR.

The requests for foreign collaboration would be considered on merits, and normally it will not be allowed where the indigenous technology is available. It would, however, not be desirable to prohibit foreign collaboration altogether because it may be required in the manufacture of more sophisticated products. Similarly where indigenous machinery was available, the import of foreign machinery will not be recommended.

A letter of intent has been issued to M/s. Modipon Limited, Modi Nagar on 30th June, 1977 for the manufacture of the following items for the capacity indicated against each:

Item of manufacture	Annual capacity (Tonnes)
(1) Edible Soya Flour . . .	45,000
(2) Soya Textured Protein . . .	30,000
(3) Soya Protein isolates and concentrates . . .	3,000
(4) Soyabean oil (by-product) . . .	16,450

The proposal of M/s. Modipon Limited envisages import of plant and equipment to the extent of Rs. 4.34 crores, and this is under examination of the Ministry from indigenous angle. A proposal from M/s. Britannia Biscuit Company Limited is also under consideration of the Government. It is not a MRTP house. No proposal has

been received by the Ministry of Industry so far from M/s. Cadbury India Limited for setting up Soya processing unit. M/s. Food Specialities Limited, whose proposal was rejected earlier, will also be eligible to apply in the light of the Ministry's Press Note dated the 29th January, 1979.

**Closure of small scale units due to non-availability of Steel Wires and Rods**

6792. SHRI JYOTIRMOY BOSU: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether exactly how many small scale units due to non-availability of steel wire rods have closed down or are working with unutilised capacity;

(b) whether it is a fact that capacity of small scale wire drawing units was 26 lakh tonnes in West Bengal;

(c) how many of them are now on the list of the Iron and Steel Controller and what is the quantity of mild steel black or galvanised wire registered licenced capacity and built in capacity of such units; and

(d) what is the capacity which is lying idle due to lack of supply of raw materials in West Bengal and in other States?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) Government are aware of the difficulties being faced by the small scale wire drawing units in general in recent months due to the difficulties in the procurement of adequate quantity of wire rods against their enhanced demand.

(b) According to the information available the number of active wire drawing units in West Bengal is 125 and their combined capacity is 1,25,000 MT per annum.

(c) Small scale industries are not required to register themselves with the Iron and Steel Controller. Only the large units are required to be registered with the Iron and Steel Controller.

(d) In a recent survey conducted, 375 small units producing MS and GI wires, in the country, have reported their capacity and production as follows:—

Year	Capacity (Thicker than 18 SWG.) (Lakh Tonnes)	Production (Lakh Tonnes)
1977-78	4.5	3.5

Regarding the 125 units of West Bengal, their combined production was 82,350 MT during 1977-78 against the total capacity of 1,25,000 MT.

**Inflow of Hippies in Goa Beaches**

6793. SHRI JYOTIRMOY BOSU: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is enormous inflow of hippies in the country specially in Goa beaches;

(b) whether it is also a fact that there are number of international gangsters among them who are wanted by interpol; and

(c) if so, what steps Government are taking to tackle the situation?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL): (a) and (b). In the absence of a precise definition of a 'Hippie', it is difficult to distinguish such persons as a category from other tourists. Reliable information in respect of the inflow into country or Goa, of such foreigners is, therefore, not available. It is also

not, therefore, possible to say whether such persons include international gangsters. However, if any foreigner comes to adverse notice, suitable action is taken against him under the relevant law.

(c) With a view to limiting the entry into Ind. of such foreigners as are likely to be a social nuisance because of their indulgence in narcotics, indecent behaviour, vagrancy, begging etc, suitable instructions have been issued to the Indian Missions abroad to be particularly cautious in granting tourist visas to such persons. State Governments have also been suitably advised to have the activities of such foreigners carefully watched and take prompt penal action for any infringement of law.

प्राम स्तर पर पचार्याय योजना लागू करना

6794. श्री चन्द्र शेखर सिंह : क्या योजना मंत्री यह बनाने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या प्राम स्तर पर पचार्याय योजना लागू करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, और

(ब) यदि हाँ, तो योजना के नगरीय स्वरूप में परिवर्तन करने और उसे ग्रामीणकृत बनाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कल्लरूर रहमान) : (क) जी, नहीं। एकोकृत ग्रामीणना के लिए उपयोगन समझा गया केवल विकास खड़ है। इसलिये देश में खट स्तर ग्रामीणना शब्द की गई है। इन योजनाओं को लैंयर करने में खण्ड में ग्रामीण और गांवों के समूह की ग्रामशक्तियों को ज्ञान में रखा जाएगा।

(ब) पचार्याय योजना के प्रारूप में कृषि और एकोकृत ग्रामीण विकास को मबरे अधिक प्राथमिकता दी गई है और इस लिए इसे नगरोन्मूल नहीं कहा जा सकता।

#### Implementation of foreign contribution Act, 1976

6795. SHRI HALIMUDDIN AIIMED Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have appointed any authority for imple-

mentation of foreign contribution act 1976 and if so, the details thereof;

(b) whether the officials working for implementation of foreign contribution Act have detected and examined any case under the rule; and

(c) if so, the number of cases being examined and details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL):

(a) The Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976 is being administered by the Ministry of Home Affairs.

(b) and (c) Since the commencement of the Act, prosecution under punitive sections of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976 has not been sanctioned in any case so far. In some cases, preliminary inquiries are being made regarding alleged violation of the provisions of the Foreign Contribution (Regulation) Act. It will not be in public interest at this stage to disclose details thereof.

#### Classification of people on socio-economic basis

6796. SHRI K. MALLANNA:

SHRI S. S. SOMANI:

Will the Minister of PLANNING be pleased to state

(a) whether there is any proposal under Government's consideration to make classification of people into majority and minority communities on socio-economic basis instead of on religious basis and to raise them to equal level by allowing various classes to progress on that basis; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING (SHRI FAZLUR RAHMAN): (a) and (b). There is no question of classifying the people into communities for purpose of

planning or economic policy. As the Hon'ble Member is aware, the current Five Years Plan has the primary objective of increasing the incomes and welfare of those sections of the community which are below the poverty line, through increased employment opportunities, higher earnings in agriculture and industry and better access to social services. In that sense, it may be deemed to distinguish between the poor who are in the majority and the non-poor who are in the minority. Success of the Plan would imply a significant reduction in the present gap in the conditions of life of these two groups.

#### Production of cotton in States

6797 SHRI MOTIBHAI R CHAUDHARY: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) the total yearly production of cotton in Gujarat, Punjab and Maharashtra;

(b) the total quantum of cotton to be purchased on behalf of the Cotton Corporation from these three States this year, the quantum of cotton purchased upto 31st March State-wise and the rates thereof;

(c) the rates at which cotton is purchased in Maharashtra by the State Cotton Corporation, zone-wise;

(d) the rates at which cotton will be purchased by the National Textiles Corporation in case of necessity from the Cotton Corporation of India and the Maharashtra Cotton Corporation; and

(e) whether the rates offered by the Maharashtra Cotton Corporation are higher than those of the Cotton Corporation of India; if so, the reasons for which higher rates are not offered to the cotton-growers by the Cotton Corporation of India?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) Final State-wise estimates of cotton production for the current cotton year 1978-79 have not yet become available. However, the estimated cotton production in Gujarat, Punjab and Maharashtra during the previous year 1977-78 is given below:—

State	Production (In lakh bales of 170 kgs. each)
Gujarat . . . . .	19.42
Punjab . . . . .	12.24
Maharashtra . . . . .	12.63

(b) A Statement is attached.

(c) The Maharashtra State Cooperative Marketing Federation purchases kapas at guaranteed prices which are on an average about 10 per cent to 20 per cent higher than the minimum support price announced by the Government for 1978-79 cotton season depending on the variety and grading of cotton.

(d) The National Textile Corporation purchases cotton from Cotton Corporation of India and Maharashtra State Cooperative Marketing Federation on negotiation basis from time to time as per market conditions prevailing at the time of negotiation.

(e) In so far as Maharashtra State is concerned, as the cotton procurement is undertaken exclusively by Maharashtra State Cooperative Marketing Federation from 16th December 1978, there is no basis for comparison of rates offered by the Cotton Corporation of India with that of Maharashtra State Cooperative Marketing Federation.

**Statement**

Details of total quantity of cotton targeted to be purchased by the Cotton Corporation of India in Gujarat, Punjab and Maharashtra and the quantity of cotton purchased in these States and the rates offered by the Corporation are as under:-

(Quantity in lakh bales of 170 kgs each)

State	Purchase target	Purchases made so far	Rates at which purchases were made by CCI during the second fortnight of March 1979	
			Variety	Rate
			(Rs. per quintal)	
			High/Low	
Gujarat . . . . .	5.00	1.44	S-4 . . . .	516/445
			Digvijay . . . .	458/425
			CO-2 . . . .	482/355
			V-797 . . . .	347/324
Punjab . . . . .	2.50	1.99	J-34 . . . .	394/267
Maharashtra*		0.61	.. . . .	.. . . .

With the revival of State cotton procurement scheme in Maharashtra with effect from 16th December, 1978, the Cotton Corporation of India is not now operating in Maharashtra. However, up to 15th December, 1978, the Cotton Corporation of India had purchased about 61.278 bale of cotton in Maharashtra.

**Setting up of Salt Industry in West Bengal**

6798. PROF. SAMAR GUHA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether the Central Government propose to set up additional salt industry along with by-product industries in the Contai area, coastal belt of West Bengal;

(b) whether the Minister of State visited the area on several occasions and had consultation with the West Bengal Government and the local administration; and

(c) if so, the reason for delay in setting up the project and when the matter will be finalised?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI): (a) It is pro-

posed to set up a salt factory in Contai Sea Board area in Midnapur District and lands admeasuring about 1,900 acres are to be handed over by Government of West Bengal to M/s. Hindustan Salts Ltd. (A) Government of India Undertaking) for undertaking manufacture of salt in the area.

(b) The Minister of State for Industry Shrimati Abha Maiti, visited Contai on 5th January, 1979 and held discussions in the matter with the Minister of Industries, Government of West Bengal and State Government officials.

(c) Some unauthorised salt manufacturers on the land have obtained injunction from High Court of Calcutta against allotment of land to M/s. Hindustan Salts Ltd. Further action on this project will be taken after the lands are transferred in favour of M/s. Hindustan Salts Ltd. for which purpose

State Government are taking suitable steps.

**Nationalisation of Key Industries**

6799. SHRI SURENDRA BIKRAM: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) latest plan of the Government of India in respect of nationalisation of key industries; and

(b) whether Government propose to nationalise the synthetic rubber producing industry of the country in view of its being a monopoly industry to form a rubber corporation?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) and (b). Minister of Industry has on various occasions, including at a Press Conference on 12th February, 1979, discussed the question of nationalisation of industries as part of the programme to implement the Janata Party resolution on economic policy and in the context of the debate on the concentration of economic power. These issues have also been raised by the Press during their meetings with the Minister of Industry. At his most recent Press Conference of 12th February, 1979 Minister of Industry spelt out the criteria for take over and nationalisation of industries as being the extent of concentration of economic power by large houses, the extent to which there is need to regulate the entire spectrum of industrial output and marketing by the State, and the areas in which the public sector has to make its presence felt. These issues are also dealt with in the Statement on Industrial Policy presented to Parliament on December 28, 1977. The question of nationalisation has been raised at various forums as a matter of public interest. Government have not yet taken any decision in this regard.

**Constitution of National Reconstruction Army**

6800. SHRI R. K. MHALGI: Will the Minister of PLANNING be pleased to state:

(a) whether the group constituted to examine the possibility of setting up a National Reconstruction Army has submitted its report;

(b) salient features of the scheme;

(c) whether the Planning Commission have considered the scheme and if so, action taken thereon; and

(d) if the report has not been submitted, the date by which it is likely to be submitted?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING (SHRI FAZLUR RAHMAN): (a) No, Sir.

(b) and (c): Do not arise.

(d) No definite date has been set for the submission of the report. The Working Group has been asked to report as soon as possible.

**STATEMENT CORRECTING ANSWER TO UNSTARRED QUESTION NO. 4343 DT. 20-12-78 RE. TRANSLATION AND VETTING WORK IN MINISTRIES**

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL): In the reply given to Lok Sabha Unstarred Question No. 4343 on 20-12-1978 it was stated that

"The quota of translation for the Legislative Department has been fixed at 1800 words per translator per day and that of vetting approximately double the quota for translation."

The above sentence may be read as under:—

"The quota of translation for the Legislative Department has been fixed at 1300 words per translator per day and that of vetting approximately double the quota for translation."

Similarly, in 'Annexure 'C' (Hindi Version) "1300 words per day" may be read for "1380 words per day."

This correction has been necessitated due to a typographical mistake. The mistake occurred in that part of the answer to the question which relates to another Ministry and it could not be noticed earlier.

12 hrs.

श्री नायूसिंह (दौसा) : अध्यक्ष महोदय, श्रीमती इन्दिरा गांधी ने अमेरिका से वहूं सारा पैसा लिया है। . . . (व्यवधान) . . . इट इज डाइरेक्ट इन्टरफोरेन्स इन इन्डियन पालीटिक्स। यह देश के बेचने का कार्य किया है। . . . (व्यवधान) . . . ये पहले कहती रही हैं कि जे ० पी ० अमेरिका से पैसा ले रहे हैं . . . (व्यवधान) . . . क्या यह हिन्दुस्तान की राजनीति में इन्टरफोरेन्स नहीं है।

. . . (व्यवधान) . . .

मैंने काल-एटेंशन दिया है, आप उसे स्वोकार कीजिए। . . . (व्यवधान) . . .

श्री विजय कुमार मलहोत्रा (दक्षिण दिल्ली) : मैंने 377 का नोटिस दिया है, आप ने उम पर क्या कँसला किया है। . . .

. . . (व्यवधान) . . .

MR. SPEAKER: Whatever has been received, I am dealing with according to the rules. (Interruptions.) No such calling attention has yet come to me. It is only now, today, it has come. All calling attention notices will be considered. So far as tomorrow is concerned, I have given permission to a calling attention about power failure in Bengal. I am

not able to select any other calling attention for tomorrow. It will be considered for next week. (Interruptions). I will certainly consider it for next week Papers to be laid.

श्री नायूसिंह : यह पूरे देश की सुरक्षा का मामला है। यह बड़ा गंभीर मामला है।

(Interruptions).

MR. SPEAKER: Don't record.

(Interruptions) \*\*

SHRI VAYALAR RAVI (Chiraynikil): Under rule 58, I am raising a point of order.

MR. SPEAKER: is it about a matter before me today?

SHRI VAYALAR RAVI: Yes. (Interruptions).

#### RE. MOTION FOR ADJOURNMENT

SHRI VAYALAR RAVI: I am raising this matter under rule 58. Now the Government have permitted their servants to participate in the RSS. . . . (Interruptions).

MR. SPEAKER: Do not record. This is not a point of order

SHRI VAYALAR RAVI: \* \*

12.05 hrs.

#### PAPERS LAID ON THE TABLE

##### DETAILED DEMANDS FOR GRANTS, 1979-80 OF MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION (SHRI ARIF BEG): On behalf of Shri Mohan Dharia, I beg to lay on the Table a copy of the Detailed Demands for Grants (Hindi and English versions) of the Ministry of Commerce, Civil Supplies and Cooperation for 1979-80. [Placed in Library. See No. LT-4261/79].

**DETAILED DEMANDS FOR GRANTS,  
1979-80 OF MINISTRY OF INDUSTRY**

**THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI GEORGE FERNANDES):** I beg to lay on the Table a copy of the Detailed Demands for Grants (Hindi and English versions) of the Ministry of Industry, for 1979-80. [Placed in Library. See No LT-4262/79].

**SIKH GURDWARAS ELECTION ENQUIRIES  
(AMDT) RULES, 1979**

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL)** I beg to lay on the Table a copy of the Sikh Gurdwaras Election Enquiries (Amendment) Rules 1979 (Hindi and English versions published in Notification No. G.S.R. 328(E) in Gazette of India dated the 2nd April, 1979, under sub-section (3) of section 146 of the Sikh Gurdwaras Act, 1925. [Placed in Library. See No LT-4263/79].

**NOTIFICATIONS UNDER ALL INDIA SERVICES ACT, 1951**

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI S. D. PATIL):** I beg to lay on the Table a copy of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (2) of section 3 of the All India Service Act, 1951:—

(1) G.S.R. 435 published in Gazette of India dated the 24th March, 1979 containing corrigendum to Notification No. G.S.R. 160 dated the 3rd February, 1979.

(2) G.S.R. 436 published in Gazette of India dated the 24th March, 1979 containing corrigendum to Notification No. G.S.R. 159 dated the 3rd February, 1979

(3) The Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength)

Second Amendment Regulations, 1979, published in Notification No. G.S.R. 471 in Gazette of India dated the 31st March, 1979.

(4) The Indian Administrative Service (Pay) Second Amendment Rules, 1979, published in Notification No. G.S.R. 472 in Gazette of India dated the 31st March, 1979. [Placed in Library. See No LT-4264/79].

**ANNUAL REPORT OF NATIONAL INSTRUMENTS LTD., CALCUTTA FOR 1977-78**

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV)** I beg to lay on the Table a copy of the Annual Report (Hindi @version) of the National Instruments Limited, Calcutta, for the year 1977-78 along with the Audited Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General thereon under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956 [Placed in Library. See No. LT-4265/79].

**AUDIT REPORTS ON THE ACCOUNTS OF DELHI FINANCIAL CORPORATION FOR THE YEARS FROM 1971-78 TO 1975-76 WITH STATEMENT FOR DELAY**

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI ZULFIQUARULLAH)** I beg to lay on the Table.—

(1) A copy each of the Audit Reports (Hindi and English versions) on the accounts of the Delhi Financial Corporation for the years, 1971-72, 1972-73, 1973-74, 1974-75 and 1975-76, under sub-section (7) of section 37 of the State Financial Corporations Act, 1951.

(2) A statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the above Audit Reports. [Placed in Library. See No. LT-4266/79].

@English version of the Report and Hindi and English versions of Review by the Government on the working of the Company, were laid on the Table on 22nd December, 1978.

12.07 hrs. .

RE. MOTION FOR ADJOURNMENT—  
Contd.

SHRI C. M. STEPHEN (Idukki). Kindly listen to us. There is an adjournment motion before you

MR. SPEAKER: I have not allowed it

SHRI C. M. STEPHEN. You have not allowed it. But there is an adjournment motion given notice of. The member is asking (Interruptions) Under rule 60, when an adjournment motion comes before you, there are only three courses open to you. You can either reject it and explain the reasons for it, or ask the member for more information or you can call for explanation from the Minister concerned. Here is an adjournment motion, and it is on the basis of (Interruptions) Under article 309, the conditions of service of Government servants are to be regulated ... (Interruptions)

MR. SPEAKER The adjournment motion by Shri Vayalar Ravi refers to the decision of the Government to amend the service rules, enabling the Government servants to join RSS, a communal organisation with political overtones, which is against the secular character of the Indian Constitution and which has disastrous consequences. I have rejected it, saying "this is not a matter for the adjournment of the legislative business". There are other courses open to you; adjournment motion is not a course open to you.

SHRI C. M. STEPHEN: This is a matter which is agitating the whole country. (Interruptions) Under article 309. . (Interruptions) The rules have statutory force. This House.... (Interruptions)

MR. SPEAKER: This is not a point of order at all. You can have a Calling Attention, but it cannot be an adjournment motion. You can raise it during the Demands.

SHRI C. M. STEPHEN: We are responsible people. Kindly listen to us while we are raising it.

MR. SPEAKER: It is not a matter for Adjournment motion.

SHRI C. M. STEPHEN: The paper has stated that specific permission is given to join the RSS. That impression is dangerous. This is a statutory matter. We have heard your ruling. You have said it is not a matter for adjournment. Kindly listen to us. I am convincing you that this is a matter for adjournment

THS MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA): Is the Leader of the opposition challenging your ruling? This will create a present which you must not allow.

MR. SPEAKER There are other ways of raising it

SHRI C. M. STEPHEN: It is a settled procedure that your ruling on the adjournment motion is not final. All parties have drawn up a procedure that when you reject an adjournment motion, it is open to us to place before you

MR. SPEAKER. My predecessors have laid down that during the Budget session, when the Demands are discussed, unless it is something very urgent and exceptional, the Speaker will not give consent to an adjournment motion

SHRI C. M. STEPHEN: The Home Ministry's Demands are over.

MR. SPEAKER: There are so many other ways of raising it. We have to be a little responsible.

SHRI C. M. STEPHEN: This is a statutory matter on which the House has authority, you must understand.

SHRI C. M. STEPHEN: This question is agitating the people of this country.

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): It is very unfortunate that a discussion is sought to be raised on your ruling. However, I would like to tell the House that what has appeared in the press is totally wrong.

SHRI C. M. STEPHEN: Let me put one question to the Prime Minister.

MR SPEAKER: The Prime Minister of the country says that what has appeared in the paper is totally wrong. What more do you want?

SHRI C. M. STEPHEN: Is it that the conduct rules have not been amended, or is it that the amendment does not give permission to join the RSS? What is baseless?

MR. SPEAKER: You can discuss it with him.

SHRI C. M. STEPHEN: I want to know from him ...

MR. SPEAKER: He says, it is totally baseless. (Interruptions) New precedents are being created in the House Shri Paswan.

—  
12.15 hrs.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

THIRTY-FIRST REPORT

SHRI RAM VILAS PASWAN (Hajipur): I beg to present in Thirty-first Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions.

—  
COMMITTEE ON PAPERS LAID ON THE TABLE

FIFTEENTH REPORT

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi Sardar): I beg to present the Fifteenth Report (Hindi and English versions) of the Committee on Papers Laid on the Table.

RE. MOTION FOR ADJOURNMENT  
—Contd.

SHRI C. M. STEPHEN: I want an explanation from him....

MR. SPEAKER: You cannot cross-examine him in the House. I am surprised to see that the Leader of the Opposition is persisting in this manner. I had expected better cooperation from him, the Leader of the Opposition. The Prime Minister said, this is baseless. If there is anything further, you can discuss the matter with him.

SHRI C. M. STEPHEN: When a statement is made by the Prime Minister on the floor of the House, the Leader of the Opposition has got a right to ask what he means by it.... (Interruptions)

MR. SPEAKER: I cannot compel him to answer.

SHRI C. M. STEPHEN: You need not compel him. If he is not prepared to answer, let him say.

Let me frame my question. There is a report in the press and the report says that the conduct rules have been amended. Is that report correct or not? If he says, it is incorrect, I want to know whether the conduct rules have been amended or not. This is the question put to him. He says, it is baseless. I want to know what is baseless. (Interruptions) I am not shouting. I am asking a question. What is baseless?

MR. SPEAKER: If he does not answer you, what can I do? I cannot compel him. (Interruptions)

SHRI YESHWANTRAO CHAVAN (Satara): It is not our intention to question your authority. But there are issues which exercise the minds not only of the members in this House but the people at large in the country. (Interruptions) Even in the Janata Party, the issue has become controversial, whether the members

of the Janata Party can become the members of the RSS (Interruptions) Now, here is a news which says that the Government have amended the conduct rules to allow Government employees to become the members of the RSS .. (Interruptions)

MR. SPEAKER: The Prime Minister says, it is baseless.

SHRI YESHWANTRAO CHAVAN: By disallowing such type of discussions and keeping them out of Parliament, you are making Parliament a 'vegetarian' Parliament (Interruptions) You must act in the true spirit of Parliament and allow discussions on such vital issues which are exercising the minds of the members and the people in the country

SHRI C M STEPHEN The statement that he made was that the report is baseless. The report has got two aspects. One is, whether the conduct rules have been amended and the other is, what is the interpretation of it. This is an elementary courtesy. When the Prime Minister makes a statement and the Opposition asks for an explanation, the doubt must be cleared. It is an elementary courtesy that he must come out and explain what he meant by it. I did not understand. Kindly explain what is meant by it. You have said that the report is baseless. Is it your statement that the Conduct Rules have not been amended, or, is it your statement that the amendment would not mean that the government employees can join the RSS? What exactly is meant? I want an explanation about that.

SHRI MORARJI DESAI: The Leader of the Opposition wants elementary courtesies. Is it an elementary courtesy to shout at me? Is that an elementary courtesy? How can I respond to that kind of thing? (Interruptions). Let me tell him that I have not made the statement without understanding it.

SHRI C. M. STEPHEN: I did not understand. That is why I asked.

SHRI MORARJI DESAI: That is the pity. You do not understand it. Government employees are not allowed to take part in the RSS activities. That does not mean that....

AN HON. MEMBER: That does not mean that!

MR. SPEAKER Mr. H. V. Kamath. (Interruptions)

SHRI C. M. STEPHEN: He is again misleading the House. He is confirming. He says, 'What I did say did not mean that the government employees cannot participate in the RSS'. That is what he said. Kindly do not keep the House in the darkness.

MR. SPEAKER: I will direct him to place the amendment on the Table of the House.

SHRI C M STEPHEN No. That is not the point.

MR. SPEAKER: You cannot dictate to me. The Leader of the Opposition has no right to dictate to me.

SHRI C M STEPHEN: I do not dictate.

MR. SPEAKER: I will ask him to place the amendment on the Table of the House and, if necessary, I will allow a debate (Interruptions)

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi Sadar): On a point of order.

MR. SPEAKER: What is the point of order? About what matter?

SHRI KANWAR LAL GUPTA: Under rule 184, Sir. You have allowed them to discuss RSS. I have nothing to say. That is your sweet will. But another matter, which is the most important and to which Mr. Chavan has also agreed, is about the money received by Mrs. Gandhi.... (Interruptions). This is a serious matter. The whole country is agitated.

MR. SPEAKER: All serious matters cannot be discussed in one day. We must find time for it...

SHRI KANWAR LAL GUPTA: I am raising a serious matter...

MR. SPEAKER: Mr. Kanwar Lal Gupta, this is an attempt to steal a march over others. I have already informed you that I am allowing a call-attention on that. You cannot raise it by a point of order. I am not allowing you any more. Do not record.

SHRI C. M. STEPHEN: Sir, I want to make it clear on behalf of my Party and on behalf of the President of my Party, Mrs. Indira Gandhi, that the report which has appeared is absolutely baseless. Not a pie has been taken: I want to make it clear. I challenge, we are prepared for any inquiry. It is baseless.

MR. SPEAKER: I am allowing an opportunity for discussion (Interruptions) I have said that I am giving an opportunity for this. Nothing more.

SHRI NATHU SINGH (Dausa): There are CIA agents sitting in Indian Parliament. This is an insult to our country.

SHRI C M STEPHEN: You are the CIA: you have a man, Dr. Subramaniam Swamy.

MR. SPEAKER: I think you are quits now.

(Interruptions)

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour): Indira Gandhi Party took money from everybody.

बौद्धी बलबीर सिंह (हैमियास्पुर) : स्टीफन साहब के बयान के बाद इस बात पर एक बहुत यहाँ पर होमी चाहिये ...\*\*

\*\*Not recorded.

MR. SPEAKER: Don't record.

Shri Hari Vishnu Kamath.

CHOWDHRY BALBIR SINGH: \*\*

MR. SPEAKER: Nothing is recorded

Mr. Kamath.

12.25 hrs.

#### COMMITTEE ON PETITIONS

##### NINTH REPORT

श्री हरि विष्णु कामत (होशगाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्राप्तकी अनुमति से छठी भाकसभा की याचिका समिति का नोंबर प्रतिवेदन (हिन्दी तथा भारतीय संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

#### PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

##### HUNDRED AND TWENTY-SECOND REPORT

SHRI ASOKE KRISHNA DUTT (Dum Dum): I beg to present the hundred and twenty-second Report of the Public Accounts Committee on Action Taken by Government on the recommendations contained in their Fifteenth Report on Custom Receipts relating to Ministry of Finance.

#### COMMITTEE ON PUBLIC UNDER-TAKINGS

##### THIRTY-SECOND AND THIRTY-THIRD REPORTS

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour): I beg to present the following Reports of the Committee on Public Undertakings:—

(1) Thirty-second Report on Action Taken by Government on the recommendations contained in the Eighth Report of the Committee on Jute Corporation of India Limited—Government's Unfair Pricing Policy for Raw Jute.

(2) **Thirty-third Report on Action Taken by Government on the recommendations contained in the Third Report of the Committee on Jute Corporation of India Limited—Jute and Exploitation of Jute Growers.**

12.27 hrs.

### MATTERS UNDER RULE 377

#### (i) NEED FOR THE ABOLITION OF CAPITAL PUNISHMENT

**श्री राम दिलास पातवान (हाजीपुर) :** अध्यक्ष महोदय, विषय के विभिन्न भागों में राजनीतिक हृत्या से भारत को चिनित होना स्वाभाविक है। लोकतंत्र का जीवन विरोध पत है। यदि विरोध पत मर जाए तो लोकतंत्र स्वतं गमान्त दी जाएगा। महात्मा गांधी तथा डा० राम मनोहर लोहिया के अनुशार गच्छे साध्य के लिए उनम साधन की आवश्यकता है। जहां सत्ता जनसत पर जबर्दस्ती कानू॰ गाकर कायम की जाती है वहां लोकतंत्र जीवन नहीं रुक जाता। लोकतंत्र का आधार विरोध का आदर तथा जीवन के प्रति सम्मान है।

आज एजिया एवं अफ्रीका के अधिकांश देशों में हृत्या की राजनीति तथा अधिनायकवादी प्रवृत्ति और पकड़ रही है। ईरान में शाह ने आगे विरोधियों को अंतर्धान मरवा दाला और अब इस्लामी गणतंत्र के दावेदार शाह का साथ देने वालों की हृत्या करवा रहे हैं। आज भूट्टो की हृत्या ने सारे विषय को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। वित ६ अप्र०, १९७९ को दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय अपील के बावजूद दक्षिण अफ्रीका के स्वतंत्रता सेनानी और सोलोमन महालक्ष्मी को फासी दी दी। उनके अलावा और चार व्यक्तियों को फासी की सजा दी गई। इसके पूर्व भारत ने भी संयुक्त राष्ट्र से अपील की थी कि वे दक्षिण अफ्रीका के अधिकृत नेता की जिन्दगी की बचाने के लिए अपने प्रबोध का प्रयोग करें।

राष्ट्र संघ की मुख्य परिषद ने भी दक्षिण अफ्रीकी अधिकारियों से अपील की थी कि वे सोलोमन महालक्ष्मी को फासी पर ना लटकायें। समाचार के अनुसार पिछले बच्चे दक्षिण अफ्रीका में १३२ व्यक्तियों को फासी पर लटकाया गया था। इनमें एक ईरैत, २६ मिथित नस्ल तथा १०५ अफ्रीकी थे।

इसके पहले नेपाल में दो नेपाली कांग्रेस के नेताओं को फासी दी गई और इन सारी राजनीतिक हृत्याओं का प्रभाव भारत के जनजीवन पर पड़ता है। नेपाली कांग्रेस, भूट्टो तथा दक्षिण अफ्रीका की राजनीतिक हृत्या ने भारत के ज्ञातिप्रय मात्मा को अकालीर दिया है और सब भीर से हृत्या के विरोध में प्रदर्शन एवं आवाज उठा रहे हैं। स्वयं भारत में भी कूछ वर्ष पहले भहुा के प्रबल विरोध भांध के दो नक्सलपत्ती किशान नेताओं को फासी दी गई।

ब्रह्म पाकिस्तान और बंगलादेश के भीतर से भारत बंगलादेश एवं पाक एकीकरण की मांग जोर पकड़ रही है। भारत सरकार को निश्चित रूप से भारत, पाकिस्तान एवं बंगलादेश के महासंघ की बात चलानी चाहिए।

मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ कि किसी देश के आंतरिक मामले के नाम पर अपनी आत्मा को नहीं बेचना चाहिए। यह चुप्पी भारत की सम्पत्ति एवं संकुलित के प्रतिकूल है तथा इससे भारत सरकार की कमजोरी फलती है। भारत सरकार को अपने देश से फासी की सजा को समाप्त करना चाहिए तथा विषय के किसी भी कोने में राजनीति हृत्या की जाये तो बिना किसी भेद भाव के उसकी तोड़ भर्तना करनी चाहिए।

**MR. SPEAKER:** Prof. Mavalankar.  
Not here. Shri Rajagopal Naidu.

#### (ii) AMENITIES TO THE WORKERS OF THE STEEL YARD IN MANDI GOVIND GARGH, PUNJAB

**SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU** (Chittoor): Sir, the Steel Yard in Mandi Govind Garh, Punjab is managed by Punjab Small Scale Industries Corporation. It is the consignment agent of the Hindustan Steel Ltd. (SAIL). P.S.S.I.C. took contract from SAIL to load and unload the steel arriving at the Railway Station in Mandi Govind Garh and to give delivery of that steel to the steel rolling mills in that town. This Corporation is getting Rs. 26/- per tonne from the Steel Authority.

This Corporation instead of employing the workers directly engaged a middle-man contractor who is giving only Rs. 6/- per tonne to the workers not only that, he has not provided any facility to the workers as provided in the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970.

As per that Act, canteens, Rest rooms, first aid facilities, wholesome drinking water, sufficient number of latrines and urinals have to be provided in that establishment. Nothing was arranged in the Steel Yard. Even the drinking water is not provided there.

When the representative of the workers represented to the Union

(Shri P Rajagopal Na.du)

Government about the plight of the workers, the State Government informed the Union Government that all facilities were provided in the Steel Yard which was beyond the truth.

I have visited the place personally and found what the workers were telling was truth. I represented the fact to the Minister of Steel and Mines twice but he was not able to do anything to protect the labourers

As per the above Act, the PSSIC which is the consignment agent has to register itself as the principal employer and the middle man contractor has to take the licence. They have not done that till now. For that contravention, they should have been punished but it was not done or they were not asked to register and to get licence. Therefore, the Labour Department is not able to apply labour laws to that Corporation. That is why no one is able to protect the workers working under the Corporation.

The workers desire that the Small Scale Industries Corporation should cancel the middleman contractor and directly employ the workers or they have to appoint the society of the workers as the contractor.

In other steel yards workers are directly employed and they are getting not less than Rs 14/- to Rs 16/- whereas these workers are only getting Rs 6/- which is quite unjust, nothing but exploitation. This system is coming in the way of getting fair wages by the workers.

I therefore request the Government to compel the Punjab Small Scale Industries Corporation, to register as principal employer and employ workers directly and provide all amenities to the workers as provided in the Act and to pay not less than Rs 15/- per tonne.

I hope that the Minister will not yield to political pressures and do justice to the workers.

MR. SPEAKER: Mr. Saugata Roy

(iii) REPORTED STRIKE BY THE EMPLOYEES OF INDIAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE, PUSA, NEW DELHI

SHRI SAUGATA ROY (Barrackpore) Sir Under Rule 377, I wish to raise the following matter in the House for the attention of Mr Barnala

"Strike and agitation by the supporting staff of Indian Agricultural Research Institute Pusa

This is to draw the attention of the House to the callous attitude of the Ministry of Agriculture Government of India to the low paid employees of IARI, Pusa. Since 5th March 1979 there has been total strike in the Pusa Campus by the 2600 supporting staff working there. Many of them have been on an indefinite hunger strike also. The employees have tried all possible peaceful agitation methods, including holding mass dharna torchlight procession throughout the night in the campus. From the last week they started courtly arrests before the Krishi Bhawan and already 500 of them have been arrested by the Police. The employees have no political affiliation. Their demands are

1 Supporting staff to be promoted after every five years' assessment as in the case of Technical staff,

2 The Grade II of the Supporting Staff viz. 200-250 to be revised and raised to Rs 210-290,

3 Selection Grade IV of Supporting Staff viz. 260-430;

4 Daily wage dismissed employees to be reinstated

I think that the Government should take immediate steps to resolve the legitimate demands and bring back normalcy in the Pusa campus.

MR. SPEAKER: Prof. Samar Guha.

## (iv) REPORTED POWER CRISIS IN WEST BENGAL

**PROF. SAMAR GUHA** (Contd): The power crisis in West Bengal has created a near catastrophic situation in West Bengal leading to closure of industrial and engineering units, and educational institutions and trade and business markets. The economic and social life of Bengal, as a result of a crisis of unprecedented dimension is almost on the verge of collapse. This crisis will spill over into labour troubles and generate unrest in the State, causing serious law and order situation.

The Central Government must intervene immediately to save West Bengal from the impending chaos and extend all assistance for tiding over the crisis.

**MR. SPEAKER:** I have fixed a Calling Attention on this issue tomorrow.

---

**RE. DISCUSSION ON DEMANDS FOR GRANTS**

**SHRI HARI VISHNU KAMATH** (Hoshangabad): Sir, as the House is aware, rather painfully aware, so far as the Demands discussion is concerned, owing to circumstances mainly or largely beyond our control we are very much behind schedule and as the dreaded doomsday, 23rd April, draws near, there is growing apprehension that more and more Ministries will be laid low by that lethal weapon—the guillotine. I think the ministers concerned will be happy but the House, I am sure, will not be happy. So, I daresay the House will agree that we must ~~try~~ <sup>try</sup> to ~~try~~ <sup>try</sup> as many Ministries as possible for execution—I mean not merely ~~try~~ <sup>try</sup> but Ministries Demands. We have ~~less~~ <sup>less</sup> than forty hours....

**MR. SPEAKER:** To be exact we have only twenty-five hours and fifteen minutes.

**SHRI HARI VISHNU KAMATH:** In that case it is more dangerous. I am sure the House will agree with me, to save as many Ministries as possible, to sit daily till 7 O'clock in the evening and also one Saturday.

**MR. SPEAKER:** I will put it before the Business Advisory Committee.

**SHRI HARI VISHNU KAMATH:** I would, however, like the Minister of Affairs Parliamentary and hard Labour—in a genuine democracy like ours Labour is not a soft portfolio—to give a firm and solemn assurance that the time allocated for the financial business till the passing of the Finance Bill will not be misappropriated or encroached upon or intruded into by legislative business.

**THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA):** Sir, on the first part of the hon'ble Member's suggestion you have been pleased to say that you will put it before the Business Advisory Committee. On the second part where he has asked me to give an assurance that no legislative business will be introduced till the Finance Bill is passed, I can say that Government has no intention of appropriating any time that has been allotted for the Demands for Grants. If any inroads are made into this time it will not be by the government.

---

12.39 hrs

**DEMANDS FOR GRANTS, 1979-80—Contd.**

**MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION**  
—contd.

**श्री नाथ लिह (दीमा):** परसों जब मैं कृषि पर बोल रहा था तो मैंने लिखा है और विज्ञापी की कही की वर्चनी की थी जिस के प्रभाव में कृषि लेन्ड में उत्पादन नहीं हो सकती है और किसान की वजा सुखर नहीं सकती

[ओ नाय मिह]

है। मैं उदाहरण देता हूँ। पूरे देश में जितनी बिजली पैदा होती है उसका केवल साड़ चौदह प्रतिशत किसानों को दिया जाता है, कृषि पर खर्च की जाती है और बाकी सारी उदायी और शहरी पर खर्च कर दी जाती है। किसानों से रेट भी तीन ऐसे की यूनिट बाज़ी किया जाता है जबकि टाटा और डिला की फैक्टरीज़ की तीन ऐसे भीर पांच ऐसे के हिसाब से बिजली दी जाती है। किसानों को क्यों क्यों हमारी दी जाती है, उन्होंने कोन सा पाप किया है जिस का खियाजा उनको सुनाने के लिए मजबूर किया जा रहा है।

मैं राजस्थान में आता हूँ। राजस्थान का इनाका हिन्दुमतान के गलिस्तान पर एक घट्टा है, काला बब्बा है, फाड़ा है। हिन्दुमतान का गुलिस्तान कहा जाता है लेकिन उसका जो एक बहुत बड़ा भाग राजस्थान का रेगिस्तान है उसकी तरफ पिछले तीस मास में घायल नहीं दिया गया है, बहाने की घोर न इर्गिंगेन की कोई व्यवस्था की गई है। तीसी नोक सभा में कामत साल्य बढ़े हुए हैं, एक मामला उठाया गया था और उस समय बैंडरेंट डिवलपमेंट बोर्ड बनाया गया था। उसने आज तक क्या किया है मुझे मालम नहीं है। उस समय सुवर्णाध्यम साहब मिनिस्टर थे। तब उन्होंने इस सवाल का टाल दिया था। कामत साल्य ने दृम पर जोर दिया था। उस में कोई प्रगति नहीं हुई है। जिनमा रेगिस्तान उस समय यो आज वह और भी ज्यादा बढ़ गया है। छाटे से देख इन्हराइल का आप ले। बहा भी भयकर रेगिस्तान या जिम को नैनेब कहा जाता था। उन्होंने बड़ी खालीरती के साथ उस पर बाब पाया और उसको गलिस्तान का बाना कर रख दिया। प्रब डजराइल में रेगिस्तान नाम की चीज़ नहीं है। उन्होंना भर में रेगिस्तान के गम्भीर बहा है। बया भारत सरकार ने कभी उनको बुलान की काशिश की है और उनको हिन्दुमतान का रेगिस्तान दिया है और उन से पूछा है कि किस तरह से इसको दूर किया जा सकता है। 1965 में इन्हराइल को कुछ एकमपर्ट बर्फी आये और वह तीन साल तक रक्त कर उन इनकों की उन्होंने कामपलट कर दी थी। नव से आज तक इन्हराइल के एकमपर्ट से कभी सम्बन्ध स्थापित नहीं किया और न ही उनको बुलाया। समय आ गया है कि वहा से विवेषज्ञों को बुला कर उनकी सलाह ले कर राजस्थान के रेगिस्तान को गुलिस्तान बनाया जाए, उनकी कायापलट की जाए।

तीस साल तक सरकार कृषि के प्रति उदासीन रही है उन्हें इसको निगमेंट किया है। यह चीज़ देश के लिए बहुत खतरनाक सांबित हो रही है। पचास प्रतिशत आय कृषि से होती है, भस्ती प्रतिशत सोग कृषि पर निभर है उसके बाबजूद सरकार कृषि पर व्याप नहीं देती है। परिणाम यह हो रहा है कि कभी महाराई बढ़ती है, कभी कम होती है, फिर बढ़ती है, फिर कम होती है। महाराई रोकने के लिए सरकार कूसते उपाय करती है। किसानों के बारे में बातें बहुत कम्ही लक्षी की जाती हैं। यह कहा जाता है कि उन्हें सुधारायें दी जा रही है, कूप फार बके उनके सिए बला ऐसे हैं,

गरीब लागे के लिए बला रहे हैं, अन्त्यावय योजना चल रही है। काम के बदले अनाज देने की जो योजना प्राप्त है बला रही है इसके अन्दर फिसानों द्वारा मजबूरी का सबा हुआ अनाज दिया गया है। कारेस गवनेमेंट के जमाने में जो अनाज भर कर रख लिया गया था और जो मढ़ गया है और जिस को पशु भी नहीं खाने हैं, वह उनका दिया जा रहा है। आप इसकी जाज करे और देखे कि कहाँ प्राप्त भाविकारों प्राप्तकों धोखे में तो नहीं रख रहे हैं। इस योजना के अन्तर्गत जो काम हो रहा है, कच्चा हो रहा है, पात से काम करता है तो वह हजार का काम हुआ है, यह दिक्षा दिया जाता है। जो कच्चा काम करवाया जा रहा है वारिशं काम होते ही यह साफ हा जाएगा। मधके, रास्त जो कच्चे बनाए जा रहे हैं इनको पक्का बनाया जाना चाहिये।

जहा तक किसानों को लोन देने का मम्बन्ध है केवल भारत प्रधानमंत्री लान ही बैंकों से किसाना तो दिया जाना है, कृषि कार्यों के लिए दिया जाना है। किसान का गम्भीरी हो वहाँ बहुत बड़ी जाती है। अगर कांड नहर्सी लगाए जाये तो गवनेमेंट 75 म 40 परसेट तक लान और सभी बैंकों द्वारा 75 परसेट लान दिया जाता है, लेकिन किसान अगर लोन ले तो उसे आसानी से लान नहीं मिलता है। आज किसान कृषि का राम मजबूरी में बर रहा है, उसे आसाने कृषि के लायक नहीं धारा है। प्रगति कृषि का इडप्रैटी की तरह बिकास किया जाये, तो काफ़ी उत्तमता ही है। मैं जानना चाहता हूँ कि वया सरकार ने कभी काई सरकार कराया है कि बाबा की दशा कीस सुधारो जा सकती है? मरा निवान है कि बाबा का इडप्रैटेट बनाए देये। बाब म जट, अनाज, रुद्धि, तेल पैदा करता है, बहा प्राप छाटी-छाटी इडप्रैटी लगाइये। किसान का सामान खेतों में उपर और उनको बहा छाटी-छाटी इडप्रैटी हो जिसमें उम कच्चे माल का पक्का माल के रूप में परिवर्तित कर दिया जाये। उमसे से किसानों की आवश्यकता में अनुमान उनको दिया जाये और बाकी को बहरों में भेज दिया जाये। अगर प्राप ऐसा नहीं करें, तो भी एक उदाहरण देना चाहता हूँ। भगवान श्रीकृष्ण ने एक मटकी फोड़ आन्दोलन शहरा के विराष में था। उमका रूप ऐसा था जैसे समाप्त होते हैं। उनका वह भान्दावान इमलिये था कि जहर याने किसानों का शायतन करते हैं। शहर वाले बाब बालों का धी-दूध मस्तन खारीदते थे, लेकिन बाब बालों को उचित मूल्य नहीं देते थे। इसीलिए भगवान कृष्ण को मटकी फोड़ आन्दोलन की जहरत पढ़ी। इसलिए आज आवश्यकता है कि किसानों की दशा सुधारी जाये, उनका गांवों में इडप्रैटेट बनाया जाये।

MR. SPEAKER: Please conclude now

SHRI HARI VISHNU KAMATH (Hoshangabad): He is the youngest Member of the House, the baby of the House; so, he may be given some more time.

**SHRI C. N. VISVANATHAN**  
(Tiruppattur): And this is the International Year of the Child, he should be given preference.

श्री नाथ सिंह एग्रीकल्चरल एजेक्शन के बारे में यह बताना चाहता कि राजस्थान में केवल एक कृषि विवरणीयालय है। वहा राजस्थान में बारंबार कफलों का नुस्खान होता है और इम चपचाप बैठे रहते हैं। राजस्थान में नवन आला पड़ा है, क्या सैलूल गर्भनमंड ने कोई ऐसी टीका भरी है कि वह देखें कि इस से बहा किनारा नुस्खान हुआ है। भरे नियांचन बहा दीमा में नहारील हैडिम्पार्ट में आल से कफल चौपट हा गयी है, लेकिन आज तक उनका कोई नुस्खान नहीं भिली। उनमें जा लगाया जिया जाता है, राजस्थान गवर्नर ने केवल उस आपो के लिये बढ़ा दिया है। क्या आप केंद्र से गांड इनजाम करें कि उनका जा नुस्खान हुआ है, उनका कांड मध्यवाचा उनका मिर पाएँ?

एग्रीकल्चरल एज्युकेशन के बारे में एक महिला श्री राधाकारों के नेतृत्व में बार्नर्ड गैर्डनी, उनके द्वारा 1948 भी दी थी। लेइन ज्यू ग्राइट के बारे में बताया। कि उनका राज्य गवर्नर के पास भेज दिया है। राज्य मंत्रालय ज्यादा ज्यादा देंगे? कई राज्य मरकार ना ऐसी हैं। मरकार ना जा कर्क यात्राना जाती है, उनके बारे में भी काई ज्यादा नहा दर्दी क्षणिक ध्यूर्ष-ध्रेमी की गवर्नर हमारे प्रधार है। मैं जानना चाहता हूँ कि एग्रीकल्चर के बारे में सरकार को क्या नीति है, और आप उन नक्त उस ग्राइट का प्रश्नित करने का ना २२१ दूरें बार म उपर मव्रो बनान का रुपा करें।

कृषि के राम आन बाल आजारा और जो हृषि पैदा रहत है उनके बारे में बहुत बातें कही गई हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। आलू का भाव 5 रुपये विकल्प बढ़ा पर है, मैंने नियम 377 के अन्तर्गत नोटिस भी दिया था, लेकिन उसे स्वीकारा नहीं किया गया। वहा आलू इतना पड़ा है कि 5 रुपये विकल्प पर बिक रहा है और यहा दिल्ली के मार्केट में, आप तो बाजार लेने नहीं जाते हों, डेंड रुपये किलो आल मिल रहा है। वहा कोई खरोदार बाला नहीं है, यह कैमा मजाक किसान के माथ है। मैं कहना चाहता हूँ कि पजाब कृषि के मामले में सदमे आगे बढ़ा हुआ प्रदेश है और उनके प्रदेश सब से बड़ा प्रदेश है। कृषि तथा निकाई मर्दी पजाब के, और राज्य मर्दी उत्तर प्रदेश के हैं। हासी समय मोका है कि वे किसानों का कुछ भला कर मिलते हैं। अब उन्होंने यह मौका खा दिया, तो मूले किसानों का अधिव्य अधिकार में दिखाई देता है। वे दोनों कृषि के एकसमांद हैं, याम्य हैं और किसान हैं। इस लिए मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि वे किसानों के लिए कुछ करे और उनकी समस्याओं को हल करें।

**SHRI K. SURYANARAYANA** (Eluru): I am very happy to participate in the discussions on the Demands for Grants of the Ministry of Agriculture. I want to make a few observations for the consideration of

the Government.

When the Food Corporation of India was started in Madras in 1965, we expected that it will render good service to the public. But to our disappointment, from that year, our troubles have increased, even though we have produced more. Along with more production by the farmers, more troubles have also been created for the farmers by the policies of the Food Corporation. Even though the previous Government and this Government are sympathetic to the farmers, the officers and their policies are going on as before, as far as rural development is concerned. We were not satisfied even with what was happening during the period of the previous Government. I am not blaming this Government alone. As far as farmers are concerned, the same consideration and treatment are being given in the matter of price fixation and procurement.

As far as Andhra Pradesh is concerned, I have been told that recently 100 telegrams have been sent to the Food Corporation from the Kailakur taluk in my constituency, which is a Kolleru area, about their not making procurement. It is not about the price, even though price also has not been fixed. I have already said that agricultural classes, including agricultural labourers in the rural areas constitute 70 per cent of the people of India. We are pouring on them only slogans and sympathetic words. We are not helping them in any practical way. If you see the other countries, you will find that the agricultural communities there are being given all facilities. Whatever our friend has said, is correct. You are procuring the produce from the villages, but you are spending money on industries located in Ghaziabad and Delhi. Because the officers are here, they will try only to give benefits to their children, and not to give benefits to villagers.

I am surprised to see that the banks are giving advances only to mill-

owners and not to the tillers of the soil. For the last 15 years, there is a rule. The Act has not been amended. The Reserve Bank has not been allowed to give a single rupee as produce loan to the farmers. The farmer is not being given a proper price; and the agriculturists are not given other facilities also.

Recently, to my surprise I have found that a circular has been issued by the Ministry of Labour, New Delhi. I asked the Labour Minister about it. He said it was not within his knowledge. It has been said that if rural development goes up, the agricultural labour will be harmed. But agricultural labour will be harmed only by urban people, because you are not paying a proper price for agricultural produce. You are developing industries only in urban areas. That is why I am blaming the officers and the Government. As my friend on the Government side said, the Government has failed, in fixing the sugar cane price, and it has not fixed the responsibility for the losses. Only in the matter of industrial, finished goods, they are taking into account the manufacturing costs while fixing prices.

Go to Korea or Japan; you will find that all the industries are not centralised in cities there, comparable to our Madras, Delhi or Bombay.

12.54 hrs.

[DR. SUSHILA NAYAR in the Chair]

Having industries in places like Faridabad is not enough. I want to suggest to the government now or hereafter also, when they are fixing the cost of the finished goods, why they should not consider the price fixation of the products of the rice producer on the basis of the cost of production. Some officers, IAS or IFS who are handling the subject, they are not bothered about agriculture, they are bothered about free education, free transport, free guest houses for their comforts. I have seen the report of the agro-industries corporation which has come today. It shows that every institution lost Rs. 10 lakhs of rupees. People there have manipulated figures; they have

manipulated import policy; they keep all the goods which are imported and are not selling them in the market immediately. In the last two months I have brought a case to the notice of the Minister of State in the agriculture ministry and he was kind enough to release the stocks of fertilisers. All high officers are sitting here. Who is responsible for this. In 1975 they imported chemical fertilisers; it is stored in my constituency for the last four years. It is Rs. 1500 only per ton. I think in the black market it is high. 1800—2000 tonnes are in the godown, a private godown. Every month they are paying Rs. 6,000 rent. All the ministers are here. Their departments are having people like this. In six years they have sold only 300 tonnes. When they were approached by the house owner, the godown keeper to vacate the godown they say: you must bear all the cost because it is not transportable, all the bags should be rebagged, and transport it at your cost. Even if the ministry ordered it, for two months it is only correspondence. But four days back I was told that at the cost of the building owner they have moved the stocks to some extent—about 200 tonnes. Is this the way? There is demand for good fertilisers, imported fertilisers. There is demand in my district which has the highest production and highest consumption also in Andhra Pradesh just like Punjab and Haryana. On the other hand, the entire agricultural community, is not satisfied about the government. Even both the Ministers have given so many assurances and both are coming from the agricultural community, we are not satisfied. What is the use of being a minister. We want benefits for their labour and material benefits from you to the agriculturists. Agriculture means what? After all the land reforms and all these things, still they say in their offices, officers drawing 10,000 and 5,000 that who are having 10 acres or 15 acres are called Kulaks, we are not for the kulaks. We are for the people who are without any earning capacity other than agriculture. We are not taking any contract from you to pro-

duce more paddy; we are producing without any contract. But in industry, only 10 or 15 per cent will be collected as share capital. About 80 per cent of the money they are borrowing from the Government. By the time they finish the construction, they are having 20 per cent back in other ways. But what about agricultural labourers? Unless agricultural labour also prospers the country cannot prosper. Please let me know. In the villages how many are without food? There are so many beggars in the cities, without food, round about your secretariat or office. Is there one man in the village like that? That is hereditary socialism or communism. We are feeding the country; we are producing without any hesitation. We, the farmers, are making so much sacrifice. Now this circular from Labour Ministry has been issued which creates a conflict between the agriculturists and agricultural labourers. They want to create an impression as if they are only for agricultural labourers.

13 hrs.

I have got reports here to show how prices are being maintained here and in other countries. In a small country like Korea, in 1970 the income of an agricultural family was 747 dollars per year as against \$ 1112 dollars which was the income of a family of workers in the urban area. Within eight years, gradually the income of agricultural families has gone up and now they are getting \$ 2876 dollars per year whereas a family of workers in the urban area gets an income of only 2879 dollars per year. In South Korea, in 1970 the price of 80 kg of rice was 7000 Wons. Gradually year by year it was increased without causing hardship to the consumers, whose purchasing capacity also has been gradually going up and in 1977, the price of 80 kg of rice was 26,260 Wons. They have brought the income of agricultural families to the same level as that of families in urban areas. No such thing has been done in our country.

The Food Corporation is a complete failure so far as Andhra Pradesh is concerned. Even the Chief Minister, of Andhra Pradesh, Dr. Chenna Reddy has blamed the Food Corporation. In my district of West Godavari alone, there is a surplus of 3.37 lakh tonnes of rabi crop lying with the farmers. The farmers are not allowed to get loans on their produce. Only the traders and millers are given loans. They are taking advantage of this to purchase the crops from the farmers at low prices. The farmers do not have even money to pay land tax. So, the rules should be amended to enable the farmers to get loans on their produce.

So far as sugar factories are concerned, some factories are making huge profits while others are suffering. Last time also I raised it. I had given a memorandum to Mr. Charan Singh, the then Home Minister, now Finance Minister, to appoint a Commission to enquire into the sugar industry. He told me that he had appointed so many commissions for which he was being blamed, so he wanted to forward my complaint to the Minister of Agriculture. But nobody is prepared to enquire. If there is some enquiry, I am prepared to give evidence. Even if you nationalise sugar industry completely, I have no objection. The Government is giving crores of rupees as loans to the sick mills. Whose money are you giving? You have duped the people. There are so many sugar factories running at losses. In the case of my own cooperative sugar factory at Bhimadole, the managing director is the Collector. The factory has incurred a total loss of Rs. 2 crores and not a pie of dividend has been declared for five seasons. We have paid Rs. 3 crores of excise duty in five seasons to the Government of India. It is not our fault. This year the farmer is not going to grow more sugarcane. The area under cultivation is going to be reduced. As a result, 100 factories would be closed in the country. Please look into the matter immediately and do something constructive.

## [श्री मुख्यमंत्री मिह मलिक]

श्री द्वितीयमंत्री, राज शुभि विमान की मात्र हमारे मासने जेरे-बहस है। इस में बाई शक नहीं कि किसी की देश की भिं-दिगी और सहत के लिये कृपि का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन अफसोस की बात यह ह कि कृपि के साथ जो सुलूक हो रहा है, वह कुछ नाजेबा इन मांगों को हमें समर्थन नहीं करता ही है। और खुशियोंमती की बात यह ह कि हमारे जो दो किसिन्स्टर इस काम का दख रखते हैं उन का कृपि से ताल्लुक रहा ह, वह कुछ किमान है, इस लिये किसान को जो ममत्याय है, उन से वे अच्छी तरह से बाकिक हैं। लेकिन उन की भी कुछ मजबूरिया है, लाचारी है। वे बरना तो बहुत ज्यादा चाहत है, लेकिन कर नहीं सकते और एक दफा इसी हाउम में खारे भान प्रताप मिह जी ने साथ अवकाश में बहा भी था—इस के बारे में मेरे व्यूज म्पार है, नेकिन मेरी मजबूरी है इस के साथ है।

मैडेम, 7-8 राज की बात है। किसी सवाल के जवाब में हमारे औपरी बरण सिह जा ने किसी भेदभाव को कहा था—अगर आप भी जगह यहा पर होते, तो आप का भी एमा ही जवाब दिना पड़ता। अफसोस यह ह कि उम कुर्स पर कोई भी बैठ जाये, लाह काई किसान बैठ जाय या काई दूसरा आदमी बैठ जाय—उम का वर्षी जवाब आया। पिछले 10 मासों में हम ने पिछले बारम हृक्मत व जमानदामाल को कृपि के बारे में देखा और प्रत्येकी जनना पार्टी के अन्दराज का भी दख रह है, मृगे तो काई नुमाया कफ मालूम नहीं दिया। हमारी हृक्मत कहनी है कि हम का एक सब से बड़ा अध्ययन है कि हम ने इस में परमानन्दी का धूम कराया—यह बात नहीं है, पिछले भी आपने जग सहाबान से पूछला चाहता है—किसान के ऊपर तो आज भी एमज़नी नहीं रह रही है, प्राज उम की क्या हालत ह। गई है, उम के साथ वहा सुलूक किया जा रहा है? यहा पर कुछ डेस्टड इन्टरेस्टम है—मृगे बचा अफसोस होता है—जब कृपि के बारे में वह पर बोलते हैं चाहे वे किसी भी वग में ताल्लुक रखते हों, यही कहने कि हमे किसानों का भला बना चाहिये, लेकिन जब किसानों का काई सम्प्रियत देने की बात आती है, तो वे उम का विरोध करते हैं। एक तरफ कहें कि रिम्प्युरेटिव प्राइम दी जाय, लेकिन जब रिम्प्युरेटिव प्राइम देने का बहल आता है तो सब खाते हो वर रुपने हैं कि मब मारे जाएंगे। महाराहा हा जाएंगी और एम से लो हृक्मत रूप बाल मिहिंग हृक्मत रूप बाले और कल्जमर भारे के भारे मर जाएंगे। हम किस्म की बातें हाउम के अन्दर करने लेंगे। अगर किसानों को ज्यादा कोपन दी जाएंगी, तो ये गब मर जाएंगे लेकिन हम ने देखा है कि आज नक तो काई मग नहीं है। अफसोस की बात यह ह कि वाई भरता नहीं लेकिन उन की लोबी जो है वे बहल मजबत है और किसान की लोगी जो है वह बटी हुई है। हृक्मिन्युलिस्टस

के महारे स्पेसमैन ऊपर से कुछ बोलते हैं और होना कुछ भी है, बाल में लौटी और मुह में राम राम बाली बात है। किसानों के बारे में हम किस्म की बातें करते हैं। कभी कभी यह भा कहते हैं कि एप्रोकल्कर जो है, कृषि जो है, उम पर देश वा एकानामी, देश को खगहाती निम्बर है और वाय में यह भी कहते हैं कि एप्रोकल्कर एक इन्डिया नवज़ह द कि इन्डिया का जहा हितना प्रोटेक्शन रखा है, बाल एप्रोकल्कर को क्या मिलता है। पावर के बारें इन्डिस्ट्रीजे के लिए हरियाणा और पंजाब में बहुत मीगर है। बहा पर 4 पैसे प्रति यूनिट बिज़री इन्डियन्स्ट्रीज का, कारबानदारी का मिलती है जबकि किसानों का 31 पैसे प्रति यूनिट दी जाती है। यह हालत आज है। इन मीगर बाज़ इन्डिस्ट्रीज बालों के लिए और इन्हें हाई बार्ड लिमानों के लिए। इन्डिस्ट्रीजेन्ट्स के लिए हृक्मतें भी हाला हैं और किसानों वे लिए क्या हाला है। हृक्मिन्युलिस्टस वो हर तरफ का प्रार्टेक्शन दिया

What about the kisan? He is entirely left at the mercy of the politician, at the mercy of the middlemen, at the mercy of thieves, at the mercy of pests, at the mercy of hailstorms, floods, droughts, animals, birds. He has to face lack of storage facilities, lack of transportation, so many things

जाता है। किसान वे दृश्यम ही दृश्यम खड़े हैं। आपने देखा कि पिछले दिनों आले गिरने लगे और पिछली बरसात के अन्दर य०पी०, बागल, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और देली आदि जातों पर करहम में भारी बर्बाद हो गई। अभी भा आपने गिरे उस का अमर एरियाणा रिली और य०पी० के अन्दर हाया और गायद पंजाब के अन्दर भी उम का अमर हाया। गे यह पूछला चाहता है कि तिस किसान की दानों के फले रखी की कफल और लारीक की कफल खराब हो जाए, तो क्या वह जिन्दा रहेगा। कोई बाल इन के जिन्दा रहने वा एपा नहीं होता। तो आज किसान की यह हालत है। वह जिन्दा रहता है और अनाज की कमी तो वह बर्दाशत कर जाता है लेकिन जाने की कमी बर्दाशत नहीं कर सकता। चारा न हो, तो किसान की नवाही ही नवाही है। इस के साथ ही दो तीन दिन से प्रालंबों का जिक्र किया जा रहा है। नायू सिह जी ने बताया कि राजस्थान में आलू 5 रुपये क्वार्टल है और कपास का क्या भाव है। इस के लिए लोग नारे लगाते हों, पिछले कपास के सोजन म हरियाणा के अन्दर सरसे में मैं ने सुना कि नाग यह नाग लगाते हों 'देखा जनता राज का ठाठ, नरमा लिकता 26०'। पहले कपास का दाम 400, 500 रुपये वा और अब 260 रुपये हो गया। जनता पार्टी के राज में नस्ता का यह भाव हो गया और किसी भी कपड़े के भाव को आप देखिये। गेंडे का पिछले मास क्या हाल तृप्ता। य०पी० के अन्दर उस को

जिसना पढ़ा और हरियाणा के मन्दर भी बरी हालत हुई। ग़ज़े का क्या दाम किसान का मिला और आज क्या हालत आल की है, प्याज की है। जिस चीज़ की तरफ भी देखो, किसान की मदद किसी बक्त पर हुक्मत करने आई। ग़ज़ा कपाम आदि जो किसान पैदा करता है उन सब कीमत इतना नीचे चली गई लैंकिन किसान की मदद किसी ने नहीं की। मुझ एक ग्रंथ याद आता है :

बशी तूफान म दूब गई मगर किभी न मदद न की आलाह भी था मलाह भी था लगर को महारा मिन न साना ।

हक्मन भी थी हमारे बजौर माहिदान भी बठ हुए थ, जनता पाटी भी यहा पर था इन्स्ट्रियलिस्ट्स भी थ इनक नुमाइदे भी थे यहा पर थे सेनेटर किसान जा आल, बपाम, प्याज आदि की बीमता भी गिरावट की बजह न सबाह हाता चला जा रहा था तो किसी न मदद नहीं की कोई उम्मको सहारा देने के लिए नहीं आया। मैं चाहता हूँ कि आप जा रहे किसान की हालत का नब दें जब वह खेत में बाम दर रहा हाना है। एक दिन एक मरीनी आदमी जब में खेत चला रहा था तो मेरे खेत म आ गया। मरी हालत का देख वह बाम से कहन लग गया कि आगर किसान न होता तो आपद खत्ती इमान वा बरनी पड़ती। मेरे मवा मटोव्य स पृथ्वा चाहता है इस इन्सान को मजारिन चीज़ की भी ना रही है। वह फूंक वै साथ हाउम मे कहा जाता है, डिन्स्ट्रियल मे एनान किया जाता है कि हमने इन्हा अनाज पैदा कर दिया है और इन्हा अनाज पैदा हो जाएगा। किसान का खून पसीनी निवल चला है वह सारा जार रगा रहा है अनाज पैदा करने के लिए यह नब डमलिए कर रहा है ताकि आपका खिला सक। अगर आप उसको कुछ सहायता दे तो आपद वह एक्सपोट करके भी आपका दिखा दे और बहत जर्दी दिखा दे। आप आल का एक्सपोट करो नहीं करते है। श्री मालन धारिया ने एक दिन कहा था कि एक्स्प्रेस हजार किलो हम एक्सपोट करेंगे। उमी दिन मैंने कहा था कि इसमें क्या हांगा? आल की फसल इतनी ज्यादा होती वाली है आप ज्यादा क्यों नहीं करते है। लैंकिन काई ध्यान नहीं दिया जाता है। मैं पूछता हूँ कि किम चीज़ की मजा किसान को आप दे रहे हैं।

नहर के किनारे तीन बैंडक बैठे हुए थे, एक के ऊपर एक। सब से ऊपर आले बैंडक जो था उसने आवाज दी टर्मटर। दूसरे ने कहा जो उसके नीचे बैठा हुआ था बबा बैठा था, खूनी न गम। सब से ऊपर इन्स्ट्रियलिस्ट था और उसके नीचे हक्मत थी। हक्मत ने कहा खूनी न गम। हक्मत ने कहा कि देने नीचे भी तो एक बबा बैठा है और वह किसान था। इस पर हीसे न कहा भर बे ह्या। ऊपर आला इन्स्ट्रियलिस्ट, बीच वाली हक्मत और ऊपर लैंकिन किसान। किसान सब से नीचे था और

सब का बोझ किसान के ऊपर था। यही हालत आज किसान की है। किसान को सभी दबाए बैठे हैं। यह नबटो वाली बात हो जाती है। बजट में किसान को क्या मिला है? पात्र रूपये धरिया के अन्दर कम हुए हैं, डीजल के मन्दर कुछ रुप मिला है। बाकी चीजों पर जो टैक्स बढ़ा दिए गए हैं क्या उसमें सारा बास किसान पर नहीं पड़ता? यहाँ पर इन्स्ट्रियलिस्ट्स के लालों भी बात है। यह तो नक्टे और लम्बी नाच वाली भी बात है। जिस की लाटी नाक हाती है उसमें ऊपर यह नक्टे एतराज करते हैं। इसरा को बहते हैं नाक आप हैं इसन बहना खब कर दिया मर गए गए, सारा बास मिलतमैन के ऊपर या कर पड़ गया। जब से मैंने जन्म लिया है या मियायत में 45 साल पहले से आया है मझ यह पता नहीं चल सका है कि एम्प्लायीज की जो डिमाइज है क्या ये हमी यन्म होती भी या नहीं? टीचमें की आज तर खन्म नहीं हुई, रेहडीबाला की नहीं हुई ब्राइज की, डेस बाला की खन्म नहीं हुई। एक के बाद दूसरी निलती जली आती है, एक का मान निया जाता है तां दूसरे साल बार और निकल आती है उनका यदा बर दिया जाता है। लैंकिन किसान को एक ही डिमाइ है, आप कम से कम या तो उसकी बेहतरी के लिये उसे प्रोटेक्शन दे उसकी फसल नबाह हो जाती है, आगे पड़ जाने ते पानी की कमी की बजह से, बरमात जू वजह से नुकसान हो जाता है, उसकी निनाने दिनों में यह डिमाइ चली आ रही है कि उसकी फसल का इश्यारेम दिया जाये। आपने उसकी फसल का इश्यारेम करने का कोई दृष्टान्त नहीं दिया है। गंगा गंगवार जिन्दा का तो जिन्दे हुए है निनान भगवर किसान मर जाये तो भी पीछे पीछे लग जाती है। उस एस्टेट डिटी और बैल्य टैक्स लगा दिया। एक तरफ तो किसान की जर्मान को एक्वायर करते हैं और दूसरी तरफ जब मर जाता है तो एस्टेट डिप्यूनी के लिये यम के दूत और उसके घर पहुँच जाते हैं कि उसकी जायदाद की कीमत क्या थी। यह एस्टेट डिटी के लिये भर हुए आदमी को भी चिपटना चाहते हैं। मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि हिन्दुमन्दान के किसान के जिसम पर आज बैपड़ नहीं है, सिफ एक लगोट उसके जिस्म पर है और ये बेस्टेट इटरेस्ट के लोग इन्स्ट्रियलिस्ट्स उस किसान के लगोट पर भी चिपटे हुए हैं। अगर यह लगोट टट गया तो यह बह बहा करें? मझे गोल्ड स्मिथ की 'दी डैवर्टेड चिलेज' पायम वा कुछ साड़ने याद आती है, जो कि इस तरह, —

"Princes and Lords may flourish or may fade, A breath can make them as a breath has made; But a bold peasantry, their country's pride, when once destroyed can never be supplied"

## [श्री मुकुनियार सिंह मलिक]

मैं आपसे यह श्वर्ण करना चाहता हूँ कि जिस किसान ने हिन्दुस्तान में आज अपना निर ऊचा किया, आपका हजारों, करोंडा रुपये का ग्रनाज बाहर से भगवाना पहुँचा था, उसन बचाया जिसके कारण आज आप दूसरे मुल्कों के मामने फैदे के साथ अपना सिर ऊचा कर के खड़े हो सकते हैं, वहरे कम्युनिटी में यह कह मिलते हैं कि हिन्दुस्तान आज ग्रनाज के बारे में आत्मनिभर है, उम किसान के साथ इस किस्म का सलूक आप न करें।

मैं श्री बरनाला माहव से नभ निवादन करना चाहता हूँ, येरा उनम बहुत अन्य विश्वास है, मैं जानता हूँ कि वह बहुत कार्रिल है, कि वह एश्रीकल्चरल पालसी, हाई नीरोंस निपारित करने के लिये हुए पा इसके साथ यांग नहे। आप स्कैडेनीवियन बट्टीज, आम्स्ट्रलिया, कनडा, अमेरिका में जाये, वहां एश्रीकल्चरल पालिसी किसान की कसलेशन से की जाती है, वल्कि किसान उसे डॉमेनेट करता है। लकिन हिन्दुस्तान में किसान के साथ क्या सलूक किया जाता है कि उसको पूछा तक नहीं जाता। किसान का नमाहान्द क्या है, उनका भड़कानी की तरह डॉट करते हैं। नीति निपारित तरत समय पास लागे का यांग करने हैं जो टड़े कमरा में बढ़वर, जिम्ले में या कोई आर बैंकर किसान की हुए पालिसी का नियारिन करा है। इसस वाम नहा चलेगा।

SHRI PALAS BARMAN (Balurghat): The Janata Government, particularly its Deputy Prime Minister and Finance Minister seems to be very much concerned regarding improving the lot of the rural people. In a country where about three-fourths of the population live in the countryside, this is as it should be. The question, however, is who are these rural people, for whom the Janata Government or its Finance Minister is really concerned? What has been the lot of the rural poor—the landless and the poor peasants—the vast army of landless agricultural labour—during the two full years of Janata Rule? How many landless peasants have been given land during this period, what has been done to ensure even the fixed minimum wages to agricultural labourers, what has been done to eradicate the bonded labour system from the face of rural India? It is by this criteria that the concern of any government for the rural poor would be judged and not

by parrot-like repetition of concern for the rural people.

The performance of the Agriculture Ministry would be judged not merely on the basis of increase in the agricultural production of the country. It is no doubt an important aspect of its job. However, no less important is the condition in which the production takes place. Under what condition the vast majority of the rural people are engaged in agricultural production? The poor peasants having a small plot of land are unable to take advantage of the improved methods of cultivation because they have no resources. The major portion of peasants in our country are in this category. Though they form a large percentage of land-holding population, the land area occupied by them is a small portion of total cultivable land. The largest section of the rural population is, however, without any land of their own. They till the land of others. Needless to say, they work in the land not of the poor peasant but of the big peasants. These are the new aristocrats. More often than not they have made nonsense of land ceiling laws and have managed to corner large area of agricultural land by means fair or foul. It is they who get maximum benefit of improved agricultural inputs. It is for them that Choudhary Charan Singh's budget is liberal. It is common knowledge that it is this section of the rural people who have thrived most after the abolition of landlordism. It is they who now lord over the country poor and keep them in abject poverty.

The Agriculture Minister fails to hold out any hope of a change in this picture and to uphold the interest of the village poor. Have any active steps been taken by him to ensure that surplus land is recovered and distributed among the poor and landless peasants? Even the work of distribution of the existing surplus land has made little headway in most of the States. The Prime Minister's home State which receives more than a fair share of the Prime Minister's

time, is reported not to have distributed any surplus land during these two years of Janata rule. How is it that the Prime Minister with his high moral stature would not make his own Party government move in this matter?

Our country has no dearth of persons who roll in wealth. If our agricultural produces fatten only a small portion of the rural people it cannot be said to have improved the face of rural India. The Janata Government seems to be committed to the service of the few rich—whether in the industry or in trade or in agriculture resulting in more and more impoverishment of the common man. Unemployment is rampant in villages but, as most of them are illiterates, their unemployment or under-employment seems to go unnoticed. The food-for-work programme has been much eulogised but it is no employment programme but a simple variation of test relief. At the end of two years of ten-year deadline set by the Prime Minister for the end of unemployment, more persons stand unemployed.

The village people require today not lip sympathy but concrete measures for their uplift. That would require certain drastic steps. The entire agricultural land should be redistributed among those who are actual tillers of the soil. Capitalistic mode of production should be banished from the agricultural field. Viable land units should be given to actual tillers of the soil. Cooperative system may be introduced to allow for large scale peasant cooperative forming with improved inputs. Agricultural people who won't be provided with land, should be provided with jobs in agro-industries and cottage and small-scale industries. The setting up of agro-industries and small and cottage industries in countryside should not end in mere talks, of which there have been no dearth. People

now want them to materialise. There is no other way to change the face of rural India. As one coming from the village, I can say that the government will be judged by what it does for improving the lot of millions of rural people. I may warn the government that they cannot be fed on mere words much longer. Time is fast running out. If even now, the Government does not change its ways, the people would not take their acute exploitation lying down any longer.

श्री तेज प्रताप सिंह (हमीरपुर) आप को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ने मेरा नाम पुकारा। मेरा नाम तेज प्रताप सिंह है, तेज बहादुर सिंह नहीं।

मैं बरताना जी को हादिक बधाई देना चाहता हूँ कि उन के नेतृत्व में कृषि मतालय ने अप्रत्येक तरफ़ी की है और इसकी हम आशा भी ये क्षमाकालीन राज में देहान की ओर आग किमाने की ओर यदि ध्यान नहीं जागाया तो चिम की ओर जागाया? 70-80 प्रतिशत नागरिक इमार देहात में रहने वाले हैं प्रीर 70-75 प्रतिशत के बीच में जो किसानी का काम करते हैं उन की बहवदी के लिए, धरान काम नहीं किया जाएगा तो हमारे देश की काई नरककी न रही सकती है उस की फाँटडेशन मजबूत नहीं हो सकती है। आप कुछ आकड़ों को दें—77-78 में 125.6 मिलियन टन खाद्यालय का उत्पादन हुआ जो कमी नहीं हुआ था। तो इसका श्रेय बरताना जी को ओर जनता पार्टी की सरकार का मिलना चाहिए। 77-78 में। (ध्यानान्तर)

सभापति मंडोदरी आप कृपया किसी की तरफ ध्यान न दे, अपनी स्पीच चाल रखें, दम दम मिनट मैं दे रही है।

श्री तेज प्रताप सिंह देखिए, उन को बीम बीम मिनट दिया है। बुन्देलखण्ड के माय यह धन्यवाद नहीं होना चाहिए।

सभापति मंडोदरी जब मधी लोग इम तरह बीस मिनट ले गे तो फिर बाकी लोग रह जाएंगे।

श्री तेज प्रताप सिंह : मधी मैं बताऊंगा कि बुन्देलखण्ड किलना उपेक्षित है। उस की ओर आप नजर रखें। आप भी बही से लोक सभा की सदस्या हैं।

77-78 में 2.6 मिलियन हेक्टेयर से लिखाई अतिरिक्त बड़ी जो पिछले दस वर्षों में 1.5 मिलियन हेक्टेयर के भीतर से आगे कभी नहीं बढ़ी। यह काम देखिए। अगले वर्ष 79-80 में 3.2 मिलियन हेक्टेयर होने जा रही है। इस से सावित होता है कि बहुत कठिन है और कमर कम कर हमारे कृषि भंडी जो और हमारी सरकार कृषि की तरफ़ी के लिए लगी

‘श्री लोब ग्रनाथ सिङ्ह’

है तो है । आप ऐसा न समझें कि मैं कोई अविज्ञानीय कार्य कर रहा हूँ । जो जीतत हमारी पैदावार वह रही है, जीतत अधिनियम जो सिवाई के साथम भूम्या किए जा रहे हैं इस के लिए वे बवाई के पात हैं । इसी तरह कॉलेजियर में हुम्या है । बिना कॉलेजियर का इस्तेमाल किए रहे हमारे बड़े भी कृषि उत्तरिन नहीं कर सकती है, पैदावार जीवी बढ़ सकती है । उस में सभी आप लेंगे कि 43 लाख टन का इस्तेमाल 77-78 में हुम्या है । यह करीब करीब 26 प्रतिशत बढ़ोत्तरी है यिल्ले वर्ष के मूकाविले में । तो मैं बाह्यिक देना चाहता हूँ और यह सही है कि वह प्रजाव ले भाते हैं, प्रजाव पर हमें नाज है, प्रजाव पर कही माने में हमारे देख के लाग नाज कर सकते हैं, लेकिन बरनाला जी जरा न्यून कर रहे हैं की बाबू करे वे प्रजाव में आगा ह हमारा न्यून कर रहे हैं और इस पोटेंशियल का न सलाल रहे हैं यह हमारे लिए कष्ट की बात है । लेकिन एक शिकायत हम का है बरनाला जी से कि प्रजाव का तो उन्होंने देखा और प्रजाव की तरकी को वह जानते हैं, हर जीज में असरत है लिए देख के भोज लिसी कान वे वह नहीं जाते हैं । कभी कभार जाते हा न जाते हा । मैं जीवी महादय वा व्यापार बुद्धेज्ञद की आग जीवी बाताना है जहा पर उन्होंने कुछ की तरकी के लिए एक धार काम खाल रखा है । भारत मरकार ने खालाम्ब की तरकी के लिए वहा पर एक धार के काम के अलावा और काई काम नहीं खाल रखा है जबकि वहा पर एकल धार ही नहीं होता है । बहा पर अब पैदावारी भी होता है सच्चलम अभ पैदा होता है । वहा पर मैंने एसी जीज पैदा होती है जिनके लिए रिसर्च करना बहुत ही ग्रस्तरी है जैसे कि अलगी हैं । ता वा हो पर इसके लिए आप काम कर रहे हैं ।

बूद्धेलखड़ मे निचाई के साधना भी प्रारं बाई भी व्यान नहीं दिया जा रहा है । जब नक बहा पर हाई ईंटिंग बेरायटीज का इस्तेमल नहीं होगा और निचाई के साधन नहीं बढ़ाया जायेग तक तक हाई की नस्की नहीं की जा सकती है । इस दश का टोटल कार्टिनेटर एरिया का 25-30 प्रतिशत मिल्हिं है जबकि बूद्धेलखड़ मे केवल 10 प्रतिशत एरिया ही नियत है । अभी मे बही पर गया ता लाग कह रह कि सन्तूल भारतगाहेशन, वाटर बोर्ड से एकमालोरेटरी ट्यूबवेल लगाए जा रहे हैं । हम लोगों को कुछ पता नहीं कि कौन जाता है और क्या प्रोद्याम है । इसलिए ऐसे प्रादेश दिये जाने का चाहिए कि कम से कम जो जटाता के प्रतिनिधि है उनको पहले से घबवत कराया जाना चाहिए और प्रारं बार कोई अवधारणा अपना यह सुनावे दें कि कर्फ अदा नहीं करते हैं तो उनको सजा मिलनी चाहिये । तो अभी तीन-चार दिन हाल, मे बहा पर गया था, हमारे पास समाप्ति यादवजी आए और कहा कि बिगहारा भाग मे एकमालोरेटरी ट्यूबवेल की ड्रिलिंग हुई है । उनको कुछ पता नहीं था कि उसका किताना डिस्चार्ज है कितना ही नहीं है । मे ने अनिस्टेट इन्जिनियर को बुलाया और जिनी मार्ग मे थे तो उन्होंने कहा कि इस ट्यूबवेल को इसलिए केल कर रहे हैं कि उसका सेलेन 15 हजार रीलन प्रति घंटे का डिस्चार्ज है जबकि सरकार का

नाम वाले हैं कि 30 हजार गैलन प्रति बंटा को विस्तारीय हो तभी उसको सरकार टेक-ऑफर करेगी। जैसकि बून्देलखण्ड रेसा पूरिया है वहां पर पानी की निकासी कम ही होती है। इस तरह की बैंकिंग लैप में भी प्राप्ति की होती है और प्रस्ताव भी पास राजनीति लेगा है कि 30 हजार गैलन प्रति बंटे के विस्तारीय की तरफ है उसको बढ़ा करके बून्देलखण्ड के इलाके के लिए 10 हजार गैलन प्रति बंटा रखा जाए। इसके द्वारा वहां पर 100-150 एकड़ मूल्य की विस्तारीय तो हो सकती है। हमारे यादव जी बता रहे थे कि इस टट्टुबोले में पानी जब निकलता है, हां उनको हां वात मालूम नहीं की 30 हजार गैलन वा विस्तारीय है वा नहीं। इसलिए, मगर सुनाव है कि बून्देलखण्ड के लिए वां बाटे विशेष हृष से की जानी चाहिए। बून्देलखण्ड के 10-15 जिले हैं। वहां पर टट्टुबोले के लिए 10 हजार गैलन वा नाम निश्चित किया जाना चाहिए। दूसरे जा वहां का पहाड़ी इलाका है, पथरीला इलाका है वहां पर आपको स्थगल रिज भेजने चाहिए जाकि पर वां भी बाट सब। मध्य प्रदेश में बून्देलखण्ड के इनाम में कुछ गेसा काम है। और वहां पर 10-15 हजार गैलन तक पानी निकल आता है जिससे सैकड़ों एकड़ जमीन पर स्थाई हाती है नथा हाई ईलिंग वेरायटीज बांझ जाती है। ना विस्तारीय के मध्य-धू मरे यह दो सुनाव हैं।

जहा तक नाथ ईस्टर्न रोजन का सवाल है, मैं अभी जनवरी म गया था मनीरुर देखने का मुसे, श्रवमन प्राप्त हुआ। बहा पर प्राप्त हेम बना रो है जिसके प्रलेखित निर्माण जनरेट हागी कान में सूख दिवाह के रो हें थे। आज बहा पर निचाहे के बनावट भी बनावे। नागरिक शहर मिजाराम में रेवेन्यू दिवाह नहीं रखे जाते हैं। बहा लेखपाल भी वही है। बहा के मन्द मन्दी से जब हम मिलने के लिये गये तो हम का बताया गया कि वहां पर ली-टिकाईस भी नहीं रखे जाते, यकोड़ी मारी जायीन सामूहिक है कम्पनीज लड़ते हैं। हम एं में कोई जान ही नहीं यह बहु अच्छी व्यवस्था है वे अपने जाता उस जमीन को आपस में वितरिक कर लेते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि उन को उस जमीन पर बहु मरी मिलता है। मैं आप से यह अनुरोध करूँगा —नार्म ईस्टर्न रोजन में जहा व्यवितरित देनेवाली की अवस्था नहीं है, उन के लिये बहु व्यवस्था की व्यवस्था नहीं है, उन के लिये बहु व्यवस्था की व्यवस्था की जिये, बनावे वह एरिया पूछि वह आएंगा, उस की तरफ़ी नहीं हो सकती।

भव ने तिलहन के बारे में कुछ शब्द कहना आहता है—इस में सन्देह नहीं कि हरारे भट्टी औ उस तरक्की व्यापार के द्वारा है। लेकिन हजारी करेंगे विषय का ध्यान देखते हाथ लाय और हम विजेतों से देख का करेंगे—यह बड़े की बात है। तेजरे यहां वेस्टस्ट्रीट

ज्यादा ज्याता है—हम देख रहे हैं पिछले दीन सालों से सरसों और ताजो नहीं ही रही है, बर्याकि उस में 'भाग' ज्यों जाता है। इस के बारे में रिसर्च हासी बाहिये ताकि हम इस से छुटकारा पा सकें।

आप पाच सालों में 17 मिलियन हैट्टेयर में एडी-ज्यान-इंटरियोजन-सीसिलिटीज बेने जा रहे हैं। लेकिन जब 90 या 100 मिलियन हैट्टेयर भूमि आप के पास प्राप्तिकृत है तो आप को 10 सालों में हर बीते के लिये पाली देने की योजना बनानी चाहिये, 17 मिलियन हैट्टेयर में पाली पहचाने से काम बल्ने बाला नहीं है। आप इस से लिये कहीं से भी लागत लीजिये, बल्कि बैंक से लीजों—लेकिन 10 सालों में सारी भूमि आपने बिलियन कर सके—ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये। आगे बाले मालों में 125 मिलियन टन अनाज पैदा करने का आप का लक्ष्य है—मैं समझता हूँ यह पर्याप्त नहीं है, आप का लक्ष्य 500 से 600 मिलियन टन बाकाल पैदा करने का होना चाहिये। इस तरह से जहा हमारे किमान तरकी बाजार होता है, वहा रह गाव में 30 सेक्टर नेट-जेस लेवर है—उन को भी लाग पहुँचेगा। मैंने आप की रिपोर्ट को पढ़ा है, बहुत अच्छी रिपोर्ट है, उस की प्रशंसा की जानी चाहिये, लेकिन साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि इसमें लेंड-रिकॉर्ड के बारे में बहुत ही काम नहीं लिया है, यह अच्छी बात नहीं है। मैं हर गाव में जाता हूँ वहा के किमान, हाइजन मस्त से अलग से मा कर लिया है। 10 मान से दा-डाई एकड़ के पट्टे दिये हुए हैं, लेकिन आगा एकड़ पर भी कम्बा करने को नहीं मिला—यह दुर्घट्यवस्था है। आप कहने हैं कि 6-45 लाख हैट्टेयर भूमि वितरित कर दी है, यह काम पर वितरित है, लेकिन उन के कम्बा नहीं मिला है। आप ऐसा करने बनाये—जो 20-0 एम-या ताहसीलांजर उन को कम्बा न दिया सके, उन को जमीनी की बाउलीजर न बता सके, उस का सप्तेष्ठ किया जाए, उन को मजा दी जाए। जब तक आप इनी सभी से काम नहीं लेंगे, यह काम नहीं चलेगा।

आखिर मे मैं एक बात कह करापोरेशन के बारे में कहना चाहता हूँ। हमारा हजारों कराड इयाया इस में लगा हुआ है, यह भी सही है कि हम का सम्मो-डाइज रेस्म पर गला मिले—लेकिन यह बात भी सही है कि हजारों टन गलना याद ले जाता है, बुरवाप से जिक्र जाना है और पता भी नहीं चलता। इस बीच जिक्र जाना चाहिये। वहाँ पर जो मजदूर काम करते हैं—एक साथ हुआ उन के समेत न में बरताला। साहब बते थे, उन के निरेवत किया गया था कि वहाँपर जो बिलोलिये हैं, ठेकेवार हैं, उन को एलिमिनेट कीजिये—लेकिन अभी नक कुछ नीतियाँ नहीं निकलती। एक बोध टूट गया था, मैंने बहा देखा कि ठेकेवार मजदूरों को 3 रुपया दे रहा था, लेकिन कामजूद 5 रुपये के लिये वस्तवत करा रहा था। इस तरह से ये ठेकेवार लूट करते हैं। पिछले दीन सालों में हमारा जितना इयाया इन कालों पर बर्च हुआ है, यदि ठेकेवार बीच में न लूटते हो आगा इयाया बर्च कर के हम उन कालों को भरा करके दे। इस लिये यह ब्रेग समाज हीमी चाहिये।

आप की रिपोर्ट में एक बीज की तरफ ज्याँच लिया गया है कि बब बल्से का उत्तरान बहुत बड़ा आएगा, तो उस के मार्केटिंग की प्रबलग पैदा होती है। बाजी हमारे नव्वूचिह जी कह रहे थे कि हमारा बाजी हमारे में मारा मारा किर रहा है। इसलिये हमको भारी से हमारा स्ट्रेचर लैयार करना चाहिये। आज हमारा यहा जो कोडापोरेटिव मार्केटिंग लैसाय-टीज है वे डार्मेट हैं, मरी जा रही है, उन के पास वैसा नहीं है जिन को निरीक्षण नहीं हो सकता है। आगामा में बहा के किसानों ने मिल कर बहुत बपता इन्डस्ट्रीजर लैयार किया है, वहा पर बिचौलिये बस्त हो गये हैं। मुझे एक जगह से जाया गया थीर बतलाया गया कि वहा पर जो महल बड़े हुए थे वे पहले बिचौलिये के थे, अब हम ने उन को बाटन कर दिया है। मारा काम किसानों के हाथ में ही थीर थार उन को बहुत अच्छी रिटेल मिलानी है यहाँ तक कि उन को 2 डालर प्रति बल्ल के डिमान से एकस्टा कीमत मिली है। जो गल्ले में प्रोफिट होता है, वे बिचौलिये आ जाते हैं। जो गल्ला बरकार का देते हैं, उस में वे एकस्टा प्रोफिट कर लेते हैं। मैं आप को बताऊं कि मैं 150 रुपा क्विटल मसूर बेचता हूँ थीर उस रेट को बिचौलिये 250, 300 रुपये क्विटल बेचते हैं थीर इतना ज्यादा मुनाफा वे कमा लेते हैं। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि एक कोडापोरेटिव मार्केटिंग स्ट्रेचर आप तैयार कीजिए। उस से यह जो प्रारंभिक गल्ले को बेचने की है या प्रारंभिक करने की है, वह हल हो जाएगी। बन्वेलचूप की ओर मैं फिर से आप का व्यापार दिलाना चाहता हूँ।

इन शब्दों के साथ मैं समाप्त हरना हूँ।

धी कलहलाल हैबराज जी (बालाघाट) : मार्गापन महोदया, कृषि मांगो पर जो बोलने के लिए आप ने मुझे अवनर प्रदान किया है, उस के लिए मैं आप को धन्यवाद देता हूँ।

कृषि मंत्रालय, कृषि विभाग हमारे भारतवर्ष की गेंडी की हड्डी है थीर इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं मानता हूँ कि पिछले दो सालों से, नई सरकार के आने के बाद, कुछ एक अच्छी बातें मामारा आई हैं थीर इस सरकार ने 80 फींटीयी गाड़ी में बैठे हुए किसानों की ज्ञान ध्यान दिया है थीर कुछ नई व्यवस्था भी की है जिस के अच्छे प्रयोगान्वयी ही हमारे उपचाने थे। किन्तु हम यह देखते बैठे था रहे हैं कि कृषि का थीर किसानों का जो सीधा सम्बन्ध कोडापोरेटिव बैंकों थीर सोमाइटीज में ही थीर उन को सहायता पहचाने के लिए, उन की उपलिंग कराने के लिए पिछले कासको ढारा जो कोडापोरेटिव बैंक, सोलाहटिया थीर पैंची विकास बैंक धार्ति सम्बन्ध बनाई गई थी, थीर बाहरे भारतवर्ष के लिए एक बहुत बड़ा कलंक है। कोडापोरेटिव बैंक या भूमि विकास बैंक, जिस दिन से इन की स्वापना हुई है, नई अलाघाट निरस्तर पिछले दिनों से बला था रहा है थीर आज भी बही जारी है। धीर हृषि मंत्रालय किसानों की मदद करना चाहता है थीर उस की मही से एलाइंगट होता है कि इतनी किसानों को सम्बोधी दी जाए।

## [की कचरालाल देवराज जैन]

इतना कहन दिया जाए, तो वह उन तक टीक से नहीं पहुँचता है। औरों कोई बनाएगा और खाने का बितरण कीह करेगा। इसी तरह से यह पर हो रहा है। अगर-अलग विभाग हीने के कारण और कृषि विभाग का सीधा सम्बन्ध न होने के कारण, जो लाल आमीण किसानों को मिलने चाहिए, वे उन्हें नहीं मिल रहे हैं। जो लोन उन को मिलना चाहिए, उस समय पर उन को नहीं मिलता रहा है। अभी नई स्टीमों वे अनुसार, आमीण किसानों को पशुपालन के लिए और कई प्रबाल क परेल उद्योग खोलने के लिए पैमा दिया जा रहा है तो उन मध्ये यह हाता है कि कामारारिटी डिपार्टमेंट में काम बरने वाले जो कमचारी हैं वे उन को बहले हैं कि अगर सरकार 50 कीमीपैका माफ करेंगी, तो दूस हम को 20 कीमीदे दी। अगर 20 कीमीदी पैका देते हों, तो आप करा दग। इस तरह की घोषणाही चल रही है कि अगर मैं यह समझता हूँ कि इस देश के किसानों का सपना पूरा नहीं बर नहीं जब तक कि पूरा नियन्त्रण इस मद्दालय के अन्तर्गत न आ जाए। इसलिए कृषि मद्दालय के माय उन सब सम्बन्धित विभागों को जोड़ देना चाहिए नहीं तो पकास सौ माल तक यही हाम उन वा मदद पहचाने की कल्पना बरते हैं वह पूरी नहीं होगी और उस में आप सकाम नहीं होगे।

हरिजन और आदिवासियों वा भूमि बाटों गई है और उस का बायक्रम भी चल रहा है और गावा मरोजागर देन वी बाटों भी चल रही है। अनाज के बदल का कायव्रम भी चल रहा है हम यह देखते हैं कि जिन हलाको मध्ये उन लगानों का दस दस और पन्द्रह पन्द्रह साल पहल बाटों जो चुकी है अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि उम वा बड़ा भी उन का नहीं दिलाया गया है और अगर कन्जा भी मिल गया है तो कृषि योग्य वह भूमि नहीं है और उन मध्ये उन में इतनी शर्किन नहीं है कि वे उस का कृषि याय बना सकें। मैं ने लास्ट टाइम भी कृषि मद्दालय की मामी पर बालने हुए कहा जा कि उम से नम उन को कथियोग्य भूमि दे और इतने मारे जा बायक्रम आप क बन रहे हैं, उन में आप उन को रोजागर वा और अनाज क बदले बाम दे। अगर ऐसा किया गया तो उन की खेती भी दुरुल हो जाएगी और हरिजन और आदिवासियों के पास जा भर्ति है वह भी खेती बरने लायक बन जाएगा। यह नहीं हां या रहा है। कृषि मद्दालय ने फूड कार्यालयान आफ ईडिंगा से अन्ती बालिटी का अनाज ऊंचे रेट पर खरीदने के लिए कहा है। मैं तुखी भी हूँ और मैंने शिकायत भी की है कि जो अनाज उमने हारा मरियों से खरीदा जा रहा है वह चरिया किसम का है और आपारियों के साथ उनकी खुली साठगांठ है और आराम से वे घटिया किसम का माल खरीद रहे हैं और नियमित रूप से उनका उस में दो रपये या चार रपये विवरन के हिसाब से बढ़ा हुमा है। इस तरह से जो बाल खरीद कर गोडाउज में रखा जा रहा है वह बहुत ही घटिया किसम का है। मैं लिख कर देता हूँ या कहता हूँ दो आपके कूड़ कार पोरेशन के अधिकारी बहते हैं कि जनता के प्रतिनिधि हमारे काम से बदल नहीं देखते हैं, हम सेट्टल गवर्नर्मेंट के व्याधीन हैं। ऐसे जिले बालाप्राप्त में आप जांच करना

कर देख ले कि वहां घटिया माल खरीद कर गोडाउज में रखा गया है या नहीं। मैंने आप से शिकायत की भी, आपने उपने जासूसीय विभाग से कर्मचारियों को भी भेजा लेविन कोई कारंवाइ नहीं हुई। जिस किसम का माल लेना चाहिये वा उमसे बहुत ही घटिया किसम का अनाज लिया जा रहा है और लिया गया है। आप काई जांच नहीं करते हैं। इस अवस्था में कैसे आपका विभाग डग से चल सकता है। पुन ऐसा आप से निर्देवन है कि आप ने रेट बढ़ाया है तो आप बालिटी को भी देखें और हमको भी देखें कि उस बालिटी वा माल आप के प्रधिकारी खरीद रहे हैं जिस बालिटी वा माल आप चाहत है कि प्रधिक रेट वे कर खरीदा जाए।

वायलड राइस जिस वा बहते हैं उसकी खरीद के मामल मध्ये बड़े उद्याग बालों का ही मोका दिया जा रहा है १० लं शंग या छाट उद्याग बालों वा माल नहीं लिया जा रहा है। आपका विभाग बालों वहते हैं कि यह चावल चबन लायक नहीं है। वह उद्याग से उमका बालिटी अल्ली हां वा बावजूद भी बढ़ा जाता है कि इसका धोरीदा नहीं जा सकता है क्योंकि यह चलने सायक नहीं है। मैं न आपका विभाग का एक्यौं से भर कर उम चावल वा संभल भी दिया है और उमका दिया हुए डक महोना हा गया है लाकन उमका एन निम्म रिजल्ट प्रान दिया गया है या नहीं, मध्ये पता नहा है। उमरा काई उत्तर मध्ये नहीं मिला है।

मैं आपका धन्यावद दता हूँ कि आपका विभाग ने बांधों तरकीबी भी है मिलाई मध्ये भी बांध है। लालन पुरान शासक के जनता से जा रिश्वतबांधी और बालिटी है इस विभाग मध्यांत भी वह बहुत सामान्य है गई है और आव दमदा बालवाला नहीं है इसका बालन क जनता मैं लैयार नहीं है। आज भी व्यापारियों से धृतले से और खलोआम रपये लिया जा रहा है। घटियावस्था का अनाज गोडाउज मध भरा जा रहा है। यह लीड है कि अनाज क मामल मध अब सरपलम हो गय है और हम का बिदेशा का भी अब अनाज भेजता पड़ेगा। इस बाल रेट ज्यादा द बर हम अच्छी किसम वा अनाज गोडाउज में रखे हैं इस और आपको विशेष ध्यान दिता होगा।

मैं यह भी चाहता हूँ कि हरिजना आदिवासियों को जा पिछे जानको न भूमि बाटों है और आप भी बाट रह वह हृषि याय बना बर ही उनको दी जाना चाहिए। जब तक उसको हृषि याय बना करत उनको नहीं बदला जाता है उनका काम नहीं बन सकता है। उनके पास इतनी ताकन नहीं है, इतन साधन नहीं है कि उसको हृषि याय बना सक। अगर आपने ऐसा किया तो उन गरीबों की बदल होगी और हमारा देश भी उत्तित करता।

भी अन्नसेवर सिंह (बागणसी) हृषि और आमीण व्यवस्था के विकास के लिए जो बड़ा सद्व दरवाजे हैं उसके भान्नमध में जो जनता पार्टी का बोलचालपत है, उसको मैं आपके मामले रखता चाहता हूँ। हृषि से आमदानी बहुत कम है और गांध के निची

अवसाय को प्रोत्साहन नहीं मिलता, इसलिए मांद में पूंजी नहीं बनती। इसलिए इसके विकास के लिये जनता पार्टी एक राष्ट्र-भाषी नीति घपनायें भी इस लेव में कम-से-कम 40 प्रतिशत खर्च करेगी। पहला बजट जब जनता पार्टी ने पेट किया तो वह 37.2 प्रतिशत था, दूसरा बजट पेट किया तो वह 40.29 प्रतिशत था और तीसरा बजट 43 प्रतिशत है। लेकिन घपने कृषि मंत्री श्री सुरजीत सिंह बरनाला और कृषि राज्य मंत्री श्री मानुप्रताप सिंह के रहते हुए मैं सोचता था कि वह जो 40 प्रतिशत का प्रस्ताव आपके पास तक पूरा किया, वह देखने में 43 प्रतिशत सगत है। देखने में यह प्रस्ताव माधृ है, लेकिन इसमें कुटिलता भरी हुई है। अग्र इस कुटिलता के जाल-बड़े का माननाय मंत्री जी काट सकते हैं इस देश पर और देश की खेती के उन्धान पर बड़ी कृपा होगी। इस पूरे के पूरे बजट में जो 43 प्रतिशत का है, इसमें जो कॉटिलाइजर पैदा होता है और उसमें जो फैक्टरियों पर पैदा खर्च होता है, वह मौ कृषि और ग्रामीण व्यवस्था में जोड़ दिया गया है। आप देखें कि कैमिली वैलेसियर पर जो पैदा खर्च होता है, उसका 7.5 प्रतिशत भी इसी ग्रामीण कृषि व्यवस्था पर जोड़ दिया गया है। स्मान स्केन इंडस्ट्री पर जो पैदा खर्च होता है, वह भी इसी बजट में जोड़ दिया गया है। नवये मंत्रीदार और नोट करने की बात यह है कि स्मान स्केन इंडस्ट्री में जो 15 लाख रुपये तक की कैमिली खड़ी करेगा, वह भी लग उद्योग धर्म में आता है। प्राज्ञ गवर के किस आदीकी की हैंगियत है कि 15 लाख रुपये का उद्योग धंधा वह खड़ा कर सके? लेकिन उम मद को भी इसमें जोड़ दिया गया है।

जो आधिक उद्ययन की पूंजी है, जिसको कहा जाता है कि हमने कानिकारी तबदीली की भूख जगाई है, हमने गांव की धोर जाने का महाप्रयाण किया है, जरा उसकी तरफ भी ज्यान दें।

सार्वजनिक लेव के लिये रखे गये कुल पूंजी विनियोग के साधनों का कम से कम 40 प्रतिशत कृषि और ग्रामीण विकास के लिये निर्धारित किया जाना नरकार का प्रति आवश्यक लक्ष्य होना चाहिये। इन पूंजीयत साधनों में पक्षी सड़कों, परिवहन और शिक्षा पर लगायी गई राशि जासिल नहीं होती।

लेकिन मैं प्राप्ते प्रनुरोध करंगा कि काम के बदले जो अनाज योजना प्राज्ञ चल रही है और उसमें जो ग्रामीण मड़के बन रही हैं, उनको मैं इसमें जोड़ दिया गया है। यदि सब को मिलाकर देखें तो और भी मजे की बात है कि जीनी, कगरकोन, जट और काटन की जो इडस्ट्री है, उनको भी कृषि के अन्तर्गत जोड़ा गया है। यदि कॉटिलाइजर पैदा होकर खेतों में उत्थान हो, इसलिए उसको खेतों में जोड़ा जाये, तो इन फैक्टरियों में जो खींचें पैदा होती हैं, जो कि खेतों में इस्तेमाल नहीं होती है, उनको इंडस्ट्री में क्यों नहीं

जोड़ा गया। दोनों तरफ दुश्मान तक चलते हैं। एक भूमि में जिसके दो जीम होती है, वह जानवर बहुत ही खतरनाक होता है। यह पूरे का पूरा शुगर के और जट जो पैदा हो, उसको भी इसमें जोड़ दें और कॉटिलाइजर भी इसमें जोड़ दें, यह ठीक नहीं। भगवर इन सारी मदों को इसमें से निकाल दें, तो मैं बड़े अवक के साथ कृषि मंत्री जी से अनुरोध करंगा कि पिछली बार जो 31, कुछ और अब की बार 34, कुछ खर्च करने जा रहे हैं, तो 40 प्रतिशत की बात प्रभुरोधी रह जाएगी। आगे हालत इतनी खराब होती।

कभी कभी शर्म आती है, लोग पूछते हैं कि जनता पार्टी ने बड़ी शर्म के साथ कहा था कि हम गांव और जा रहे हैं, महाप्रयाण कर रहे हैं और जब हमारे मंत्री और हमारी जनता सरकार के लोग कहते हैं तो गालिब का एक शेर याद आ जाता है:—

ग्रा वका ना-आशाना, कब तक सुन तेरा गिला, बेवका कहते हैं तुमको, और शर्माता हूँ मैं।

बेवका श्रीमान को कहते हैं, लेकिन शर्माता हमें पड़ता है। लेकिन शर्मांकर भी काम करते चले जा रहे हैं। विचित्र स्थिति है। सारे के सारे कृषि जोवन में आज एक विष घुल रहा है, जरासा इन सब जीवों की तरफ नजर ढालें।

14 hrs.

इस देश में जीनों का दाम तय होता है क्योंकि वह फैस्टरी में बनती है लेकिन गन्ने का दाम तय नहीं होता कि इसका लाभप्रद मूल्य क्या है, लाभप्रद मूल्य और समता मूल्य क्या है। आज तक इन जीनों मूल्यों—लाभप्रद मूल्य, समता मूल्य—के निर्धारण की कोई व्यवस्था नहीं हुई है। जीनों का दाम तय होता है, क्योंकि उसको फैस्टरी और इंडस्ट्रियलिस्ट बनाता है—उसका लाभ प्राइवेट सेक्टर में उद्योगपतियों को मिलता है और प्राइवेट सेक्टर में व्यारोकेट्स को मिलता है। पंजीपतियों, व्यूरोकेट्स और सरकार के इस विचार से गन्ने का दाम तय नहीं होता है, लेकिन जीनों का दाम तय होता है। यही हालत लड़ी की है—लड़ी का दाम तय नहीं होता है मगर कपड़े का दाम तय होता है। आज ही इस सदन से इस बारे में बहुत चल रही थी, जिसमें उद्योग मंत्री, श्री जाजे कर्मनीस, से सवाल किये गये। श्रीमती बन्द्रावती ने कहा कि जब पिछले साल लड़ी का दाम 355 रुपये प्रति किलो था, तो कपड़े का दाम 5 रुपये प्रति मीटर था, लेकिन इस साल जब लड़ी का दाम 260 रुपये प्रति किलो है, तो कपड़े का दाम 11 रुपये प्रति मीटर है। जब लड़ी का दाम घटे, तो कपड़े का दाम बढ़े, यह व्यवस्था कैसे चलेती? इस व्यवस्था के बारे में हमें भी आपको सोचना होता।

14.02 hrs.

[SHRI Dhirendranath Basu in the Chair].

इन चीजों को पैदा करने में चार तरह की पानी इस्तेमाल होते हैं। कबीर ने कहा है :

माया महाठगनि मै जानी,

केशव की कमला बन बैठी, शिव के भवन भवानी।

पढ़ा की मृत्यु बन वैठी, लांगूल मे भई पानी।

पानी का बड़ा महत्व है। लेकिन मरकार गेह और ग्रनाज पैदा करने के लिए जो पानी बेचती है, उस पानी के चार दाम है। राजकीय नलकप से जो पानी मिलता है, उसके अलग दाम है। नहर से मिलने वाले पानी के अलग दाम है। बाध में जो नहर निकलती है, उसके पानी के अलग दाम है। डाल कमाई जाना, लिफ्ट इरिंगशन, के पानी के अलग दाम है। पांचवा पानी वह है, जो निजी नलकप से निकला जाता है, उस के दाम अलग है। लेकिन जब गेह बाजार में आवेगा, तो उसका एक ही दाम है। ऐसा नहीं है कि जो जालान और गेह, 60 रुपये प्रति एकड़ वे पानी से पैदा किया जायें, उस का दाम अधिक है। गेह 15 रुपये प्रति एकड़ वाले पानी से पैदा किये गय जालान और गेह का दाम कम है।

मेरे एक मवाल के जवाब में राज्य मवी ने बहुत पहले कहा था कि मरकार ऐसी व्यवस्था कर रही है कि मधी पानीयों के दाम एक ही जाये। इस बात को माल, डेंग साल हो गया था, आज नक उस योजना पर भ्रमन करो नहीं किया गया? पानी के दाम को नहीं एक विषय बने, जबकि पानी से उत्पादित चीजों के दाम एक है?

हमारे देश मे 35 करोड एकड जमीन पर  
खेती हो रही है। उसमे से 10, 11 एकड  
जमीन ऐसी है जहा एकांड इरियेशन है  
और जहा उत्तरक का भी इस्तेमाल होता है। अगर  
फी-एकड टन भी मान ले तो 11 एकड  
जमीन से लगभग  $16\frac{1}{2}$  करोड टन का उत्पादन  
होता है। लाखी 12 करोड टन का उत्पादन  
मिक्वाई की है, जिसे आस्तमान महारे, आकाश  
आसर या अधिकान आमे कहते हैं। अगर वहा  
का उत्पादन प्राथ टन की एकड मान लिया जाये,  
तो वहा 12 करोड टन का उत्पादन होता है।  
इस प्रकार हमारे देश मे कुल उत्पादन 28  
करोड ट० का हुआ। लेकिन सरकार की ओर  
से बताया जाता है कि पिछले माल 12.60  
करोड ८० का रिकार्ड उत्पादन था और अब  
15 करोड ८० का रिकार्ड उत्पादन था।

सबाल यह है कि ये आकड़े बलाने व से कौन  
लोग हैं, किन एजेंसियों द्वारा ये आकड़े बनाये  
आते हैं? इस दैश में 60 करोड़ लोग दूर होते  
हैं। जेल मैनुफ्लास के अनुसार एक आदमी को  
750 ग्राम आजाज मिलना चाहिए। इस विसारण  
में 60 करोड़ लोगों के लिए 16.20 करोड़  
टन आजाज बैठता है, लेकिन 12 करोड़ टन  
उत्पादन बताया जाता है। इस स्थिति में कहना  
पहसु है कि या तो ये आकड़े गलत हैं या और या  
हिन्दुस्तान के आधे आदमी आज भी भूखे रह  
रहे हैं। लेकिन मेरी ममक में ये आकड़े बलान  
हैं, उत्पादन उदाहर हो रहा है। इस मरकार का  
नियर्यात की दिलानी के कारण आज देश का  
किसान रोज बरोज दिवर हो रहा है। इस गांवों  
की ओर महाप्रयाण करने की बात करते हैं,  
नगर शहर की अट्टालिकाओं को ऊंचा करने का  
काम कर रह है। 1974 में अनाज वा नियर्यात  
हड्डा—460.29 हजार टन, 1975 में 2449.6  
हजार टन, 1976 में 18250 हजार टन  
1977 में 18036 हजार टन—इस ता अपर्याप्त है  
कि निरन्तर घटना यद्य।

आप चीनी को लीजिये—1974 में, 443 01 हजार टन का नियांत हुआ, 1975 में 996 01 हजार टन, 1976 में 843 07 हजार टन नियांत है, लेकिन 1977 में 251 08 हजार टन नियांत है—हम का अप्प है कि 1977 में प्राप्ति में भी कम चीनी नियांत है।

1973-74 में गन्धे का मूल्य 10 26 70 प्रति विकल्प निश्चित किया गया, 1974-75 में 10 40 20 प्रति विकल्प, 1975-76 में 11 60 प्रति विकल्प, 1976-77 में 10 80 20 प्रति विकल्प और 1977-78 में 10 80 30 प्रति विकल्प

बौद्धरी बलद्वीर सिंह (होशियारपुर) यह मत्त्य वहाँ है? यह तो मिर्क कागज पर है।

धी चालूहोर तिह यह बात टीक है—  
 10.80 रु प्रति विटल कागज पर है जब  
 कि 4 से 5 रुपये प्रति विटल में गशा विटल  
 या किसानों ने उस को दियासलाई लगा कर  
 जाना दिया। आप देखिये १०क तरक किसान  
 की हालत यह है कि गशा उस को जलाना पड़े  
 रहा है तरह मन्दे भाव पर बचेना पड़े रही है  
 दूसरी तरफ आप जरा चालून के पीछे दूसरी तरफ का  
 को देखिये। यह हमारी अपनी भूमिकार है, यह  
 भूमिकार आधिक नीति के द्वितीय से ममता मूल्य  
 चाहती है, पैरिटी-प्राइस चाहती है, नैकिंत जग  
 चीजों के दामों को देखिये। 1971 में चालून का  
 थोक सूचीक 103.3 था, 1974 में 174.7  
 था, 1975 में 188.2 था, 1976 में 154.9  
 था, लेकिन 1977 में 163.6 हा था। हम का  
 धर्य है कि 1975 में 188.2 था लेकिन 1977  
 में 163.6 पर चला गया, यानी 6-7 परसें-

सवभग माइनस हो गया । यही हालत खेड़ी ० रुपये है ।

अब मैं आप का व्याप खेड़ी में इस्तेमाल होनेवाली चीजों के मूल्यों की ओर ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि जो चीजें खेड़ी में पैदा होती हैं उन के मूल्य नों पटते जा रहे हैं सेकिन औं चीजें खेड़ी में इस्तेमाल होनेवाली हैं—उन के दाम बढ़ते जा रहे हैं। हमारी कृषि व्यवस्था रीढ़ से जुड़ी हुई है, आज हमारी रीढ़ टूट रही है, परंपरा हाने जा रही है, इन्सान मरने जा रहा है। आज इनान खेड़ी नहीं कर रहा है, आज उम को डागर करे, जानबर करे, आज इन्सान के मृत्यु में जानबर खेड़ी में लगा हूँगा है। मैंने पिछले माल भी कहा था कि कृषि लाग कृपि वा 'कृपि भवन्य चीजेन' ममझते हैं लेकिन मैं इन का 'कृपि मम्भन्य जीवन' ममझता हूँ। आज कृपि में मृत्यु लाग नगे हुए है जो इन्हाँ अधिक परिश्रम करते हैं जो दोपहर का इनानी मल्ली धूप में अपना रुद्धिया का जलाने है लेकिन फिर भी उन का १४० के मुकाबले में कम दाम वाले १४० के मुकाबले में बढ़ रहे हैं और इन्हीं नरक आप यह देखिये कि खेड़ी में काम आने वाली जो इसी चीजें हैं उन के दाम कितने बढ़ गये हैं। आप बैटरी को ही न लीजियाँ। बैटरी ड्रेवर में इस्तेमाल होती है ग्रोंसेंटर का दाम बितना हो गया है। बैटरी जो लोह और आकमाइद लगता है, उम वे दाम एवं वय में बार दफा बढ़ते हैं। मिलनार १९७५ में दाम ४६०० रुपये पर भींडूक टन और और आकमाइद १९७८ में वे ९,१०० रुपये पर मेट्रिक टन हो गये। उम के बाद जनवरी में वे बढ़ कर ११,००० रुपये पर मेट्रिक टन हो गये और किरि कि ३ मार्च १९७९ को वे बढ़ कर १४,१०० रुपये पर मेट्रिक टन हो गये। इस वर्ष के अन्दर दूसरे दाम हो गय। १९७१ में जो ड्रेवर २४ हजार रुपये का मिलना था, उम के बाद बढ़ कर ६० हजार, ६१ हजार और ६२ हजार रुपये हो गये यानी दूसरे और तीसरे उम के दाम हो गये।

अब आप दीजल का देखिया। १९७१ में यहाँ उम का इंडेक्स नम्बर १०४.५ था, वह १९७७ में बढ़ बढ़ कर २१३.५ हो गया। १९७१ में १०४.५ और १९७७ में २१३.९ और दीजल का भौजूदा दाम जो बढ़ गया है, उम को प्रगर मदेनजर रखा जाए, तो यह २१३.९ बढ़ कर २४० हो जाएगा। आप ने यह भी देखा कि जिस गझे से खींची जनती है, खींची के दाम तो बढ़ गये सेकिन गझे का दाम नहीं बढ़ा बल्कि घटा है। कहीं कृषि बात नहीं हुई और खींची का दाम ३० प्रतिशत बढ़ गया। पहले उम का दाम २.२० रुपये किलो था और प्रब यह बढ़ कर ३.४० रुपये प्रति किलो हो गया। (व्यवस्था) नहीं बढ़ा बात रुपये की याद करते हैं, तो फिर इंदिरा गांधी की तारीकी गिरी होपी है वहीं हम तो आप की तारीकी करना चाहते हैं। २.१५ रुपये प्रति किलो चीजीं आप भी देते थे। इसी नरक का विज्ञान

का इंडेक्स नम्बर आप देखे। १९७१ में यह १०१.५ था और १९७७ में यह बढ़ कर १७१.६ हो गया है। ट्रैक्टर का १९७१ में १०४.६ था और १९७७ में यह बढ़ कर २०३ हो गया है। किर कृषि फार्म हो का आप देखे, १९७१ में जहाँ इस का इंडेक्स नम्बर ११३.६ था, १९७७ में वह बढ़ कर २१६.९ हो गया और भौजूद पटानायक माहबूब नम्बर २१८.८ हो गया है, जो २६५ रुपये प्रति क्विटल हमें उड़ मिलती थी, उन से बड़े हुए काफ़डे के दाम ३६०.०० प्रति क्विटल हो जाएंगे। इसी तरफ से आप यह देखें कि पिंड नाहा, जिस का इंडेक्स नम्बर १९७१ में १०० था, वह १९७७ में बढ़ कर १८१.६ हो गया और कॉलाइजम का जो १९७१ में १००.३ था वह बढ़ कर १८६.५ हो गया, आप की मरान हुपा के बाबजद। इस तरह से आप देखें कि मारी चीजों के दाम बढ़ते रहे जा रहे हैं, यही में जो चीजें इस्तेमाल हाती हैं, उन के दाम घाँड़ की रफ्तार से बढ़ रहे हैं और किसान जो इनाना परिश्रम बरगा है और किसान जो चीजों को पैदा बरगा है, उस की उन चीजों के दाम घाँड़ की रफ्तार में भी बढ़ते रहे हैं हम आप का मवारबवाद देते लेकिन मुदारबवाद तो अब भी देंगे क्योंकि दाम माइनस की तरफ जा रहे हैं। आज किसानों का गादाम भी तरफ जाना पड़ता है, गादाम किसान भी तरफ नहीं जाते हैं। व्यवस्था यह हानी चाहीह कि उन के लिए गादाम वहीं पर हा भी जो उन की कमत है, उम वा गादाम लागेंगे हो। इस की साथ आप जैसे गादाम में रखे हुए माल के ३५८ शतांशी में कैश-प्राइट मिलता है, पाइवाम मिलता है, उमीं तरह से जो माल किसान रखे हो उन को भी एडवान्स मिलता चाहिए। प्रगर इस तरह की व्यवस्था नहीं होती तो किसान इमेजा लटता ही रहता। अब उस को पेसी की जरूरत होती है, तो उम का अपना माल बेचना ही पड़ता है और डिलेम में करनी पड़ती है। ऐसी व्यवस्था हानी चाहिए, जिस से किसान को ऐसा न करना पड़े।

काम के बदले अनाज याजना का जित्र करते हुए, यान में एक बात और आप की सेवा में अंज बरता चाहता है। १ लाख १६ हजार मेट्रिक टन आन्द्र प्रदेश में पिलूस माल गेहे आवाटित किया गया लेखिन ५८ लॉड्ज द्वारा २३४५७ मेट्रिक टन और इसी नरक से हर प्रदेश में हुआ कि जितना आवाटित हुआ वास के बदले अनाज याजना में उम की पांच -८००००० भी खर्च नहीं हुआ। इस का कारण क्या है। इस के बाबां में आया जाए, तो पता चलेगा कि जो गेहे या बाल इस योजना के अधीन दिया गया, उम में से ५० से ले कर ७५ प्रतिशत तक गड़ा हुआ था या चुराव था। इस कारण से यह योजना टीक से नहीं चल पाई और इस तरफ आप भी घ्यान देना चाहोगा।

इस के अलावा में यह भी कहना चाहूँगा कि पिलूस माल ११२.५० रुपये का समर्थन मूल्य आपने दिया था। इस माल के लिए भौजूद कुछ नहीं

## [र्षी बन्द्रोबाबर सिंह]

किया है लेकिन आज ये ह बाजार में 80, 90 रुपया पर ब्लैटल बिक रहा है और जहां समर्थन मूल्य पर ब्लैटल बिक रही है, वहां बित्रिये की गाँजनी रहती है या बिचौलिये की एजेंसी रहती है और उन के जरिये मे गेह लिया जाता है और वे ज्यादा मुनाफा कमा रहते हैं।

एक मालिनीय सवाल बांरे भी नहीं है।

श्री बन्द्रोबाबर सिंह: बोरो का तो इन्तजाम कर लेंगे। प्रति मेरे मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि कृषि का अगर उद्योग को नरप. माना जाए, तबीं जो कृषि का विकास हो सकता है। इस मेरा जो सामने की कमिया है, उन को छिपाने से कोई कायदा नहीं होगा। इस सम्बन्ध मेरे मैं एक बोर कहना चाहता हूँ।

"हमान आज भी हैं गुनामां मेरमग्

यह बात और है कि नरीके बदल गये॥

केवल तरीके ही बदले हैं, और कुछ नहीं बदला।

इन शब्दों के माय मेर यह कर गमान करता हूँ कि इन्हें बुद्धिमान, योग्य, सुविधाज्ञ संस्कारित लोगों के मतलब मेरहने हां भी अगर गांवों का विकास नहीं हो सका, तो मेरा यही नहीं मानता कि आगे यह ही सकेगा। यह श्रेय इन लोगों का जाए और अन्य का लेने के लिए जहां भी नड़ा पड़े, हमें नड़ा चाहिए। इन शब्दों के माय मेरुषि मतलब की मार्गों का गमर्थन करता हूँ।

SHRI VENUGOPAL GOUNDER (Wandiwash): Mr. Chairman, Sir, I rise to support the Demands of the Ministry of Agriculture and Irrigation. I would be failing in my duty if I do not congratulate the Ministry for having raised the production of foodgrains to the extent of 125 million tonnes. Though we are proud of raising the production to that level, yet what about the man who has achieved this target, who has produced 125 million tonnes of foodgrains? What steps we have taken to take care of his interest? He is not expected any Bharat Ratna or any such thing from you. He wants food, cloth and a shed. We will be failing in our duty if we do not provide him with food, cloth and shelter. We are talking too much that we have achieved our target. But one thing the Minister should not forget. The monsoon was very very favourable to them and because of that, they have achieved this target. So, they should not be complacent about it. Otherwise, the situation would be very difficult.

The Ministry should bear in mind the fact that if the monsoon fails what would be the position? And keeping that in mind, they should plan their strategy.

When the Ministry of Agriculture ask us to produce more, they should find markets for the produce in foreign markets. Otherwise, the person who produces will suffer more because the law of supply and demand will have greater force. Unfortunately, in Tamil Nadu and some other States the sugar cane growers have left their land fallow because a proper price is not paid to them. The agriculturists say that they are not getting their dues from the mills and the mill owners say that they are not able to get a proper market because there is no demand for sugar. The result is that the farmers are suffering a lot. The Ministry should come forward to help those farmers in such cases where the demand is less.

Of course, organisations like the Food Corporation of India and the Civil Supplies Corporation are purchasing it. But they should not be guided by the rules about grades and so on. Now what happens is that when they are purchasing from the farmers, they are guided by the rules about grade and so on. But when they are put to loss, they give some other reason for the loss. I would say that the Ministry of Agriculture need not be strictly guided by the rules; at least in the matter of purchasing foodgrains let them be magnanimous. Let them find ways and means to purchase all the foodgrains that the farmers offer for sale. Let them not make the farmer go back with his produce on the ground that it is not up to the quality or grade.

Coming to the question of marketing, a person who produces industrial goods fixes the price for his product while a person who produces foodgrains is not in a position to fix the price for his own produce. We should create conditions where a farmer can fix his price for what he produces. Now the price is fixed by a middleman, who

knows nothing about farming. As far as possible, we should try to eliminate the middleman so that we can do something for agriculture.

The FCI is functioning only in big cities like Madras. It has no offices at the taluka or zilla parishad level. There should be branch offices at every taluka so that the farmers can take advantage of it for the disposal of their produce.

Paddy can be cultivated only through irrigation whereas wheat can be cultivated with or without irrigation. The support price fixed for wheat is high, whereas that for rice is very low. There is a lot of discrimination here. There is a demand that the cultivation cost of paddy should be taken into consideration, as it is more on account of irrigation, whereas it is less for wheat because it can be cultivated without irrigation. So I am at a loss to understand why wheat is fixed a higher price in comparison with paddy. This discrimination should be removed and both wheat and paddy should be given the same price.

Now there are Commodity Boards to look after the interests of those commodities like the coconut Board, Coffee Board, Tea Board, Cashewnut Board and so on. In the same way, there should be boards for groundnut, paddy etc. consisting of real farmers, and not those who know about farming only from books. The Board should consist of people who know the practical difficulties and it should look after the interests of the farmers and make necessary recommendations to the Government.

The Agricultural Prices Commission was appointed in 1965. From then onwards there was no further Commission. Of course, it was revived or reintroduced in a different form. So, I suggest that a Price Commission may be appointed so that the cost of the paddy, groundnut, chillies etc. is taken into consideration and a support price is given to these crops.

Another point is that wheat was purchased and it was given to the public at subsidised prices. In these same manner, the paddy may be purchased at a higher cost and it may be given to the public at a subsidised rate. Suppose, the prices of industrial goods have increased, nobody bothers. For example, if the price of cloth has gone up more than 20 or 30 times, nobody bothers, not even the Government bothers. But they should bother very much if the prices of foodgrains have increased. People will be interested to see that the prices are reduced. But the Government should take into consideration the fact as to how far the farmers could be benefited by the increase in the price. If there is so much increase then the Government should come forward to subsidise these things.

There is one more important thing which I would like to mention here. I would like the Minister of Agriculture to allot more funds for irrigation because we have got a vast source of water. Particularly, we have got perennial rivers in the North. There is a lot of dispute regarding the sharing of river waters. Each State is quarreling with the other on who should be benefited. Ultimately neither is benefited, the entire water goes to the sea. So, the inter-State waters should at least be nationalised or the Minister should take care to see that the disputes are settled immediately.

There is a big and ambitious plan for connecting the Ganga and Cauvery rivers, for which the World Bank has agreed to give assistance and the experts have also pointed out that it is feasible. If the two rivers are connected, definitely the farmers will be benefited. Not only that. The employment possibilities are also greater. You can give employment to both educated and uneducated agriculturists. There is a lot of potentiality for employment. In respect of agriculture, definitely there is a chance to increase all such potentialities. So, kindly take interest and consider whether it is possible to unite the Ganga and the Cauvery. You take

[Shri C. Venugopal]

the water to the South so that the southern people will also be benefited. Then not only the South but the entire North also will be benefited.

MR. CHAIRMAN: Please conclude now.

SHRI VENUGOPAL GOUNDER: Now, there is agrarian unrest throughout the country. If the problems of agriculturists are not solved, and if we fail to give proper attention to agriculture, then we will be failing in our duty.

With these words, I conclude.

श्री भारत शूद्धम (नैनीताल) मध्यापवि महादेव, भाज हम कृपि नदा मिकाई मवालय की अन्यदान मांगा पर बचाई कर रहे हैं, जिस बातान यांकी में हम भाज रह रहे हैं, उमर्मे मैं इस मवालय के मविया के भाग्य की सराहना करना चाहूँगा और कहूँगा कि वे भाग्याली हैं, क्योंकि यद्यपि मझी मवालयों के अन्यनगन आने वाली चीजों का अभाव है—इश म यन्त्रित तेल कोयला, जिलों और लाला नहीं मिलता है मव चीजों का अभाव है—, मगर यदि मवालय के अन्यनगन आने वाले खाद्यालय की बहुतायत है, तो ये जगह मिलते हैं, कोई लालन लगानी की ज़रूरत नहीं है।

लेकिन इसके लिए किसको धन्यवाद दिया जायें, किसका श्वार्षी दी जायें? प्रकृति को, जिसम यमय पर वर्षा हुई, या उस किसान को जा भूखा रह कर भी, अभाव में रह कर भी, जिसन को जानता है?

वह हड्डाल नहीं करता है, अपर्याप्त दा करता है और उस को उपज जो भी भाव मिल बेचता पड़ता है। इस के लिये मैं किस को धन्यवाद दू—विसान को धन्यवाद दू, मा प्रकृति को धन्यवाद दू, लेकिन इस मवालय को धन्यवाद नहीं दिया जा सकता है। किसान के द्वारा ज्यादा पैदा करने के बाद, देश में खाद्यालयों की बहुतायत के बाद भी भाज किसान की विद्युत अच्छी नहीं है, लेकिन यदि आप कारबाना मैं देंखे, वहा जब उत्पादन बढ़ता है, उन की विद्युत बहुत अच्छी हो जाती है।

मैनीफेस्टो की बात मैं इस लिये नहीं कहना चाहता, क्योंकि हमारे मझी जी का गमन्य जनता पार्टी के मैनीफेस्टो से नहीं रह है। लेकिन मैं पक बान कह मकता हूँ—किसान हने के नात उद्दीपन भी अपने किसानों से जायदा किया या कि किसान को बोझाई के दिनों में मूल्य की घोषणा कर देंगे। पांग्रीकल्चर प्राइम कमीशन के तौर-तरीकों के बारे में यह तक चिल्ला रहे थे कि वह गलत है, उस को हम ठीक करें—लेकिन क्या ही रहा है? भाज गोट कट रहा है—मझी जी यहा बैठे हैं, भाज तक दे किसानों को उसकी कीमत नहीं बतला सकते हैं कि वह क्या भाज बिकेगा। भाज किसानों द्वारा

पंचा की जाने वाली तमाम चीजों की सही लागत निकाली जानी चाहिये और उस पर उस को उचित नक़ा हिया जाना चाहिये, नाहिं वह जीवित रह सके। लेकिन होता क्या है—शहरों में रहने वाली 20 लॉटिक आबादी को जेब को देखा जा रहा है, उस का बजट क्या एलार करता है, वह किस भाव पर बारीद मक्ता है—उस को दृष्टि में रख कर हिसाब लगाया जाता है, क्योंकि वे जानते हैं—यदि मजदूर को ऐसा नहीं मिलेगा तो कारबाने का उत्पादन गिर जाएगा, वह हड्डाल, करेगा, शहरों में रहने वाली को बिल्डिंगों को तोड़ेगा, मविया के घरों पर प्रश्ना देगा, ला एण्ड शार्डर की रिस्टरिंग देगा करेगा, युरोपेंटम आमाने वे नहीं बैट मकेंगे, लेकिन बेचार निमान बया बरेगा—हिसाल यह मव कुछ नहीं कर मवन, इमलय किसान वे बारे में उन को कोई चिन्ना नहीं है। किसान खेदी छोड़कर हड्डाल नहीं कर मवना, बरना वह क्या खायेगा? वह प्रकृति पर निर्भर है, प्रकृति उस का नन्हवाह का परियर नहीं दिला मवनी। यदि उस ने हड्डाल कर दी और बोझाई का मोसम निकल गया, तो वह खाने को कहा से लायेगा। इमर्निय, मध्यापवि महादेव, इस नौकरशाली का, इस अफमशाली को, पूरा यमधिकार है कि उस वा जायण करे और हमारे मवीं जी उसी प्राधिकारीवां द्वारा दा गई ग्रिपार्टी का गमथन और हिसायन करते हैं।

मझे आश्चर्य हृषा—पांच दिन मैं मवीं जी से बात कर रहा था। उन्हें दहा—मैंन भा बहन हड्डालों का है, नारे लगाये हैं। इन मव बातों का भानता हूँ—वयोंवाले हम लोगों आपाजीजन मे गह चुके हैं। इमलिये ग्राम जब कि मैं मवीं बना हूँ तो हड्डालों और नारों में अपने को कोई फक नहीं पड़ता। हमने भी मर्दबाद कहा था, हमने भी धर्मने दिये एं हमर्लिये ग्राम यह हमारे दरवाजे पर भी हो जाय, तो इस से क्या ग्रन्तर पड़ता है।

किसान की भाज जा इधर्नि है—ग्रनेक बक्ता उसके बारे म बताना चाहूँ है—भाज पैदावार मैं लेकर उसके जीवन से सम्बन्ध रखने वाली प्रत्येक वस्तु—चाह येतों में लगाने वाली बस्तु हो या तक के बरीदर पर लगाने वाली बस्तु हो—सब मस्ती होती जा रही है, लेकिन उस के द्वारा जो वस्तये पैदा होती है, वह यदि यमधिक पैदा कर दे तो बाजार मे बिल्डिंगों परिसरी है, उन की कोई कीमत नहीं होती, कोई उन का बरीदर नहीं होता। भाज आल की यही जालत है, पिछले साल गजे की यही जालत थीं। हमारे मवीं जी धोषणा कर दी गई आप को एक्सपोर्ट करने की छूट है। किसान को कहते हैं कि तुम एक्सपोर्ट कर दो। इसका यही मतलब हृषा कि कमरे के सारे दरवाजे बन्द कर दिये और नाली अपनी जेब में रख लो, फिर कहते हैं कि तुम पर कोई बन्धन नहीं है, तुम बाहर चले जाओ। विदेशी को माल तब तक नहीं भेजा जा सकता, जब तक यमकार दूसरी सरकार से बात कर के नियमन का प्रबन्ध नहीं करती। किसान स्वयं बाहर नहीं ले जा सकता, यहा पर बिक्री की व्यवस्था नहीं है। कृषि मवालय अगर किसान द्वारा उत्पादित बन्सुओं का विपणन टीक से नहीं करा मवना है, किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य नहीं दिला मवना है तो उसने किसान की

बहुवीं भी जो विम्बेशारी अपने कष्टों पर सी हुई है उसका वह निर्णीह नहीं कर सकता है और बहुवीं का पहल नहीं हो सकता है।

हृषि मन्त्रालय के साथ सिवाई जूरी हुई है। यह सरानीय चीज़ है कि इस को हृषि मन्त्रालय के साथ ही रहना चाहिये। तिसकी मालसे में पिछली सरकार के मुकालों हमारी सरकार ने कम समय में अधिक सिवाई भी सुविधायें जुटाई हैं और आगे के लिए भी उसकी बड़ी भारी जोंगना है। किन्तु कानूनिक प्रकार होता है उसका एक उदाहरण में देना चाहाना है। इस मध्य के अन्दर पहली बार बोल किर देने में इसकी जरूरी थी। आज दो बार बार किर देने में इसकी जरूरी थी। आगे दो बार बार किर देने में इसकी जरूरी थी। इसके बाद बोल हुए भी मैंने इसकी जरूरी थी। आज दो बार बार किर देने में इसकी जरूरी थी। ऐसे लोक में 1974 में विवराई हैं बनाने के लिए, उसका शिलायाम कर दिया गया है, योजना आयाम से वह एप्रैल हो गया है। 62 करोड़ उस पर लागत आयी गई। 1974, 1975 और 1976 निकल गए। 1977 में निर्वाचित आया। मैं निर्वाचित हा कर आया। तब इस हैप का कुछ पता नहीं था। एक बर्जंड रवाया इस माल उसके निर्गत रखा जाना था जो उसके डिजिनर पर खर्च होता था, अकस्मया पर खर्च होता था। इवन बर्जंड नक जाने के लागा महके बना देते थे, ये, लाटी लाटी टम्पारेंजी पुनिया बना देते थे और बाहर आया थी तो सब नज़र हो जाना था, सब बह जाना था। अगल गाल किर बना देते थे। इंपर्टेंट थीक बह रहा है। तो उस में काम करते हैं उनको नीकरी पकड़के लैनिन ईम कवा नहीं निकल कर आ रहा, किसान का खेत के बास्ते पानी क्या नहीं मिल रहा है, परशानी क्या है, जब मैंने पूछा तो मूले बताया गया कि डिजाइन अभी एप्रैल नहीं हुआ है, एक नया डिजाइन कार्ड अभीरीके बना देते थे उस प्रकार का बनाया जाए, तो 62 करोड़ अब आएगा और अगर अपने परम्परागत डिजाइन के मुनाबारी का शायद उस पर बिश्वास नहीं तो मत्तर करोड़ खर्च आया। यह जो खर्च है यह तब हान की बान थी। जो बहे हीझीनयर थे वे कहने थे कि बह 6 माल लना नहीं चाहिये, आठ करोड़ कम खर्च करके अब बना दिया गया और अगल कल का टृट गया तो क्या हो। भारतीय इंजीनियरों की या तो बुद्धि पर बिश्वास नहीं या ईमानदारी पर बिश्वास नहीं। ईमानदारी पर बिश्वास की ही क्याकि चंचिया हो रही है, बैमानी हो रही है। इसका नीतीजा यह हुआ कि आज चार माल नक ईम नहीं बना और बनना शुरू नहीं हुआ। फ़ीडर बनलज बन गई है, बरेज का प्रबन्ध हो गया है किन उम कही नहीं है, चार माल हो गए हैं डिजाइन ही नहीं तैयार होता है। 62 करोड़ की जगह अब अम्बी करोड़ में भी नहीं बना सकीकि इस बीच कीमतों में बहुत ज्यादा बढ़ती हो गई है। कल को एक अग्रव खर्च होगा। इस नरह में आप जो रुपया खर्च कर रहे हैं वह किसान तक पहुँचेगा, उसका साम उस नक पहुँचेगा इसका बिश्वास नहीं होता है। यह कागजों में ही पढ़ा रह जाएगा जैसे पिछले पांच माल से यह ईम पढ़ा हुआ है। यहीं हान सब जगह है।

हृषि मन्त्रालय के अन्दर एक आद्य विभाग आया है। उसने बैयरहाउसिंग कारपोरेशन की कल्पना की थी। किसान को उसकी फसल भारीकृति में आपने पर जो परेशानी होती है, उसके दाम जो गिर जाने हैं, उसके

पास होलिंग ईपेसेटी जो नहीं होती है, अपने माल को दोके रखने की जरूर नहीं होती है, उसकी होलिंग ईपेसेटी प्रदान करने के लिये बैंकों से बह जो बाल इन गोडाउज़ में रखेगा उसके अर्थेस्ट कर्जा दिलाने के लिये बैयरहाउसिंग कारपोरेशन की कल्पना को गई थी। इस नरह से जब बाहर ठोंडे हो गे तब वह बैंक देशा इस बाले इन गोडाउज़ की अवस्था की गई थी। मैं अली महादय से पूछता चाहता हूँ कि बैयरहाउसिंग कारपोरेशन का गोडाउज़ में रखेगे वैंकों में कितने परसेट माल एक० सी० आई० का अपने गोडाउज़ में रखता है और कितने परसेट किसानों का रखता है। यह कारपोरेशन तो आपका कमाऊं पृथक बन गया है और इसने चार करोड़ कमा कर भी आपको दे दिया है लोकन कितने प्रतिशत माल किसानों का रखता है अपने गोडाउज़ में इसके आकड़े तो आप जरा देखें। १५० सी० आई० के लाम के लिए बैयरहाउसिंग कारपोरेशन का क्या निर्माण हुआ था? क्या किसान के लाम के लिए नहीं हुआ था? अब वर किसान का गलन नहीं रखेंगे उसको अब अप्रिय राशि नहीं दिलाने और १५० सी० आई० को दे कर उन में रुपया कमाया जाएगा और इस तरह से बना जाएगा और चार करोड़ का लाम बिश्वास जाएगा तो क्या नहीं इन गोडाउज़ को १५० सी० आई० को ही ट्रांस्फर कर दिया जाता है? नब इस कारपोरेशन की जरूरत यहा है? कोई जल्दत नहीं है। १५० सी० आई० ने एक बर्जां लाल लख टन का व्यापार किया उसके पास मन्त्र इवार कम्बिनेशनों की फोटो है, इसीलिए हजार मजदूर उस में काम करते हैं इन मजदूरों का शायद बरने के लिए उन्हाने टेकेदार खेड़ कर रखे हैं और टेकेदार और कम्बिनेशनों की फोटो है, इनकी अनुदान लेने वाले जो रहे हैं। गत बर्षे ५७० करोड़ का अनुदान आपने दिया था। क्या यह अनुदान उपभोक्ताओं का लाम पहुँचाने के लिये दिया था? आप देखें कि उसके ब्राउंड मूल और इष्ट मूल में १५ रुपये का अन्नर होता है यानी १४० रुपये टन का अन्नर होता है और उपभोक्ता का पास पहुँचने पहुँचते वह २५० रुपये प्रति टन हो जाता है। इन्हाने डिक्सेम हाने के बावजूद एक० सी० आई० अपना खर्च नहीं बता सकती है। उसने पिछले माल ४५६ करोड़ की माग की थी जो बढ़कर ५७० करोड़ लग गया यानी सबवा हो गया। बया उसका व्यापार घटने वाला है कि इस माल ५६० करोड़ की माग की जा रही है? बाल म बचल कर इसका बढ़ाया जाएगा और मैं समझता हूँ कि इनको सान भी करोड़ का बढ़ाया जाएगा। नेश में एक करोड़ बीस लाख आकड़ों अपने आकड़ों के हिसाब से लोग बोरजमार हैं। अब अग्रव यशर यह सूपया दिया जाए तो रह एक को माटू परग महीना बिया जा सकता है। यह बिश्वास कितना खट्ट और इनाफ़िजेट है यह आप जानते ही है। इनके द्वारा खरीदे गए चावल का नमना आपके पास भी पहुँचा चका है। ग्रायकेट शावास में यह गला रखा हुआ है। इस में दग अनिश्चित भी चावल नहीं है। किसान लान लान कर १५० सी० आई० का गला देने हैं गेट ला बर देते हैं तो उन लोन लूनिया लगाई जाती है लेकिन जब वह कृज्युमर के पास आता है तो उसके अन्दर हुआ गिला होता है? कहा कौन मिलाता है? आपके १५० सी० आई० के कम्बिनेशनी मिलाते हैं। आप का जो क्वालिटी इस्पैक्टर होता है उसका एक प्रतिशत मवा प्रतिशत मिला रहता है और वह एक माल में इस नरह से चार पांच लाख रुपया कमा लेता है। आपकी

[श्री भारत भूषण]

तनवाह से कई गुना अधिक आय उसकी होती है। एक दो साल के बाद उसको अगर निकाल भी दिया जाता है तो उसको कोई परवाह नहीं होती है।

रुद्रपुर में जो इनकावायरी दुई है मैं नहीं समझता हूं कि उस में किसी को कोई सजा होने वाली है। वहां लोग मिले हुए हैं। वे आप से अपनी बात का अनमोदन करा लेते हैं। हमें आप से यह आशा थी कि कोई बात होती आपके विभाग की तो मंत्री जी जज बनेंगे हमारी बात भी सुनेंगे और विभाग की बात भी सुनेंगे और जजमेंट देंगे। लेकिन यह हमारी बदकिस्मती है कि मंत्री महोदय भी बकालत करने लग गए हैं अपने विभाग की और अपने अधिकारियों की जज होने के बजाय। यह हमारी बदकिस्मती है। कुरुप्पन का नमूना मैं दे ही चुका हूं। इसके अन्दर दस परसेट भी चावल नहीं है। नव्वे परसेट चावल निकाल लिया गया है और ठेकेदारों से कूड़ा मिलवा दिया गया है और गोडाउंज में इसको लगवा दिया। इस सब बैंडीमानी को छिपाने के लिए करदानाओं से इन्हें सैकड़ों करोड़ रुपया चाहिये ताकि ये जो माल खराब हो गया है बरवाद हो गया है और इन्हें देंगे इसको छिपा सकें। आपने गांवों में फूड फार वर्क चलाई है। अधेर के हाथ बटेर आ गया है। एफ.सी.आई. द्वारा सारा वह दैमेज़ माल खराब माल उस में भेज दिया गया है और बांट दिया गया है और सारे गोडाउंज कीयर किये जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि एफ.सी.आई. को आप वाइंड अप कर दें। बाजार में माल वैसे ही काफी मिल रहा है और किसी को इस की जरूरत नहीं है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि इस मंत्रालय को एकीश्वरीयेटी लाना है कि किसान के हित में चलाना है तो कागज पर स्कीम देकर नहीं केवल कागजों में लिख कर नहीं बल्कि किसान को हित पहुंचाने की देखभाल करनी चाहिये। आप किसान और वर्कर के कस्टोडियन बनिये भ्रष्ट अधिकारियों से नजात पाइये। 3 वर्ष से अधिक जहां अधिकारियों को हो गये हैं उनका तबादला कीजिये।

मैं समझता हूं कि फूड कार्पोरेशन के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने बड़ी खुबी के साथ फूड कार्पोरेशन के अन्दर सड़े हुए गल्ले को फूड फार वर्क के लिये बाहर भेजकर फूड कार्पोरेशन को बचाया है। अब उनको विभाग का सचिव बनाया जा रहा है। क्योंकि उन्होंने मवियों को खुश किया है डिपार्मेंट को ठीक चलाया है और आपके फूड फार वर्क के काम को खुबी से अच्छा सेहरा पहना दिया है।

जो आप के द्वारा हो रहा है इसके लिये तो आपको बधाई है फिर भी मैं भजबूर हूं इस संसद में आपका साथी हूं इसलिये आपके अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं और इस प्रार्थना के साथ कि बजट में जो प्रावीजन दिये गये हैं वह कागज में न रखकर जमीन पर ले आइये और व्यावहारिक रूप में चलाइये ताकि देश की जनता खुशहाल हो सके।

SHRI B. K. NAIR (Mavelikara): I would like to congratulate the Minister for achieving 4½ million tons additional food-grains last years as compared to the year 1975-76. But I would like to remind him that this maximum production has been the result of the labours put in the last 30 years by the previous Government. If Mr. Barnala would refer to the figures of production in earlier years, he will find that in 1950-51 the production was 55 million tonnes, it jumped to 104 million tons in 1973-74, in 1974-75 it was 100 million tons and in 1975-76 it was 121 million tons. As compared to 121 million tons he has achieved an increase of 4½ million tons. Certainly this is something to be congratulated upon but, while congratulating the Minister, I would also like to use this forum to send my fervent prayers to the Heavens that the weather Gods may continue to shower their grace and favour cultivation with favourable seasons. More than anything else, in the last two or three years, the Government and the people have been fortunate in having very favourable weather conditions. That, in fact, has contributed to higher production more than anything else.

While there is reason for satisfaction there is no ground for complacency on his part, I would also like to remind him that we in this country have to plan for the future. It is time now that we begin planning for the future. While we have been able to achieve more than a 100 per cent increase in production in the last 30 years, we should be aiming at another 100 per cent increase in the coming twenty years or so because our population is going to be nothing less than 1000 million by the turn of the century and our need for foodgrains would be about 230 million tonnes. How are we getting ready to meet that situation? Are we only going to pat each others back saying we have achieved two million or three million tons more? That sort of thing will not do. We have to plan for a substantially higher rate of increase in production in the coming 20 years or

so. That fact, I don't think, has been properly brought out in the Budget. The seriousness of the problem will bring to our mind what the hurdles are in trying to achieve this substantial increase in production.

The hurdles are many. Firstly, as many friends have emphasized, the peasants of this country, the Kisans of this country feel abhanded. They feel they are orphans. They feel the Government is against them, that the entire society is against them and that they have to slave for the country. In fact, about 20 per cent of the population is dictating terms to the peasants. The peasants are at the mercy of the consumer, of the city man, of the town folk, of the bureaucrats of the officers of the middle-class people, and ultimately, of the merchants. All these people sit on his head and they are reducing the life of the peasant to one of slavery so much so he does not get his dues. He is labouring like a slave. Each man in the city is having at least four persons as slaves for him in the villages. All his luxuries and comforts and the high standard of living are being maintained by the city man at the cost of the kisans. That is how the system is functioning. Now, what is the solution? It has been said by the Members in this House and I would also say that the solution has to come from the peasants themselves. Kisan organizations have to come up. Mao-tse-Tung once said that the villagers should encircle the towns; he urged on the under-industrialised countries to encircle the industrialised countries. The peasants have to encircle the towns and try to dictate their own terms. Now, as it is, their produce is at the mercy of the traders and consumers. The entire system has to be changed. Of course, that will take a long time, but the process has to be started. Ultimately the time will come when the actual producers, the sons of the soil, will begin dictating their terms to the city-man who

is now leading the artificial life of glitter.

Coming to the problem of price-fixation, we have a machinery here, the Agricultural Prices Commission. I do not know what is the standard that they are following. They claim to aim at fixing a uniform price for the produce for the whole country. But the cost of cultivation, the labour involved and the inputs involved do not bear out or substantiate their claim that a uniform price can be fixed. For example, in 1975-76—I would read out certain figures—the yield per hectare of paddy in different States was as follows: Andhra Pradesh, yield per hectare, 2,485 kilograms, Tamil Nadu 3,225 kilograms; Punjab 3,867; and now coming down, in Bihar the yield per hectare was only 1,382. Then if you come to my own State, namely, Kerala, the yield will not be more than 1,200 kilograms per hectare. Therefore, what is the philosophy in trying to apply a uniform price for the entire country? The cost of production is different in various States. For example, in our own State, Kerala, the wages are higher than in most other States; in Kerala, the agricultural workers get Rs 10 per head per day and the women workers get about Rs. 7 per day. While this is so, how can you have a uniform price for the produce for the whole country? The cost of production is entirely different in various States. About fertility and other things, of course, there is no solution; there can be no uniformity. I would suggest therefore that there should evolve some method of subsidising the production in high-cost areas. In our State, Kerala, we have to pay high electricity charges for pumping out water. That may be subsidised. In high-cost areas, fertilisers, for example, may be supplied at subsidised rates. Without some such method of trying to equalise or make uniform the cost of production, we cannot just fix a uniform price for the whole country.

MR. CHAIRMAN: Please try to conclude in two minutes.

SHRI B K NAIR: I would like to emphasize certain aspects about Kerala.

One is this. There is a reference in this Report to the difficulties in Kuttanad. In Kuttanad the cost of production is high, and Mr Barnala is advising 'Why not diversify to some other crops?' For diversification also, the land has to be prepared and money has to be spent. Will you subsidise this to some extent? People are prepared to diversify in certain areas. Kuttanad measures about 60 000 to 65 000 hectares. One part can be separated from the other. But certain people have to continue with paddy cultivation because the Government of Kerala is insisting on paddy cultivation being continued because all these years there was shortage of paddy in Kerala and they could not depend on the Centre's supply. Now of course the supply position has improved. The Central Government has to persuade the Government of Kerala to do away with the Land Utilisation Act. That is hanging on the neck of the cultivators. Once the Land Utilisation Act or that burden is removed the peasants will be free to go in for their own crops and the peasants will be getting a better return and also the country will be benefited to that extent. That is one aspect.

The Minister is also in charge of Fisheries. We have got about 6 million fishermen employed all along our coast. What do we do for these fishermen? Have the government taken any serious note of their plight? Many of them go out into the sea in the monsoon season and die in accidents. Serious cyclones are there. Have the Government ever thought of having some sort of insurance for them or giving some compensation to them? In Kerala the practice is that the Minister goes to the man's house and gives Rs 50/- to the wife of the dead fisherman. Photos are taken, everything is displayed properly, and the chapter is closed. We have to go in for a serious project for helping the fishermen. My

suggestion in this, we are getting about Rs 180 crores from exports of fish products. Why not have some sort of a cess say 1 or 2 per cent, on the exports? It will easily fetch you about Rs 2 crores and with some contribution from the government also, you can draw up a welfare scheme and help these fishermen families during their days of distress or during the days of unemployment and when fatal accidents take place. And then the Food for Work Programme. It is not a success in Kerala. You supply half wheat and half paddy. You have announced that the entire quantity will be given in paddy, but that has not been implemented. The quantity supplied is very low compared to the wages the agricultural labour gets in Kerala. They get Rs 10 per day and you give only 2 1/2 kg of foodgrains and that is nowhere as a fair compensation. Some higher quantum of rice may be given for the day's work and some share of it may also be given in cash. While discussing the Sugar Mills take-over Bill I said a portion of the wage may also be given in the form of sugar. When you are giving food why not add some sugar too? Why not give them say 1/2 kg of sugar as part of the wage?

There is another aspect. The Minister is also in charge of Food. There is a lot of complaint about the quality of foodgrains supplied in our State. The rice supplied there is fine and superfine which do not sell. After all it is important for the poor people and they cannot pay Rs 1.87 or Rs 2 for your rice. So it is lying there and nobody wants it. Whenever the wholesaler takes it from the depot he is not able to sell it. People insist on having only coarse and medium quality rice. If that can be arranged that will go a long way to meet their needs.

There is one more aspect. A lot of this rice is lying there. Why not pass it on to the open market or the super-bazaar where the well-off people can go and buy it?

Sir, our people are not used to the Punjab boiled rice. A lot of it is lying there unsold. It takes 2 to 3 hours to cook. I suggest the entire thing should be taken away.

Then, a word about land reforms. Kerala Government has been constrained recently to go in for amending the Land Reforms Act. It is a very unfortunate development. We have been claiming all these days that Kerala is the foremost State in the matter of land reforms and we have set up model land reforms. But they have been constrained to go in for amending it, as a result of which 9 per cent of the surplus land is to be retained by the land-owners in the name of gift lands and gift lands are sought to be excluded from the operation of the Land Reforms Act. This is a highly retrograde measure and the Government of India should not give its approval to this Bill particularly because this land should be assigned to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

MR. CHAIRMAN: Shri R. P. Das.

SHRI R. P. DAS (Krishnagar): Mr. Chairman Sir. While taking part in the discussion....

15 hrs.

SHRI M. R. LAKSHMINARAYANAN (Tindivanam): Sir there is no translation.

SHRI R. P. DAS: Translation is going on.

MR. CHAIRMAN: Translation is there. Mr. Das you may carry on.

SHRI R. P. DAS: Mr. Chairman Sir. While taking part in the discussion on the Demands of the Ministry of Agriculture many hon. friends have already put forward their views. I would like to say my say perhaps in a slightly different way. Sir, during the last two

years weather was very kind to us. There was good rain and because of this and because of the millions of the cultivators, the country had a record production of food grains and other crops. It is no doubt an event for which the government should be congratulated and along with the government I would like to congratulate those who were engaged in cultivation and also the fine weather which could make this record production possible. But this record production has also created some difficulties and I would like to deal with them now. One of the foremost problem of bumper production is the sharp fall in the prices of the food grains and other cash crops. The agriculturist's main problem today is how to market his produce at a remunerative price. It may sound paradoxical but it is true that even though there is such good crop, every section of the population has not been equally benefited by it. You will be surprised to know Sir, that more than 30 crores of population do not have any purchasing capacity. This lack of purchasing power is a matter which should be taken a serious note of because we have seen when production of sugarcane was more the price of the sugar had gone down to Rs. 2.10 to 2.15 a Kg. but the consumption of sugar had increased from 37 lakh tons to 45 lakh tons i.e. only an increase of 8 lakh tons. This amply proves that unless the purchasing power of the people is raised, mere good production will not help the poorer sections of the population, on the other hand, it will help only the capitalists and a limited few who control the trade. I would therefore say that if the Government which stands by its promise to uplift the lot of the peasants and poorer sections of the society is really able to fulfil its promise then the problem can be solved as otherwise the over production is a danger signal which will create catastrophic situation in the country particularly in the field of agriculture.

\*The original speech was delivered in Bengali.

15.04 hrs.

[SHRI M SATYANARAYAN RAO in the Chair]

While on the one hand, the vast majority of the rural population is suffering from the lack of purchasing power on the other hand there has not been no real redistribution of land among the landless. The tenancy system in our country today despite various legislations passed both by the Central Government and the States continue to be semi-feudal and capitalistic in pattern. According to agricultural census figures 15 per cent of the land owners own 31 per cent of the cultivable land, 5 per cent of the land owners own 37 per cent of the cultivable land and the 4 per cent of the top land owners own 60 per cent of the cultivable land. These figures more than amply show how in the matter of land ownership the rich continue to have their stranglehold over the poorer sections and how the real tiller of the soil live in a state of hopeless exploitation. The natural consequence of this phenomena is the rise of capitalist penetration in the sphere of agriculture which is apparent in the States of Punjab, Andhra Coastal areas of the South and to some extent in some blocks and talukas of Maharashtra, U.P., Bihar and West Bengal. I may mention here that the characteristic feature of this capitalist penetration arises out of better availability of irrigation facilities, possession of better technological equipment and know-how, massive capital investment and accumulation of land in a few hands. Although a total capitalistic domination over agriculture has not taken place yet the prevalence of spread of semi-feudal capitalism in the sphere of agriculture is clearly discernable. What is the result of this capital penetration? The result obviously is that these very few persons are cornering and arrogating to themselves the benefits of good agricultural production which ought to have been transferred to the actual cultivators. As a result of this the poor cultivators, marginal farmers, landless

labourers, share croppers and the members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are being exploited continuously. The rich is becoming richer and the poor poorer. As I have already stated the purchasing power of a vast majority of the cultivators and the rural population is dwindling very fast. Their condition is so pathetic that they get full meal for 130/140 days in a year. They have no work for the whole year and their wages are far from remunerative. And all these have caused a disastrous effect on the purchasing power of the common man who has no shelter to live, no food to eat, no clothes to wear and cannot afford the necessities of life like his brethren in the cities. The number of such deprived population is no less than 30 to 35 crores. When the production increases and the people have no purchasing power a demand is usually made by the capitalist lobby that the surplus foodgrains should be exported or the Government should buy all the surplus. We know that the FCI is purchasing the surplus foodgrains and they have built a buffer stock. But one who is aware about the functioning of the FCI knows it too well that there is rampant wastage in the process of collection and storage by the FCI. The people and the toiling masses I must warn the Government will not tolerate a paradoxical situation where in the midst of plenty there should be colossal wastage resulting in starvation of the people. Unless the Government is able to bring about a rapid change in the whole situation the results are bound to be dangerous.

Mr Chairman Sir towards the end of February and early March this year under the leadership of Andhra Kisan Sabha nearly 75,000 cultivators had launched an agitation. This agitation had spread rapidly over the 9 districts of the State including Nellore, Wrangal, Krishna, West Godavari and other places. The agitators took possession of 8000 acres of land held illegally and they distributed it amongst 20,000 cultivators. The most remarkable feature

of, this agitation was that more than 50 per cent of the agitators were women. In this struggle two cultivators were shot dead. The matter was raised in the Andhra Assembly and the Minister assured the House that all land illegally occupied would be recovered and an enquiry into the matter has been ordered. I am referring to this glorious struggle only to suggest that the above incident is a red signal which tell to the nation that unless land is properly distributed, unless cultivators are given remunerative price for their produce and unless their wages are reasonable, the exploited multitude will not tolerate the exploitation for ever. They will unite and will rise all over the country to take possession of the land from those who hold them in illegal possession as in Andhra and will force the Government to change their agricultural policy. Before the situation comes to a point of explosion it becomes a political and moral responsibilities of all the political parties of the country that they should bend their energies to end the present exploitation of the landless and the poor cultivators that is rampant all over the country today.

I would like to touch upon another matter of importance. It is irrigation. When we talk about irrigation in the House an impression is created that irrigation is a new creation which has lived only for the last 32 to 35 years. But everyone of us know that it is not so. All the early civilization of the world had an elaborate system of irrigation but with the afflux of time and because of willfull neglect these systems got destroyed and were replaced by modern techniques. The tragedy of the matter is that while we discarded the old we could not implement the modern schemes of irrigation either completely or fully. As a result of this we still find in our country that only 25 per cent of the cultivable land is irrigated and the rest of the 75 per cent is denied irrigation. During the last 20 years, out of 148 major irrigation projects only 20 could be imple-

mented and the Damodar Valley project in West Bengal is one of them. So far as the medium irrigation projects are concerned out of 756 projects only 447 could be completed. So far as the DVC is concerned it was proposed that 7 dams will be constructed but this was not done. Out of these 7 only 4 were constructed and 3 still remains to be done. As a result of this last year the heavy water discharge, in the catchment area due to heavy rains created such a terrific depression that the surplus water which could have been contained if the proposed 3 bands were constructed, broke through its banks and devastated villages, roads, rail lines, and caused untold sufferings to the inhabitants. It is very unfortunate that such an incidents should occur because we know it can be averted. The flood cannot be described as an accident and it is quite likely that under similar circumstances an equally devastating floods may occur in the State and to remedy the situation I would urge upon the Government that the 3 dams should be constructed without further delay, afforestation should be done on the hills and tributaries made out of the main stream to channel out the surplus water in times of need. The West Bengal Government have been persistently suggesting to the Centre about these needs but the authorities that be do not seem to bother or attach any importance to these measures and the result is that hundreds and millions have suffered last year and may be many more will suffer in future.

A word about the Ganga basin water resources organisation. Circle Office No. 2 of this organisation has been located at Varanasi, without much justification and as a result it, is causing a lot of inconvenience in its operation. This office has to oversee the agreement that India has entered into with Bangladesh regarding distribution of water through Farrakka. The Circle Officials have to come Farrakka and Calcutta every now and then to hold talks with their counter parts to watch the joint observation work. They have

[Shri R. P. Dass]

also to run to Calcutta for purchasing spare parts, hold discussions with Calcutta Port authorities regarding hydrological observations, to deal with the disputes arising out of Teesta water and also their location in Calcutta for the purposes of forecasting floods would be very helpful. For all these reasons it is very necessary that the Circle Office should be shifted from Varanasi to Calcutta and I would urge upon the Government to take immediate steps in this matter.

Finally, I would conclude by saying that I have just now received intimation from Dandakarnaya that the flour supplied by FCI is of very poor quality and I am laying on the Table a specimen of the same and will urge that something should be done in this regard also.

**SHRI BALDEV SINGH JASROTIA (Jammu):** Mr Chairman, Sir, I am thankful to you for this opportunity that has been given to me to speak on the Demands of the Ministry of Agriculture and Irrigation.

Sir, Agriculture is the main industry of the country. I congratulate the hon. Minister and the farmers who have produced wheat, rice and jowar in abundance so as to surpass all the previous records. But at the same time I feel sorry on the ground that sugar production has fallen. So is going to be the fate of potatoes which have got a poor market and no provision for storage etc. I need not go into details but I share what other hon. Members have said.

Sugar and Potatoes need a policy. There should be a common agricultural policy in toto so that the people who produce will not suffer in the matter of marketing, price etc. The country demands that, as in the case of the success in rice, wheat, jowar etc. so also we should have success all round and the present suffering or shortage of cereals, cotton and pulses should be removed. Heavy expenditure is being

incurred on the import of oil etc. which can be saved by being self-sufficient in these things. Our farmers have been under a delusion and a confusion. Sometimes they are asked to produce wheat, but when there is some shortage of sugar, they are asked to produce sugar and so on, without any specific policy in this connection. So, what is needed is that the hon. Minister should take care to see that the farmers are helped by guiding them in these matters as well. Deforestation is going on unabated in this country due to which floods and soil erosion take place in those places where rivers are flowing. This should be stopped. Necessary land reclamation and soil conservation programme should be undertaken for creating an infrastructure for agricultural production in the country. In this connection, I may mention about the J&K State, more particularly Jammu region where four rivers—Chenab, Tawi, Ravi and Basantar—are flowing. Due to deforestation these rivers cause erosion in and around so many areas of the villages in this region. If these rivers are tamed by constructing bunds over them, I think hundreds of acres of land can be brought under cultivation and we can increase the agricultural production. More agricultural production means more progress in the country. Therefore, the Government should give thought to these problems so that there is more and more agricultural production in the country.

Now, I come to the modern village. If our country is to advance and progress, we should modernise our villages. As it is, in whatever field the country advances, the benefit does not go to the villages and the villagers are continuing in the same old way of living. I would therefore call upon the hon. Minister concerned to kindly look into these matters and see that in the village the block developmental work is entrusted to the Gram Panchayats or B.D.O's.

There is another important point which I would like to bring to the notice of the hon. Minister. In my own

home town, that is, Kathua in J. & K. State, which is 1025 ft. above the sea level, Morchila known as Guuchhi is produced. Normally it is produced in the hilly areas at a higher altitude. But now the experiment has shown that it can be produced 1026 ft. above the sea-level. It is a very good commercial crop and it can be produced in large quantities, especially after this experiment has been successful. But I am very sorry to say that nothing has been done by the Ministry concerned so far in this direction and early action in this regard is called for.

Now, recently, the Jute Technology Research Laboratory at Calcutta has been successful in developing the technology of commercial utilisation of agricultural waste produced from cotton and jute. Out of these waste materials we get fibre like things. If these waste products are put to proper use, I think it can supplement the income of the farmers. They will thus be benefited. Now, it has also been revealed that this fibre-like material can also be got from pineapple and bananas. The hon. Minister should pay attention to this aspect so that things like hard-board, paper board, kraft paper, etc. can be manufactured from these waste materials and this can be an additional income to the farmers. I hope the hon. Minister will take special care and in this very budget he would make provision for this. If the hon. Minister is not aware of these things, it is high time that the hon. Minister, in his reply, made positive statement on this point.

Much has been said with regard to Food Corporation of India. I would call it 'Food Corruption of India'. Mr. Bharat Bhushan has already demanded immediate overhaul of this organisation. If the closure of this organisation is attempted, it will benefit the farmers and the nation to the tune of crores of rupees which are at present being wasted. There are about 25,000 labourers in the F.C.I. and these poor people are being exploited by the

contractors and the middlemen. The contractors and the middlemen are the beneficiaries. Every year, more than 5.0 crores of rupees are wasted on account of this organisation. And who is earning? It is only the Food Corporation of India employees who are earning and to which they would not be entitled otherwise. This can be utilised for the nation in other ways gainfully. I hope the hon. Minister incharge of this portfolio will take early steps in this direction and the contract labour system would be abolished and the labourers concerned would be given the best benefit.

The other day, the hon. Minister for Agriculture was kind enough to take part in the meeting of the Food Corporation of India, Workers' Union held on 31st March, 1979. There they voiced their grievances and among others their demands are abolition of contract labour, abolition of private storing agency system, doing away with discriminatory treatment to FCI's direct payment workers, equal day equal work, evolving a scientific system for kind of labour welfare scheme, workers participation in management etc. I am sure, the hon. Minister will consider very sympathetically the genuine demands of the FCI workers who have been clamouring for such a long time. These workers have been facing difficulties at the various depots. The hon. Minister was pleased to say some time back that direct payment would be introduced to the labourers working in the FCI. I am sure, in keeping with that assurance given to the labourers in the FCI, he will implement this at the earliest and fulfil his promise. The direct contract labour system should go away and direct payment system to the labourer, which will benefit the workers and others should be introduced immediately.

With these words, I support the demands for grants of this Ministry and I hope, the hon. Minister will take due notice of the points made by me.

**SHRI DAJIBA DESAI (Kolhapur):** Mr. Chairman, Sir, a large number of hon. Members have already participated in the discussion and they have pleaded the case of cultivators and agriculturists and have voiced their grievances. Last year also, a number of hon. Members advocated the same line of attitude, but we got no response from the Government. Even in the last year, the hon. Minister for Agriculture announced in this House that he would have a fresh look about the terms of reference of the Agricultural Prices Commission and the personnel of the Agricultural Prices Commission, but after six months actually nothing has happened. In his speech even the Finance Minister and the Deputy Prime Minister realised that agriculture has the largest potential for generating employment and for providing purchasing power to the large majority of people and there cannot be any let up in the task of development of agriculture. But can the Minister for Agriculture and Irrigation say that this approach is reflected in the demands for grants, or the programme of agricultural development, programme of irrigation, programme of rural development or the food programme? In fact, this requires a large investment and a greater effort in a number of directions and a better organisational set-up.

As I said, the sentiments or the approach expressed by the Finance Minister and Deputy Prime Minister are not reflected in the demands for grants of the Ministry of Agriculture and Irrigation. Take for instance the question of procurement and agricultural price policy. What has been the experience during the last year?

Last year, in spite of demands from every section of the House that remunerative prices should be fixed and Government should come into the market to purchase all available market surplus, Government insisted that the Food Corporation of India and

some other agencies will purchase in the open Mandis, paying only a support price. Actually, the result was that the marketing machinery with the Food Corporation or with bodies like NAFED could not reach the Mandis, and the cultivator had to sell his produce at distress prices. All the cultivators in India who were producing wheat, paddy, sugar-cane, potato and jute had to sell their produce in the market at distress prices, price lesser than the support prices. Even the Government could not give the support price to the cultivators. That is the plight of the cultivators.

It is not that the prices of agricultural commodities are going down, that those of industrial commodities are going up, and that there is a big gap between the two. But it is the act of omission on the part of the Government i.e. because of Government's policy that this gap has been widening day by day. The result, next year, is going to be the same. The Food Corporation or any other authority or machinery of the Government of India cannot reach every Mandi and every cultivator; and they cannot purchase all the agricultural produce offered by the cultivators. And the Government has dumped the cultivator in the lap of the traders; and the traders have amassed a lot of profits. So, this is the policy of free trade.

Government is taking credit, saying that because of free trade, there is a surplus of agricultural produce, foodgrains etc, and that in every market, you can purchase anything at a reduced or reasonable price. But what is the result? This is the result of free trade which I want to tell the Janata members: this is the policy by which the Government has reduced the cultivators to a pitiable condition.

One hon. Member has just described the working of the Food Corporation. But what is the attitude of the

Government here? Government has calculated the subsidy to the Food Corporation as a subsidy to the cultivators. It is an anomaly, Food Corporation spends Rs. 17 per quintal for just keeping the stock; and again, it spends Rs. 32-80 per quintal for carrying the stock. All these Rs. 560 crores have been debited or credited to the account of cultivators. Is it justice? In fact, this is not given to the consumers. No subsidy is given to them. The only subsidy given to the consumer is Rs. 2.50 for wheat and Rs. 5 or Rs. 7 per quintal for rice. But actually, the carrying cost of buffer stock is supposed to be Rs. 560 crores—or it is there for maintaining the stock. It is not a subsidy given either to the consumer or to the cultivator. It is just a trading account.

In the matter of rural development, Government has come forward now with an Integrated Rural Development Programme. The name appears big. And some voluntary agencies are to be approached and taken into this movement. This Integrated Rural Development Programme is a combination of 5 previous programmes, viz. Small Farmers' Development Agency, DPDA, Desert Area Development Programme, Drought-Prone Area Programme and lastly the Food for Work Programme. Already, out of 5005 blocks, some 2,000 blocks have been covered under these 5 schemes.

Now 300 blocks are to be taken up this year under the integrated rural development scheme, because the Agricultural Department says that financing of these 2000 blocks will be on an old pattern. But the small cultivators—people holding below 5 acres of land—landless labourers, workers will get subsidy at the rate of 25 per cent, 33 per cent and 50 per cent. Is the Government aware that these small cultivators are eligible for getting loan because they are in arrears of loan? Unless they clear their previous loan, they are not eligible for

getting further loan. In a number of districts and blocks, the banks are not prepared to finance these projects because of this. The project officers just complete the forms for minor irrigation, for land development and so on and forward them to the banks. If the banks agree to finance them, they are eligible to get subsidy. It means the banks cannot give them loan because they are defaulters. Then the Government has no reason to give them subsidy.

Under the integrated rural development scheme, they have to identify the cultivators. In that process, one or two years ago, Then the proposals have to be submitted to the project officers. That takes one year. For the last three years, I ask the Government to give the estimate of expenditure on this scheme. It is a small scheme. In India, the cultivators who are holding less than half an hectare of land, their number is 2.31 crores; the cultivators who are holding less than one hectare of land, their number is 1.25 crores; and the cultivators who are holding less than 2 hectares of land, their number is 1.34 crores. Then there are six crores landless labourers. It means there are 10.90 crores eligible people. Out of them, they have identified 1.60 crores. This is the report of ten years. In 10 years, they have completed this thing

If you want to take up this scheme, these people must be given the facility of finance and the defaulters must be treated as new applicants. Their loans must be cancelled. This is a good scheme. But if it has to be implemented, then the Government should come forward with definite proposals and take all the people into confidence.

We oppose voluntary agencies, because they are sponsored by Tatas and Birlas. These agencies will play havoc in the rural areas and therefore we oppose them. With these words, I conclude my speech.

**चौधरी बलबोर सिंह (होशियारपुर) :** सभापति महोदय, कृषि मंत्री किसान का बेटा हो और दोनों कृषि मंत्री ही किसान हों फिर भी कृषि और किसान की यह हालत हो कि जो बढ़ पैदा करता है, उसका मूल्य उसे न मिल मिले, तो कारखानेदारों की लाबी कितनी ताकतवर है कि बजट पर उन्होंने तूफान मचा दिया है कि यह किसान का बजट है, यह शहरियों के खिलाफ है, यह सिंक देहानियों के हक्क में है। किसान को मिला क्या है? उसे मिंक एक बोरे खाद पर 5 रुपये का मनाफा हो गया है। एक बोरे खाद पर मिंक 5 रुपये की कीमत में कमी हो गई है और उसका जो आलू था, जिसे सरकार ने 50 रुपये खरीदने का हुक्म दिया, कि इससे कम होगा तो सरकार खरीदेगी, इस हाउस में इस बात का एशोरेंस है, और वह आलू जो कि 50 रुपये वाला है वह 5 रुपये बोरा बिक और यही नहीं बल्कि 3 रुपये बोरा बिके। पैने चार रुपये का बोरा आता है और पौने 3 रुपये का आलू बिके। आलू की छांटाई पर भी 3 रुपये लगते हैं और मण्डी तक पहुंचाने का पैमा भी लगता है।

यह बात अचानक नहीं हो गई है, मन्त्री जी को याद होगा कि जब यहां दिसम्बर में इजलास हो रहा था, तो उस बक्त मैंने कहा था कि आलू का इंतजाम कीजिए। आलू पैदा करने वाले बेचारे उल्ल बन गये हैं, उन्हें सूझ नहीं रहा है कि वह क्या करें। लाखों रुपये का नुकसान उन्हें हुआ है छोटे-छोटे जमीदार का जिसको पैदा करने पर 20, 20 और 25, 25 हजार रुपये खर्च हो चुका है और अब उस प्रादमी को उसके 2 हजार रुपये नहीं मिल है। वे लोग बिल्कुल तबाह हो गए हैं।

मैं एक वर्निंग और आपको देना चाहता हूं कि जो गेहूं की फसल आ रही है उसमें इतना गेहूं आ रहा है कि वह आप संभाल नहीं पायेंगे। बीच के दलाल सत्यानाश कर देंगे, फूड कापेरिशन वाले।

जनता पार्टी ने मैनिफेस्टो में कहा था कि किसान जो भी पैदा करेगा, उसको जब वह चीजेगा, उस बक्त उसे बना दिया जायेगा कि उसे यह मोल मिलेगा। यह मैनिफेस्टो अकाली दल और जनता पार्टी का है। हम जितनी देर बिरोधी दल में 2 है, लगातार इस बात के लिए सरकार की टीका-टिप्पणी करते रहे कि किसान को पहले बता देना चाहिये कि उसकी चीज का क्या भाव होगा। आज भाक्ट में गेहूं आना शुरू हो गया है लेकिन सरकार ने अभी तक भी जिस भाव पर गेहूं खरीदा जायेगा, उन भावों का एलान नहीं किया है। नये हो गये हों तो पता नहीं, लेकिन एलान नहीं किया है।

यह कितनी बड़ी बात है कि किसान जो पैदा करे, उसका भाव सरकार मुकर्रर करे और सरकार भी उस बक्त मुकर्रर करे जब उसका माल मंडी में आ जाये। एक नरफ तो किसान की चीजों की कीमत सरकार मुकर्रर करती है और दूसरी तरफ कारखानेदार हैं जिसके माल की कीमत वह खुद मुकर्रर करते हैं। वह अपने माल की चीमत जब मर्जी आया बढ़ा लेते हैं।

अम्बेसेडर कार सन 1970 में 17 हजार रुपये की थी आज उसी कार के दाम 53 हजार रुपये हैं। 1970 और 1979 के बीच में 3 गुना दाम ज्यादा बढ़ गये हैं। आपको शायद याद होगा कि कार की कीमत बढ़ाने के लिए जब जस्टिस हिदायतउल्ला के पास गये तो उन्होंने मजाक में कहा था कि इस कार की हर चीज बजती है, लेकिन हार्न नहीं बजता है। हार्न के बगेर सब चीज बजती है। कार की कीमत 17,000 रुपये से बढ़ कर 53,000 रुपये हो गई है। इसी तरह क्रेस्टर की कीमत 19,000 होती है से बढ़ कर 60,000 रुपये हो गई है। कारखानेदार की बनाई हुई हर एक चीज की कीमत बढ़ गई है।

आज सवालों के जवाब में उद्योग मंत्री, श्री जार्ज फर्नाण्डीस ने कहा है कि कपास की कीमत कम हुई है और कपड़े की कीमत बढ़ गई है।

हम लोग, जनता पार्टी वाले, इस बात का केंडिट लेते हैं कि हमने प्राइसिंग को काबू में रखा है। श्री बरनाला और श्री भानु प्रताप सिंह बतायें कि क्या उन्होंने किसान को मार कर प्राइसेज को कोल में रखा हुआ है? कारखानेदार की चीजों की कीमत कहां है और किसान की चीजों की कीमत कहां है? जिन चीजों की कीमतें कम रखने के बारे में सरकार क्रेडिट लेती है, वे तो किसानों की पैदा की हुई चीजें हैं। जो चीज किसान पैदा करता है, उसकी कीमत कम है, और जो चीजें वह खरीदता है, उनकी कीमत ज्यादा है, जैसे लोहा, कोयला, और सीमेंट बगेरह।

सीमेंट की कीमत पहले 11, 12 रुपये थी। जब जनता पार्टी ने राज्य सम्भाला तो उसकी कीमत 17 रुपये के करीब थी। लेकिन आज सीमेंट की कीमत 26 रुपये से ऊपर होने वाली है। ब्लैक में उसकी कीमत है यह कहने की ज़रूरत नहीं है।

किसान जो चीज पैदा करे उसको उसका मोल न मिल सके यह इन्साफ की बात नहीं है। मैं किर वार्निंग देना चाहता हूं कि सरकार अपनी मशीनरी को तरतीब दे, उसको करें। किसान का गेहूं मण्डी में आ जाये और भाव मुकर्रर कर दिया जाये 115 या 120 रुपये और मण्डी में किसान को 90 या 100 रुपये से भी कम मिले। मिनिस्टर साहब मण्डी में जा कर इस बात की एनकवायरी करें।

**श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) :** आप एनकवायरी क्यों नहीं करते हैं और उसकी रिपोर्ट मिनिस्टर साहब को क्यों नहीं देते हैं? पब्लिक के रिपोर्टेटिव क्या करते हैं? क्या मिंक मिनिस्टर ही एनकवायरी करेगा?

**चौधरी बलबोर सिंह :** हम तो करते हैं—हम अब भी कर रहे हैं। आपकी जुबान बंद थी। आप बोल नहीं सकते थे। हम करते हैं और मण्डी में जा कर भी लड़ाई करते हैं कि इस दंग से नहीं होगा।

मैं भली महोदय से कहता कि वह इसकी एक साथ्यती करता है। मध्यी में नापेड बौद्ध सरकार की ऐजेंसियों ने भालु बस रूपये बोरी के विसाव से लिया है, और वही इन्हीं 50 रुपये बोरी दिया है। किमान को उसकी धीमत नहीं मिल सकती। जो सालियत सरकार ने थी, उमका फ्रायदा फिर उस भालुनी ने उठाता, जिसके पास दौता था, जो खरोद सकता था और जो किमान था। एकमालायट कर सकता था।

किमान की बातें हर एक सदस्य ने की हैं। मैं इन बारे में कुछ युक्ताव दिया चाहता हूँ। एक युक्ता यह है कि सरकार पूँड कारपरिशन के खर्च को कम करें। एक बोरी को सारा माल रखने का 32, 33 या 37 रुपये का जो खर्च है, वह बहुत ज्यादा है, उमको कम लिया जाये। सरकार किसान के घर में भानाज रखे और उत्तरों के खर्च दे। इस खर्च के बारे में एक बार 32 रुपये का गेलान हुआ था और दूसरी बार 37 रुपये का। पता नहीं कि भ्रसली खर्च कितना है। पिनिस्टर सालव मुख्य बता दे, तो मैं उसके मुताबिक बात करूँ। अग्रणी पूँड कारपरिशन के गोदाम में 35 रुपये खर्च होते हैं, तो सरकार किसान से कहे कि वह उसमें गैरु 115 रुपये-1-2-3 रुपये, यानी 140 रुपये में लेंगी, और फला महीने में लेंगी। इससे सरकार का खर्च कम हो जायेगा और उसे गोदाम बनाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। किसान जो सरकार कुछ एडवाइस दे दे, व्योकि उसके पास ऐजेंसियों नहीं हैं, वह आपने माल की भेजी नहीं करता है और उसे एकदम मध्यी में बेचता पड़ता है। सरकार आपना माल गोदाम में रखती है। वह सबको कि उसका माल किसान के द्वारा में पड़ा है। किसान इस माल को सम्पादन कर और थीक तरह से रखेगा, भीमायियों से महफूज रखेगा। बरकार उसकी खर्ची दे। इससे किसान को पैदा विल आयेगा, सरकार स्टोरेज की शार्टेंज की भ्रस्या की हमकर सकती और किसान की दूसरी भेत्रत का कुछ भी दैन लिन सकेगा। यह युक्ता मैंने दिया है—इस पर अमर करा जाया।

मैंने लिखने साल भी कहा था—जितने सरकारी भूलाजिम हैं, जितने कारखानों में काम करने वाले मालाजिम हैं—इन मध्य लोगों को एक साल का राशन जाय और उस की कीमत 12 लिंगों में उन से बहसुल की जाय। जो सरकारी कर्मचारी हैं उन की तनबकाह से हर मधीने उस की कीमत का बारहवा हिस्सा काट लिया जाय, इसी तरह से कारखाने के कर्मचारियों के बेतान से काटा जाय। इस से यह काफ़ा होगा कि करोड़ों मन भानाज जो भर्तियों में रहा होता है, लोगों के भरी में पहुँच जायगा और हमारे यहाँ जो स्टोरेज की विक्रत है, वह विक्रत हल ही आयगी।

दूसरा युक्ता यह है कि हमे माल बाहर भेजने की अवस्था करती चाहिए। इन बहत हमारे यहा व्यापार-कारबाहीसिव है। पिछले 30 सालों के कारपीसी राज में हम कारता-गदाई ले कर कभी अमरीका के पास, कभी रूम के पास जाते हैं।

जी एम० रामलीलाल रेड्डी। हमने 1 करोड़ टन भानाज आप को दिया था।

बोधरी बलबीर सिंह नेहुँ सालव नो हर बहत जबाब देने के लिए रेडी है। लेकिन वह घपनी बात भन गये। मैं आप को एक कहानी सुना द। एक राजा विवार पर गया, अपने साथियों से बहुत बारे निकल गया। एक जगह उस का एक बाग नज़र आया, वह अन्दर बला गया। बाहर दिखा कि एक बुद्धिया बैठी थी। उसने कहा—मा, पानी पि नापो। बुद्धिया ने कहा—बेटा, पानी की बया बात है, मैं तुम्हे रस पिलाता हूँ। उसने दो सन्तर पेंड म सं ताड़ी और उस वा रस लिकाना। दो सन्तरों से गिलास भर गया, इसलिए इस पर टैका लगाना चाहता है। जब वह बापस लौटा तो कि उसी जगह पर गया और बुद्धिया से रस पिलाने का कहा। बुद्धिया ने फिर दो सन्तरे लांडे और रस निवालने लगी, लेकिन इस बार उतना रस नहीं निकला। राजा ने पूछा—मार्हि, क्या बात है, सब दो सन्तरों से गिलास भर गया था, इस दफा नहीं भरा? बुद्धिया ने जबाब दिया—बेटा, यह के राता की नींवत मे फर्क था गया है।

आप की नींवत खण्डव थी, इसी लिए लगातार आप वे जाय दें कमी रही। वरना आप बतानाइये—आप के जितने लगाये, क्या उन का असर 1977 के बाद ही होता था, पहले उन का असर क्यों नहीं होता? आज किसान ज्यादा पैदा करता है—तो आप उसे ज्यादा पैदा करने से मत रोकिये। लेकिन हमारे मिनिस्टर कहते हैं कि उस बोरी की म फलन कम कर दो। गोले की फसल कम कर दी जायेंगी तो फिर काइकूप आयेगा, उस के बाद आप फिर कहेंगे कि ज्यादा पैदा होगे। इसी तरह से गैरु भी बात है—आप गैरु की पैदावारा कम होंगी, तो फिर दिक्कत पैदा होंगी। इस लिए यह गवन पानिमी है। आप भेदभावी कर के किसान को ज्यादा पैदा करने के लिए ग्रोसाराइज़, और जो सामान ज्यादा पैदा होता है उस को विदेशों से, दूसरे देशों से भेजने का प्रयत्न कीजिए। आने वाले के निवारियों में भिड़िया लगाना कीजिए, बाहर की भर्तियों में मृत्ति-किल प्राहक छहें की ज़रूरत है। बाहर के लोग यह कहते हैं कि जब हमें माल की ज़रूरत होती है, तब ही आप देते नहीं हैं, लेकिन जब हम दूसरा इत्तजाम करने जाते हैं, तब हमारे पास उसे भेजने के लिए आते हैं।

मैं एक ग्राह युक्ताव देना चाहता हूँ—हरियाणा और पंजाब में आप सरिजियों को बहुत देनी से पैदा करायें और राज और गहरी ही गल्फ़ कार्पूरों में ऐसा इन्हजाम कीजिए कि उस को बहा बेचा जा सके। उन के साथ इन्हजाम करे ताकि सामान बाहर भेजा जा सके। जब आप का वैटन बल जागता, तो यहाँ के आदिवासियों को पैसा भिलेगा, किसानों को आपनी भेदनत का दाम मिल भरेगा और बाहर के देशों की भी अनाज भेजा जा सकेगा।

समाप्ति महोदय श्री ए० सौ० जार्ज़।

बोधरी बलबीर सिंह तिर्क एक मिनट भी दे दीजिए।

समाप्ति महोदयः साप बहुत बोल चुके हैं।

श्री ए० सी० जार्ज

SHRI A. C. GEORGE (Mukandapuram): Mr. Chairman, Sir, at the very outset when I participate in this discussion on Agriculture Ministry, instead of going through the normal ritual of either congratulating him or decrying him I only want to say how lucky he is. During the past two, three years, the agriculture in this country has been fairly good, because of God's grace and nature's kindness. Weather is fairly good. The monsoon is rather favourable. The farmers are basically hard-working. Mr. Barnala is lucky and this Government is now fairly on a good footing.

When he took over, we had a stock situation which was unique and unprecedented in the history of independent India. So, he inherited one of the best stocks of foodgrains this country ever had. I particularly congratulate him because unlike the other Ministers, he did not spoil what he got in a Government where almost all other Ministers, whatever they inherited like a prodigal son or like a spoilt child, they were in a spree of frenzy to fritter away everything that they got. Here I mention the Finance Ministry. They inherited a foreign exchange reserve of nearly 4000 crores which was accumulated with hard labour of our boys in foreign countries, in which the contribution of Keralites is not very small. Now, the Finance Ministry has tried their level best to see how to empty the coffers. About Commerce Ministry, the same thing applies. For the first time since independence we have record adverse balance of payment of nearly Rs. 1600 crores. I am proud to say because I was the junior Minister of Foreign Trade that we handed over a surplus balance of payment.

About Industry Ministry, the less said the better. The speeches which the Minister makes at lunch, after lunch and at dinner, all are contradictory. And the officers say that they do not take them seriously. So, they blow hot and cold. One day it is

nationalisation, the other day it is de-nationalisation.

About External Affairs Ministry, we know how an aggression was committed under the very nose of our External Minister.

Mr. Barnala, I thank you very much. You did not atleast spoil what you got. I am reminded of a small story which has its bearing on the Agriculture Ministry. In a congregation the cap of the priest was sent for contribution. It was a misers' congregation. In that crowd the cap went round without contribution of a penny. Finally, from that congregation the cap came back to the parson. He took it up, looked into the cap and found there was nothing; he just turned it up and shook it; there was nothing. Then he raised his hand up and said "Oh! Lord I thank thee from his congregation I got back at least my hat." This is the case of the Agriculture Ministry. From the Ministry of Agriculture we got back our hat. So, I congratulate him for not spoiling it.

Of course, he did something in Kerala. Perhaps, he was under the evil influence of the Kerala Government at the time of the constitution of the Coconut Board. Of course, I know that it has been passed in a hurried manner. It has not only been concentrated, but super-concentrated with bureaucracy. It is not going to serve the purpose which he has in mind.

I never question in *bona fides*, because I know that in his heart of hearts he is a son of the soil, he is a farmer and the blood of a farmer is in him. So, I never question his *bona fides*. Kerala is a State where the name of the State itself is inherited from a tree. I was trying in my own limited way to find out whether there is any other instance throughout the world of a country being named after a tree, but I could not find one. It is only in Kerala it was known as the land of Keras, which means coconuts. Of course, some of our friends

in the north pronounce it as Kerala, which means bittergourd.

The production of coconut is our mainstay. The other day we were reading that in spite of the efforts made by the Government to increase the acreage under coconut cultivation in Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh, Orissa and Bengal, the production of coconut has gone down by about 7 per cent in a decade. Here I want to make a specific suggestion for his consideration. In the Kuttanad area, which is the main coconut producing area, we are facing one of the biggest attacks of a disease by insects because of which the coconut production is going down. Since none of us has found a solution for this virus so far, I want to make a suggestion. Just as we did once for rubber, we must go in for a complete removal of the trees. In rubber what was done was slaughter tapping after which the emaciated trees were cut off. We gave both subsidy and loan so that there will be an incentive for the farmer to cut down the old trees. Instead sticking to his meagre income, since we have not found a solution for this virus, we should encourage the farmers to cut down the trees and replant them. I would request the Agriculture Minister to take immediate measures to create a fund for coconut replantation. In order to encourage the farmers, we have to give the incentive of a loan as well as subsidy so that the farmer will be forced to cut down his trees, which are virus-ridden, and plant new trees. For that a coconut Development Fund has to be created so that the present virus may be fought and production may be increased with a new variety of plantations.

So far as the Coconut Board is concerned, even at this stage I would say that the Minister must take measures to re-vamp it, to regroup it and make it more popular-based rather than bureaucracy-based.

Then I come to another point. We have now got a regulated market, co-operatives and so many other methods

to see that the farmers get a proper remuneration for their work. In the hilly slopes of the Malabar area, known as the *Malayora Pradesam*, people from the plains have gone to the mountain slopes, cultivated the virgin land and made a paradise out of it. Even though in a State like Kerala we have got a lot of transportation facilities, in the slopes of the hills there are no proper roads. The realisation of the farmer for any crop is directly related to the accessibility to the market. In a State like Kerala, where virgin land has been cultivated and many cash crops have been grown, where there is cultivation of the hill slopes of Kerala, there should be a connecting road from Quilon via Kottayam, Idiki, Ernakulam, Trichur, Palghat, Calicut, Malappuram to Cannanore. There is a proposal for a hill side road, which should be looked into by the Transport Ministry. All these areas should be directly linked so that the farmers can get a reasonable realisation for their efforts. I would urge upon the Government to take steps to see that a specific allotment is made for this type of facilities for the farmers who have gone to the inaccessible areas and created wealth there for the benefit of the country.

16 hrs.

Sir, in my constituency there is a proposal for a sluice-cum-bridge in Elanthikkara Kanakkankadavu across Chalakudy river. It is a multi-purpose project. It is a project which will create a bund and save at least 13,000 acres of good paddy land from erosion by saline water. This proposal is jointly funded by the State Government and the Central Government. It is a bund-cum-bridge. It will serve the purpose of bridging the river and at the same time the bund will serve the purpose of preventing the paddy land from being eroded by saline water for which purpose there is this proposal. So, I urge upon the Minister to kindly fish out the old files and see that it is sanctioned immediately. I understand the sea-erosion is also coming under the

## [Shri A. C. George]

purview of the Agriculture Ministry. These days when we talk about disarmament and peace and preventing war, there is a regular war going on at the coast of India, at the western coast especially the south western coast coming down from Karnataka to Kerala and the eastern coast of Andhra Pradesh and Tamil Nadu. This coast has to be protected by anti-sea erosion measures. The funds allotted to Kerala are only a pittance, if not meagre. So, I hope the anti-sea erosion measures will be taken to protect the coast.

जी अमरीतह भाई पटेल (पोरबंदर) : सभा-पति महोदय, कृषि और मिलाई मंत्री ने इस विभाग की जो मार्ग सदन के सामने रखी है, उनका समर्थन करने के लिए मैं बहुत उम्मीद हूँ। गत 2 साल में कृषि सिवाई मंत्रालय ने अप्रृत्यक्ष-कर उत्पादन, सिवाई जल और देरी उद्योग में काफी प्रगति की है, लेकिन मैं कुछ प्रमुख बातें इस मदन के सामने रखना चाहता हूँ।

जब कृषि राज्यमंत्री श्री भानुप्रताप सिंह जी राज्य मंत्री नहीं थे, संसद् सदस्य थे, तब उहोंने एक पत्रिका निकाली थी। उसके कुछ उद्योग में सदन के सामने रखना चाहता हूँ। कृषि साधनों पर सभी प्रकार के अप्रत्यक्ष-कर उनके उत्पादन मूल्य के प्रतिशत के रूप में इस प्रकार हैं:—

उद्योग पर 41.99 प्रतिशत कर है, कौटनाई दबाओं पर 55.00 प्रतिशत, बिजली की मोटरों पर 26.73 प्रतिशत, ट्रैक्टर पर 44.74 प्रतिशत, ट्रैक्टर युजों पर 26.93 प्रतिशत और डीजल तेल पर 74.47 प्रतिशत कर है।

मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि क्या उनके मंत्रालय में कोई योजना है जिससे इन अप्रत्यक्ष करों को कम किया जा सके? वह अप्रत्यक्ष करों को कम करने के लिए क्या उत्पादन चाहते हैं?

भारत का राजपत्र को 9 मार्च का प्रकाशित हुआ है इसमें कॉटिलाइजर के दाम लिखे हैं। 19 प्रकार के कॉटिलाइजर इसमें लिखे हैं। मेरे पास सभय बहुत कम है, इसलिए सभी को पहला नहीं है, लेकिन 3, 4 के बारे में बताना चाहता हूँ। अमोनियम सल्फेट, यूरिया, सुपरफोस्फेट ड्रिप्पल, डायोनियम फास्फेट के बारे में बताता हूँ कि इसमें लिखा है कि इनका प्रति टन का भाव इस प्रकार है:—

अमोनियम सल्फेट 890 रुपये, यूरिया का 1450 रुपये, सुपरफोस्फेट ड्रिप्पल का 1600 रुपये और डायोनियम फास्फेट का 2200 रुपये, एन० पी० के 1800 से 2000 रुपये और सूर फास्फेट ड्रिप्पल (पाउडर) का 1500 रुपये है।

जाज भनाज का दाम क्या है, 20 रुपये किलो का दाम 20 रुपये है। एक टन पर 1 हजार फिलो होता है, उसके हिसाब से लगाईये तो एक किलो कॉटिलाइजर का दाम 2 रुपये पड़ता है और भनाज का दाम 1 रुपये भाता है जब कि खाद का दाम 2 रुपये होता है। यह बान अच्छी नहीं है। अनाज का जो दाम होता है, उससे ज्यादा दाम कॉटिलाइजर का नहीं होना चाहिए।

जहां तक बाणिज्यिक फसलों का सम्बन्ध है, हमारे देश में पांच मूल्य तिलहने पैदा होते हैं: मूँगफली, तौरिया-मरसां, तिल, अलसी और अरण्डी। कुल मिला का तिलहन का उत्पादन 1973-74 में 80. 85 लाख मीट्रिक टन, 1974-75 में 80. 53 लाख मीट्रिक टन, 1975-76 में 90. 91 लाख मीट्रिक टन, 1976-77 में 70. 83 लाख मीट्रिक टन और 1977-78 में 80. 93 लाख मीट्रिक टन हुआ। 1978-79 में वह 88 लाख मीट्रिक टन होने वाला है। सभी तिलहनों में मूँगफली की पैदावार 70 प्रतिशत है। पिछली सरकारों ने तीस सालों में मूँगफली के बारे में कुछ नहीं किया। क्या हम भी कुछ नहीं करना चाहते हैं?

गुजरात, और गुजरात में खास कर सौराष्ट्र, और सौराष्ट्र में खास कर जूनागढ़, राजकोट, जामनगर, अमरेली और भावनगर वैग्रह जिले देश की एक-तिलाई मूँगफली पैदा करते हैं। सरकार ने इसके लिए क्या किया है और क्या करना चाहती है? मैंने सुना है कि जूनागढ़ में राष्ट्रीय मूँगफली अनुसंधान केन्द्र बोला गया है। लेकिन वहां पर काम कुछ नहीं हुआ है। मैं जूनागढ़ में रहता हूँ। मैं हावे मंत्री से प्रारंभा करना चाहता हूँ कि इस राष्ट्रीय मूँगफली अनुसंधान केन्द्र में तुरन्त काम शुरू करें।

स्वार्यात्म महोदय, कृषि विभाग की 1978-79 की रिपोर्ट, देज 9, पैराग्राफ 12 में कहा गया है कि 1978 से 1983 के बीत तक कृषि-जिसों का नियंत्रण 3125 करोड़ रुपये तक बढ़ सकता है। वह किस तरह बढ़ाया जा सकता है? वह बहुत कृषि-जिसों की नियंत्रण-बंदी की आती है। जिस पर किसी प्रकार का नियंत्रण-बूल्क नहीं होना चाहिए। नियंत्रण पर एस० टी० सी० और नाइड की मानोपसी नहीं होनी चाहिए। उत्पादकों, किसानों, व्यापारियों और परिसंस्करणकर्ताओं की सलाह और सेवाएं सक्रिय रूप से लेनी चाहिए। कृषि-जिसों पर नियंत्रण-बूल्क रद्द करना चाहरी है।

विभिन्न कृषि-जिसों पर प्रतिटन के हिसाब से नियंत्रण-बूल्क इस प्रकार है: एस० पी० एस० मूँगफली की गिरी : 1500 रुपये, मूँगफली साड़ुत : 1150 रुपये, रुई : 2500 रुपये, मूँगफली की खीली (टीप्रायर्स) केक : 255 रुपये। क्या मंत्री महोदय वित्त मंत्रालय से बात-चली कर के इस नियंत्रण-बूल्क को रद्द करना चाहते हैं? 3125 करोड़ रुपये का नियंत्रण सरकार किस तरह करती?

करेगी ? जब उत्पादन होगा, तभी वह निर्यात कर यकीनी। लेकिन निर्यात-गुलब को कम नहीं दिया जाना है, वर्तिक उसके बढ़ाया जाना है। पाच मात्र दिन पहले एक सदात वे जबाब से बताया गया वि एच्च० पी० एम० और मात्रुत्र भगवत्ता और रुई का निर्यात गुरुह बढ़ा दिया गया है। यदि मध्यो महादय गामपांड वा बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें वित मन्त्रालय से मिल वर निर्यात-गुरुह का रद्द करना चाहिये।

जना तक कृषि मूल्य आयोग का सम्बन्ध है, प्रश्न यह है कि वह भाव ऐस तय करता है। कृषि-उत्पादन के मूल्य तय करते हुए इन बांगों का ध्यान रा ना लाइंगों (१) कृषि की जमीन की कीमत, (२) जमीन की कुल कीमत का बेक रेट के लियावत से ५ प्रतिशत प्रति वर्ष व्याज, (३) लियावत का कुटुम्ब द्वारा की गई महत्त्व, (४) ब्रह्म-मज़दूरों का दी गई मज़दूरी, (५) प्रायाल इंजिन, विजनी के पम्पम, ट्रैक्टर, ट्रैक्टर वर्गोंह और बारा और यता का व्यवह, (६) बैल की कामत, (७) विजनी, इंड ग्रामल, कॉटन नाईजर, बीटनाईक दबावा का खर्च, (८) लिया गया कर्ज़ और उत्पका व्याज, (९) जमीन महसूल और उपवर।

यह सब लियावत लगा कर लागत तय होनी चाहिये, जैसा कि उद्योग और व्यापार म होता है। इसके अलाया हुई मूल्य आयोग म काई विस्तार नहीं है। उसमें सब एक-एकीशन म बैठन वाले लगा है। किसी ने खेती देखी नहीं है, नदी भी नहीं देखी है जायद हवाई जहाज से देखी होगी। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप एकीकल्पर प्राइम कमीशन में किसान के प्रतिनिधि को रखिए।

अन्त में मैं कुछ सुझाव सदन के सामने रखना चाहता हूँ—

१ कृषि उत्पादो की लागत—मध्यो प्रकार का खर्च गिन कर उनका भाव तय किया जाये।

२ मूरगफली एच्च० पी० एम० डी० आयल्ड केबस (मूरगफली की खली) रुई वरीरह इन सब कृषि उत्पादो का निर्यात गुरुक रद्द किया जाये।

३ नियात और प्रामीण भागों में पिछड़ हुआ—गुजरात को खाल प्रवार से—प्रार्थिक सहायता दी जाये।

४ कृषि भाव व्यव (एकीकल्पर प्राइम कमीशन) में किसानों को पूरा प्रतिनिधित्व होना चाहिये।

५ फसल और पशु बीमा योजना को शीघ्र अमल में लाये।

६ गुजरात के सौगढ़ प्रदेश के समृद्धतीय जमीन के कुओं का पानी खारा हो गया है। माध्यव

पुर, बेंड, पोरबन्दर, मियापारी, शोका, नवलखी, माडबो तक “झार प्रवेश अवरोधक योजना” के लिए वित्तीय सहायता दी जाये।

७ फटिलाईजर डीजन, कुछ आयल और कोट नाशक दबाव, कृषि उपयामी यन्त्रो, मशीनों का उत्पादन शल्क रह किया जाये।

८ मूरगफली जैसी मूल्य तिलहन के लिए जनागढ़ म मन्जूर किये गये “अमूस प्रान केन्द्र” का कार्य शीघ्र चालू किया जाय।

९ मूरगफली का न्यूनतम सहायक मूल्य २५० रुपये प्रति लिंगटल होना चाहिये।

१० किसानों के लिए ५ प्रतिशत ही दर से कर्ज़ा दिये जाने का प्रबन्ध जीता चाहिये।

११ निर्भदा योजना का कार्य शीघ्र चालू किया जाये और इस योजना में केन्द्रीय सरकार पूरी वित्तीय सहायता दे।

१२ गुजरात के प्रामीण सम्पर्क मार्गों के लिए पूरा अनुदान मन्जूर किया जाये।

१३ कृषि त्रिन्सा वा निर्यात बाधा जाये और कई निया बाने के तेलों का धायात बन्द किया जाये।

इन शब्दों क साथ मैं कृषि मकानाय की माया का समर्थन करता हूँ तथा मधी महादय से प्रायावता करता हूँ कि वे भेरे सुखावा पर व्यान द।

SHRI A. R. BADRI NARAYAN (Shimoga) I rise to oppose the Demands for Grants in respect of the Ministry of Agriculture and Irrigation for the reasons that have been reflected by my cut motions, several in number. I hope the hon. Minister for Agriculture will go through these cut motions and try to afford as much relief as is possible.

With regard to the Central Budget, we are all happy that the Budget is now rural-oriented, a departure from the usual practice of its being urban-oriented. I am glad that the hon. Finance Minister has provided considerable money for the development of rural areas, from the point of view of agriculture, rural industries, roads and things like that, which go to make up the prosperity of the villages. I am very happy that the Agriculture Ministry is headed by a son of the soil, who is himself a practical and pragmatic farmer and

[Shri A. R. Badri Narayan]

who has abundant sympathy for the agriculturists. I hope that the red tape of the bureaucracy would not come in the way of implementation of the pious intentions of the Central Government. The Janata Government has solemnly pledged to end the neglect of agriculture and solve the problems of poverty and unemployment within ten years by adopting the strategy of accoiding the top most priority to agriculture and cottage industries. With all the pious intentions of the Government, the agricultural production in this country has been characterised by extreme instability resulting in chronic shortage of foodgrains and also of raw materials, necessitating massive imports which in foodgrains alone is more than Rs. 6,000 crores and in edible oils, it is about Rs 1400 crores. This lag in agriculture has restricted the expansion of the home-market, has hampered the industrialisation of the country, has caused repeated crisis in the formulation of the plans and has also made us increasingly dependent on the imperialists' aid, undermining the economic independence of this country.

Even the limited wealth that is produced by the farmers is all inequitably distributed in the country. The States have drained a part of the income by its taxes and duties; the monopolies and the multinationals have drained through price loot in the capital market; the landlords, the usurers, the hoarders, the profiteers and the bureaucrats have drained through rent, interest, profit, bribes, etc. The peasants produce plenty and suffer while the exploiters fatten, prosper and flourish.

Under the land reforms, only 1,29 million acres of surplus land out of available 21.52 million acres have been distributed. About 20 million acres are yet to be distributed. The Janata Government has put land reforms in the reverse gear. Though I belong to Karnataka, I must in fair-

ness say that practically the tenancy is abolished in the State of Karnataka and the tiller of the soil is now the owner of the land. I would request the Janata Government to see that, in various States, instead of aiding and abetting the landlords to snatch away the tiny patches of land distributed to the poor peasants, this must be put an end to. Several Janata State Governments are shamelessly seeking to enact reactionary amendments to ceiling laws as a legal cover in the marauding of land reforms. Equally shameful is the record of subjecting the peasantry to intensified price loot.

The *Economic Times*, index says that the prices of agricultural commodities have fallen and the prices of manufactures have risen further. The agricultural production has declined by 10 per cent whereas the production of manufactures has increased by 6 per cent, thus causing 15 per cent loss to the agricultural sector. It amounts to roughly about Rs. 2500 crores in a year. This is the annual tribute that is paid by the farmers to the capitalists, the industrialists and the monopolists. The agricultural inputs over 1970-71 output have gone up as follows: diesel—116.6; lubricating oil—209.3; electricity—95.6; cement—87.8; iron—80; fertiliser—75.9; pesticide—131 and tractor—118. While the output of wheat has gone up only by 48 per cent, paddy by 51 percent, jowar by 54 per cent, jute by 40 per cent, cotton by 79 per cent, sugarcane by 33 per cent, the general index of all commodities has risen by 86 per cent. Since 1970-71 the prices of agricultural in-puts, except fertilizers, have risen much higher than the prices of agricultural outputs. The fall in agricultural prices has not been passed on to the consumers. Thus, while raw materials are cheaper, the manufactured items are dearer, for example, cotton and cloth, jute and gunnies, tobacco and cigarettes, oil-seeds and edible oils. The fall in whole-sale prices has not been reflec-

ted in retail prices; for example, the wholesale price index for food articles has fallen by 10 per cent but the index of consumer prices has risen by 10 per cent. In December 1978 it was 340 and in March 1977 it was 312. The peasants who are the majority consumers have lost both as producers and as consumers and the gainer are industrialist and traders and the big capitalists, the sharks of the so-called free market. Firstly, they dismantled controls, demolished food-zones and have withdrawn restrictions on forward trading speculation, hoarding land profiteering and, secondly, they have liberalised the credit for hoarding, profiteering and speculation, while restricting the same to State Trading agencies like the FCI, the CCI and the JCI. The increase in bank credit to the private commercial sector has gone up to 2275 crores during 1977 as against 1592 crores in the previous year. There is liberalised import of raw materials in which our production is sufficient to meet our domestic requirements, viz., cotton, rubber, copra and jute. They imported 14 lakh bales of high-priced cotton, paying a subsidy of 72 crores, and 100 crores for staple fibres.

Fourthly, there should be a comprehensive distribution system and a widening up of the existing one whereby we are left to the mercy of big traders and mill-owners. Salt, cement, paper, coal, diesel, Kerosene, cooking gas, soda, edible-oils, etc. are all disappearing from the market.

Again, the sugarcane price has been reduced from Rs. 12.50 and Rs. 16.50 per quintal to Rs. 10/-, though the cost of cultivation has gone up. It should not be less than Rs. 12.50 per quintal.

Apart from these things, I wish to say that the farmer is the producer for the country and he deserves the same attention as industrial workers now get. Concentration hereafter should be not only on the industrialists but also on the farmers. The

human facilities that have got to be given to the farmer should not be delayed.

MR. CHAIRMAN: Please conclude

SHRI A. R. BADRI NARAYAN: One more point, Sir, and I will conclude. You must conquer the adverse effect of floods on the one hand of delayed and reduced monsoon on the other. I would also refer to unharvested river waters and linking of the rivers. I am very happy that the Prime Minister has been pleased to announce some days back that the Garland Canal scheme has been under the consideration of the Central Government and that the USSR and the World Bank are likely to finance us, assist us with money as well as with technical knowhow. Leave alone the Garland Canal scheme, there are the South Indian rivers which flow to the west without being utilised in any manner; the water is unnecessarily flowing into the Arabian Sea. A method must be found out to link these various rivers of the South so that we may utilise the waters properly.

Hon. Chairman has been very good to me. He has been asking me to stop. I have got quite a number of points to speak on, but I do not wish to transgress the ruling of the Chair. So, I conclude by appealing to the hon. Agriculture Minister to bear in mind the several points which I have been trying to give in a very constructive manner. I hope he will apply his mind and do the things which are the most dear to his heart in the agricultural sector.

कृषि और सिवाई मंत्रालय में राज्य नंदी (श्री जात्य प्रताप लिह): भविष्याता महोदय भव तक हारि और सिवाई मंत्रालय के अनुदानों पर जिन भाननीय सदृश्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं उन सभी के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ। कुछ ने हासारी प्रबंधन की है, बासाई दी है और कुछ ने हासारी आलों का ना की है।

श्री एम्. राम गोपाल रेड्डी : निम्ना नहीं की है।

श्री भानु प्रताप सिंह : जिस ने निन्दा की है उसको भी मैं धन्यवाद देता हूँ और उसका कारण बताता हूँ ।

आज जो देश में कृषि की स्थिति है उसका एक सुनहला पहलू है और एक काला पहलू है । जिसने केवल सुनहला पहलू देखा है उसने बढ़ाई दी है और जिस ने सिफारी काला पहलू देखा है उसने निन्दा की है । मेरा माननीय सदस्यों से अन्तरोध है कि एक संतुलित बैलेन्स व्यवस्था लेना चाहिये । हमने कुछ उपलब्धियों की है ऐसी उपलब्धियों जिनके बारे में दूसरे देश वाले हमारी आज प्रशंसा कर रहे हैं । लेकिन हममें कुछ अभी कमियां भी हैं उससे मुझे इनकार नहीं है । मैं दोनों पहलुओं पर थोड़-थोड़ा प्रकाश डाकने की कोशिश करूँगा ।

जहाँ तक उपलब्धियों का प्रश्न है मैं ज्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि उसकी चर्चा तो दूसरे ही करें तो ठीक होगा । मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ कि जो देश 2 वर्ष पहले तक दूसरों के सामने अपना पेट भरने के लिए हाथ फैलाता था आज वह दूसरों का पेट भरने योग्य बन गया है । अभी योड़े समय पूर्व हमारे जारी साहब उद्धर से बोल रहे थे उन्होंने भी लैफ्ट हैंडेड कम्प्लीमेंट दिया उन्होंने कहा कि सब मंदालयों को तो नहीं कह सकता मगर कृषि मंदालय को कह सकता हूँ कि जैसा उन्होंने चार्ज दिया था उसको बिगड़ा नहीं है । इसको मैं लैप्ट हैंडिड काम्प्लीमेंट इस लिए कहता हूँ कि ठीक है उन्होंने एक अब भंडार दिया था लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूँ—वह इस समय यहाँ मौजूद नहीं है—कि वह अब भंडार किस प्रकार से बना था । क्या वह अब इस देश में पैदा हुआ था ? विदेशों से मंगा कर अरबों रुपयों या विदेश भेज कर वह अब भंडार बना था । उस अब भंडार को बनाने का दूसरा तरीका यह था कि अपने देश के किसानों के घरों से जबरदस्ती पुलिस भेज कर उनकी मर्जी के खिलाफ बहुत कम कीमत पर ज़रिया गलता बसूल किया गया ।

आज हमारा अब भंडार न तो विदेशी अब्ज से भरा है और न हम ने किसी किसान से उसकी मर्जी के खिलाफ ज़रिया बूझली की है । जो कर्ज़ा उन्होंने लिया था उस कर्ज़े को हम ने उतार दिया । सोवियत रूस से जो 20 लाख टन शेहूँ लिया गया था वह करीब करीब उनको बापस दिया जा चुका है । उलटे हमने उनको दो लाख चावल देने का टन अभी फैसला किया है । अगर इन दोनों परिस्थितियों में जारी साहब को कोई अन्तर न पर नहीं आता है तो मैं तो यही कहूँगा कि देखने का दोष है ।

हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि जहाँ तक किसानों का प्रश्न है कॉर्पोरेशन के शासन और आज के शासन में उनको कोई अन्तर न ज्ञान नहीं आता है । यादवाश्वत्रें बहुत छोटी हुआ करती हैं इस लिए मैं बहुत संक्षेप में केवल कुछ पार्यंट्स बता देना चाहता हूँ कि क्या अन्तर हुए हैं ।

पहला अन्तर तो यह हुआ कि पहली पांचों पंच वर्षीय योजनाओं में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए व्यय की गई धनराशि 19 से 23 प्रतिशत होती थी मगर अब उसको करीब करीब दुगना कर दिया गया है । इसके परिणाम भी सामने आने शुरू हो गये हैं । पांचों पंच वर्षीय योजनाओं में सिचाई पर जितना व्यय हुआ था उससे अधिक इन पांच वर्षों में सिचाई पर व्यय होने जा रहा है । पिछले वर्ष 28 लाख हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि में सिचाई पहुँचाई गई । यह विना धन को लगाने हुए नहीं हो सकता था । इसमें बहुत बड़ी धनराशि लगानी पड़ी है ।

अभी कुछ दिन पूर्व सोवियत यूनियन के डिपुटी मिनिस्टर, एग्रीकल्चर, मुझ से मिलने आये थे, जब मैंने उनसे कहा कि भारत में 28 लाख हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि में सिचाई की व्यवस्था एक साल में की गई है, तो उन्होंने बड़ा आश्चर्य किया और कहा कि हमारे इन्हें बड़ी विशाल देश में किसी एक साल में दस लाख हैक्टेयर से अधिक अतिरिक्त भूमि पर सिचाई की व्यवस्था नहीं हुई ।

जब इस सरकार ने चार्ज लिया था, उस समय एक राज्य से दूसरे राज्य में अब नहीं जा सकता था । राज्य तो छोड़िये, एक ज़िले से दूसरे ज़िले को अब नहीं जा सकता था । और मेरा ज़िला तो ज़िला तो इतना बदकिस्मत था कि नदी के इस पार आधे ज़िले से नदी के उस पार भी अब नहीं जा सकता था । इमज़ैन्सी से पहले भी और इमज़ैन्सी के दौरान भी चारों तरफ किसानों को बेर कर उनको लटने की व्यवस्था बनी हुई थी । वे अपना माल कहीं बेच नहीं सकते थे, सिवाये सरकारी एजेंसियों को । उसके दृष्टिरिणाम भी थे, परन्तु उसकी कोई चिन्ता नहीं की जाती थी ।

जिनता सरकार ने पहला काम यह किया कि इस देश में एक बाजार कायम किया “एक राष्ट्र एक बाजार” का जो उद्देश्य था, उसको प्राप्त किया । दिल्ली के निवासी भले ही इसके लाभ को न समझते हों, लेकिन जा कर बम्बई और पूना के लोगोंको पूछिये कि उनको कितनी राहत मिली है—केवल इस कारण से कि खाद्यान्नों के आवागमन पर से सारे प्रतिवन्ध हटा दिये गये हैं । जिन लोगों को दस बारह रुपये किलो के हिसाब से चावल मिलता था, आज उनको दो रुपये किलो के हिसाब से चावल मिल रहा है ।

चीनी की दोहरी नीति थी—चीनी दोहरे मूल्य पर विकती थी । एक माननीय सदस्य ने कहा कि अब तो जानी 2-90 रुपये पर आ गई । लेकिन वह भले होये कि पहले व्या स्थिति थी । अग्र प्री-चीनी और लेची-चीनी की वेटेड-एवेज़ ली जाय तो आज की चीनी से भाव ऊँचा था । जहाँ तक उपलब्ध का प्रश्न है—गांव वालों की चीनी नहीं मिलती थी और मेरा तो ऐसा विश्वास है कि चीनी की उस दोहरी-मूल्य-नीति के कारण इस देश में कम से कम सैकड़ों करोड़ रुपये की ब्लैक मनी जैनरेट होती थी, उसको हमने समाप्त किया और इस का एक लाभ अभी भी स्पष्ट है कि चीनी की खपत देश में एक दम बढ़ गई ।

पिछले दिनों हमारे सामने एक सब से बड़ी समस्या थह थी कि यीनी उद्योग से उत्पादन बढ़ाने से ज्यादा था, बहु समस्या प्राप्त: सुलभ नहीं है। जिस गति से यीनी की व्यापत बढ़ी है—इसको ल होने के बाद से— आप देखें कि 60 लाख टन यीनी की व्यापत इस देश में हो जायगी और साथ ही साई-ल: लाख टन हम विदेशों को भी भेजेंगे। इस प्रकार हम से हम यह कह सकते हैं कि जितनी यीनी बनेगी; उस से कुछ ज्यादा ही बेश के प्रबन्ध बढ़ाने होने वाली है तथा विदेशों को भेजी जाने वाली है। इस तरह से यीनी उद्योग को जो सब से बड़ी समस्या थी, उस को हम ने हल किया है।

अब मैं “फूड-फार्म-वर्क” के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। आप को मालूम है—पीछे “फूड-फार्म-हंगर” नाम की एक स्कीम चली थी, वह अन्तर्राष्ट्रीय स्कीम थी, परन्तु जितना उस स्कीम के अन्तर्गत सारे संसार में अनाज व्याप होता था, उस से ज्यादा “फूड-फार्म-वर्क” योजना के अन्तर्गत भारत सरकार ने पिछले वर्ष व्याप किया है। जो लोग भूखे रह जाते थे, जिन को पूरे वर्ष काम नहीं मिलता था, वर्षोंके हमारे यहां खेतों में चन्द महीने ही काम होता है, ऐसे लोगों को बेकारी और भूखारी का मामना करना पड़ता था, आज उन्होंने हमारी इस योजना के कारण भर्टोट भोजन पाया है। हम लोग यह चर्चा करते हैं और वह लोग भी हैं कि योंही भजद्वारों को मिनिमम वेज मिलना चाहिये। लेकिन मैं आगे से कहना चाहता हूँ—फूड-फार्म-वर्क योजना में काम करने वाले आज जो उन को मिला है, वह मिनिमम-वेज दिलाने में उन की नहीं मिल सकता था। आज इस योजना में एक व्यवित को 4 किलो ग्रॅम मिल रहा है, तब फिर वह 2 या 3 रुपये की भूमध्यरोपी करने नहीं जायगा। इस तरह एक व्याप हम ने लोगों को रोजगार दिया, लोगों को पेट भरा और दूसरी तरफ बहुत सारे नियोनी-द्व्युरेविल एमेस्ट भी बढ़े हुए हैं। मैं माननीय सदस्यों को आमन्त्रणा देता हूँ—वे चल कर दें, राजस्वान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में किस तरह से काम हुआ है और गांव वाले इस योजना से कितने बुक थे।

एक विकायत यह की गई कि “फूड-फार्म-वर्क” योजना में सहा हुआ। अनाज दिया जाता है। श्रीमन, यह नियान्त व्यवस्था है, वर्षोंके राज्य सरकारों को मने वारम्बार व्यवस्था लिखा है कि इस घले को उसी प्रकार से स्वीकार करें जिस प्रकार से “फिफर प्राइस-शाप्ट” का गलता स्वीकार करते हैं। प्रत्येक राज्य सरकार को यह अधिकार है कि घले का चार्ज लेने से पहले उस की क्यालिटी को इस सकारे है। किसी भी राज्य सरकार के ऊपर कोई भी दूसी माल जबरदस्ती नहीं बोप जायगा, यह बात बारबार स्पष्ट की जा चकी है और उन को भी अपना अधिकार भालूम है। जहां तक फूड-फार्म-वर्क का माल है, उस के लिए मैंने विवेष रूप से लिखा है कि व्यापत उन को यह गलत माल में लिख रहा है लेकिन इस की नियन्त करके बैबलप्रैंट विपाटमेंट को बढ़ानी है। इस लिये इस वर्ष को देख कर मैं और इस के लाभ ही यह भी क्षम्य जाहता हूँ कि किसी दात्य सरकार

ने आज तक भेरे पास गले की ब्लाइटी के बारे में या कम से कम कूब-नार-वर्क के गले के बारे में लिख-कर नहीं भेजा बहिक उल्टे आज उस की मांग इतनी ज्यादा है कि हम को सोचना पड़ता है कि क्या हम उस की मांग को पूरा कर सकेंगे। पहले तो, प्रारम्भ में यह योजना गूँड़ की गई थी, उस ममत्य हम को यह कहना पड़ता था कि आप इस काम को करवायड़ए लेकिन आज यह इतनी लोकप्रिय हो गई है कि हमारे लिये मुसीबत हो गई कि हम किस हद तक उन की मांगों को पूरा कर सकेंगे।

रोजगार बढ़ाने के लिए दुध योजना भी चालू की गई है जिस पर अगले पांच वर्षों में लगभग 500 करोड़ रुपये खर्च आएगा।

कृषि और तिचाई मंत्री (श्री बुरवीत रिह बरनाला : रात सालों में।

भी चालू प्रताप तिहः : इस से मैं समझता हूँ कि छोटे किसानों को और भूमिहीनों को बहुत राहत मिलीगी।

फॉटोलाइजर्स की कीमत पिछले 2 वर्षों में 200 रुपये तक पिछाई गई है— (अवधान) ... आप जरा सोचने की कोशिश कीजिए कि इन के बावजूद एटोलियम से तय होते हैं। 1970-71 के गुवाहाटी में एटोलियम किस भाव पर मिल रहा था।

मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि अगले वर्षों के बाल्दर जो कर्जे दिये जायेंगे, उस का सूची भी 2 प्रतिशत नियाया गया है। पिछले कई वर्षों से देश में जो तम्बाकू पैदा करने वाले किसान हैं, उन को एक्साइज इम्प्रूटी वर्षोंके में परेशान किया जाता था और उन की संख्या बहुत बढ़ी है। आज वे राहत की मांस ले रहे हैं क्योंकि इस से सरकार ने उन से एक्साइज इम्प्रूटी को बमूली बन्द कर दी है।

अब तक हम क्या कर चुके हैं, उस के बारे में मैंने 10, 11 व्याख्यास के बारे में बताया है। जो पहले नहीं होता था और जिस के बारे में हम सरकार ने कुछ किया है, वह मैंने आपूर्ती को बताया है। अब मैं यह बताना चाहता हूँ कि आप हम लोग क्या करना चाहते हैं। यह मैं मानता हूँ कि जो बहीदारी की योजना बनती है, बहुत से किसान अपना गलता स्पोर्ट प्राइस पर भी नहीं बच पाते। यह बात सही है परन्तु उस में कोठिमायाहा है, उन की ओर भी आप ध्यान दें। सारी बहीदारी एक० सी० रुप० रुप० की है। बहुत सारी बहीदारी की है और यह बहीदारों को बारम्बार लिखा जा चुका है कि जो भी गलता वे बहीदारी अगर वह स्पेसीफिक्सन के मुताबिक हैं तो, उनका बहीदा कर के भारत सरकार उस को ले लेगी। अगर कहीं कोई भी कमी होती है, तो उस के लिए यह बहीदार भी जिम्मेदार है। बहुत सी राज्य सरकारें ऐसी हैं जो एक० सी० रुप० की अपने एक्सिया में आपैटेज नहीं लगाए देती। तरह तरह के कम के दौर्दृ हैं। कहीं

[श्री भानु प्रताप सिंह]

पर राज्य सरकार और एक० सी० आर्ड० दोनों जीविदी है, किनी गज्य में केवल एक० मी० आर्ड० बरीदी है और किनी गज्य में केवल गज्य की अपनी आजेन्नी लखीदी है । तो हम जीज को भी आप समझें । यह मास होते हुए भी हमारा यह बहुत रस्त फैसले है और इस फैसले से हम ने मासी मरण मत्रियों को अवगत करा दिया है कि हमारी भी छुपी राज्यांशु अपने अपेक्षाएँ प्राप्त थोपिए होती और उम को अपग वरापे द्वारा अपने राज्य में बरीदेंगे और वह हमारी एक० मी० आर्ड० के अन्यैसीकृदण व मनाक्षिण हागा, तो उम की कीमत द कर और उम को खरीदने का खंड भी दे कर भाग्य सरकार उम को ले लेंगी । आज इस बात की भी आपव्यक्ति का है कि जहा आप हमारे ऊपर आपने लगाने हैं तुम गज्य सरकारों पर भी दबाव डालने की कृपा करे । नायडू मालव बार बार नाराज होते हैं । उनकी नारात्री मेरी समझ में नहीं आती है । हम ने आनंद प्रशंस की सरकार के मुङ्ग मत्री का स्पष्ट कर दिया है कि वह जांह जिताना भी चावल और धान खरीदे सब एक० मी० आर्ड० लेने को नियम है । इस बातों वह डग नारात्री को कृषु उत्तर भी करने की कृपा करे ।

इन भव कठिनाइयों को दबाने हुए एवं नई योजना बनाने का फैसला किया गया है जिस का जिक्र हमारे बिन मली ने अपन बट्ट मारण में किया था और वह सामीण गोडाउज बनाने की है —

श्री वदमाचरण सामन्तसिंहेरा (पुग) : फँड-फार-बर्क में प्राप्त उड़ीमा को चावल क्यों भेजते हैं वह तो बहा पहले से ही काफी है ?

श्री भानु प्रसाद सिंह उन से प्राप कर्हे कि हम को लिख कर भेज दे । अबदंस्ति हम किसी को नहीं देते हैं । मानेगे तभी देंगे ।

करते गोदावार्तंक की नई योजना स्वीकृत हो चुकी है। इस योजना का उद्देश्य यह है कि 5-6-7 वर्षों के बीच में एक देव या दार्शी सी टन के लिए गोदाम बने और वहाँ छोटे वित्तान नकदी के साथ कर घरणा वस्त्रा रख सके और वहाँ दोनों ही काम कर सकें। अगर बांधना चाहें तो स्पोर्ट प्राइवेट ट्राई टो बैच दोनों और अपर रखना। बाहर हो तो रख सकें। और अपर रखना। बाहर हो तो रख कर उसके मुकाबले से उसको नकदी काम बचाने के लिए वैक से एडवांस दिला दिया जाएगा। यहीं किसान हैं जिन को सब से ज्याद रका की आवश्यकता है। यह केवल राज्य सरकार पर ही निर्भर नहीं है। यह तो हम बाहर हो कि किसान भी स्वयं संगठित हो। हम बाहा नहीं करते हैं कि किसान सब लोक बर लिया है और कुछ करने को बाकी नहीं है। लोकिन हम बाहते हैं कि आप बरा हाथारी कठिनाईयों पर भी गौर करे। पहली तो यह है कि लोकी का कारोबार देता नहीं है कि जिस को तकाल दुकान लिया जा सके। एक फसल अपर इस साल मारी जाएगी तो उपरे साल आप उस में कुछ संबोधन कर सकें। लोकी ने बहुत लोटी जान बदल दिया है तो एक

साताहा और दस दिन में उसको ठीक किया जा सकता है लेकिन स्वच्छ बागाने से जैसे एक पक्षा जलने समयता है तभ मर्ह से खेती के बारे में नहीं हो सकता है । अब तक की जो व्यवस्थायें थीं वे कमी का मुकाबला करने के लिए थीं । देखें कमी का एक तात्परण या । उद्देश्य यह था कि गांवी से आधिक से अधिक गलती कितान का विकास हो जाए ताकि गांवी से जैसे भी ही उपभोक्ताओं को विलापा जाए, उनकी रक्षा हो जाए । यह आवश्यक भी था । आज परिस्थिरता बढ़त गई है । आज की परिस्थिति में मैं समझता हूँ कि गांवी में गोदाम बनाने चाहिये ताकि लोटे कितान को दूर जा कर परेशान न होना पड़े और वे अपना माल रखने के लिए कुछ भी मिल पाए और जब खाद्य बढ़े तो उसका नाम उठा मर्ह । इसी उद्देश्य से करन गोडांउड बागाने वीं योजना रखी गई है ।

यहाँ मार्ग की गई है जिस पर विचार हो रहा है लेकिन अभी नव अर्थात् फैसला नहीं हुआ है कि जो खालीपाल किसान स्थय रखे रहे और बाद में मालाई करें गवर्नेंट को तो उमका भी जो लखा एक-मीलाई है बैरीट का भाना है वह प्राधिक दे कर उससे ले लिया जाए। ईकैप्रियोकारी के लिये उमीद दीर्घिया इसमें सभी का लाभ है। आगे इस बात को इस प्रकार से बयां किया जावत से ग्राप्त होता है। ये प्राचार और हरियाणा में मई वे शूल में घायेंगा कई बार 6 हफ्ते से ज्यादा टाइम नहीं लिलता है तो उम बक्त हमारे पास रखने की जगह की कमी होती है डास्टोंसे की कमी होती है। सधी प्रकार से मिडियों में भी जगह नहीं रहती है। इस प्रकार से हम भाना गया है कि हूँ तो मान रखा जायेगा प्राचार रुक्ल गोडाउन्स में और कुछ किसान भपने बर पर ही रख ले तो उसकी बरसात के बाद अन्तर्वर नवबर में और किर जलतरी, करवरी, मार्वे में सरकारी भाव देकर ले लिया जाये। किसान भाव किसान करो यहाँ? जब पूरे वर्ष तक एक ही भाव रहता है तो उक्ता परिवर्तन हुआ होता है कि हरेक यह बहाता है कि दुकान बलते ही पहुँचा दिया जाये। तो इससे जहाँ एक-मीलाई ०० पर बहुत बड़ा भार आता है बहा यह भी होता है कि जब बहुत लोग इकट्ठे होते हैं तो किसानों के साथ दूर्घट्यहार भी होता है। लेकिन उस बार को कम करने की समझता है कि यह दो योजनाएँ साथसाथ लिया जायें।

अन्त मे यह भी कहना बाहर हूँ कि जैसे हमारे वित्त भवीती भी मैं बोचित किया है अब तक सिवाई के लिये तिर्फ़ 2 हैट्टर तक के किसानों को लालीडी मिलती भी भव सोचा जा रहा है कि यह 4 हैट्टर तक के किसानों को मालीडी भी जायेगी। उद्देश्य यह है कि प्रधानके से भारी छोटे नस कूप बलाकर किसान नमाय नामावरित बने।

मैं एक छावक के नामे कह सकता हूँ कि जोती अच्छी बही कर सकता है जिसका पारी का लोट उसके अपने फ़ॉटोज़ में हो। यह तभी सचमू है जब अधिक दे अधिक किसान अपने नेत कूप बतायें। अपने देवते में बहुत कम उत्तर भारत का भाव है जोही नीचे पारी की कमी बढ़ावी है जहाँ आसानी से वासी निकल सकते हैं। दो उत्तर कंत का हमें जान उठाना चाहिये। आप—जीव जल्दी

कि भौमम की जगा मे कुछ हमारे हम बात पर मै उनकी आलोचना नहीं करूँगा यह अपने विचारों को रख सकते हैं, लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि यदि हम मिक्काई के माशनों को बहत तजी मे बढ़ा सके, तो हम भौमम के उत्तर बहात मे इस देश को मिक्कि मिल सकती है। आज भौमम प्रजाव का कुछ नहीं विवाद मिलता है, आप विवाद नहीं करें, तो ऐसा भी भौमम होगा, प्रजाव और लक्ष्यान्वय व परिवर्ती उत्तर प्रदेश मे कमल होंगी। तो हम उसी स्थिति मे पहुँचने के लिये किसानों की महायाना करना चाहते हैं कि वह अधिक ले अधिक नक्कप बनाये।

एक बात की मै और नर्सरी करना चाहता है। गरीबी दूर करने की वजहीं है, लेकिन गरीबी कैसे दूर होंगी? जाव की गरीबी दूर करने के लिये वा चीजों की मावध्यता है। एक तो पजी और दूसरे कुछ नया जान विजान। प्रगत काई नमज्जना हा कि कवल इस बात की चर्चा कर के कि वह रिकान नहीं द्वारा लग रहे हैं, या इस प्रकार की बातें कर के काई गरीबी दूर करने की कार्यालय है वह ग्रामीणतक नाम नहीं उठा सकता है, लेकिन इस की गरीबी दूर नहीं होगी। गरीबी दूर करने के लिये पजी और नहीं जानकारी का पहलाना बहुत जरूरी है। जहा तक पजी का प्रश्न है, मैं बताना चाहा है कि मानन मरकार जिनसा व्यय करनी ची, उसका दृग्मन व्यय अब करने जा रही है। हमको अन्तरिक्ष हमारी यह भी कार्यालय जाना कि हम वहा कुछ आशी जानकारी भी पहलायें। ब्रह्म मै कपी कृषि अन्तरिक्ष केंद्र पर जाता हा ता ऐसा लगता है कि यहा जानकारी का ऐसा लज्जीरा है कि प्रगत इस। इन्साल हा तो इस देश का चिक्क बदल सकता है। लेकिन दूसरी की बात है कि वह जानकारी, जिसमे दूसरे देशों के लोगों ने कामया उठाया है, हमारे देश के लोगों ने उसमे नाम नहीं उठाया। हा बीज जरूर कुछ खखरा गा है, लेकिन बाकी जानकारी वही भी यही रह गई है।

एक योजना, जिसका निवारी जी ने जित्र किया—  
सीट टैक्स—उसका उद्देश्य है कि जितने अन्तर्द्वान केन्द्र हे वे अपने पड़ोस मे बायीं गरीब लोगों को छाट कर याने विजान के द्वारा उन्होंने जीवन सराव को ऊचा उजाने की कोशिश करे। '50 हजार पर्सिवार लाइट जायेंगे। इनके प्रतिरिक्ष एक योजना यह भी है कि यारों से कुछ पहे लिखे लडकों को लेकर उन केन्द्रों पर दो तीन महीने रखकर किसी एक काम के लिये प्रशिक्षित किया जायेगा—जाहे आटिक्कल इन्टर्विनेशन हो, सेटिक्सर हो, पोली कीपिंग हो या इजन रिपेयर, मोटर रिपेयर का काम हो। उन्होंने भी धर्ये यारों मे बल सकते हैं उनकी दृष्टियां देने के लिये एक योजना तैयार की जा रही है। इन्टर्विय डेवलपमेंट ल्याक्षण मे पहले से ही यह योजना लाग है लेकिन हु यह की बात है कि लोगों को यह मालूम नहीं है। मझे स्वयं इस बात पर ध्यान देना है, यद्यपि एक माल मे गाड़िलाइन्स लैखी हुई है लेकिन इसकी जानकारी नहीं है। 2300 अन्तर्द्वान मे बड़ाकर 2600 अन्तर्द्वान मे लाग किया जा रहा है। हमारा प्रयत्न है कि यह योजना सारे देश मे लाग की जाए। यारों के जो पहे लिखे जीजावन है उनको नया काम सिक्काया जायेगा। नौकरी देने के लिए हम उनको

यह काम नहीं सिक्का रहे हैं बल्कि लीग, चार, पांच महीने की उनकी ट्रेनिंग होती जिसमे वे काम सीख कर गांवों मे जाये और सेल्फ एप्लायड वर्सन की तरह मे अपना कारोबार बाल करे। इसमे एक तो उनका आगता रोजगार दो जायेगा और दूसरे लोगों के लिए उदाहरण भी बनेगे। (व्यवस्थापन)

दो एक बातें मै और कहना चाहता है। माननीय मदम्हो ने कुछ ऐसी बातें कहीं जिनका उत्तर देने से यद्यपि नीतीजा नहीं निकलता किर भी मै निवेदन कर, जैसे बन्द शेष्वर मित जी ने यहां पर कहा कि जेल मे जितना गानन दिया जाता है उसके हिसाब मे देखा जाये तो इस देश के जिन कम अनाज पैदा हो रहा है किर भी कहा जाता है कि अनाज काजिल है इम्फेस सरकार के मारे आकड़े गलन है। माननीय मदम्हो बेकल यह अन्न गा कि जेल मे बन्द नहीं रहते। बालिंग की बराक और दमरी नरक मवी की बरगव मे बोझा फक्क है। (व्यवस्थापन)

इस बात की चर्चा भी की गई कि पहले चीनी बहूत एकपाठ होती थी और यह सरकार निकम्भी है, एकपाठ की रक्त कर पा रहा है। उन्हे नहीं मालूम कि अन्नराज्यीय बाजार मे चीनी का बया भाल है, जिस गमय का माननीय मदम्हो जिक्र करते हैं उम ममय अन्नराज्यीय बाजार मे चीनी का मल्य 700 पाउड प्रति टन या और प्राय 100 पाउड प्रति टन है। उम ममय की सरकार ने चीनी बेच कर भूतका कमाया था हम आज भी बेचते हैं लेकिन बाटे पर बेचते हैं।

एकपाठ की बात भी यही गई है। इस विषय मे मझे ज्यादा नहीं कहना है मै भी एकपाठ का बड़ा हिमायती है लेकिन माथ ही मै यह बनलाना चाहता है कि एकपाठ भी ऐसे नहीं हो सकता है कि आज आपाने फैलाया किया कि एकपाठ होगा और कल एकपाठ हो जाये। इनिया के लोग मह बाये बैठे नहीं रहते हैं। एकपाठ के लिए हर उत्तरको अपने कम्पटर बनाने पड़ते हैं अन्नराज्यीय जगत मे आपाने प्रबोध नया होया और उसके जगत मिलेगी या नहीं मिलेगी—यह देखना है। हमारा यह है

17.00 hrs

जी बन्दन लिह (कैरगाना) नेपालमैन मालब मझे एक बात कह लेने दीजिये। जन भेदे बच्चे ने टेलीको लिया किया कि गिताजी 20-25 मंग्ल लेने आया। बड़ी मशिकासे मे भग मिली, मै भग लेने गया तो वह अफमर भीटिंग मे था। मेरे बच्चे ने कोट-नाशक दवा भी लाने वे लिये कहा था, जब मै उम के केन्द्र मे पहचा नी मालम हुआ कि यह कानून है कि आइंटर देने के एक महीने बाद मिलेगा। मैने कहा कि सोइग का टाइम तो अब है, मै सीन दिन बाद मोर्त्य करने जा रहा है, दवा एक महीने बाद रिहाई तो उम मे बया फायदा होगा। मवी जी इस तरह के कानून को बदलिये, जब रत आज है। एक महीने बाद मिलेगी, इस से बया फायदा है।

श्री भानु प्रताप सिंह यह जिकायत भुत कर मुझे बोडा अफमान दृष्टा है। मैं ना चौधरी मालव को बहुत प्रछाल किमान मानता थाया हूँ। जिम टीक की प्राप बात कर रहे हैं—वह इन शाकप्लेशन है, जब किमान पहली बार मूँग बोता है तब उस को डालनी होती है। जब वह तिलहन या दूमरी कफले उस से ने चूका है तो उस को दोबारा डालने की ज़रूरत नहीं होती है।

श्री भानु प्रताप सिंह खेत की मिट्टी को बदला नहीं जा सकता है।

श्री भानु प्रताप सिंह आप उम्मीद बात मानते हैं।

अन्त में केवल एक बात कह कर मैं अपना आपण नमात कहूँगा। यह मान कर जलना कि केवल भारत सरकार या भारत सरकार के मर्दी कृप्ति की विद्युति को मुद्धार मनके हैं—यह एक गलत धूमणा है। इस काम में बहुत सारे करीक हैं। सब से बहा करीक से राज्य सरकार है, उस के बाद सब्द्य किमान है। बडिया से बडिया योजनाये बाही भई है, लेकिन यहाँ भीके पर दीजल न मिले, पटिलाइवर न मिले तो विकल होती है—हम ने उन मम्माओं को पूर करने का प्रयत्न किया है लेकिन उब के महयोग में ही यह काम मफल हो मृक्ता है।

आप की चर्चा की गई। आप के बारे में कहना चाहता हूँ—सरकार की पूरी महानुभूति होते हुए भी किमानों की समस्ति मदद नहीं की जा सकी और उस का यथा दरार है कि मदद करने के लिये जो एकांक-टेक चाहिये वह नहीं है। हमारे पास पर्याप्त कॉल-स्टोरेज होने चाहिये, रेफिनरेटेड-ब्रेंगन होने चाहियह—लेकिन दाना नहीं है। जो थोड़े-बहुत कॉल-स्टोरेज है—वे सब भर चर्चे हैं। हम ने गोप्य सरकार से कहा है कि आधिक से आधिक सक्षया में कॉल-स्टोरेज बनाये जाने चाहियह। अधीक कृष्ण दिव पहले हमी विषय पर बात बदलने के लिये में बेस्ट बागल गया था। उन्होंने कहा कि हमारे पहला बिजली बड़ी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमारी बात को माना और कहा कि हम 160 नये कॉल-स्टोरेज बनायेंगे, लेकिन यह उन के सब्द्य भीजी जा पड़ जाया पास आया है कि उन के पास सीमेन्ट नहीं है। आप इस बात पर विचार कीर्तये—कृप्ति की मम्माया का बहुत ज्यादा सम्बद्ध विजली, सीमेन्ट, दीजल और सोहेजालों से है। इस मार्गी अर्थ-व्यवहार में डॉन का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, कभी-भी योडा-बहुत मनमेद हो सकता है। कूप लग कहते हैं कि हम पुराने बर्द पर खेती करे, छोटे-छोटे उड़ान हो, तो उन से बेज का जला होता है। मैं कहता हूँ—उधोग की बात तो छोड़ दीर्खिये, खेती भी उस तरह नहीं बहुत सकती है, जब तक हमारे उधोग ऐसे न हो जो हमारी खेती की आव-स्यकता की पूर्ति कर सके।

17.04 hrs.

[Dr. SUSHILA NAYAR in the Chair].

इसलिए आप हम का जब जाचे, प्राके, तो इन सारी बातों को ध्यान में रख कर आके। यह कहाना आसान है कि सरकार ने कुछ नहीं किया लेकिन जिन परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं, उन की तरफ भी प्राप ध्यान दे।

माल की बात बहुत की जाती है पर आल का क्या किया जाए। मैं पिछले माल से पूछ रहा हूँ कि हम का यह तो कहाँदिया जाता है कि किमानों की मदद कीजिए मार जल में यह पूछता हूँ कि किम प्रकार से मदद की जाए, तो बार्ड उत्तर नहीं मिलता।

अन्त में मैं कुछ एक०सी०प्राइ० के बारे में कहना चाहता हूँ। मैं सब्द्य यह दावा नहीं करता कि यह एक बहुत बड़ीया और एक०प्रियेन्ट आर्मेनियन है, एक०न जिम प्रकार में आलोचना की गई है वह भी बहुत भी नहीं है। मब से फैलने वाले भी यह बात ग्राहित करना चाहता है कि एक०सी०प्राइ० का बाप केवल व्याद करने उपभोक्ताओं का बदला पठवता नहीं है। यह एक प्रकार में इन्होंने हैं। जो आप 570 रुपॉइंट्स का बाल करते हैं कि इन्होंना बाटा होता है, उम से से आधे में ज्यादा बकर स्टाक के लिए है पर यह तो एक पर्सियाँ मैटर है कि यहा हम का बकर स्टाक रखने की ज़रूरत हो या नहीं? अगर ज़रूरत हो तो उप का आप उद्यात्र समानिये, उम को नक्सान में मन गिनाये। यह अब जै जिनने भी खाल पदाय प्राइ० योग०सी० में जो एक०सी०प्राइ० का आर्मेनियन है और एक०सी०प्राइ० में जो एक०सी०प्राइ० का आर्मेनियन है, उन मब का यह कहना है कि रिंजर्ब फृट स्टाक हाना चाहिए, न केवल धाने लिए स्टाक फृटस्टाक का होना चाहिए बल्कि और दूसरा के लिए भी हाना चाहिए। अब यहर दूसरे बकर स्टाक रख रहे हैं, तो वह न केवल धाने देगवासियों के तिम सीमेवत के बहत काम आगामा बल्कि और जो हमारे पड़ामे है उन के काम भी यह सदलता है और इस के बहत पर जो खर्च होता है, उम का अगर आप आप आगामा कर रहे हैं। एक०सी०प्राइ० में भी उमी प्रकार के लाग है, जैसे कि और दूसरे मध्यी विभागों में और उमी बाजार आग लाइट में है। इस देव म ईमानदारों का क्या स्टैन्डार्ड है, यह मब को मालूम है लेकिन मैं यह जबर कहना चाहता हूँ कि आज तक किसी माननीय सदस्य ने एक०सी०प्राइ० के किसी कमेवारी या अधिकारी के बारे में यह शिकायत नहीं भेजी है। हाँ, पचासों माननीय सदस्यों ने उन्हीं अधिकारीयों और कमेवारीयों के लिए पैरवी की है, जिन के बारे में यहा खड़े हो कर उन का नालायक और बेईमान कहते हैं।

ओ एम० रामगोपाल रेड्डी: रिकमेंडेशन करते हैं पैरवी की दूर नहीं करता है। . . . (व्यवहार) . . .

श्री भानु प्रताप सिंह: जिनको यहाँ कहते हैं कि भ्रष्ट है उन्हीं की पैरवी करते हैं . . . (व्यवहार) . . . मेरे पास शिकायत नाएं या प्रमाण लाएं, तो

मैं देख सकता हूँ लेकिन मेरे पास प्रभी तक कोई शिकायत नहीं लाई गई है।

अन्त में एक बात और कहना चाहता हूँ कि सरकार चाहे केंद्र की हो या राज्यों की ही, वे प्रगति यात्रा की नहीं कर सकती जबतक कि किसान समर्पित है। कर लद अपने गहायता न करे। दुर्निया का कोई भी मूल्य में इसी जानता जहा कि जिमान अपने माल का बचते के लिए इनमें समर्पित न हो। यहाँ पर ही ऐसा है कि मारी बांबों की आज्ञा सरकार द्वारा, बरन की की जाती है। कोई काम हो, वह केंद्रीय सरकार की मदद में बरना चाहते हैं और अगर केंद्रीय सरकार न इसी वित्त जाए, तो यह राज्य सरकार की मदद बाहरे है परन्तु मैं यह जानता चाहता हूँ कि यह न उत्पादन किया। यहाँ पर उस कार्रवाई की नहीं है उस बांबा आपने आग बेचने वाला। बेचते में कुछ मदद नहीं हो। सबना है लॉबिया के जो दूसरे लाभ है, वे अपने सहकारी भगठन बनाते हैं और अपने माल का बचत है। दूसरे दशा म जाने की जा रह नहीं है। आप अपने यहाँ सी जुर्जरग का न ले। उत्तर प्रदेश और बिहार और उत्तराखण्ड में लाग भी यह कहते हैं कि धान का जो गम्भीर मन्धा के ५५ रुपये अपने माल का बचत है, वह कम होना चाहिए कि जिमान का इस के बारे में शिकायत नहीं है क्योंकि उन्होंने किसानों की एक बांधापरेटिव सामाइटी बना रखी है और उसी धान का व ४५ रुपये भी बजाए । १०० रुपये पर किसानों से खरीदती है और उस धान की खरीद कर उस का साल बनाती है और बगल में ही, फेंग्राइम साप के पास, उस को बेचती है। तो आज इस बात की भी आवश्यकता है कि लोग कुछ अपने कर्तव्य का समझें, जो जनता के नेता हैं और जो गाव वालों के प्रतिनिधि बन कर आए हैं, वे उनको समाव दें, उनको समर्पित करें।

यहाँ पर अस्ट्राचार की काफी चर्चा की गई है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। ऐसे को लेन-देन में होने वाले अस्ट्राचार के विषय में इन पूरी सीधियों की गई, कुछ गम्भीर भी ये लेकिन कुछ हल नहीं निकल सका। पूछा गया कि कोई हल हो तो बनाया जाए लेकिन कुछ हल नहीं निकला। अन्त में इतना हो हल निकल पाया कि किसानों का कोई संगठन हो जो उनके लिते ही बहों रखा करे तभी उनकी रक्षा हो सकती है।

अपने देश में क्या होता है इसका एक उदाहरण मैं आपको देना हूँ। गोडा जिले में नलकूप बनाने के लिए एक समर्पित प्रयास चल रहा है। उस में सो अस्ट्राचार नहीं हो सकता है। बजाय इसके कि देशल शिकायतें करने रहे हैं हम को देखना चाहिये कि आखिर हम भी प्रतिनिधि हैं, हमारा भी कुछ कर्तव्य है, बहा जा कर इस देशे पर और इसको दूर करवाएं....  
(इंटरव्यू)

एक भावशील तत्वात्मक : संतद सदरयों की बात कोई मुनता नहीं है।

धी माल प्रतिप सिंह : मैं नहीं माल सकता हूँ कि समद सदस्य अगर ध्यान दे तो उनके देखते हूँ प्रस्ताचार हो सकता है।

SHRI M RAM GOPAL REDDY (Nizamabad): Madam Chairman, at the outset I congratulate both the Ministers for having done good work and I support their demands from this side of the House for they have done good work in the field of sugar industry; they have reduce excise duty; they have decontrolled sugar and they have given freedom to the sugar factories to export sugar. This is a good thing which they have done.

The Food Corporation of India has done its best to accommodate as much foodgrains as possible and the procurement is more than the capacity of the godowns. Now the Minister says that he is going to construct some godowns in the villages. I want to know how much time he will take to complete that scheme. He wanted some cold storage. He must not put this scheme into cold storage; he must put it into action.

I also want to congratulate our scientific officers who are doing very good research work. They have produced high yielding and disease resistant varieties; for which the Minister has not congratulated them; I want that at least his senior colleague Mr. Barnala should pay good compliments to scientists who have done excellent work. Nowhere in the world has such a phenomenon occurred. Our yields have gone up on account of the efforts of the government plus our scientific research work. They are doing good work in this country, which is comparable to any other country including America or Russia. It should not be forgotten. The worry in this country is not on how much we produce but now the fertility of the soil is decreasing; desert is advancing. I want to know from the Ministers what they are going to do, when they are going to complete the Rajasthan canal that can stop the advancement of the desert. It is a national prob-

[Shri M. Ram Gopal Reddy]

lem; it is not the problem of Rajasthan. If anybody thinks that it is the problem of Rajasthan he is not doing justice to this country. Rajasthan canal must be completed in the shortest possible time and all the green patches that are to be developed must be developed. In this country we are mercilessly and wrecklessly cutting the trees; that is causing inundation by rivers which take away the fertile soil to the Bay of Bengal or to the Arabian Sea. That must be stopped. It is a national problem. I want that the fertility of the soil must not only be maintained but improved. One Minister is coming and another Minister is going. In between, whether the fertility of the soil is increased or not? This is important for this country and not how much we are producing?

Now the per acre yield will go down because you are producing more with the application of inorganic fertilisers. Inorganic fertilisers are destroying the fertility of the land. We want manure—cow dung and other organic matter. We want green leaves. The trees have been cut. In Haryana and in Punjab many trees have been planted and protected. In this country if 100 trees are cut, not a single tree is planted. Trees must be planted which will protect the fertility of the soil and prevent soil erosion. If there are no trees, soil erosion occurs. Due to soil erosion river belt is filled up. That is why floods are caused. Brahmaputra is eating away good soil of that area. Similarly soil erosion by sea is causing great havoc in all the coastal areas. Day by day our country is becoming small because of soil erosion by sea and rivers. What has been done in Bombay Marine Drive, such sort of thing must be done in this country. Then alone we can protect soil erosion by sea and wind. We must grow trees. We must have a plan. Formerly, our Shri K. M. Munshi had planned for tree-planting. That plan was not properly implemented for various reasons. I want to know from the Minis-

ters how they are going to protect forests. The minimum requirement of the forest is that about 33 per cent of the total area of the land should be under forest. Now it has gone to 24 or 22 per cent. Day by day, it is decreasing. That is the greatest danger. Now the fertility of the soil has gone down. The production of the soil also will go down. It is a serious thing. This point has not been made by anybody.

It is very good that the Janata Government, for whatever it may be, they are paying attention to the kisans. In Andhra Pradesh our Chief Minister has exempted the land revenue on 2 1/2 acres and below. Will similar instructions be given to the other States—at least to the Janata-ruled States? That must be implemented. If you protect the small farmers, then alone there will be prosperity. Of course, in your younger days you might have sung:

मेरी गाना के गिर पर ताज रहे,  
तो ताज नी आ गया है,

Now we are independent.

धर-धर में आदमी के घनाज रहे।

मगर धर-धर में घनाज नहीं है। तो आपके गोदाम भरने से लोगों का पेट नहीं भरता है। लोगों का पेट भरता है तो उनमें खरीदने की जिक्कित पैदा करनी चाहिये। जापके पैदा करने के बास्ते आप क्या करना चाहते हैं? आपके पास मरम्मत घनाज इम बास्ते हैं कि आदमी खरीद नहीं सकता है। आप पूँछ कार बर्क में खाना देकर उससे काम लेना चाहते हैं। यह स्कीम अच्छी होती, मगर इनका ज्यादा प्रचार नहीं होना चाहिये। देश के बाहर यह बात नहीं जानी चाहिये कि यहाँ के लोग इनसे गरीब हैं कि खाना मिलने के नाम पर काम करने को तैयार हैं। यह हमारी सैल्क ईस्पैट को बिलाएँ है। आप मेहरबानी कर के इस स्कीम का नाम बदल दीजिये। जैसा आपने विविधत हस्पताल का नाम डॉ राम ननोहां लोहिया हस्पताल किया है, किसी और हस्पताल का नाम हुपलानी हस्पताल किया है, और कुट्टम कल्याण बनाया है, इसी तरह से इनका नाम भी बदल दीजिये। यह कृषि कार बर्क वहूंत खराद चीज़ है, इनका प्रचार नहीं होना चाहिये।

यदि कृषि कार बर्क के लिये लोग काम करने को आ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि लोग यरीब हैं। खाना खरीदना चाहते हैं, तो उनकी पर्चेविग कीरणिटी होती चाहिये। कृषि कार बर्क पर आपको पूरा आन नहीं देना चाहिये।

• यह कहना कि पूर्ण कापोरेशन सब करपान है कला है तो मेरी कास्टोट्रैन्सी में भी 7, 8 जगह पूर्ण कापोरेशन कुले हैं एक दो जगह पर और बालने का था। बाली मैं लैटर लिखता हूँ कि वैरेंग स्टिटर और पर्चेंजिंग सेटर खुल निकालवाद आनंद प्रदेश में। मैं कहना चाहता हूँ कि जो एमपीओ 10 हैं वुरा भला कहने को आते हैं वह खुद प्रकाशन कर्यों नहीं लेते? जब मैं कर सकता हूँ तो दूसरे एमपीओ 10 भी कर सकते हैं उमर्के बाल्स पालियामेट का फोरम और समय बर्बाद नहीं होना चाहिए।

कौन ऐसा व्यक्ति है वह जेनेरल मैनेजर हो या कोई और अफसर कि अपर कोई पालियामेट का मन्त्रवर डट कर कहे कि गोंदा नहीं होना चाहिए जो किर भी वैसा करने की इच्छा करें? हम लाग तो आपोरेशन में ही अब हम लोगों की बात चलती है तो आप लोगों की गवर्नेंट तो स्टेटर और स्टेटमेंट में ही आपकी बात क्यों नहीं चलती है? इन बातों की शिकायत यहां पर नहीं आनी चाहिए? मिनिस्टर भारतवाया पूर्ण कापोरेशन के लैटर को एक लैटर लिखना ही काफ़ी है। फॉट कापोरेशन हो या कार्ड और संस्था हो ऐसा नहीं हो नहीं सकता है कि वह पर्लिक ग्रिंजेंटेटिव्ह की बात का न माने। आखिर इसमें हमारा कोई पर्यावरण में लोगों नहीं है। हम किसानों के त्रायांदेश हों। हम यही चाहते हैं कि किसानों के साथ न्याय होना चाहिए उन्हें पूरा गोपनिया दिलाना चाहिए। उनकी लूट बखूब नहीं होनी चाहिए। और उन्हें आपारायिक के लंगूल से बचाना चाहिए। ये काम करने के लिए हम लाग पर्लिक के लिए जेनेटिव हैं। अगर हम लोगों की बात वहां नहीं चलती है तो मिनिस्टर साहब को कहने से वह आदर्शी वहां से जो सकता है सपर्द और इच्छामिस हो सकता है। इसलिए हम लोगों को इस बारे में प्रयत्न करना चाहिए।

**श्री हरीकेश बहादुर (गोरखपुर) :** मध्यापति महोदय हृषि मंत्रालय को अनुदान-माली पर बोलने के लिए आपने मुझे जो अवसर दिया है उमर्के लिए मैं आपको अन्यवाद देना चाहता हूँ।

आज कल हृषि के बारे में हमारे देश में आम ध्वारणा बन चुकी है कि हमारा देश अनाज के उत्पादन में आत्म-निर्भर हो गया है और हम दूसरे देशों को अनाज भेजने लगे हैं। यह एक बहुत ही प्रमद्रापी की बात है और हम किसी दूसरे को अपने अपने महोदय को बदाइ देना चाहते हैं। यों तो हमारे देश में जो बलाइमेट है वह भी इस स्थिति के लिए मूल्य रूप से बहुत हर तक विप्रेश्वर है जिसमें हृषि का उत्पादन बड़ा है। लेकिन हमें अभी बहुत कुछ कार्य करने हैं। सब से पहले मैं फॉट काटोल के बारे में कहना चाहता हूँ।

मेरा मुश्वास है कि हमें हृषि को बाह्य से बचाने के लिए पूर्ण स्तर पर कार्य करना चाहिए। सरकार ने इस दिशा में कुछ कदम भी उठाये हैं लेकिन इस बारे में जिसी तत्पत्ता की आवश्यकता है वह हमें नीचे के कर्मचारियों और दूसरे लोगों में विदाई नहीं लेती है जो इस कार्य को करने के लिए विष्वेश्वर है। मैं

खास तौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाद की स्थिति पर कुछ कहना चाहता हूँ। पूर्वी उत्तर प्रदेश में तमाम नदियों में हर साल भयकर बाढ़ आती है जिससे हृषि का बहुत नुकसान होता है। मैं अपने लिंगे गोरखपुर में राष्ट्रीय पालिया रोहियों और नायायी नदियों की बाढ़ के बारे में मैत्री महादेव से निवेदन करवा कि जो बांधने की स्कीम बालू की गई है उसे प्रतीक्षी प्रकार्यान्वित कराये अन्यथा इस समय लोगों को बहुत शर्त उठानी पड़ती है और हृषि का बहुत नुकसान होता है।

इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूँ कि पूरे उत्तर भारत और देश के कापी बड़े हिस्से में पलट कटोल के कैटन दम्भूर की गोरखेंड फैलाल की स्कीम पर गम्भीराया के साथ विवार करना चाहिए। उन्हें मंसद, गदरमें उन्होंने गोरखेंड फैलाल स्कीम के बारे में बहुत विस्तार के मायथ बनाया था। जो बातें उन्होंने बनायी थीं अबर वे सब ठीक हैं तो हम कह मरकते हैं कि गोरखेंड फैलाल के बनने के बाद न कोबल बाढ़ पर नियंत्रण हो जायेगा किंतु करोड़ों लोगों की संख्या। मिलन की भी सम्भालना है। इस लिए हम स्कीम पर बड़ी गम्भीरता के साथ विवार करना चाहिए। योगाना मंत्रालय की मालियों पर हृषि चर्चा का जवाब देने होते हैं। प्रधान मंत्री जी ने भी इसका चिन्ह किया था और कहा था कि सरकार उमर्के बारे में कायथ कर रही है। लोकन याद वह बहुत ही युक्तिकूल स्कीम है तो देखना चाहिए कि उस जलवी से जल्दी कार्यान्वित किया जाये।

फॉट कटोल के अलावा दसरी बात में शगर इंडिया के कापी बड़े हिस्से में बहुत बहुत ही उठाया है बराबर यह कहा है कि शगर इंडिया में तमाम मिल मालिक हमारे किसानों का और आम जनना का शोषण कर रहा है। उस शोषण से मुक्ति के लिए और साथ ही उस पर पूरी तरह से एक नियंत्रण स्थापित रखने के लिए जिस से कभी उस की कमी न होने पाये शुगर इंडस्ट्री के राष्ट्रीयकरण की दिशा में सरकार को अवश्य सांचना चाहिए।

लैटर रिफार्म के बारे में यह कहना चाहूँगा कि वे दिसंबर की जो स्कीम बलाई गई है उस में मैत्री भी ठीक दृग में जमीन का बटवारा नहीं हो पा रहा है और लंगूलों की जमीन नहीं मिल पा रही है। इस में राज्य सरकारों की विष्वेश्वरी है लेकिन केंद्रीय सरकार को भी इस में नवायना दिशाने की आवश्यकता है। तमाम लोगों के अंदर मीलिंग के बाद जमीन निकली हूँदी है लेकिन उस का टाइक बांड से बटवारा नहीं होता है। जिस की जमीन निकली हूँदी है वही लोग उस पर खेती भी कर रहे हैं। इसलिए आज जो हृषि के कायथ में लगे हुए मजदूर हैं उन की दशा मुश्वारने के लिए और साथ ही भूमिकाओं की दशा को भी मुश्वारने के लिए उस भूमि के बटवारे पर सरकार को तत्काल इवान लेने की आवश्यकता है। उस में किसी प्रकार की कमी करना देश के गोरख लोगों के प्रति एक बहुत बड़ा अन्याय होगा जब कि हमारी सरकार बचनबद्ध है कि मरीचों का हित करती है।

## [श्री हरीकेश बहादुर]

बनो के बारे में मैं यह कहना चाहूँगा कि आज हमारे पहाड़ों के अदर जो जगल काटे जा रहे हैं या बाटने की ओर याजनाएँ हैं उन्हें तुरन्त राकता चाहिए। हम नवे त्रिशत लगाने चाहिए न कि गंभीर जाता से जगल काट जाने चाहिए ज्ञान तोर से पहाड़ा से जगल काट जाने से जा म स्वतन्त्र हाता है उम से वितानी हाती उठानी पड़ती है। गंभीर भागीरथी में भ स्वतन्त्र के बाद जो एक बहुत बड़ी बट्टान आ कर रुक गई थी उम से विताना खतरा पड़ा हा गया था यह हमे पता है। तो जगल काटने स हम तरह की शटनाएँ हाती हैं इमरिंग बजाय जगल काटने के नवे जगल लगाने की विद्या स सरकार को विजेष ध्यान दिना चाहिए।

इर्गेंशन ईमिलिटीज के बारे में यह जान बर व हमे प्रयत्नता हई है कि सरकार ने दूस पर विजेष ध्यान दिया है। नेविन हमे इस विद्या म भी बहुत तेजी क माप काये करने की आवश्यकता है और गजय सरकारों का जहा कंट्रीमीट्री सरकार इग बाय व नियं पैम दीनी है बहुत उम पैस बर व एक अपनी विभागी से अलग नहीं हा जाना चाहिए बल्कि दबाव गजय सरकारों पर इस बान वा दबाव भी बड़ाने को कायाज उगे रहा चाहिए कि राज्य सरकारें इस काम का दूरी तेजी स करें। अगर इर्गेंशन ईमिलिटीज ठीक डिम स नहीं दी जायगी तो कृपि का उत्पादन नहीं बढ़ाया और इस आत्म निर्वना के जिम नव्य तक पहुँचना चाहत है बहा तक नहीं पहुँच पायग।

शामीन विकास के कायांकम के सबध मे माननीय मंत्री जी ने बहुत सी बातें बतायी हैं। बात बहुत उत्साह-बढ़ा है। बहुत तेजी मे यह बाम हो रहा है और खास तोर से यह जा फूट फार बके स्कीम चली है उस मे नमाम गोव के अद्वालिक रोहम बत रही है और दूसरे तरह के भी कार्य नहीं हैं लेकिन उन कार्यों मे जिस तरह की तेजी होनी चाहिए वह नहीं है क्योंकि हम वे देखा है कि सरकारी भविधारी जा राज्य सरकार मे मम्मतिन है वे लोग उम पर विजेष ध्यान नहीं दे रहे हैं। नेविन उन के न ध्यान दिने के बावजूद भी क्यांक जन प्रतिनिधियों का उम पर दबाव रहता है इमरिंग काफी काम हुआ है। अगर उम मशीनी का स्ट्रीम लाइन बरने की व्यवस्था की जा गके तो वह भी करना चाहिए और सरकार का उम विद्या मे भी साजना चाहिए।

इडियन कौमिल आफ ऐश्वीकल्चरल रिसर्च के बारे मे कुछ कहना चाहता है। यह संगठन हमारे देश मे हाँच के उत्पादन को बड़ाने के लिए नवे अनुसधान करने के लिए बनाया था और इस ने महाव्यूर्ध कार्य भी किया है। नेविन दुर्भाग्य की बात है कि यह पता नहीं चलता कि यह अचंक कृषि उत्पादन के लिए बना है या सूसाइड के नवे नवे तरीके बढ़ाने के लिए। हमेशा ही बहा पर सूसाइड होना रहता है और नवे नवे नरीके से होता है। कभी कोई गले म फूमा लगा लेता है कभी कोई ऊपर से कूद जाता है कभी कोई लीनीरी मजिल से कूदता है कभी कोई चौथी मजिल से कूदता है। इस तरह के त्रासम काये

बहा पर हो रहे हैं। माननीय मंत्री जी को देलना चाहिए कि बहा पर क्या कारण है जो इस प्रकार की बातें होती हैं। कहा जाता है कि आई० सी० ए०० आर०० मे बैजातिको के गुट बन हुए हैं और ये एक दूसरे से इस प्रकार की प्राइवेट्स्टोर्स मे रहते हैं कि एक दूसरे का पाव खोचने मे लगे रहते हैं। माननीय मंत्री जी को देलना चाहिए कि मही तरीन से वहा उनका प्रोमान बनेरह मिले और जो सुविधाएँ प्रावश्यक हैं वह मिले। इस पर ध्यान दिन चाहिए।

पैटेंट रिसर्च इस्टीच्यूट जा है उस के बारे मे मे ने एक पत्र लिखा था माननीय मंत्री जी को २३ नवम्बर १९७८ का। वह पत्र उन्होंने एकतालज किया है। उम क बाद उम म क्या हुआ है कुछ नहीं पता चला। बात क निवाश क बार म मैं बहुत आशांत लगाना ये जा सक सिल य। वह मैंने उन बा भज थे। मदा लगता है कि उम पर कार्ट कायपवाही नहीं हुई आवश्यका माननीय मंत्रों जी ने हमे सचिन दिया हाता। इस प्रकार मे त्रासम लागा क बार मे जैसा कि अमी भान प्रताप नियं जी कह २८ वे कि आप नाम कार्ट बात बातें नहीं हैं तो इन बाताने हैं और उम पर कार्ट कायपवाही नहीं होती है तो उमस पर कार्ट बायवाही हुई थी। उनके ऊपर क्या कायपवाही हुई है—इस सम्बन्ध मे कोई जातकारी नहीं है। सम्भवत कोई कायपवाही हुई हो नहीं है। आज माडेन बैकरी की स्थिति यह है कि उसकी यूट-लाईजेंशन कीरेमीटी लगातार घटी चली जा रही है। मदालय की आर से जो किनाब दी गई है उसमे बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई हैं किन्तु उसकी रिस्ति दिन प्रति दिन खाग जीती बली जा रही है। उसमे केवल नोवरकारी का ही बोल बाला है। यह भी लिखा हुआ है कि कायपनी पेय-२७ का उत्पादन भी कर रही है लेकिन यह देख कर बड़ा दुख होता है कि पेय-२७ का कजम्मान उस मात्रा मे नहीं हो रहा है जिनना कि दूसरे देयों का है। कायपनी अपने प्रोडक्ट का उम क्वार्नटी का नहीं बना पा रही है जिम क्वार्नटी की आवश्यकता है। इसी प्रकार से और भी भी उद्देश्य थे जिनमे त्रासम लोटो वा रेटेल्समेट होता है। तो इसको बचाने के लिए भी सरकार को ध्यान देना चाहिए।

विली मिल्क स्कीम के बारे मे मैं कहना चाहूँगा कि गवर्नेंट इसको कायपनी के रूप मे बदलने की योजना बना रही है जिनके कारण बहुत सारे कर्मचारियों से लोक आवाज है। वे यह समझते हैं कि कुछ नवे तरीके के उपकरण आपके और कायपनी बना कर कुछ इस प्रकार के काम किए जायेंगे जिनमे त्रासम लोटो वा रेटेल्समेट होता है। तो इसको बचाने के लिए भी सरकार को ध्यान देना चाहिए।

एक सी आई के गोदामो के बारे मे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं बहुत सलों मे, जो प्लाइट्स मैंने लिख रखे हैं उनको बता रहा हूँ ताकि मंत्री जी उम पर ध्यान देसके। एक सी आई के गोदामो के

लिए बहुई बैंक ने तरामग 360 करोड़ रुपया दिया है जिसका अधीन अमीर नक्काश की गुणवत्ता दीक ढंग से नहीं होती है। लास तीर में लाइन एरियाज में कही एक सी आई के गोंदाम नहीं बन रही है। यदि उत्पादन बढ़ा है तो उस का रखने के लिए जगह भी चाहिये। हमें यह आज सहना है की हमें यहां इस मदन में तरह तरह की बातें आती हैं लेकिन उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस के अलावा बोरा की कमी की बात भी कही जा रही है। यदि बोरे नहीं होते तो उम को कैसे रखा जायगा? यह एक बहुत बड़ी समस्या है जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

प्रोपाइड रेलवे लाइनहाइन क्षेत्र एरियाज के बारे में रेल मवी जी ने कहा था कि बहा कृषि कार्यम है जहा कृषि की कानी पैदावार हाती है वहा रेलवे लाइन बनायागे। मध्ये पना नहीं रेल मवालिय की ओर से काई गल माल के पाम आया है या नहीं जिसके पासार पर आप बता सके कि कौन से खें हैं जहा पर रेलवे लाइन बनाई जायगी। उदाहरण के लिए उनके प्रदेश में जो गम्फुर काठामोदाम लाइन है वहा पर कृषि का बहुत बड़ा खेत है। गम्फुर काठामोदाम की पीफले से ही प्रोपाइड लाइन थी लेकिन उस का राक दिया गया है। उम का रेलवे बनाने नहीं जा रही है। इमलिय कृषि मवी जी का कहना चाहिये कि रेलवे ने अगर इस तरह की कोई योजना बनाई है तो उम रेलवे लाइन को पौर्ण बनाना चाहिये।

गेहूं बरेह की प्राइम के बारे में मैं कहना चाहुंगा कि कृषक जा कुछ भी दैदा करते हैं उम का उचित मूल्य उन के मिलना चाहिये। उम का क्या प्रबन्ध हो रहा है उस के बारे में मवी जी को स्पष्ट करना चाहिये। जाव के दाम तो जरूर कम किए गए हैं। पहले भी कुछ कम हुये थे। आजाज के दाम भी कुछ बढ़ा गए हैं लेकिन उम के बाजार कृषक महसूस करता है कि उम का उचित मूल्य नहीं दिया जा रहा है। मैंने उमीद है कि मवी जी अपने जबाव में इन सारी बातों को ग्राह करें। किसानों को गहर देने के लिए वे आम तौर से कृषि याकामों बनायेंगे। अन्न में पुन दोहरा देना चाहता है कि पलड़ कट्टों के ऊपर वह विशेष रूप से ध्यान देयों कि उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा तमंगा बालू सजलमन हो जाता है, और उम में बड़ी क्षमता होती है।

**SHRI K. MALLANNA** (Chitradurga): Madam Chairman, at the outset I want to congratulate the Agriculture Minister for having tried to help the agriculturists in the country. 60 per cent of the agricultural families are living below the poverty line. Government have introduced some measures in order to improve their economic condition in the rural areas, like the Food for Work Programme,

Drought-Prone Areas Programme, Desert Area Development Programme, Small Farmers Development Agency, Tribai Area Development Programme and Hilly Area Development Project, apart from the Antyodaya or village development. These are the measures taken by the Government to ameliorate or improve the working conditions of the rural folk.

Madam Chairman, I am coming from a constituency which has been declared as a backward area by the Planning Commission and almost all of my constituency is covered by the DPAP programme and also by Small Farmers Development Agencies (SFDA). Both these programmes are Centrally sponsored schemes. These schemes are introduced just to help the rural folk, i.e., the very oppressed and depressed class in the existing rural society.

Madam Chairman, the drought-prone area in the country covers nearly 74 districts in 13 States. That means, it covers 12 per cent of the total population. In terms of area it covers 5.66 lakh square kilometres, that is, 20 per cent of this area. I find now that for the year 1979-80 it has been allotted Rs. 59.44 crores. I feel it is very insufficient because the Planning Commission has declared more than 200 districts as backward areas under the drought-prone area programme. Madam the idea behind this is to tap the underground water and to irrigate these areas with underground water and river water. They have taken up soil conservation, then horticulture and so many other programmes to improve and provide jobs to the rural people, namely, the small farmers and the agriculturists.

Madam Chairman, under the IRD programmes that is the Integrated Rural Development programmes, the DPAP and SFDA programmes are included. Unfortunately they have not planned anything except mentioning about some soil conservation and some afforestation. Planning should be made according to the situation of the area. Take, for example, my constituency.

[Shri K. Mallanna]

Though it is declared as under drought-prone area programme, they want to dig up the underground water. There is a big river called Bhadra going by the side of my constituency. If Bhadra water is taken to my constituency, it covers about 12 to 13 taluks. Then if all the 12 or 13 taluks are irrigated by this Bhadra project, I think what the Government has thought to improve this under the DPAP programme will be successful. It is only by investing money on the minor irrigations, that too which cost above Rs. 50,000, that success can be achieved. But nothing is mentioned about minor irrigations, about the tubewells and borewells. If we request the agency to take up a tube well or bore well, they will say it does not come under minor irrigation, and so it cannot be taken up under DPAP. But then, how can you fan underground water without tube wells or bore wells? So, it is only a name sake.

In the DPAP areas, agro-based industries should be started. They are said to be encouraging horticulture, sericulture, piggery, poultry etc., but it is all only in name because implementation is not properly done. I want the Ministry to take up these things intensively.

So far as advance of loans to these programmes is concerned, the banks are giving a lot of trouble and causing a lot of inconvenience to the poorer section of the society. Though a subsidy of 30 to 60 per cent is given to agricultural labourers and farmers, the nationalised and local banks are not coming forward to help these poor people. So, I request the hon. Minister to look into the matter and give them easy loans.

Unfortunately, though these programmes are meant for the economic development of the poorer sections, they have not been properly implemented. I suggest that agricultural centres should be started at least in the DPAP areas like the industrial

centres which have been started in the city and town areas to help small-scale and other industries.

The poor ryots and agricultural labourers have no house or shed to rear poultry. When they ask for a loan, the bank people enquire if they have got a shed or a house, and that too scientifically constructed. They say they cannot afford it, and the bank people do not give the money.

Similarly, sericulture requires well-built weather-proof houses for the cocoons to be reared properly, but small farmers owning two or three acres of land are unable to build these houses, and the bank people are not giving them money, with the result they are unable to take to this industry.

If at all there is any programme to help the rural folk, it is the dairy farming programme. Here also, the bank people reject loan applications on the ground that the ryots have no proper cow sheds. I would request the hon. Minister to consider all these things and to establish agricultural centres in the rural areas.

I want to stress one more point. As far as the milk societies are concerned, we have to consider the pricing policy. In my State, the State Government has, with great difficulty, introduced in certain pockets a scheme called Karnataka Dairy Scheme, under which the minimum price fixed for milk is Rs. 1.35 per litre. In Gujarat it is Rs. 1.85. I do not know about other States. The cost of the inputs are rising. The cost of feeding the cattle has gone up. The cost of buffaloes and cows has also gone up. So, they are not able to maintain the cattle. It is very difficult to purchase milch animals because they are very costly. So, I would request the hon. Minister to fix up the minimum price for the milk because that would help many people in the rural areas. It would also give employment to many people. Easy availability of manure would enable them to improve the fertility of the land.

Then I would come to the marketing facilities in the rural areas. Under DPAP programmes, poor ryots and agriculturists are being given loans to purchase buffalows and cows. But they are not finding market for the milk. So, they are unable to repay the loans advanced to them. So, I would request the Minister to take the necessary steps to improve the marketing facilities. If they are really keen to improve the economic condition of the small and marginal farmers, they have to establish agricultural centres, fix the minimum price for their produce and also improve the marketing facilities.

‘श्री हृष्मदेव नारायण यादव (मध्यवनी)’  
मध्यापन जी, आमी जा बहव चाव रही है, उग क  
बारे में गत में पहले मैं यह बहना चाहा कि किसानों  
से सम्बन्ध रखने वाली इम बहन में नीन तरह के लाग  
ह, जिहाने चिन्हा लिया है। एक तो वास्तव में  
किसान ह, जो गाव में बैठे की भेंट पर बड़ा हो कर  
धारणी खेती करता है। दूसरा वह है, जो कोटी  
गहर में रखता है लेकिन उम का कांसं देहान में है  
और वह भी धारणे आग का किसान करता है और  
नीने ऐसे लोग हैं जो एधर-कण्ठान मकानों में  
गढ़ो पर बठ ५२ वें बैठन किसानों से सम्बन्धित कुछ  
किनारे पठ कर प्रान डै इकट्ठा कर लेते हैं और वे भी  
धारणे आप को किसान ममताते हैं।

सही मायने में गाव की समस्या के बारे में  
ऐसे लोग विवार करते हैं जिन्होंने गाव को कभी देखा  
नहीं, जिनके घर की घौरतों को भादो की धार्धी रान  
में टिटुना भर कीचड़ हैल कर कभी सहक के किनारे  
पालाने पर नहीं बैठना पड़ा, वह कभी गावबाली  
घौरतों की कठिनाई के बारे में नहीं जान सकते।  
गांज भी गाव में बसने वाली करोड़ों में नहीं धौरते हैं,  
जिनको १२ वर्षे तक पालाने की धारणे पेट म सदा  
कर रखना पड़ता है, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक उनके  
पालाना जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। सूर्यास्त  
होता है तो गाव के बाहर जब पालाने का जाती है  
और सहक के किनारे पर आपाने पर बैठती है, उस  
मध्य कोई राहीं रास्ते से निकलता है तो धारा  
पालाना पेट में लेकर खड़ी हो जाती है। गाव  
में बसने वाली उम करोड़ों घौरतों के बारे में वे जान  
मकता है जिस ने कभी उस वातावरण को देखा हो,  
बहा पला हो, जिसको उम वातावरण की असाधित  
का जान हो। आजाद भारत में गाव में बसने वाली  
करोड़ों महिलाओं के पालाना जाने की भी व्यवस्था  
नहीं हो चाहूँ और न जाता राज्य में ही उस तरफ कोई  
दृष्टि है और न उमको सुपारने की चिन्हा है।

जिस देश में माताएं रोगिणी होती, रोगिणी के  
पेट के कभी स्वस्थ संतान पैदा नहीं हो सकती, देश  
की संतान भाव के पेट से ही रोगिणी होती, उस संतान

से कभी देश की भीमामां की सुरक्षा नहीं हो सकती।  
इसलाला अगर भीमामां की सुरक्षा करती है तो गाव  
की करोड़ों महिलाओं के स्वास्थ्य को ठीक करने के  
लिए पहले उनके पालाने की व्यवस्था करनी होती।

आज हम खेती पर चर्चा करते हैं। खेती के  
लिए जो जाग चिम रहे हैं, एक तरफ साकारी तरफ  
है और दूसरी तरफ व्यापारी। इस व्यापारी और  
नीव रखाती की खेती में खेती चिम रही है। बवीर-  
दाम ने कहा था—

खेती चाहते देख बार दिया कबीर राय,  
दो पाठन के बीच में साक्षित बचा न काय।

यामार्दी की बात जब इम बरते हैं तो उमको बयो  
नहीं बढ़ावा मिलेगा? व्यापार में नाइट्रेग, परमिट,  
प्रम, तरक्की, मनाफा और काइबर-टेक्नोलॉजी यह  
कुछ है लॉसिन जी मन नाइट्रेग, न परमिट, न प्रम  
और न खेती वरन् बाला क पास फाइन-स्टार हाउस  
जहा वर्ट मार्ट का टर्ग मक। जहा गुब्ब और  
मुखियां का बाबार है, वहा व्यापार की नरकटी  
होगी, खेती म यह मुख-मुखियां नहीं हैं इसलिए  
जिमानी की उपका टानी रहेंगी। आज जब यह कहते  
हैं कि जनना सरकार ने बहुन ज्यादा चिमा, मैं बिल  
मती का बधाई देना चाहिया कि उहोंने आपने इम  
नज़द में गाव के प्रति, किसानों के प्रति कुछ ध्यान  
दिया है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी देख ले कि  
गहरा म बगने वाले जो मट्टीभर आदमी हैं, जिनके  
हाथ में समाजान गव है और दूसरे साधन है वही  
आज इन मतों के खिलाफ और दृम बजट के खिलाफ  
रायां राडा किये जाए हैं कि यह बजट महगाई का  
बजट है और पला है।

मैं पूछता चाहता? कि इतने दिनों में आपने  
गाव के लिए क्या किया में यह भी कहना चाहता  
कि हमारे क्षुपि भटी जी और दसरे लाभ करते हैं कि  
गाव बाला के लिए बहुत कुछ किया गया है, गाव  
पर बृत इनका चिमा है, लॉकन हैरत में पड़ जाता  
है जब इनका चिमा है, इन सामान का धार्यिक सर्व-  
क्षण देखता है जिसमें लिक्का है कि खौदी पचवर्षीय  
याजना पर जहा कृषि और समस्त लक्ष पर १४.७  
प्रतिशत खेती दिया गया था, वहा १९७८-८३ की  
याजना में जो इन्होंने दर्जाया है वह १३.२ प्रतिशत  
है। यह आधिक संवेदन इन्होंने का दिया है।  
जह मानता है कि खेती की तरफ हम बढ़ रहे हैं। खौदी  
पचवर्षीय याजना में जहा ११.७ प्रतिशत खेती पर  
ध्यय था वहा ७४-८३ याजी प्रगताविन योजना में  
इसे घटाया गया है जिसका प्राप्त अधी तैयार नहीं  
है। उम्म १३.७ प्रतिशत है और १९७८-७९  
वाले परिवर्यप में बताया है कि १५.० है। मिथाई  
में जहा खौदी योजना में ४.६ प्रतिशत बताया गया है  
वहा १९७८-८३ वाली योजना में ११.५ है, केवल  
२ प्रतिशत की बर्दी यह बता रहे हैं। १९७८-७९  
में जो १० प्रतिशत इन्होंने खेती में रखा है जब कि  
१९७८ से ८३ वाली योजना में १८.२ प्रतिशत कमी है।

उदोग में जहा खौदी पचवर्षीय योजना में  
१८.२ प्रतिशत इन्होंने रखा था वहाँ १९७८-८३ की

## (श्री हृष्म देव नारायण यादव)

योजना में 19 २ प्रतिशत है। यहां भी जो बड़े उद्योग हैं, उसके अनुमान अगर खेती पर वर्धीय योजना के अनुबन्ध इनकी जो योजना बनत जा रही है उसमें इन्होंने 1 2 प्रतिशत यादा वर्ज रखा है और कृषि में 1 व्यापक कम कर के रखा है। यह इनकी सर्वेक्षण की किनारे में प्रकाशित हुआ है।

मेरे एक प्रश्न के उन्नर में वित मरी ने नवम्बर, 1978 तक बैंकों द्वारा दिय गय कर्डों के बारे में ये आकड़े दिये कृषि 11 5 प्रतिशत लघु उद्योग 11 6 प्रतिशत बड़े उद्योग 39 6 प्रतिशत । हिन्दूनालान के लगभग 70 प्रतिशत लोग खेती पर निष्पत्ति करते हैं और 80 10 प्रतिशत लोग यादा में बसते हैं। कृषि पर नियर करने वाले लगभग 70 प्रतिशत लोगों का केवल 11 5 प्रतिशत बैंक क्षण दिये गये जब कि बड़े उद्योगों को 39 6 प्रतिशत दिये गये। ये आकड़ क्या दर्शाते हैं? सरकार की तरफ से कहा जाता है कि हम ये खेती की तरफ बढ़ 23% और बड़े उद्योगों में ग्राहकाकार को ग्रह्य करने के लिए अधिक बैंकिंग करण की तरफ बढ़ 20% है। लेकिन बैंकों का दृष्टिकोण यह बताता है कि मरकार आधारण किंवद्दीकरण और खेती की तरफ नहीं बढ़ रही है क्योंकि कृषि का कम क्षण दिया जा रहा है।

सचावति महोदय माननीय मदम्य दो मिनट में समाप्त करे।

श्री हृष्म देव नारायण यादव : मन्य मदम्यों को 15, 15 मिनट दिय गये हैं। मझे यादा समय और दिया जाय।

सचावति महोदय नहीं माननीय मदम्य दो मिनट में समाप्त कर दे।

श्री हृष्म देव नारायण यादव जिस देश में खेती पर भार जिनता कम होता है वह देश उतना ही धनवान होता है। क्या कृषि मदालय द्वारा हम दिया में काई कार्यवाही की जा रही है जिस खेती पर से भार को कम किया जाय? खेती पर भार तब तक कम नहीं होगा जब तक कि कुटीर उद्योगों को बढ़ावा नहीं दिया जायगा। कम में कुन आवादी का 31 4 प्रतिशत भाग खेती पर निर्भर है अमरका में 4 0 प्रतिशत ब्रिटिश में 2 8 प्रतिशत और याजना में 20 7 प्रतिशत लाग खेती पर निर्भर है लेकिन भारत में जनसंख्या का 64 7 प्रतिशत भाग खेती पर निर्भर करता है।

यह दर्शाता है कि जिस देश में खेती पर जिननी कम जनसंख्या का भार है वह देश उतना ही माल दार और व्यापक है लेकिन जिस देश में खेती पर ज्यादा जनसंख्या का भार है वह देश उतना ही गरीब है। अगर हम भारत जैसे गरीब देश के आगे बढ़ावा चाहते हैं तो उसकी तरक्की करना चाहत है तो खेती पर से भार को कम कर के अधिक से अधिक

लोगों की कुटीर उद्योगों की तरफ ले जाना होगा। लेकिन कुटीर उद्योगों का वितान तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि हम यह तय न करे कि जिन बस्तुओं का नियंत्रण मनुष्य के हाथों से हो सकता है उनका उत्पादन बड़े कारब्बाना में नहीं होगा।

मेरे मामने प्रतिव्यक्ति उपचार के बारे में भारत सरकार के ये आकड़े हैं —

	1955-56	1977-78
किलोग्राम	किलोग्राम	
खाद्य नल	2 5	3 9
नीनी	7	47 2
मरी बाटा	11 1 मार	11 8 मीटर

इससे पता चलता है कि बहा 1955-56 में कपड़े की प्रति व्यक्ति उपलब्ध मात्रा 14 मीटर थी बहा 1977-78 में वह बट कर 11 माटर रह गई। एक तरफ 4 इंच के दाम रकम हा रहे हैं और दूसरी तरफ कपड़े के दाम बड़े रह है।

18 hrs

गांवों के मुधार की बात कही जाती है मगर श्री जां कनीहीम उद्यान मरी ने यह कहा है कि नीनल टैक्साइल कापरिशन अपने उत्पादन में से कल्प 40 प्रतिशत माटा और माधारण कपड़ा बनाता है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस देश में 60 ००० सौखी लाग गरीबी को रेखा के नीचे रहते हैं और 80 ००० सौखी लाग गांवों में रहत हैं बाटा की नीनल टैक्साइल कापरिशन का दृष्टिकोण यह हाना चाहिये कि वह अपने उत्पादन का 60 या 80 ००० सौखी मोटा और माधारण कपड़ा तैयार करे। ऐसा करने पर ही यांग बालों के तन पर कपड़ा हो सकता है। ऐसा नियम अगर सरकार किसानों और गांव बालों के लिए कुछ करना चाहती है तो उसे इस दिया में सोचना होगा।

1971-72 में कृषि उत्पादों का सूचकांक 100 4 था और थाक कीमतों का सूचकांक 105 6 था। 1971-72 में लेकर दिसंबर 1979 तक थाक कीमतों का सूचकांक निम्नतर बढ़ता चला गया है और यही दिवान विनियमित उत्पादों के सूचकांक की गही है जो लगातार बढ़ता रहा है। कृषि के सबक प्रक द्वाम की ओर गए हैं। प्रतील 1977 में जहा दूसरी बल्टों का सूचकांक 181 था वहा कृषि का 172 था। 1978 में जहा दूसरी बस्तुओं का सूचकांक 184 पर ही चढ़ा है वहा कृषि उत्पादन की बस्तुओं का सूचकांक 172 से बढ़ कर 169 पर चला गया है। तो लगता है कि कृषि उत्पादन की बस्तुओं का सूचकांक द्वाम की ओर चला जा रहा है और दूसरी बस्तुओं का सूचकांक बढ़ता चला जा

रहा है। जब तक उस का रोका बही जायेगा तब तक विकास नहीं हो सकता है। इमिराए सरकार को इस दिशा में भी साबना चाहिये।

18 02 hrs.

## HALF-AN-HOUR DISCUSSION

## POSTAL ACCOUNTS IN HARYANA

ध्रीमती भूमाल गोरे (बम्बई उनर) सभापति महादया, 12-3-74 का प्रस्तुत संघर्ष 284 का जो उत्तर दिया गया है उस के बारे में यह जब्ता बताना चाहती है। उस दिन सभाव के जबाब में जो बताया गया उस में यह कहा गया कि 50 हजार रुपये से ऊपर के डिपार्टमेंट 1971 में सभापति भ्राफिसेज म किए गए उस के बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाव कर रहा है। मैं उस दिन बगवर प्रूफली रही कि कुल मिला कर 74, 75 और 76 तीन सालों में इस प्रबाल के कितने लागी ने डिपार्टमेंट किए थे और कितनों के बारे में जाव अभी तक हो गई है। मूले जो मानूसत मिली है उग के मूल्यांकित 1974-75 और 76 में लगभग 71, 2 प्रतिशत हजार रुपये के ऊपर के डिपार्टमेंट हायाणा के पास्ट भ्राफिसेज म हुए। इन व बारे म दृष्टने नायक चीज तो यह है कि उस में कई डिपार्टमेंट से है कि वहा 30 मार्च का डिपार्टमेंट किया, 2 अप्रैल का पेटा उसी एकाउंट में से आपस लिया, 29 मार्च का डिपार्टमेंट किया, 29 अप्रैल का डिपार्टमेंट से लिया था कि 31 मार्च का डिपार्टमेंट किया और 3 अप्रैल को से लिया। ऐसे ही तीन बार दिन के लिए इनकी बड़ी रकम डिपार्टमेंट कर के जो आपस में भी गई उसमें कई व्यवितरण डिपार्टमेंट भी हैं, कई पूलिनर्मिलिटीज के हैं, कई पुलिस इसप्रेस्टस के हैं, तहसीलाधार के हैं, जो एम्स के हैं, कोपापेरेटिव मिलस के हैं, जिला परिवार के डिपार्टमेंट है, कई तरर के डिपार्टमेंट इस प्रकार के हैं और इस के बारे में विस्मर्द, 1977 से इस सरकार के पास नागतार कई शिकायतें पाई हैं, इसके बावजूद भी अभी तक इन की जाव पूरी नहीं हुई है यह हमारी विकायत है।

उस दिन के मध्याम के जबाब में कम्प्युनिकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से बताया गया कि इस में केवल 13 केसेज हैं जिन में पास्ट डिपार्टमेंट के स्लस का उल्लंघन किया गया है। मैं यह कहता चाहूँगी, उस दिन भी मैं बार-बार कह रही थी कि जो 10 फरवरी, 1978 के करेट में आया है, उस ने जो लिस्ट पाई है और जो पकाल नाम आए है उसे से 13 केसेज ऐसे हैं कि जहां पोस्ट्स डिपार्टमेंट के स्लस आयाये हुए हैं ऐसेकिन उस के साथ साथ जोकी कई डिपार्टमेंट के केसेज हैं, तो इन जानना चाहते हैं कि कुल मिला कर किसने ऐसे केसेज हैं। केवल करेट में जो पकाल केसेज थिए गए हैं उन की बारे में बताने भी बहरत नहीं हैं, 74, 75 और 76 सालों में कुल मिला कर किसने एकाउंट ऐसे खोले गए, किसी के बारे में

पोस्टल डिपार्टमेंट के स्लस का उल्लंघन हुआ और उस के बारे में गमधीरी तक क्या हुआ?

मत्री महोदय उस दिन बार बार कहते रहे हैं कि जाव बस रही है, ऐक्षण से रहे हैं, कार्यालयी की जा रही है। इस प्रकार की बातें बह करते रहे। मेरा यह कहना है कि जब 77 साल से यह बात बह रही है और जब काफी बाते सामने आ गई है, इनकम टैक्स विभाग भी इस के बारे में तलाशी कर रहा है। तो ऐसी परिवर्तिति में इस में ज्यादा समय नहीं बताना चाहिये। मैं यह भी कहता चाहूँगी कि 2 अप्रैल 1974 का कवर लाल गुल जी के अनस्टार्ट व्हेचन नम्बर 1762 का जो जबाब दिया गया है उस में 1974 साल के 5 लाल के ऊपर के जो डिपार्टमेंट हैं, उन के 85 केसेज के नाम दिए गए हैं। मूले खोद है कि इस निष्टि में भी नाम दिया है, किनना डिपार्टमेंट रखा उस की तारीख दी है लेकिन उस का जो द्वम्पत्रूण ग्रन है कि यह डिपार्टमेंट किर से वापस कह दिया गए, कब विद्वान किए गए, या क्या एकाउंट था इस की तारीख नहीं है। इस से ज्यादा जाक होता है। यह तीन दिन के लिए पांच लाल आठ लाल बस लाल ऐसा एकाउंट रखा गया। किस के नाम से रखा गया, क्या बेनामी एकाउंट थे, इस के बारे में तीन केसेज के बारे में तो उस दिन भी निर्माण नामांकन से अपने जबाब में कहा था कि ये बेनामी एकाउंट हैं, ऐसा लग रहा है—धारा 3ी सी का पांच लाल का डिपार्टमेंट, श्री गण के गण, ज्वाइट डायरेक्टर इडल्डीज, हरयाणा गवर्नरेंट का पांच लाल का डिपार्टमेंट और श्री कम्पीरा लाल, दि दिन स्टूडेंट ब्राफ डल्ली यन्विनीटी का 1 कराड 35 लाल का डिपार्टमेंट। मैं कहता चाहूँगी कि केवल 14 लाल के बारे में ही आप मत कहते हैं, 74, 75 और 76 इन तीनों सालों में लगतार हरियाणा के पोस्ट भ्राफिसेज में इस प्रकार के एकाउंट्स खोले गए। ऐसा लग रहा है कि इस का उपयोग बेनामी एकाउंट्स काल कर कुछ राजनीतिक कामों के लिए हो रहा था। तो क्या यह बात सही नहीं है? इसके बारे में काइनेस डिपार्टमेंट भी जाव कर रहा है। कहा तक इस की जाव हुई है, यह मैं जानना चाहूँगी।

तीमरी बात यह है कि जो जाव अभी तक हुई उस के आधार पर क्या आप इन डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी हैं उन के ऊपर काई ऐक्षण लिया? आप ने कहा है कि तीन पास्ट मार्टर इन्वेन्टरी हैं। उस दिन भी आप ने यह कहा था। तो इस में ऐक्षण लेन में इनकी दोनों बातों हो रही हैं? इस से ऐसा लगता है कि लोगों के मन में जो जाक पैदा हुआ है वह बिल्कुल बाजिब है। तीन दिन के लिए, 6, 8 या 10 लाल काई नहीं रखता है। कुछ न कुछ इस में दाल में काला है। असलियत क्या है यह सरन की जानने की डिक्षा है। मैं मत्री महोदय से कहूँगी कि आप हुए कर के पूरी तरह से बताए। उस दिन जैसा लग रहा था कि तेरह केसेज ही हैं, उन में से किसने पर ऐक्षण से रहे हैं या उने का विचार बल रखा है, इस प्रकार भी बात आप मत करें। नम् 74, 75 और 76 इन तीनों सालों में किसने एकाउंट्स में

## [धीरमसी भूमाल गोरे]

और क्या हुआ है मह बताएं। अगर काइमेन्ट डिपार्टमेंट के पास दूसरे मामलों के बारे में जांच बल रही है तो उन की तरफ से भी जवाब माने की जरूरत थी। अतिथर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस में जांच करेगा तभी पूरा पता बतेगा। क्या इस जांच में बंधी लाल या दूसरे राजनीतिक नेताओं का सम्बन्ध है और क्या बेनामी एकाउंट्स का प्रयोग किया गया है, इस का भी ठोस जवाब माना चाहिये। मैं भी महोपर्य से मालां कर्गी कि इस के बारे में पूरा जवाब दें।

डा० रामचंद्र तिहू (भागलपुर) : सभापति महोदया, सब से पहले "करेट" के 3 फरवरी के इश्यू में 30 करोड़ रुपये के बेनामी घोटाले का लिक आया था। जब कुछ लोगों ने कहा कि यह मनवड़न बात है तो फिर "करेट" ने अपने 10 फरवरी के द्वंद्व में इस का पूरा घोरा ही दिया, जिस में डिपार्टमेंट और विद्युत्पालक—करनाल हैड पोस्ट-पार्किंग—के 23 केंसेंज का उल्लेख है। म इन को पूछा नहीं, लेकिन सब के नाम, डेट-आफ-डिग्राजिट, डेट-आफ-विद्युत्पालक और उस के बाद रोहनक हैड प्लाटर के 1973 से 1975 तक के 26 केंसेंज के डिपार्टमेंट और विद्युत्पालक का उल्लेख है। हम को तो यह देख कर आश्वस्य होता है—30 ताँ 30 को कामयारी लाल ने 1 लाख 35 हजार जमा कराया था और ताँ 2 को वह निकाल लेते हैं। हमें तो यह मारा काम लो हुआ है—घोटाले का काम मालूम पड़ता है। जिस विभाग ने जो उत्तर दिया है—उस में तो बहुत घोड़ा कर के दियाया है, जैसे आइस-बर्ग होता है, 1/10 भाग पानी की ऊपर होता है, 9/10 भाग नीचे होता है। इस को देखते हुए मैं तो यह समझता हूँ कि आधे पट्टे की चर्चा तो बहुत कम है, इस पर 2 घण्टे की चर्चा होनी चाहियी थी।

काइमेन्ट मिनिस्टरों ने जो उत्तर दिया है, उस में 145 लाख के बेनामी—ट्रॉजेक्शन का लिक किया है...

Shri R. P. Singh, the then District Industries Officer at Panipat—Rs. 5 lakhs.

Shri N. K. Garg, the then Joint Director of Industries in Haryana Government—Rs. 5 lakhs.

Shri Kashmire Lal, the then Student of the Delhi University—Rs. 1.35 crores.

यह क्या तामा है? उस समय के जो राजनेता थे, वे तो अट्टाचार में जामिल थे ही, लेकिन जो आप के डाक-तार विभाग के, पोस्ट-पार्किंग के लोग थे, वे भी अट्टाचार के प्राकान्त समूद्र में दूब थे और जब हमारे संचार मंत्री जी ने बतलाया कि हम उन के ऊपर एक्शन लेंगे—क्या उनके देसा कहने की जरूरत थी?

यह एक्शन सो कमी का हो जाना चाहिये या ताकि वे भारी कोई देसा काम न करें। उन्होंने तबने में भूमाल बहिन के प्रेस के उत्तर में बतलाया था कि हम उन पर कार्यवाही करेंगे—बह कार्यवाही अब तक क्यों नहीं हुई? याज भूमाल बहिन ने उन को जो बचती थी है कि अब तक उन्होंने क्या किया—यह ठीक ही है।

इस में दो मुख्य बातें हैं—मैं जानता हूँ इस सारे घोटाले को ले कर संचार मंत्री कह देंगे कि यह वित्त मंत्रालय का काम है और वित्त मंत्रालय कह देगा यह पोस्ट आर्किट का काम है, जिनका जहानुम में जाय। मैं आप से जानता चाहता हूँ—यदि यह आप के वज्र की बात नहीं है और वित्त मंत्रालय के लिए किसी मरमदी की सीमा का बद्धन है—तो क्या वे इस बड़े घोटाले की जांच करने के लिए—जिसमें 30 करोड़ का बकाल तो मुना ही है हो सकता है कि 130 करोड़ हों—सी० बी० आई० को जांच के लिए भरेंगे? मुझे तो पूरा विश्वास है कि इस मामले में लोगों पांती का काम बह रहा है। मोठनहिंदा ने कहा है कि उस के करोड़ रुपया दिया है, वह राजा कर्ता गया? इन्दिरा गांधी जी के पास मकड़ों करोड़ रुपया पहुँचा—उस का पता कैसे लगेगा? सभापति महोदय क्या सार्वजनिक जीवन को स्वस्थ और साक रखने के लिये मुझ संचार मंत्री जी से यह आशामान रिल सकता है कि वे इस सारे बेनामी घोटाले की जांच के लिए इस मामले को कानूनी जांच घरों को देंगे?

इसी बाबल यह है कि आप के विभाग की जो नीति है कि इच्छियुक्त एकाउंट में 25 हजार रुपया जमा किया जा सकता है और जो रिस्ट एकाउंट है उस में 50 हजार रुपया जमा किया जा सकता है, लाख-लाख-दो लाख और पांच-पांच लाख पोस्ट आर्किट में किस नियम के तहत जमा किया गया यह बताया जाए। आप एसा करके नियमों का भंग किया गया है तो भी तक उनको इच्छित करने में, जो कि इससे सम्बन्धित है आपके कदम बढ़ो बढ़वारा रहे हैं। इन दोनों बातों का म आप से स्पष्ट उत्तर चाहता हूँ।

संचार बंधी (बी० बृजलाल बर्मी): माननीय सदस्या ने बहुत अग्रणी प्रश्न किया है और उस दिन का हवाला दिया है कि हम ने केवल 13 केंसिल का ही क्षेत्र उल्लेख किया जाकी हमने क्षेत्र नहीं बताए और उन को हमने बताया। लेकिन ऐसी बात नहीं है। उस दिन संचार लिक करेट काम देते का था। आज जब आपने सारे संचार पूछे हैं तो मैं कुछ उत्पार्कान्त नहीं और हर चीज बताऊंगा। सब से पहले उनका प्रश्न यह था कि 13 केंसिल ये था और ज्यादा ये और एक लाख की बीचे या कहीं सालों के थे। म बता दूँ कि 1973-74 में ऐसे 1180 केंसिल में जो 1 के 25 हजार की लिकिट और पचास हजार की लिकिट दें ज्यादा के बीचे इच्छियुक्त केंसिल थे। 1974-75 में 616 केंसिल थे, 1975-76 में 8 केंसिल थे और 1976-77 में 84 केंसिल थे। 8 ऐसे केंसिल जो लिकिट दें वह जाकरानी में अलग अलग जगह प्रकाश-प्रकाश ढंग से रखना जाना किया गया।

25 हजार और 50 हजार से ऊपर। हमने थोई कार्बोरेट क्षेत्र नहीं की और करनी चाहिये थी या नहीं करनी चाहिये थी यह भी मैं आपको बता देता है।

जीवती मूलाल भोरे सभी केसिम में नियमो का भग हुआ है?

भी बुज लाल बर्मा। हमार नियमो म यह है कि ईविडियन केसिम म 25 हजार जमा हांता चाहिये और अगर उजाइट थाता है तो पचास से ऊपर नहीं हा सकता है परन्तु उसमें अगर उजाइ जमा है तो हम उस पर आज नहीं देते हैं। नियम ५ और ९ के मूलांक आज न देने की बात प्राप्त है। पचास हजार से या पचासीम हजार से ऊपर किसी की जमा राखी हो तो उसके ऊपर जितना रकम है उस पर हम आज नहीं देते हैं। इन नियमों का आधार लेने हुए हमारे कर्मचारीयों ने उसका जमा कर लिया। इस खाता में और इन नियमों की जहां से उस पर काई कारबोरेट करने से हम ने ग्रानी प्रस्तुत करने की। दुसरा गवान यह उठाता है कि यह वैसे ही गया,— कंस दा तीन दिन में विडार १५ नियम गया, तीन नारीय का जमा हुआ और दा नारीय को वह विडार हो गया निर्दंश दा तीन राज के लिए जमा हुआ। यह मूल आज है। एक महात्म्य न बताना है कि एक आदमी ने १ करोड़ ३५ लाख केंस जमा करवा दिया। अब आप जानते हैं कि जिम करने की यह बात है उस बतन बहा पर कीम भक्ती था, कैसा बहा पर जासन था, हिम प्रकार की जार जबदस्ती वहां पर चल रही थी। एक गरीब कर्मचारी जो बहा पर डाककाने में काम बने रहा था उसकी छाती पर बैठ बैठ उसको बारबार करने के लिए कहा जाता हो तो उस करन बहा पर जासन था। मरकारी आधिकारियों द्वारा उसके साथ जबदस्ती की गई। उसने सोचा कि नियमों के मूलांक उसने जमा किया। जमा करना उसका कर्ज था। विडार नियमों के मूलांक हुआ। काता उसका बाबर है, सफहै। उसको कोई कारण नहीं हुआ बल्कि नुकसान यह हुआ कि उसको आधिक देर तक बैठाना पड़ा, और हर प्रकार से उसको ढार हुआ, भय हुआ। जिस अवस्था में जमा और विडार किया गया उसको बहां में उसका कुछ अविलम्त कायदा नहीं हुआ बल्कि नकलीक ही उलटे हुई।

तीन आधिकारियों के ऊपर हमने एक्षण लिया और वह इन्सिए लिया कि उसको ठीक डग से जो कुछ करना चाहिये था वह नहीं हुआ। एक्षण इस कारण से नहीं लिया कि उसने पचासीम या पचास हजार से ज्यादा जमा किया। उसकी पाच छ महीने इनक्री-मेंट्स रोकी और उसके लिलाफ जब वे भ्रील में गए तो उनको बानिय मिली और वे छट गए।

डा० रामबी लिह बेनामी किसी नाम से क्या हो नकला है?

भी बुजलाल बर्मा बेनामी नहीं है हमारे खातों से किस के नाम से जमा हुआ और किस के नाम से विडार हुआ “विल्कुल साक है।”

डा० रामबी लिह हस्ताक्षर किस ने प्रभागित किए हैं?

भी बुजलाल बर्मा। यह जाच का सबाल है। लेकिन हमारा काम एवं दैसी का काम होता है। हम उसके हककार नहीं हैं। अगर एक गरीब आधिकारी जमा है कहीं से पचास हजार लाता है या एक करोड़ लाता है अब वह कहा से लाता है इसकी जाच हम नहीं कर सकते हैं, यह हमारे आधिकार से बाहर की ओर है। हम सिक जमा करने वाले हैं और विल्कुल देने वाले हैं। इसके अलावा इससे हमारा कुछ भलबस नहीं है कि कैसे और कहा से काई लाया है, . . .

डा० रामबी लिह बाहर चारी करके लाया हो?

भी बुजलाल बर्मा नोटी कर के लाया हो तो भी हमारा काम जमा बनता है। हब नहीं कह सकते हैं कि बाहर वा वैसा है भी और जमा नहीं करेंगे। अगर हम गोंगा करेंगे तो उनटे हमारे ऊपर कारबोरेट हो जाएंगे।

यह कहा गया है कि दो नीन रोज के लिए जमा हुआ जो कि नदा हाना चाहिये था। इसके बारे में फाइलेन्स डिपार्टमेंट के पास हमारे आधिकारियों ने रिपोर्ट की कि इस प्रकार से जमा नहीं रहा है इसको आप दें। १९७४ बै रिपोर्ट की। ऐसी बात नहीं है कि नहीं की। परन्तु एक्षण हम नहीं ले सकते हैं। फाइलेन्स डिपार्टमेंट या इनकम टैकम वाले लेंगे। हम ने उनको सूचना दी है। हमारे आधिकारियों में हांसाना गवर्नरमेंट की भी सूचना दी ही और १९७४ में दे दी। जहा नक कायमीरों लाल की बात है हमने २१-७-७४ को बैकिंग विशाग को इस की सूचना दी। जिम किसी के बारे में डाउन हुआ उसकी सूचना दी। बहुत से डाउनकर्ल लगे उनको सूचना अनवरी, १९७५ में दी, हमारे आधिकारियों ने दी। लंकिंग सब चीजें जो हुई हैं ऐसी पर्सनलिया में हुई है कि जिम का जानते हुए भी हम कुल कर नहीं सकते थे। फाइलेन्स डिपार्टमेंट और इनकम टैकम डिपार्टमेंट का कारबोरेट करनी चाहिये। इनकम ने पहले ही स्पीकर साहब को हमारा किया था कि जो जानकारी ये विशाग दे सकते हैं वह हम नहीं दे सकते हैं। हम तो सिर्फ खाता रखने वाले हैं और अपनी के बतौर काम करते हैं।

जीवती मूलाल भोरे तीन केसिम में क्या जमा दी?

भी बुजलाल बर्मा मैंने बताया है कि इनक्री-मेंट्स रोकी थी। किंतु उसके बाद भ्रील में उनको दोषी नहीं पाया गया। इन्सिए इनको निर्क बानिय दी गई और छोड़ दिया गया।

SHRI VAYALAR RAVI (Chirayinkil) There are some arrears in the rural areas of Haryana. E.D.S. are there

[**Shri Vayalar Ravi**]

in the post offices. But are they authorised to collect money? I think they have not been authorised to do it. What arrangement have you made in these areas?

**SHRI BRIJ LAL VERMA:** It is not only the case of E.D.S. in those post offices, but it is in the case of others also. This thing has happened with regular Government offices also.

**SHRI VAYALAR RAVI:** They have no authority. But what arrangements have been made to collect the money?

**SHRI BRIJ LAL VERMA:** It has not been made....

**श्री राजकीय सिंह :** मैं एक अनियम सवाल पूछता चाहता हूँ। हमारे संचार मंत्री वहाँ ही असहाय और निरीह अनुभव कर रहे हैं। उनसे हम विद्या में अग्र छुल नहीं हो सकता, और वित मंत्री भी छुल नहीं कर पा रहे हैं तो संचार मंत्री जी भी मंत्रिमंडल के एक सदस्य है और ज्यादा रिसॉर्टिविल्टी है। अब अपने नहीं ही बकाया और वित मंत्री इस पर कार्यवाही नहीं कर रहे हैं तो आप तो इसके महत्व को समझते हैं। या अपने मंत्रिमंडल में से जा कर सी० बी० आई० की जांच के लिए आपना प्रस्ताव रखेंगे ताकि इसकी पूरी तहकीकात ही और इस पर कार्यवाही हो सके।

**श्री बृजलाल वर्मा :** मैंने पहले ही कहा कि हम इस में विकलूल असहाय नहीं हैं। हमने पूरे-पूरे कामकाज जो हमें मिले हैं, काइनेस विपाटमेंट और इनकम-टैक्स विपाटमेंट की दो विंग हैं और उनकी जांच चालू है। ऐसी बात नहीं है कि जांच चाल नहीं है। जिस विपाटमेंट ने बोगल कप से यह जमा कराया है, यहाँ तक कि गवर्नरेंस बांकिमंडल को दबाव डालकर, बैंकों के अधिकारियों पर दबाव डालकर, अपने लैंके से विद्या कर के पोस्ट मार्किस में जमा कराया, इस बास्ते जमा करते हैं कि दो-तिहाई पैसा हैल्पेटमेंट काढ़ के लिए मिलता है, इसलिए यह सारी जीवे करते हैं।

**एक भागीदारी सदस्य :** क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि किस एजेंसी ने यह करवाया?

**श्री बृजलाल वर्मा :** बंसीलाल। इस बास्ते ऐसी बात नहीं है, यह सब किया गया है और जीर्णवर्द्धी से अफसरों को दबाकर जैक आफिसरों को बदा कर यह सारी जीवे उन्होंने की है।

जिन अधिकारियों ने इसमें एकत्र लेना है, सुचित कर दिया है, उन्हें सुचित कर दिया है, यह मत सोचिये कि हम किसे चाहते हैं।

**श्रीमती भूषाल गोरे :** आपके आफिसर्स को इस प्रकार दबाया गया तो आपकी ओर भी विमेदारी है, इसकी पूरी जांच करनी हांगी, आप इसे परस्त कीजिए।

**श्री बृजलाल वर्मा :** हमने कर दिया है।

**श्रीमती भूषाल गोरे :** नहीं तो आपके आफिसर्स और पोस्ट आफिसेज बदनाम हो रहे हैं। आपको यह करना चाहिये कि पूरी जांच सी० बी० आई० की तरफ से हो जाये।

**श्री बृजलाल वर्मा :** यह किया है और उसके साथ-साथ 14 करोड़ 54 लाख रुपये....

**एक भागीदारी सदस्य :** क्या यह सरकार इसकी इन्वेस्टीगेशन सी० बी० आई० को सोचेगी?

**श्री बृजलाल वर्मा :** इस प्रकार से जो ग्राविंग्स विपाटमेंट ने कर्ज के कप में ज लिया है उसके बसूली के लिए काइनेस डिपाटमेंट ने 7 किलों की है और हरियाणा विपाटमेंट से बसूली कर रही है। इसकी भी कार्यवाही काइनेस डिपाटमेंट ने कर दी है और उनसे बसूली भूक हो गई है। यह सारी कार्यवाही हो रही है। जिस प्रकार से बोगल हंग से जमा कर के ज्यादा पैसा कर्ज में से लिया जाता है, जब वे लेने वाले जो ग्राविंग्स विपाटमेंट ने जाता रहा है, वह इसका फायदा न उठा पाये, इसके लिए भी काइनेस डिपाटमेंट ने कार्यवाही कर दी है। इस प्रकार से यह मत सोचिये कि किसी भी प्रकार से काइनेस डिपाटमेंट या इनकम-टैक्स डिपाटमेंट कप बैठा है। कार्यवाही भूक हो गई है। क्योंकि यह पुरानी सरकार का गलत काम है और उस गलत काम को हम किसी भी प्रकार से बदाकर करने के लिए तैयार नहीं है, जो कुछ भी हो सकता है, नियमानुसार हम काम कर रहे हैं। माननीय सदस्य यह न तोचें कि हम किसी बात को उनसे लियाएंगें। यह सब से बड़ा स्वतंत्र है, जहां पर सारे देश के प्रतिनिधि हैं। हम उनसे कोई बात छिपायेंगे नहीं, और नियमानुसार जो भी उचित कार्यवाही हांगी, उसको करेंगे, और इसमें किसी प्रकार से भुक्तान नहीं करेंगे।

18.31 hrs.

*The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, April 12, 1979/Chaitra 22, 1901 (Saka)*

---

---

© 1979 BY LOK SABHA SECRETARIAT

---

---

Published under Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure and conduct  
of Business in Lok Sabha (Sixth Edition) and printed by the General Manager,  
Government of India Press, Minto Road, New Delhi.

---

---